

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 92वीं बैठक



दिनांक : 31.01.2004

समय : 10.30 बजे पूर्वान्ह

स्थान : कान्फ्रेंस हॉल,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद ।

एक सुन्दर शहर-हमारा संकल्प

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 31-01-2004 की कार्यसूची ।

मद सं०	विषय	पृष्ठ सं०
1-	प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 23-6-2003 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	1-5
2-	प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 23-6-2003 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या ।	6-28
3-	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अलोकप्रिय अनिस्तारित सम्पत्ति का मूल्यांकन हुडको से कराकर ज्वाइट वेचर के आधार पर विक्रय करने के सम्बन्ध में।	29
4-	शाहदरा से गाजियाबाद तक दिल्ली मेट्रो के निर्माण का अनुमोदन।	30
4(क)-	मैट्रो रेल के निर्माण हेतु अर्थ प्रबन्ध।	31-32
5-	राष्ट्रीय राजमार्ग-58 दिल्ली सीमा से मेरठ तक 6 लेन डिवाइडिड एक्सप्रेस वे का बीओटीओटीओ पर निर्माण के सम्बन्ध में विचार व प्रस्ताव एमओएसटीओ को प्रेषण।	33
6-	राष्ट्रीय राजमार्ग -58 (मेरठ रोड) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 24 (हापुड रोड) बाईपास को जोड़ने हेतु 6 लेन लिंक रोड के निर्माण के सम्बन्ध में।	34-38
7-	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के भूखण्डों के ले-आउट प्लान के पुर्ननियोजन/ भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	39-41
8-	नेहरूनगर योजना के सेक्टर-3 स्थित एच ब्लॉक में 367.19 व०मी० व्यवसायिक भूखण्ड का भू-उपयोग आवासीय परिवर्तन के सम्बन्ध में।	42-43
9-	पटेलनगर ए-ब्लॉक में स्थित लोकल शाप भूखण्ड को आवासीय में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	44-45
10-	गाजियाबाद नगर में फ्लाई ओवर, रोड ओवर ब्रिज एवं ग्रेड सैपरेटर्स बनाये जाने के सम्बन्ध में।	46-50
11-	इन्दिरापुरम योजना के स्वर्णजयन्ती पार्क के सौन्दर्यीकरण एवं विकास के संबंध में।	51
12-	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मे प्राँपर्टी मैनेजमेन्ट साफ्टवेयर के सम्बन्ध मे।	52
13-	प्राधिकरण की योजनाओं का लैण्ड आडिट सर्वे कराये जाने के सम्बन्ध में।	53
14-	गढमुक्तेश्वर में भूमि अर्जन के सम्बन्ध में।	54
15-	ग्राम मोरटा, रईसपुर,ढरगल,महीउद्दीनपुर, मैनापुर, हरसांव, सदरपुर की 1000 एकड भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में।	55
16-	ट्रान्सपोर्ट नगर योजना विकास हेतु ग्राम बौझा एवं घूकना के अर्जन प्रस्ताव निरस्त करने हेतु।	56
17-	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन /वर्कचार्ज कर्मचारियों को वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।	57-59
18-	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन/ वर्कचार्ज/ संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु उपरान्त उनके आश्रित को प्राधिकरण में रखे जाने विषयक।	60-61
19(क)-	श्री अजयपाल सिंह ,दैनिक वेतन लिपिक की पत्नी के ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान विषयक।	62

- (ख)–श्री प्रतोष कुमार शर्मा अवर अभियन्ता के पिता के ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान किये जाने विषयक। 63
- (ग)–श्री एच0 के सिंघल, अवर अभियन्ता की पुत्री के ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान किये जाने विषयक। 64
- 20– विजयनगर पुर्नवास योजना (सेक्टर-11 व 12) में झुग्गीवासियों को आवंटित भूखण्डों पर ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में। 65–66
- 21– कौशाम्बी योजना में रियायती दर पर रजिस्ट्री हेतु समय वृद्धि हेतु प्रस्ताव। 67
- 22– संजयनगर योजना में रिक्त भवनों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में। 68
- 23– शास्त्रीनगर, लाजपतनगर अपार्टमेन्ट मय गैराज व राजेन्द्रनगर के रिक्त भवनों को नीलामी द्वारा बेचे जाने के सम्बन्ध में। 69.69ए
- 24–(क) किराये की सम्पत्तियों के निस्तारण की सीमा दिनांक 31-3-04 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में। 70–73
- (ख) भवन सं0 एन-80 संजयनगर सेक्टर -23 जी0एम0पी0 को अमितव्ययी घोषित करने के सम्बन्ध में। 74
- (ग) संजयनगर योजना के अन्तर्गत एन0-ब्लाक में स्टाफ के लिए निर्धारित मूल्य पर भवन सं0 एन-90 कय करने के सम्बन्ध में। 75
- 25– कुरसैला बिल्डर्स को वैशाली योजना में आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-21 पर देयता के सम्बन्ध में। 76–78
- 26– श्री शिरडी साई दिव्य ज्योति को आवंटित भूखण्ड जो निरस्त किया गया था, की बहाली विषयक। 79
- 27– गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रोग्रामर के पद पर कार्यरत श्री अतुल शर्मा का विनियमितीकरण किये जाने विषयक। 80–84
- 28– श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल भूखण्ड स्थित नीति खण्ड-3 इन्दिरापुरम पर भुगतान विवरण में भुगतान में विलम्ब एवं तदनुसार ब्याज को माफ करने के संबंध में। 85
- 29– रिट याचिका सं0 54927 / 2002 मै0 खेमका स्टूअर्स लेजर लि0 बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं अन्य में मा0उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के सम्बन्ध में। 86–91
- 30– भूखण्ड सं0 ए-309 व 309-ए सूर्यनगर गाजियाबाद के पास रिक्त भूमि 131.81व0मी0 श्रीमती शैलकुमारी सिंह को आवंटन के विषय में। 92
- 31– परमवीर चक्र,गोल्ड मैडल पाने वाले सैनिक अधिकारियों/ कर्मचारियों और खिलाड़ियों को रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में। 93
- 32– उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को प्राधिकरण योजना में भूखण्ड आरक्षित करने के सम्बन्ध में। 94
- 33– खसरा नं0 781, 782, 776, 2524 (क) ग्राम डासना मसूरी गाजियाबाद में जमियत कालिज आफ फार्मसी एण्ड एलाईड साईन्सेज के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में। 95
- 34– भवन सं0 बी-65 एच0आई0जी0 डुपलेक्स संजयनगर के सम्बन्ध में। 96
- 35– हरित क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में नीति। 97
- 36– प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्कूल भूखण्डों के आवंटन हेतु नियम व शर्तों के सम्बन्ध में। 98

- 37- प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित सामुदायिक केन्द्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में। 99-102
- 38- विभिन्न योजनाओं में पेट्रोल पम्प हेतु रिक्त भूखण्डों को नीलामी द्वारा आवंटित किय जाने के सम्बन्ध में। 103
- 39- प्राधिकरण की वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 की बैलेन्सशीट अनुमोदन हेतु। 104-167
- 40- गाजियाबाद महायोजना 2021(प्रारूप) की स्वीकृति के सम्बन्ध में। 168-173
- 41- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार कराये गये विजन स्टेटमेन्ट-2021 का प्रस्तुतीकरण व अनुमोदन। 174-182
- 42- अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 31-1-2004 के अतिरिक्त मदों की कार्यसूची

-
- | | |
|---|---------|
| 42- प्राधिकरण में एक नग इन्डिकाकार कय करने के सम्बन्ध में । | 183 |
| 43- उ0प्र0सरकार द्वारा आवासीय क्षेत्र में पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की नीति निर्धारण के सम्बन्ध में । | 184-185 |
| 44- गाजियाबाद महायोजना- 2021 तथा मोदीनगर महायोजना 2001में विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं / उपयोगों की अनुमति के सम्बन्ध में । | 186-190 |
| 45- प्राधिकरण में ई0डब्ल्यू0एस0 वैशाली योजना में समर्पण / निरस्तीकरण के फलस्वरूप रिक्त हुए भवनों को मूल्यांकन हेतु ब्याज की गणना अवधि के पुनरीक्षण हेतु प्रस्ताव | 191 |
| 46- श्रीमती सुधा गुप्ता का परिवर्तन शुल्क माफी के सम्बन्ध में । | 192 |
| 47- भूखण्ड सं0 9,10,10-ए व 10बी प्रताप विहार शिक्षक सहकारी आवास समिति को (सामुदायिक एवं शिक्षक भवन) पर देय लेवी भू-उपयोग परिवर्तन की तिथि तक प्राप्त करने व इसके पश्चात की लेवी माफ करने तथा 5 वर्ष का निर्माण हेतु समय प्रदान करने के सम्बन्ध में । | 193 |
| 48- भूखण्ड सं0 आर-171 नन्दग्राम पर देय चौकीदारा शुल्क माफ करने के सम्बन्ध में । | 194 |
| 49- महाविद्यालय श्रेणी के दो विद्यालयों का मानचित्र स्वीकृत किये जाने विषयक । | 195 |
| 50- बिन्सार कोपरेटिव सोसायटी को इन्दिरापुरम में अभय खण्ड-4 में मोड्यूल-1 को जारी भुगतान विवरण दिनांक11-8-99 से 31-1-2004 तक अक्टूबर,1999 में जारी भुगतान विवरण में प्रेषित शर्तों के अनुसार भुगतान विवरण बढ़ाने के सम्बन्ध में । | 196 |
| 51- राजेन्द्रनगर एवं शालीमार गार्डन कालोनी में 500 वर्गमीटर से बड़े भूखण्डों पर अतिरिक्त चौथी मंजिल की स्वीकृति के सम्बन्ध में । | 197-200 |
| 52- स्व वित्त पोषित आधार पर थोक विक्रेताओं की मार्बल मार्केट के विकास के लिए प्रस्ताव | 201-202 |
| 53- गोविन्दपुरम योजना के 'ए' ब्लाक स्थित स्कूल की भूमि पर जा रहे हाईटेंशन लाईन के नीचे की भूमि का भू-उपयोग स्कूल से ग्रीन किये जाने के संबंध में । | 203-204 |

मद संख्या : 1

विषय : प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 23-6-2003 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 23-6-2003 का कार्यवृत्त प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यगण को अवलोकनार्थ भेजा गया था ,जिसमे श्री राजेन्द्र त्यागी ,सभासद नगर निगम गाजियाबाद जो बोर्ड के सदस्य है , के द्वारा भेजे गये कार्यवृत्त पर अपनी राय भेजी गयी है । बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ संलग्न है । पत्र पर की गयी कार्यवाही का व्योरा बोर्ड की अगली बैठक में रखा जायेगा । अन्य सदस्य से कोई टीका प्राप्त नहीं हुई है । अतः कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है ।



ग्राहक

सभासद एवम्

सदस्य, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड

निवात :

आर-7/137, राजनगर,

गाजियाबाद ।

(वार्ड नं० 31, राजनगर)

दूरभाष : निवात : 4781295

4719929

कार्यालय : 4840536

4840537

19 जुलाई, 2003

उपाध्यक्ष,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

गाजियाबाद ।

28/5
24/7

द्वारा : सचिव,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

गाजियाबाद ।

विषय : आपके द्वारा भेजे गये कार्यवृत्त पर भरी राय ।

मान्यवर,

मुझे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 23/6/2003 का कार्यवृत्त अवलोकनायें भेजा गया, जो मुझे 11/7/2003 को प्राप्त हुआ । कार्यवृत्त को पढ़ने के बाद निम्नलिखित के अलावा भरी सहमति है । जिन बिन्दुओं पर भरी असहमति है, उन पर मैं अपने विचार, जो मैंने बोर्ड बैठक में रखे थे, पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ :-

मद संख्या-3 :

जी0डी0ए0 का वित्तीय वर्ष 2003-04 का आय-व्ययक पर चर्चा करते हुए मैंने निम्नलिखित सुझाव दिये थे, जो बोर्ड द्वारा माने गये थे, लेकिन इस कार्यवृत्त में अंकित नहीं हैं :-

1. बजट चुक के अनुसार अवेध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही करना हमारे कार्यों में शामिल है - लेकिन खेद का विषय है कि अवेध निर्माणों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है । मानचित्रों का खुला उल्लंघन करते हुए बहुमुंजलीय आवासीय फ्लैट्स की जेस बाढ़ सी आ गयी है और सम्बन्धित विभाग मूकदर्शक बन चुका है ।

2. बजट चर्चा के दौरान पिछले वर्षों के मलवा चार्जिंग नगर निगम को हस्तान्तरित करने का बोर्ड द्वारा फैसला लिया गया । क्योंकि इस सम्बन्ध में स्पष्ट शासनोदेश हैं । इस सम्बन्ध में आश्वासन या परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है । माननीय

File (प्रमाण)
4/4/2004
(23/7/03)

तथागी

सभासद एवम्

सदस्य, गाजियानाद विकास प्राधिकरण बोर्ड



निवास :

आर-7/137, राजगढ़,

गाजियानाद ।

(पार्स नं० 31, राजगढ़)

दूरभाष : निवास : 4781295

4719923

कार्यालय : 4840586

4840587

// 2 //

अध्यक्ष जी मैं भी इस पर स्पष्ट आदेश दिया था । लखनऊ, इलाहाबाद आदि नगर निगमों में मलवा चार्जिंग पहले से ही नगर निगमों को दिये जा रहे हैं ।

3. सुपरविजन चार्जिंग जो 50 लाख इस वर्ष के लिए रखे गये हैं, भरी जानकारी के अनुसार यह सुपरविजन चार्जिंग इसलिए लिए जाते हैं, कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप निर्माण हो तथा इनका सही तरह से सुपरविजन हो - लेकिन क्या ऐसा हो रहा है ?
4. स्पष्ट तौर पर सामुदायिक केंद्रों को नगर निगम को कालोनियों के हस्तान्तरण के साथ ही हस्तान्तरण की बात बोर्ड में रखी गयी थी, जिसका सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया था । लेकिन कुछ सामुदायिक केंद्रों को जी०डी०ए० द्वारा अपने स्तर पर ही प्रतिष्ठापूर्ण तरीके से रखरखाव कर नागरिकों को उपलब्ध कराने की बात भी तय की गयी थी । लेकिन अध्यक्ष महोदय ने ऐसे निर्देश नहीं दिये थे, कि नगर निगम सर्वप्रथम अपनी कार्यकारिणी में यह प्रस्ताव लाये कि किन शर्तों पर इन सामुदायिक केंद्रों को लेंगा ?
5. बजट पर चर्चा के दौरान भैंरें द्वारा अध्यक्ष जी से आग्रह किया गया था कि " ट्रेनिंग तथा वर्कशॉप " के मद में जो 15 लाख रुपये प्रस्तावित हैं, इस राशि को बढ़ाना जायें तथा जी०डी०ए० के कर्मचारियों व अधिकारियों को अच्छी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जायें, जिससे वह जनता के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट आदि ना करें तथा ग्राहक को भगवान समझें तथा जी०डी०ए० की प्रतिष्ठा के लिए कार्य करें ।
6. "कन्सल्टेशन कास्ट बजट में 7500 लाख रुपये घनराशि रखी गयी है । लेकिन बोर्ड में चर्चा के उपरान्त भी वह सूची नहीं भेजी गयी है - कहाँ कहाँ क्या-क्या विकास के कार्य होंगे ?
7. रखरखाव एवं सफाई के मद में नगर निगम को दिये जाने के लिए 100 लाख रुपये की राशि बजट में रखी गयी थी, जिसको मेने अध्यक्ष जी से बढ़ाने का आग्रह किया था, कि यह राशि कम से कम 20 करोड़ होनी चाहिए । क्योंकि पिछले दिनों जी०डी०ए० के द्वारा गोविन्दपुरम, प्रताप विहार आदि जो कालोनियां नगर निगम

न्यायी

सभासद एनम्
सदस्य, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड



निवास :
आर-7/137, राजनगर,
गाजियाबाद ।
(लार्ड नं० 31, राजनगर)

दूरभाष : निवास : 4781295
4719923
कार्यालय : 4840586
4840587

// 3 //

कों हस्तान्तरित की गयी हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है और ये कालोनियां अद्वैकसित ही नगर निगम को हस्तान्तरित कर दी गयी हैं । इन कालोनियों में सीवर एवं इनेज के डिस्पोजल की भी कोई व्यवस्था नहीं है । अन्य नागरिक सुविधाओं की हालत बहुत ही खराब है । इस पर माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा स्पष्ट व्यवस्था दी गयी थी, कि इन हस्तान्तरित कालोनियों में बाकी बचे कार्यों को जी०डी०ए० ही करायेंगा, जिसकी सूची जी०डी०ए० व नगर निगम के अधिकारी मिलकर बनायेंगे । जो भी वास्तविक व्यय आयेंगा, वह पूर्ण रूप से जी०डी०ए० ही वहन करेगा । माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा यह भी स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि भविष्य में जो भी कालोनियां नगर निगम को हस्तान्तरित की जाएं, वह पूर्ण विकसित अवस्था में ही हस्तान्तरित हों । अद्वैकसित नागरिक सुविधाओं के साथ कोई भी कालोनी भविष्य में नगर निगम को हस्तान्तरित ना की जाये । उपरोक्त कार्यवृत्त में कहीं भी अंकित नहीं है ।

॥2॥ मद संख्या-9 :

यह निर्णय लिया गया था कि शासनादेश में संशोधन होने तक चार-मंजिले फ्लैट्स का मानचित्र पास करने से पहले उस भूखण्ड के आसपास के पड़ोसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है, लेकिन बोर्ड के निर्णय के बाद भी इस तरह के मानचित्र बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के पास किये गये हैं ।

॥3॥ मद संख्या-24 :

जी०डी०ए० के स्टाफ क्वार्टरों व अन्य विभागों को किराये पर आवंटित परिसम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है । कृपया मुझे अवगत कराने का कष्ट करें कि इन परिसम्पत्तियों पर पिछले 10 वर्षों में कितना किराया वक़ाया है? विशेष रूप से जो मकान जी०डी०ए० के दैनिक घेतन भोगी स्टाफ को किराये पर आवंटित हैं, क्या उनके घेतन से प्रतिमाह किराया काटा जा रहा है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो कितने वर्षों का वक़ाया है और क्यों नहीं वसूला गया ?

र त्प्याग्नी

सभासद एवम्

सदस्य, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड



निवासा :

आर-7/137, राजनगर,

गाजियाबाद ।

(वार्ड नं० 31, राजनगर)

दूरभाष : निवास : 4781295

4719923

कार्यालय : 4840586

4840587

// 4 //

॥4॥ मद संख्या-39 :

के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि यह प्रस्ताव क्यों रखा गया तथा फिर क्यों वापस ले लिया गया ? इस प्रस्ताव की ^{विषय} ~~विषय~~ सामग्री की तथा प्रस्तावों में कहे गये कथन की गम्भीरतापूर्वक जांच करायी जानी चाहिए ।

मान्यवर, अन्त में बैठक समाप्ति से पहले यह भी तय हुआ था कि अगली बोर्ड बैठक में पहले स्थगित प्रस्तावों पर ही चर्चा होगी, जो इस कार्यवृत्त में कहीं भी अंकित नहीं हैं । शेष पर मेरी सहमति है ।

धन्यवाद,

प्रतिलिपि सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

॥1॥ श्रीमान अतुल कुमार गुप्ता जी, प्रमुख सचिव, नगर विकास,

उ०प्र० शासन, लखनऊ । एवम्

अध्यक्ष, जी०डी०ए० बोर्ड, गाजियाबाद ।

॥2॥ सचिव, आवास, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।

भवदीय,
(रजेंद्र त्प्याग्नी) 21/7/0

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 23-6-2003 की अनुपालन आख्या

क्रम सं०	विषय	निर्णय	अनुपालन आख्या
1-	प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 20-2-2003 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20-2-2003 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गयी।	बोर्ड बैठक दिनांक 23-6-2003 का कार्यवृत्त सदस्यगण को भेजा गया। श्री राजेन्द्र त्यागी सभासद को छोड़कर अन्य किसी सदस्य से कोई टीका प्राप्त नहीं हुई है। श्री त्यागी का पत्र बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
2-	प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 20-2-2003 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या।	प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 20-2-2003 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई।	कार्यवाही वांछित नहीं है।
3-	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2003-2004 का आय-व्ययक।	उपाध्यक्ष द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के आय-व्ययक की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए अवगत कराया कि वर्ष 2002-03 की प्रस्तावित आय रू० 20688-50 लाख के सापेक्ष रू० 30483-75 लाख की कुल आय इस वर्ष अर्जित की गई जो कि प्रस्तावित आय का 147-34 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2003-04 में रू० 24114-50 लाख की आय एवं रू० 24783-60 लाख का व्यय प्रस्तावित किया जा रहा है। उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा बैंकों / हुडको	

के समस्त ऋणों का प्रतिदान समय से अग्रिम में कर लिया गया है , जो कि अपने आप में एक मिशाल है एवं इस प्रशंसनीय कार्य की प्राधिकरण की सर्वत्र प्रशंसा हुई है । अध्यक्ष तथा सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्राधिकरण के इस भागीरथ प्रयास को सफल बनाने में सहभागी अधिकारियों / कर्मचारियों की प्रशंसा की गई एवं उन्हें शासन स्तर पर पुरस्कृत किए जाने का निर्णय लिया गया ।

जिन निर्माण एवं विकास कार्यों का आय-व्ययक में प्राविधान किया गया है, उनका विवरण भी बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए एवं प्राविधानित सभी कार्य समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

शासकीय ऋण के भुगतान के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि सचिव, गा0वि0प्रा0 अपने स्तर पर शासकीय विभागों एवं प्राधिकरण की आपस में क्या-क्या देनदारियों अवशेष हैं, उसका विवरण अद्यावधिक तैयार कर शासन को विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत करेंगे । तद क्रम में शासकीय ऋण के भुगतान हेतु भुगतान विवरण तैयार कर लिया जाए ।

इसी प्रकार अनिस्तारित सम्पत्ति के निस्तारण हेतु और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा ऐसी सम्पत्तियों

दिनांक 1-4-2003 से 15-12-03 तक निर्माण एवं विकास कार्यों पर किये गये व्यय का विस्तृत विवरण चार्ट संलग्न है।

शासकीय विभागों पर प्राधिकरण की देयता को शासकीय ऋणों में समायोजन करने हेतु प्राधिकरण के पत्रांक 39/ ले0अनु0/ 03 दिनांक 4-6-03 एवं पत्रांक 936 दिनांक 7-11-03 द्वारा शासन से अनुरोध किया गया है।

अनिस्तारित सम्पत्ति की कार्य योजना बनाकर निस्तारण किया जा रहा है।



का अद्यावधिक विवरण तैयार करते हुए निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए ।

मनोनीत सदस्यगणों का मत था कि नगर निगम को हस्तान्तरित कालोनियों में प्राधिकरण द्वारा निर्मित सामुदायिक केन्द्रों का रखरखाव उचित ढंग से किया जाए । कई सदस्यों का मत था कि प्रथम चरण में कविनगर, नेहरूनगर एवं विवेकानन्द नगर में निर्मित सामुदायिक केन्द्रों को नगर निगम को हस्तान्तरित कर दिया जाए । अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि नगर निगम सर्व प्रथम अपनी कार्य कारिणी में यह प्रस्ताव लाएँ कि किन शर्तों पर इन सामुदायिक केन्द्रों को लेगा तथा इस बीच प्राधिकरण अपने स्तर पर भी दिल्ली नगर निगम से जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ बिड / औक्शन करने से क्या फिगर सामने आयेगी, पर भी रिपोर्ट तैयार कर लें, किन्तु इन सामुदायिक केन्द्रों के रेट युक्ति संगत होने चाहिए ।

स्टैकिंग चार्जेज के सम्बन्ध में मा० गैर सरकारी सदस्यों ने इसे नगर निगम को दिए जाने की संस्तुति की गई , जिसे उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया और यह आश्वासन दिया गया कि इस पर परीक्षण कराकर शासनादेश के अनुरूप अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

नगर निगम द्वारा अपनी कार्यकारिणी से हस्तान्तरित कालोनियों में प्राधिकरण द्वारा निर्मित सामुदायिक केन्द्रों के रखरखाव सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नोएडा से वहाँ की व्यवस्था का प्रारूप प्राप्त कर रहा है। तदनुसार शर्तें निर्धारित की जायेगी।

स्टैकिंग चार्जेज के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से हर्ष ध्वनि के साथ प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2003-04 का प्रस्तावित आय-व्ययक उपरोक्त टिप्पणियों के साथ स्वीकृत किया गया ।
उपाध्यक्ष द्वारा बजट पारित होने पर अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यगणों का धन्यवाद किया गया ।

- 4- गढमुक्तेश्वर शहर के सुनियोजित विकास हेतु भूमि अर्जन प्रस्ताव । प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । अनुपालन हो रहा है ।
- 5- आवास विकास परिषद द्वारा अर्जित की जा रही ट्रोनिका सिटी के पास ग्राम मण्डौला नानू व अगरौला की भूमि एवं प्रताप विहार योजना के पास ग्राम मिर्जापुर कैला अकबरपुर बहरामपुर एवं शाहपुर मिटठेपुर की भूमि में से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अर्जन हेतु भूमि प्राप्त करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में । प्रस्ताव स्वीकार किया गया । निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
- 6- राष्ट्रीय राजमार्ग-58(मेरठ रोड) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-24 (हापुड रोड) बाईपास को जोड़ने हेतु लिंक रोड के निर्माण के सम्बन्ध में । प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । 6 लेन का रोड तैयार किये जाने हेतु प्रस्ताव पुनः मद संख्या-6 पर प्रस्तुत किया जा रहा है ।



- 7- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संयुक्त उद्यम (ज्वाइन्ट वेन्चर) द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन कराने के सम्बन्ध में ।
- प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। वॉच्छित कार्यवाही प्रारम्भ कर ली जाए। चूँकि यह एक प्रकार का नया प्रयोग है, अतः यह भी निर्देश दिए गए कि इस सम्बन्ध में एक प्रेजेन्टेशन बोर्ड के सदस्यगणों को विस्तृत में दिखाया जाए, जिससे कि उन्हें इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सही जानकारी प्राप्त हो सके । तदोपरान्त ही अन्तिम रूप से कमिट (Commit) किया जाये।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी के सम्बन्ध में शासन द्वारा नवीन नीति तैयार की गयी है तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 8- आवास विभाग के अधीन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित परिसम्पत्तियों पर पावर आफ एटार्नी के माध्यम से अन्तरण करने के दिनोंक 31-3-2003 तक कार्य योजना शा0सं0क0नि0-5-412/11-2003- 312(286)/2002 दिनोंक 23-1-2003 के अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।
- प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
- अनुपालन हो चुका है। कुछ मामले अभी रजिस्ट्री हेतु शेष हैं जिसके सम्बन्ध में शासन से आदेश मांगे गये हैं परन्तु अभी शासन से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
- 9- प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित राजनगर, कविनगर, नेहरूनगर, शास्त्रीनगर तथा सूर्यनगर, चन्द्रनगर व रामप्रस्थ, रामपुरी एवं रामप्रस्था योजनाओं आदि में चार मंजिले फ्लैटों की अनुमति न दिये जाने के सम्बन्ध में ।
- क्योंकि वर्तमान व्यवस्था जिसमें संशोधन का प्रस्ताव है, शासन के आदेश द्वारा निर्धारित है, निर्णय लिया गया कि इसे शासन को विचारार्थ एवं शासनादेश में संशोधन हेतु भेजा जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि इस बीच प्राधिकरण शासन के संलग्नक पत्रांक के क्रम में जिस भूखण्ड का
- भवन उपविधि में संशोधन विषयक प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। अभी शासन से दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। प्राधिकरण में जमा होने वाले मानचित्रों पर निर्णयानुसार पडोसी से अनापत्ति प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

मानचित्र भविष्य में स्वीकृत करेगा, उसके पडोसी से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा ।

- 10— यू0पी0एस0आई0डी0सी0 इण्डस्ट्रीयल एरिया के सडक की दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र में हुए अनाधिकृत निर्माणों को समायोजित करते हुए एक सैक्टर प्लान बनाने के सम्बन्ध में ।
- प्लान बनाकर नियमानुसार सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की जायें तथा अन्तिम रूप से स्वीकृति से पूर्व पुनः बोर्ड के समक्ष लाया जाये ।
- जनसामान्य से आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। कुल 3 आपत्ति/ सुझाव प्राप्त हुए हैं। आपत्तिकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से समिति के समक्ष सुनवाई करके सैक्टर प्लान को अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- 11— गढमुक्तेश्वर ब्रजघाट विकास क्षेत्र में प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से कराये जाने वाले कार्य ।
- प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
- अवस्थापना निधि से हाई मास्ट लाईट लगाने का कार्य की निविदा हो चुकी है तथा अन्य कार्यवाही चल रही है।
- 12— गोविन्दपुरम योजना में ई-ब्लॉक एल0आई0जी0 (के होम) भवनों के मूल्यांकन एवं विक्रय के सम्बन्ध में ।
- प्रस्ताव स्वीकार किया गया । पूर्ण प्रयास किया जाए कि सम्पत्ति का निस्तारण प्रस्ताव के अनुसार निर्धारित अवधि में हो जाए ।
- अनुपालन किया जा रहा है। इंस्टेन्ट सेल योजना चलाई जा रही है।
- 13— गोविन्दपुरम योजना में जे-ब्लॉक एच0आई0जी0 डूप्लैक्स भवनों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में ।
- प्रस्ताव स्वीकार किया गया । पूर्ण प्रयास किया जाए कि सम्पत्ति का निस्तारण प्रस्ताव के अनुसार निर्धारित अवधि में हो जाए ।
- अनुपालन किया जा रहा है। इंस्टेन्ट सेल योजना चलाई जा रही है।
- 14— लाजपतनगर एपार्टमेंट योजना के अन्तर्गत रिक्त भवनों को मय गैराज के दिनोंक 31-7-2000 के मूल्य पर विक्रय किये जाने हेतु ।
- प्रस्ताव स्वीकार किया गया । पूर्ण प्रयास किया जाए कि सम्पत्ति का निस्तारण प्रस्ताव के अनुसार निर्धारित अवधि में हो जाए ।
- प्रस्ताव पुनः मद संख्या- 23 पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

- 15- शास्त्रीनगर योजना में निर्मित शेष बचे 38 भवनों की तत्काल आवंटन योजना निकाले जाने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव स्वीकार किया गया। पूर्ण प्रयास किया जाए कि सम्पत्ति का निस्तारण प्रस्ताव के अनुसार निर्धारित अवधि में हो जाए। अनुपालन किया जा रहा है। इंस्टेन्ट सेल योजना चलाई जा रही है।
- 16- इन्दिरापुरम आवासीय योजना के नीति खण्ड-3 में निर्मित एच0आई0जी0 डूप्लैक्स भवनों को तत्काल आवंटन में विक्रय हेतु मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में। प्रस्ताव स्वीकार किया गया। पूर्ण प्रयास किया जाए कि सम्पत्ति का निस्तारण प्रस्ताव के अनुसार निर्धारित अवधि में हो जाए। अनुपालन किया जा रहा है। इंस्टेन्ट सेल योजना चलाई जा रही है।
- 17- इन्दिरापुरम आवासीय योजना के अग्र खण्ड-3 में निर्मित मिनी एम0आई0जी0 (एफ0एस0) भवनों के विक्रय हेतु मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में। प्रस्ताव स्वीकार किया गया। पूर्ण प्रयास किया जाए कि सम्पत्ति का निस्तारण प्रस्ताव के अनुसार निर्धारित अवधि में हो जाए। अनुपालन किया जा रहा है। इंस्टेन्ट सेल योजना चलाई जा रही है।
- 18- कौशाम्बी योजना में रजिस्ट्री में गति प्रदान करने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्रस्ताव पुनः मद सं0-21 पर प्रस्तुत किया जा रहा है।
- 19- किराये की सम्पत्तियों के निस्तारण की समय सीमा दिनोंक 31-7-2003 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 1 व 2 को स्वीकार किया गया। प्रस्ताव पुनः मद सं0-2431 पर प्रस्तुत है।
- 20- स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में। प्रस्ताव वापिस लिया गया। कार्यवाही वांछित नहीं है।
- 21- भवन संख्या बी-48 नेहरू एपार्टमेंट को भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उ0प्र0 के कार्यालय हेतु किराये पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में। क्यों कि शासन द्वारा किराये पर सम्पत्तियों के आवंटन पर प्रतिबन्ध है, परन्तु वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रस्ताव शासन को संस्तुति के साथ सन्दर्भित किए जाने का निर्णय लिया गया। निर्णयानुसार शासन को पत्र भेजा जा चुका है।

- 22- 30प्र0 विधान सभा / विधान परिषद के सदस्यों को प्राधिकरण योजना में भूखण्ड आरक्षित करने के सम्बन्ध में । प्रस्ताव स्वीकार किया गया । अनुपालन हो चुका है ।
- 23- प्राधिकरण बोर्ड में जनता के प्रतिनिधि के रूप में नामित सदस्यगण को भूखण्ड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में । बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को सन्दर्भित किए जाने का निर्णय लिया गया । निर्णयानुसार शासन को पत्र भेजा जा चुका है ।
- 24- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण स्टाफ क्वार्टर्स व अन्य विभागों को किराये पर आवंटित परिसम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में । प्रस्ताव स्वीकार किया गया । स्टाफ कर्मचारियों को नामित करने की सुविधा अनुमन्य की गयी । एकमुश्त भुगतान पर केवल 10 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी । स्टाफ क्वार्टर्स में भूमि के वर्तमान मूल्य तथा भवन के डेप्रिसिएटिड मूल्य पर मूल्यांकन किया जाये और इसी फार्मूले पर जिन भवनों का विक्रय हो चुका है, उनके मामलों का भी परीक्षण कराकर यदि इससे कम धनराशि पर मूल्यांकन हुआ है तो अन्तर की धनराशि की वसूली की जाये । अन्य विभागों के लिये भी उपरोक्तानुसार कास्टिंग कर सम्पत्ति का निस्तारण किया जायेगा । अनुपालन किया जा रहा है ।
- 25- पटेलनगर ए ब्लॉक स्थित लोकल शॉप भूखण्ड को आवासीय में परिवर्तन के सम्बन्ध में । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया । प्रस्ताव पुनः मद सं०...9.....पर प्रस्तुत किया जा रहा है ।



- 26- खसरा नं० 154 ग्राम अबुपुर एवं खसरा नं० 128 एवं 131 ग्राम युसुफपुर मनोटा के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया । प्रस्ताव वापिस लिया गया ।
- 27- खसरा नं०-389 ग्राम औरंगाबाद गदाना मोदीनगर के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया । प्रस्ताव वापिस लिया गया ।
- 28- एफ-7 गोविन्दपुरी मोदीनगर के भू -उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव । प्रस्ताव वापिस लिया गया । कार्यवाही वांछित नहीं है ।
- 29- गोविन्दपुरम योजना के ए-ब्लाक स्थित स्कूल की भूमि पर जा रहे हाईटेंशन लाईन की नीचे की भूमि का भू-उपयोग स्कूल से ग्रीन किये जाने के सम्बन्ध में । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया । प्रस्ताव वापिस लिया गया ।
- 30- 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन विजयनगर में पुर्नवास योजना में झुग्गी झोपड़ी वासियों को आवंटित प्लान पर ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में । प्रस्ताव स्वीकार किया गया । प्रस्ताव पुनः मद सं० 20 पर रखा जा रहा है ।
- 31- संजयनगर योजना के सडक के अधिक भाग का भू-उपयोग आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया । प्रस्ताव वापिस लिया गया ।

- 32— गाजियाबाद जनपद स्थित मोदीनगर की महायोजना के अर्न्तगत ग्राम बेगमाबाद, बुढाना, औरंगाबाद, गडना की भूमि पर भू-उपयोग परिवर्तन औद्योगिक से आवासीय/वाणिज्य किये जाने के सम्बन्ध में । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया । प्रस्ताव शासन को विचार हेतु भेजा गया है ।
- 33— नेहरूनगर योजना के सेक्टर-3 स्थित एच-ब्लाक में 367.19 वर्ग मीटर व्यवसायिक भूखण्ड का भू-उपयोग आवासीय परिवर्तन के सम्बन्ध में । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया । प्रस्ताव पुनः मद संख्या 8 पर प्रस्तुत किया जा रहा है ।
- 34— कुरसेला बिल्डर्स को वैशाली योजना में आवंटित गुप हाऊसिंग भूखण्ड सं०-21 पर देयता के सम्बन्ध में । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया । प्रस्ताव पुनः मद सं० 25 पर प्रस्तुत किया जा रहा है ।
- 35— भूखण्ड संख्या बी-68 पटेलनगर-2 पर देय ब्याज, दण्ड ब्याज एवं लैवी को माफ किये जाने के सम्बन्ध में । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया । प्रस्ताव वापिस लिया गया ।
- 36— श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप, मा० सदस्य, विधान परिषद, उ०प्र० को आवंटित भवन संख्या जी-554, गोविन्दपुरम के विपरीत देय दण्ड ब्याज से मुक्त करने के सम्बन्ध में । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया । प्रस्ताव वापिस लिया गया ।
- 37— मै० बाबा कन्स० प्रा० लि० द्वारा निर्माणाधीन वैशाली योजना में गंगा टावर के कार्य में हो रही बचत के फलस्वरूप प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया । प्रस्ताव वापिस लिया गया ।

व्यवसायिक केन्द्र ब्लाक संख्या-6 के अवशेष कार्य को इसी अनुबन्ध के अन्तर्गत पूरा कराने के सम्बन्ध में ।

- 38— श्री शिरडी साई दिव्य ज्योति को आवंटित भूखण्ड जो निरस्त किया गया था, की बहाली विषयक । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया । प्रस्ताव पुनः मद संख्या 26 पर प्रस्तुत किया जा रहा है ।
- 39— गाजियाबाद विकास प्राधिकरण योजना में सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि को हरपाल सिंह मैमोरियल एवं रिसर्च फाऊन्डेशन हेतु आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में । प्रस्ताव वापिस लिया गया । कार्यवाही वांछित नहीं है ।
- 40— गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन / वर्कचार्ज कर्मचारियों को वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया । प्रस्ताव पुनः मद सं० 17 पर प्रस्तुत किया जा रहा है ।
- 41— श्री प्रतोष कुमार शर्मा, अवर अभियन्ता के पिता के ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान किये जाने विषयक । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया । प्रस्ताव पुनः मद सं० पर प्रस्तुत किया जा रहा है । (प्रस्ताव)
- 42— न्यू एडवांस एजुकेशनल सोसायटी, 38 रमते राम रोड, गाजियाबाद को वैशाली योजना में स्कूल भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया । प्रस्ताव वापिस लिया गया ।
- 43— ब्याज दर में कमी के सम्बन्ध में । प्रस्ताव स्वीकार किया गया । निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

Se

- 44 आयकर धारा- 10(20-ए) के अधीन छूट समाप्त होने के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली टैक्स प्लानिंग । प्रस्ताव स्वीकार किया गया । टैक्स प्लानिंग के अनुसार प्राधिकरण के लेखे तैयार कर दिनांक 1-12-03 को विकास प्राधिकरण की आयकर रिटर्न दाखिल कर दी गयी है।
- 45 गाजियाबाद नगर में रोड ओवर ब्रिज तथा फ्लाई ओवर बनाये जाने के सम्बन्ध में । प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई । लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही की जा रही है। संशोधित प्रस्ताव पुनः मद सं०-18 पर प्रस्तुत किया जा रहा है।
- 46 गढमुक्तेश्वर - ब्रजघाट क्षेत्र में मानचित्रों पर शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में । प्रस्ताव स्वीकार किया गया । बोर्ड निर्णय अनुसार मानचित्र शुल्क लिया जा रहा है।
- 47 रिट याचिका सं० 54927 /2002 मै० खेमका स्टूअर्स लीजर लिमिटेड बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के सम्बन्ध में । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया । प्रस्ताव पुनः मद संख्या-29 पर प्रस्तुत किया जा रहा है।
- 48 वैशाली ग्रुप हाऊसिंग योजना में आवंटित आवासीय भूखण्ड सं० 18 का विक्रय विलेख निष्पादित किये जाने के सम्बन्ध में । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया । प्रस्ताव वापिस लिया गया।
- 49 डा० उषा गुप्ता को आवंटित नर्सिंग होम के सम्बन्ध में ब्याज माफी हेतु प्रस्ताव । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया । प्रस्ताव वापिस लिया गया।

क्र.सं.	कार्य का नाम	उत्केदार का नाम	अनुबन्ध सं०	अनुबन्ध / विचलन धनराशि लाख में	प्रारम्भ तिथि	समाप्ति तिथि/ समय वृद्धि तिथि	प्रारम्भ से 31.3.03 तक व्यय लाख में	1.4.03 से 15.12.03 तक व्यय लाख में	कुल व्यय	भौतिक प्रगति % में	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
				अभियन्त्रण खण्ड - 1							
1	गविन्दपुरम में सड़क सं०-1 की साइड वर्ज का कार्य।	मै० रोहित कन्स०	194 dt. 16.3.01	2.88 26.3.01	19.4.02	2.83	2.76	2.83	2.83	100	
2	गविन्दपुरम में ब्लाक जै० में अवशेष नाली,सीवर,जलापूर्ति	मै० अनुज कन्स०	320 dt. 3.7.03	3.85 7.9.02	7.11.02	1.61	4.01	4.01	4.37	100	
3	सेजयनगर योजना के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में सड़क का निर्माण।	मै० चोधरी कन्स०	379 dt. 10.12.02	3.90 18.12.02	30.4.03	4.01	1.4	0.92	4.01	100	
4	कपूरपुरम में 24 मी व 45 मी चौड़ी सड़क के सेन्ट्रल वर्ज	मै० अनुज कन्स०	410 dt. 27.2.03	2.80 10.3.03	9.4.03	0.92	1.47	2.39	2.32	100	
5	सेजयनगर योजना के ग्राम रईसपुर में सड़क व नाली काकार्य	मै० बी०एन०गुप्ता	401 dt. 18.11.03	4.96 1.2.03	30.10.03	2.39	1.66	0.93	3.86	100	
6	स्वर्णजयन्तीपुरम के ABCDE पाकेट में सीवर कनेक्शन का कार्य	मै० सुन्दर भारद्वाज	157 dt. 18.11.2000	2.40 1.12.2000	30.3.03	0.93	1.89	1.11	2.59	100	
7	गविन्दपुरम में 64 Duplex मवनो का अवशेष कार्य।	मै० मारत कन्स० क०	109 dt. 31.3.98	6.04 12.4.99	31.8.02	1.11	0.71	0.71	3.00	100	
8	गविन्दपुरम में मवन सं० ए-300 की मरम्मत का कार्य।	मै० राजीव कन्स०	400 dt. 18.1.03	0.69 1.2.03	31.7.03	0.71	10.00	10.00	0.71	100	
9	गविन्दपुरम में SPS का निर्माण।	UP JAL NIGAM					0.97	0.25	1.22	100	
10	गविन्दपुरम के ABCDE के मुख्य रोड के किर्नेक्शन का कार्य	मै० नवनीत कुमार	173 dt. 16.11.95	1.23 16.11.95	3.11.01	0.25					
11	गविन्दपुरम योजना ए ब्लाक स्थित पुलिस चौकी का निर्माण	मै० कृष्णपाल कन्स०	385 dt. 19.12.02	1.92 30.12.02	31.12.03					80 %	अनुबन्ध प्रक्रिया में
12	गविन्दपुरम योजना में ग्राम हरसांव का विकास कार्य।	मै० वर्दान्त कन्स०क०	544 dt. 17.12.03	31.24 20.12.03	19.6.04						अनुबन्ध प्रक्रिया में
13	स्वर्णजयन्तीपुरम योजना के ग्राम सदरपुर का विकास कार्य।	मै० कृष्णपाल कन्स०	543 dt. 17.12.03	3.97 22.12.03	21.3.04						अनुबन्ध प्रक्रिया में
मांग -1				3.83							
14	स्वर्णजयन्तीपुरम योजना के ग्राम सदरपुर का विकास कार्य।	मै० जै० एस० बिल्डर्स									
मांग -2											
15	सेजयनगर योजना के डिस्ट्रिक्ट सेंटर के मुख्य नाले पर दो पाईप कनेक्टों का निर्माण कार्य।	मै० बी०एन०गुप्ता एण्ड क०	517/AO/EE-1/03 DT-20-10-03	2.68 3.11.03	04.01.04					5 %	
	योग			72.39			10.15	24.76	34.91		
				अभियन्त्रण खण्ड - 2							
1	इन्दिरापुरम अहिंसा खंड-2 में आन्तरिक सड़कों का कार्य	मै० कृष्णवीर एण्ड क०	297/AO/EE2/02	30.50 15.4.02	09.03.04	4.08	19.44	4.08	23.52	77 %	
2	इन्दिरापुरम के अहिंसा खंड में 80फुट चौड़ी सड़क का कार्य	मै० एस०ए० कन्स०	367/AO/EE2/02	31.93 6.12.02	5.6.03	11.08	13.98	11.08	25.06	78 %	
3	इन्दिरापुरम के सड़क सं० 6 का 5 पार्ट पर सेन्ट्रल वर्ज कार्य	मै० अजय बिल्डर्स	376/AO/EE2/02	14.30 15.12.02	15.11.03	4.30	8.98	4.30	13.28	92 %	
4	इन्दिरापुरम के वैभव खंड में आन्तरिक सड़क का निर्माण	मै० ए०एस० बिल्डर्स	380AO/EE2/02	46.28 13.12.02	12.12.03	28.79	5.14	28.79	33.93	73 %	
5	इन्दिरापुरम के वैभव खंड में मुख्य सं० 8के निकट सड़क व पुलिया का निर्माण कार्य	मै० पियूषा कन्स० क०	377/AO/EE2/02	32.07 22.12.02	30.6.03	14.83		14.83	14.83	46 %	
6	इन्दिरापुरम के अहिंसा खण्ड 2 में विकास कार्य	मै० कृष्णवीर एण्ड क०	398/AO/EE2/02	45.08 20.1.03	19.10.03	14.46	4.50	14.46	18.96	42 %	
7	इन्दिरापुरम के स्वर्ण जयन्ती पार्क में मुख्य पथ का निर्माण कार्य	मै० एम० एस० त्यागी	412/AO/EE2/03	53.17 7.3.03	15.12.03	63.14		63.14	63.14	92 %	

क्रमांक	कार्य का नाम	लेखदार का नाम	अनुषंग सं०	अनुषंग / विवरण संनराशि लाख में	प्रारम्भ तिथि	समाप्ति तिथि / समय वृद्धि तिथि	प्रारम्भ से 31.3.03 तक लाभ में	1.4.03 से 15.12.03 तक लाभ लाख में	कुल लाभ	भौतिक प्रगति % में	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
9	इन्दिरापुरम के नौवें काल्ड 3 व शक्ति काल्ड 2 व 4 में अवस्था निदान एवं का कार्य	श्री अजय शिखर	444/AO/EE2/03	9.50 16.03	30.8.03	30.8.03					
10	इन्दिरापुरम के शक्ति काल्ड 4 में नौवें का कार्य	श्री प्रदीप शर्मा एच के	446/AO/EE2/03	24.37 16.03	30.11.03	30.11.03		21.42	21.42	87 %	
11	इन्दिरापुरम के शक्ति काल्ड 2 में व 155 कुट रोड के बीच वाली मार्ग व सार्वजनिक स्थिति बनाने का कार्य	श्री अजय शिखर	452/AO/EE2/03	16.15 7.603	6.9.03	6.9.03					
12	इन्दिरापुरम के शक्ति काल्ड 2 में सड़क व एलसीसीसी का कार्य	श्री एन एल शिखर	455/AO/EE2/03	14.30 5.603	4.8.03	4.8.03		12.53	12.53	87 %	
13	इन्दिरापुरम के शक्ति काल्ड 2 में रोड का 6 एन अवस्था नाने का निर्माण कार्य	श्री अजय शिखर	451/AO/EE2/03	10.48 10.6.03	9.12.03	9.12.03		7.43	7.43	75 %	
14	इन्दिरापुरम के नौवें काल्ड 3 में सड़क व एलसीसी का कार्य	श्री जे के शिखर	420/AO/EE2/03	7.77 25.4.03	24.12.03	24.12.03		5.52	5.52	71 %	
15	इन्दिरापुरम के शक्ति काल्ड 4 में एलसी का निर्माण कार्य	श्री अजय शिखर	464/AO/EE2/03	6.42 26.6.03	25.12.03	25.12.03					
16	इन्दिरापुरम के शक्ति काल्ड 2 में 155 कुट रोड व नाने का निर्माण कार्य	श्री अजय शिखर	478/AO/EE2/03	21.99 21.7.03	20.10.03	20.10.03		17.24	17.24	78 %	
17	शक्ति काल्ड 2 एलसीसी तक सड़क व एलसीसी का कार्य	श्री राजकुमार शर्मा	473/AO/EE2/03	30.99 1.9.03	30.11.03	30.11.03		27.79	27.79	89 %	
18	शक्ति काल्ड-4 में सड़क व एलसीसी का कार्य	श्री राजकुमार शर्मा	474/AO/EE2/03	24.98 1.9.03	30.12.03	30.12.03		24.81	24.81	98 %	
19	शक्ति काल्ड-4 में एलसी का अवस्था कार्य	श्री एन के	464/AO/EE2/03	21.33 1.9.03	30.11.03	30.11.03		20.81	20.81	97 %	
20	नवम्बर वारानी एलसी में मिट्टी नाला का कार्य	श्री इन्दिरा शिखर	520/AO/EE2/03	10.22 8.10.03	7.11.03	7.11.03					
21	वाणिज्य जलपुष्टि का लक्ष्यकार	श्री दीपशि शिखर	525/AO/EE2/03	2.93 24.11.03	23.11.04	23.11.04					
22	नवम्बर वारानी एलसी में मिट्टी एलसी टवला करने का कार्य	श्री अजय शिखर	531/AO/EE2/03	3.33 21.11.03	20.1.04	20.1.04					
23	नवम्बर वारानी एलसी में मिट्टी एलसी टवला करने का कार्य	श्री अजय शिखर	532/AO/EE2/03	52.72 02.12.03	8.2.04	8.2.04					
24	नवम्बर वारानी एलसी में मिट्टी एलसी टवला करने का कार्य	श्री अजय शिखर	533/AO/EE2/03	52.72 3.12.03	2.6.04	2.6.04					
25	नवम्बर वारानी एलसी में मिट्टी एलसी टवला करने का कार्य	श्री एन के शिखर	536/AO/EE2/03	1.31 9.12.03	2.6.04	2.6.04					
26	नवम्बर वारानी एलसी में मिट्टी एलसी टवला करने का कार्य	श्री एन के शिखर	538/AO/EE2/03	1.20 9.12.03	1.2.04	1.2.04					
27	इन्दिरापुरम के नौवें काल्ड 3 में सड़क व एलसीसी का कार्य	श्री अजय शिखर	537/AO/EE2/03	2.24 20.12.03	11.02.04	11.02.04					
28	इन्दिरापुरम के नौवें काल्ड 3 में सड़क व एलसीसी का कार्य	श्री अजय शिखर	160 of 6 12-00	5.93 8.12.2000	31.3.2000	31.3.2000	5.07	0.87	5.93	100.00	

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध सं०	अनुबंध / विवरण धनराशि लाख में	प्रारम्भ तिथि	समाप्ति तिथि / समय वृद्धि तिथि	प्रारम्भ से 31.3.03 तक व्यय लाख में	14.03 से 15.12.03 तक व्यय लाख में				भौतिक प्रगति % में	अन्य विवरण
								10	11	12	13		
1			4	5	7	8							14
28	इन्दिरापुरम के सीवर लाइन के रखरखाव का कार्य।	श्री शिवम बिल्डर्स।	341 dt. 6.8.02	10.11	6.8.02	5.8.04	4.60	1.36	1.36	5.96	65.00		
29	इन्दिरापुरम से जलापूर्ति का दैनिक रखरखाव का कार्य।	श्री चोहरी कन्स०	345 dt. 23.9.02	1.60	23.9.02	22.9.03	0.47	0.80	0.80	1.27	98.00		
30	इन्दिरापुरम पार्क में सड़क सफाई का कार्य।	श्री दीपाशी कन्स०	378 dt. 16.11.02	2.55	16.11.02	17.8.03	1.14	1.44	1.44	2.58	100.00		
31	इन्दिरापुरम में सड़क सं० 12 पर टेन्स का कार्य।	श्री राज कुमार त्यागी	383 dt. 12.12.02	41.07	12.12.02	30.6.03	43.08	44.32	44.32	44.32	100.00		
32	इन्दिरापुरम सड़क सं० 11.1 पार्क पर टेन्स का कार्य।	श्री राज कुमार त्यागी	384 dt. 17.12.02	45.39	17.12.02	16.2.03		6.82	6.82	49.90	100.00		
33	इन्दिरापुरम के शक्ति खण्ड-1 में सड़क पर टेन्स का कार्य।	श्री हरी शंकर शर्मा	388 dt. 28.12.02	6.86	28.12.02	13.4.03		8.97	8.97	8.97	100.00		
34	इन्दिरापुरम में सड़क सं० 10 पर टेन्स का कार्य।	श्री निशान्त बिल्डर्स।	389 dt. 28.12.02	53.59	28.12.02	27.4.03		55.18	55.18	55.18	100.00		
35	इन्दिरापुरम के मुख्य सड़क पर टेन्स का कार्य।	श्री इन्दिरा बिल्डर्स।	399 dt. 1.2.03	51.87	1.2.03	21.5.03	16.83	41.31	41.31	58.14	100.00		
36	इन्दिरापुरम में कलवर्ट के पास रोड कांसिंग का कार्य।	श्री कोशिक बिल्डर्स।	405 dt. 8.2.03	1.79	8.2.03	7.3.03	1.84	1.84	1.84	1.84	100.00		
37	इन्दिरापुरम में सड़क सं० 10 पर सीवर लाइन गैप का कार्य।	श्री कोशिक बिल्डर्स।	406 dt. 8.2.03	3.24	8.2.03	7.3.03	3.23			3.23	100.00		
38	इन्दिरापुरम में सड़क सं० 4 पर सेंट्रलवर्ज की मरम्मत का कार्य।	श्री कोशिक बिल्डर्स।	407 dt. 8.2.03	2.31	8.2.03	7.3.03		2.32	2.32	2.32	100.00		
39	इन्दिरापुरम में शक्ति व नीति खण्ड में पटरी ड्रेसिंग का कार्य।	श्री दीपाशी कन्स०	415 dt. 11.3.03	1.66	11.3.03	10.4.03	1.43	0.24	0.24	1.67	100.00		
40	इन्दिरापुरम में NH-24 के साथ नाले के दो गैपों का कार्य।	श्री शिवम कन्स०	424 dt. 26.3.03	10.66	26.3.03	25.6.03		11.61	11.61	11.61	100.00		
41	इन्दिरापुरम में सड़क सं०-4 से STP तक टेन्स का कार्य।	श्री निशान्त बिल्डर्स।	428 dt. 10.3.03	18.39	10.3.03	9.6.03		20.08	20.08	20.08	100.00		
42	इन्दिरापुरम के नीति खण्ड में प्रीमिसिंग का कार्य।	श्री राज कन्स०	475 dt. 26.6.03	42.99	26.6.03	25.9.03		47.23	47.23	47.23	100.00		
43	इन्दिरापुरम के सड़क सं०-1 के टी जखान पर सेंट्रलवर्ज का काटकर सड़क निर्माण का कार्य।	श्री जय अम्बिका बिल्डर्स	431 dt. 10.4.03	6.18	10.4.03	30.6.03		3.73	3.73	3.75	100.00		
	योग			874.47			129.73	524.31	524.31	654.05			
				अभियन्त्रण खण्ड - 3									
1	कोशाम्बी योजना में ग्राम भोंवापुर का विकास कार्य	श्री दिनेश कुमार कन्स०	493/AO/EE-3/03	6.42	11.8.03	10.11.03		2.17	2.17	2.17	43.00		
2	कोशाम्बी योजना में सेंट्रल पार्क की मरम्मत का कार्य	श्री जे०के० बिल्डर्स	468/AO/EE-3/03	2.26	5.7.03	19.11.03		1.41	1.41	1.41	82.00		
3	कोशाम्बी योजना में व्यवसायिक प्लॉटों का विकास कार्य	श्री आर० के० कन्स०	391/AO/EE-3/02	13.93	01.01.03	31.3.03	2.42	0.00	0.00	2.42	17.00		
4	कोशाम्बी योजना में 15 मंजिले भवनों में फायर फाइटिंग की सैन्टीनेन्स का कार्य	श्री फायर वर्ल्ड सं० इजी०	93/AO/EE-3/98	40.31	16.11.98	31.12.03		18.53	18.53	18.53	45.00		
5	कोशाम्बी योजना में डबटों की लॉकज ठीक कराने के संबंध में	श्री एन०बी०सी०सी	M O U	324.13	1.11.01		109.42	104.93	104.93	214.35	86.00		

क्र.सं.	कार्य का नाम	उत्केदार का नाम	अनुबन्ध सं०	अनुबंध / विवरण घनराशि लाख में	प्रारम्भ तिथि	समाप्ति तिथि / समय वृद्धि तिथि	प्रारम्भ से 31.3.03 तक व्यय लाख में	1.4.03 से 15.12.03 तक व्यय लाख में	कुल व्यय	भौतिक प्रगति % में	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
6	ग्रामिणी विभिन्न योजनाओं में कुड़ा उठाने का कार्य	श्री० वर्दान्त कन्स० क०	497/AO/EE-3/03	21.77	28.8.03	19.8.04	4.99	4.99	4.99	22.00	
7	ज्ञान खण्ड व अमय खण्ड के मुख्य मार्गों की हेन्स कारपेटिंग का कार्य	श्री० राज कन्स०	522/AO/EE-3/03	92.86	13.11.03	12.2.04	38.08	38.08	38.08	41.00	
8	अमय खण्ड -1 में एचओआईडीओ भवन सं० 149-181 के सामने का विकास	श्री० आर०एस०वी०	477/AO/EE-3/03	3.77	21.7.03	20.10.03	2.08	2.08	2.08	55.00	
9	न्याय खण्ड 2 व 3 में पाईप लाइन बिछाने का कार्य	श्री० कुमार बिल्डर्स	447/AO/EE-3/03	6.87	2.6.03	1.12.03	2.88	2.88	2.88	41.00	
10	न्याय खण्ड, ज्ञान खण्ड व अमय खण्ड की सड़कों की प्रीमिसिंग	श्री० शिवम कन्स०	490/AO/EE-3/03	33.89	11.8.03	10.2.04	30.37	30.37	30.37	89.00	
11	अमय खण्ड-3 के अपूर्ण भवनों के मध्य विकास कार्य	श्री० ए०एस० बिल्डर्स	460/AO/EE-3/03	42.56	16.6.03	15.12.03	18.73	18.73	18.73	44.00	
12	न्याय खण्ड -1 में मूखण्डों का विकास कार्य	श्री० गुरुकुल स्टोन	457/AO/EE-3/03	12.56	15.6.03	15.10.03	3.61	3.61	3.61	28.00	
13	अमय खण्ड-3 के अपूर्ण भवनों का विकास कार्य	श्री० भवानी कन्स०	469/AO/EE-3/03	45.52	22.6.03	11.1.04	33.85	33.85	33.85	74.00	
14	न्याय खण्ड-1 के सामने सड़क सं० 1 व 2 पर हेन्स कारपेटिंग का कार्य	श्री० टैक्नोफाट कन्स०	498/AO/EE-3/03	78.56	3.9.03	2.12.03	32.08	32.08	32.08	40.00	
15	न्याय खण्ड, ज्ञान खण्ड व अमय खण्ड में सीवर अनुसंधान वार्षिक रखरखाव का कार्य	श्री० मोहन कन्स०	434/AO/EE-3/03	2.44	1.5.03	30.4.04	1.23	1.23	1.23	50.00	
16	न्याय खण्ड, ज्ञान खण्ड व अमय खण्ड में वाटर मैन हाल का अनुसंधान	श्री० कुमार बिल्डर्स	369/AO/EE-3/03	3.27	6.12.03	5.12.03	0.56	2.16	2.72	83.00	
17	ज्ञान खण्ड-1 में स्थल कार्यालय की वाटरन्डीवाल का कार्य	श्री० दिव्या योगेश	501/AO/EE-3/03	0.89	19.9.03	18.10.03	0.72	0.72	0.72	80.00	
18	इन्दिरापुरम योजना में मुख्य मार्गों की पटरी ड्रेसिंग का कार्य	श्री० ए०एस० बिल्डर्स	501/AO/EE-3/03	11.35	23.7.03	20.10.03	5.60	5.60	5.60	49.00	
19	50वर्षीय योजना के अन्तर्गत इन्दिरापुरम, कौशाम्बी व वैशाली में चौकीदार रूम, स्टाफ रूम व वाटर टर्क्स की बारन्डीवाल	श्री० राकेश कुमार त्यागी	535/AO/EE-3/03	43.80	10.12.03	9.4.04				10.00	
20	गंगा जल योजना के अन्तर्गत मुख्य योजना का क्रियान्वयन	यू०पी० जल निगम	MOU	3656.56			2211.20	1300.00	3511.20	96.00	
21	इन्दिरापुरम, वैशाली व कौशाम्बी में गंगा जलसंरक्षण व वितरण	यू०पी० जल निगम	MOU	2247.58			1456.00	650.00	2106.00	94.00	
				6691.30			3779.60	2253.42	6033.02		
	योग				अभियन्त्रण खण्ड - 4						

क्र.सं.	कार्य का नाम	उत्प्रेक्षक का नाम	अनुबन्ध सं०	अनुबन्ध / विचलन धनराशि लाख में	प्रारम्भ तिथि	समाप्ति तिथि/ समय वृद्धि तिथि	प्रारम्भ से 31.3.03 तक व्यय लाख में	कुल व्यय	भौतिक प्रगति % में	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	7	8	10	12	13	14
1	डी एल एफ कालोनी शालीमार गार्डन के मुख्य नाले तक एस डबल्यू डेन का कार्य	मै गुरजर कन्स०	454/26.03	9.48	26.03	19.03	3.01	3.01	85 %	
2	गगन विहार से तुलसी निकेतन तक अघूरु पड़े नाले का कार्य	मै० भारत बिल्डर्स	225/AO/EE-4	22.48	7.03	6.104	13.36	13.36	70 %	
3	राधेश्याम पार्क में सड़क, नाली निर्माण व सड़कों की मरम्मत का कार्य	मै० वीरेन्द्र त्यागी	476/7.03	33.13	6.803	5.12.03	7.48	7.48	40 %	
4	तुलसी निकेतन से शालीमार गार्डन तक सीवर का कार्य	मै० ए०एन०बी०	392/4.6	46.29	1.1.03	30.4.03	23.68	41.41	95 %	
5	शालीमार गार्डन में हतिगस्त मुख्य सड़कों का निर्माण कार्य	मै० केशव कन्स०	416/2.3.03	44.59	11.03.03	10.7.03	40.48	40.48	90 %	
6	हस्तिनापुरम योजना के अन्तर्गत टीलागाव में गेट न० 2 का विकास कार्य	मै० बुद्धिल इंजी०	437/	25.18			20.42	20.42		
7	इन्द्रप्रस्थ योजना के पाकेट डी में सड़कों का कार्य	मै० मुकेश वर्मा	445	51.83	25.8.03	7.2.04	36.52	36.52	80 %	
8	शालीमार गार्डन एक्स-1 में टंक सीवर लाईन डालने का कार्य	मै० राजेश्वर बि०	443/25.5.03	127.71	7.6.03	6.3.04	108.79	108.79	80 %	
9	राजबाग कालोनी से वृंदावन गार्डन तक मुख्य सड़कों का कार्य	मै० दिनेश कुमार	515/	7.57	18.8.03	17.10.03	4.23	4.23	90 %	
10	शालीमार गार्डन एक्स-1 में टंक सीवर लाईन डालने का कार्य पार्ट ए	मै० ए०एस०बिल्डर्स	450/29.5.03	115.96	5.6.03	4.3.04	29.54	29.54	35 %	
11	इन्द्रप्रस्थ योजना के पाकेट ई में सड़कों का कार्य	मै० ए के कन्स०	495/14.8.03	38.92	1.9.03	30.3.04	6.57	6.57	20 %	
12	शालीमार गार्डन के पाकेट ए एण्ड बी में आन्तरिक विकास	मै० जी एण्ड जी	530/25.11.03	68.00	25.11.03	24.08.04	17.35	17.35	40 %	
13	इन्द्रप्रस्थ योजना के पाकेट ई में वाटर एवं सीवर का कार्य	मै० कृष्णावीर	504/15.9.03	9.09						अनुबन्ध की प्रक्रिया में
14	इन्द्रप्रस्थ योजना के पाकेट एफ में सड़कों का कार्य पार्ट ए	मै० प्रशान्त	542/11.12.03	35.09	12.12.03	11.09.04			5 %	निविदा प्रक्रिया में
15	इन्द्रप्रस्थ योजना के पाकेट एफ में सड़कों का कार्य पार्ट बी	मै० ए०के०कन्स०	539/9.12.03	35.09	15.12.03	14.09.04				
16	इन्द्रप्रस्थ योजना के पाकेट एफ में सड़कों का कार्य	मै० एन०एस०इन्टर०		65.00						
17	इन्द्रप्रस्थ योजना के पाकेट एफ में उच्च जलाशय का कार्य	मै० जल निगम	एक्स०३०३०	105.00						
18	इन्द्रप्रस्थ योजना के पाकेट एफ में सीवर डालने का कार्य			48.00						
19	इन्द्रप्रस्थ योजना के पाकेट डी की सड़कों पर एस डी सी का कार्य			41.00						
20	हस्तिनापुरम को दिल्ली सीमा से जोड़ने का कार्य	मै० शिवा बिल्डर्स	486 dt 1.8.03	35.16	30.9.03	29.2.04	7.00	7.00	10 %	
21	तुलसी निकेतन के दो नलकूपों की बोरींग का कार्य	ए०एन०जल निगम		8.00					95 %	
22	तुलसी निकेतन के बोरींग के उपर पम्प हाउस राइजिंग मेन का कार्य	ए०एन०जल निगम		58.00						
23	शालीमार में ब्लाक सी की हति गस्त सड़कों का कार्य	मै० बुद्धिल इंजी०	437 dt 14.5.03	35.96	14.5.03	13.11.03	32.57	32.57	95 %	
24	शालीमार के सीवर से हति गस्त सड़कों का कार्य			35.00						
25	शालीमार एक्स-1 में मुख्य सड़कों का कार्य			52.00						
26	राजेश्वर गोल्ल कोर्स की बाउंड्रीवाल का कार्य	मै० पिपूबा कन्स०	485 dt 29.7.03	44.00	18.8.03	17.2.04			10 %	
27	जे०पी०एन०कलेव से मोहन नगर तक नाले का कार्य	मै० राजेश्वर बि०	305/ dt 26.4.03	35.00	26.4.02	25.8.02				
28	शालीमार एक्स 2 के ए बी व सी की आन्तरिक सीवर का कार्य									

[illegible]

क्र.सं.	कार्य का नाम	उपेक्षार का नाम	अनुबन्ध सं०	अनुबंध / विषयानुसार लागू धनराशि	प्रारम्भ तिथि	समाप्ति तिथि/ समय वृद्धि तिथि	प्रारम्भ से 31.3.03 तक व्यय लाख में	14.03 से 15.12.03 तक व्यय लाख में	कुल व्यय	भौतिक प्रगति % में	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
22	देहाती सै० 3 के भीट मार्केट हेतु एगो रोड का कार्य	मै० एस०आर० एन्ट०	500/AO/EE-5/03	1.88	22.9.03	22.11.03	4.71	0.90	0.90	40 %	कार्य प्रगति में
23	देहाती योजना में सीवर व्यवस्था का रखरखाव	मै० दीपान्त्री कन्स०	496/AO/EE5/03	1.83	25.8.03	24.2.04	5.09	2.50	2.50	55 %	कार्य प्रगति में
24	देहाती योजना में ग्रुप हाउसिंग मूडरव 6ए के बराबर में सड़क एवं नाली का कार्य	मै० आर०एस०बिल्डर्स	465/AO/EE5/03	6.02	24.6.03	23.10.03	5.48	12.74	18.22	50 %	कार्य प्रगति में
25	देहाती सै० 9 में एस०पी०एस० से सेंटर जोड़ने का कार्य	मै० अजय कन्स० क०	317/AO/EE5/03 dt.25.6.	5.39			3.75	0.41	5.12	100.00	
26	देहाती के नलकूप स० 1 से 5 में पानी की मात्रा बढ़ाने का कार्य	यू०पी०जल निगम		6.71			5.09	1.60	6.69	100.00	
27	देहाती के उच्च जलाशयों सै० 3, 4 की लोकेज मरम्मत का कार्य	यू०पी०जल निगम		27.26	6.6.02	5.10.02	5.48	12.74	18.22	95.00	
28	देहाती सै० 6 में नलकूप पर प्लान्ट पम्प हाउस व राइजिंगमेन	यू०पी०जल निगम		8.09	1.2.03		5.11	2.97	8.08	100.00	
29	देहाती में छ. माह के सड़क सफाई व मलबा डिस्पोजल	यू०पी०जल निगम		3.28	18.12.02	17.6.03	3.75	0.43	4.18	100.00	
30	देहाती योजना के 1, 2 व 3 की सड़कों की रिसर्फेसिंग का कार्य	मै० दीपान्त्री कन्स०	395/AO/EE5/03 dt.4.1.0	60.24	1.2.03	31.5.03	39.24	26.95	66.19	100.00	
31	देहाती योजना के 4 व 5 की सड़कों की रिसर्फेसिंग का कार्य	मै० राज कन्स० क०	409/AO/EE5/03 dt.10.3.	52.43	25.2.03	24.6.03	22.05	34.62	56.67	100.00	
32	देहाती अपार्टमेंट में तीन माह हेतु रखरखाव का कार्य	मै० शिवा बिल्डर्स	411/AO/EE5/03 dt.10.3.	1.70	1.1.03	30.3.03	0.91	0.79	1.70	100.00	
33	रामपुरी सड़कों की रिसर्फेसिंग का कार्य	मै० ए०बी०एन०कन्स०	4221/AO/EE5/03 dt.13.3.	28.87	15.3.03	14.6.03		30.68	30.68	100.00	
34	देहाती के 2 व 5 में पार्को की मरम्मत का कार्य	मै० ए०के०कन्स०	4321/AO/EE5/03 dt.12.3.	2.01	30.3.03	29.5.03	4.80	2.06	2.05	100.00	
35	देहाती में 576 व 144 EWS मदनो की मरम्मत का कार्य	मै० आर०एस०एन्ट०र०	4231/AO/EE5/03 dt.21.3.	6.70	9.4.96	6.12.03		1.51	6.31	100.00	
				2226.90			1203.85	247.42	1451.26		
योग											
अभियन्त्रण खण्ड - 6											
1	प्रताप बिहार एक्स० में शिरोपरी जलाशय का निर्माण कार्य।	उ०प्र० जल निगम	463/EE6/03 dt.24.9.03	65.76	24.9.03	23.9.04		6.57	6.57	30 %	पानी मरा होने के कारण
2	प्रताप बिहार एक्स० में पाकेट-ए का विकास कार्य।	मै० एस०एस० बिल्डर्स	521/AO/03 dt.23.10.03	80.47	15.11.03	14.5.04				5 %	
3	प्रताप बिहार एक्स० में पाकेट-बी का विकास कार्य।	मै० सतीस कुमार		56.95							
4	प्रताप बिहार एक्स० में पाकेट-सी का विकास कार्य।	मै० राजेश्वर बिल्डर्स	503/AO/03 dt.8.9.03	67.18	24.9.03	23.3.03					
5	प्रताप बिहार एक्स० में सीवर लाइन का कार्य।	मै० राहुल कन्स० क०	527/AO/03 dt.24.11.03	33.13	2.12.03	1.6.04					
6	नरराव देवरस योजना के मुख्यधर्मा में मिट्टी नई का कार्य।	मै० सजय कन्स० क०	528/AO/03 dt.24.11.03	70.27	28.11.03	24.3.04		7.40	7.40	15 %	
7	प्रताप बिहार सै०-12 एवं ब्लाक में नलकूप व पम्प हाउस की स्थापना कार्य।	उ०प्र० जल निगम	418/EE6/03 dt.6.8.03	12.80	7.8.03	6.10.03				50 %	
8	पाण्डव नगर में शिवा इन्स्टीट्यूट के निकट सड़क का निर्माण कार्य।	मै० मधुरी कन्स० क०	520/EE6/03 dt.25.11.03	8.87	5.12.03	4.2.04					
9	शास्त्रीनगर में कम्युनिटी सेंटर की मरम्मत का कार्य।	मै० मेघना कन्स०	510/EE6/03 dt.1.10.03	1.85	7.10.03	5.12.03		0.60	0.60	50 %	
10	पटेलनगर में कम्युनिटी सेंटर की मरम्मत का कार्य।	मै० युजमान कुमार	508/EE6/03 dt.27.9.03	2.45	6.10.03	5.1.04		1.45	1.45	80 %	
11	प्रताप बिहार सै०-12 में अवशेष सड़कों का कार्य।	मै० एस०एस०बिल्डर्स	439/EE6/03 dt.22.5.03	30.05	24.5.03	23.11.03		17.32	17.32	90 %	
12	प्रताप बिहार सै०-12 जी ब्लाक में सड़क व नाली का निर्माण	मै० आर०एस० कन्स०	438/EE6/03 dt.19.5.03	13.40	24.5.03	23.12.03		8.22	8.22	95 %	

क्र.सं.	कार्य का नाम	उद्देश्य का नाम	अनुबन्ध सं०	अनुबन्ध / विचलन धनराशि लाख में	प्रारम्भ तिथि	समाप्ति तिथि/ समय वृद्धि तिथि	प्रारम्भ से 31.3.03 तक व्यय लाख में	14.03 से 15.12.03 तक व्यय लाख में	कुल व्यय	भौतिक प्रगति % में	अन्य विवरण
			4	5	7	8	10	11	12	13	14
1	नन्दग्राम में मेरठ तिराहे पर नाले व सड़क का निर्माण कार्य	श्री राकेश कुमार त्वागी	4442/EE6/03 dt.22.5.03	28.58	24.5.03	31.12.03		23.07	23.07	90 %	
13	प्रताप विहार सौ-12 आर ब्लाक में रिटैनिंग वाल का निर्माण	श्री इन्द्रा बिहारी	4332/EE6/03 dt.24.4.03	6.43	28.4.03	22.10.03		2.77	2.77	60 %	कार्य बन्द कराया गया
14	प्रताप विहार सौ-11 एच ब्लाक में ई0डब्ल्यूएस0 मवनों की श्रुटिंग का कार्य।	श्री एन0के0एन0	66/EE6/02 dt.17.5.02	12.50	20.5.02	19.11.02					
15	प्रताप विहार सौ-11 एच ब्लाक में ई0डब्ल्यूएस0 मवनों का निर्माण कार्य।	श्री कृष्णादीप एड्ड क०	27/EE6/02 dt.27.7.02	53.90	27.7.98	31.3.02	35.20		35.20	65 %	कार्य बन्द
16	माउरवा देवरस योजना प्रताप विहार का कार्य।	श्री एन0के0एन0	53/EE6/99 dt.14.10.99	69.23	16.10.99	31.3.01	23.38		23.38	35 %	
17	प्रताप विहार जे ब्लाक में सड़क,नाली व पार्क का निर्माण	श्री विष्णु कन्त०	97/EE6/00 dt.11.1.00	14.60	13.1.00	31.3.02				100 %	
18	प्रताप विहार सौ-12 में सीवर सेनहोल का कार्य।	श्री विकास कुमार	404/EE6/00 dt.29.1.03	1.64	12.2.03	9.3.3		1.64	1.64	100 %	
19	प्रताप विहार जे ब्लाक में सीवर लाइन का कार्य।	श्री पुनराश कुमार खन्ना	419/EE6/00 dt.11.3.03	7.13	12.3.03	11.5.03		7.13	7.13	100 %	
20	प्रताप विहार सौ-11 ई0 ब्लाक में व्यवसायिक पार्कट का	श्री बदरान्त कन्त० क०	294/EE6/00 dt.12.3.03	0.45	21.3.03	28.3.03		0.45	0.45	100 %	
21	प्रताप विहार सौ-11 ई0 ब्लाक में वाटर लाइन का कार्य।	श्री दीपान्वी कन्त० क०	306/EE6/00 dt.28.3.03	0.45	28.3.03	9.4.03		0.43	0.43	100 %	
22	अम्बेडकर रोड डिस्ट्रिक्ट सेक्टर की बाउन्ड्रीवाल का कार्य	श्री जय अम्बिका बिहारी	448/EE6/00 dt.28.5.03	4.62	12.6.03	11.10.03		4.62	4.62	100 %	
23	प्रताप विहार सौ-12 में रिटैनिंग वाल का निर्माण	श्री बदरान्त कन्त० क०	467/EE6/00 dt.25.6.03	9.96	27.6.03	26.8.03		9.96	9.96	100 %	
24	SE 386 शास्त्रीनगर की मरम्मत का कार्य।	श्री के0पी0 कन्त० क०	624/EE6/00 dt.8.9.95	0.59	8.9.95	19.6.03		0.57	0.57	100 %	
25	पटेलनगर स्थित पार्क की मरम्मत का कार्य।	श्री दीपान्वी कन्त० क०	351/EE6/00 dt.19.5.03	0.48	14.5.03	18.6.03		0.47	0.47	100 %	
26	प्रताप विहार एक्स0 में शिरोपरी जलाशय का निर्माण कार्य।	श्री कुमार बिहारी	303/EE6/00 dt.26.4.02	68.70	15.5.02	14.2.03	61.24	7.46	68.70	100 %	
27	शास्त्रीनगर में स्ट्रेडियम की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	श्री केशव कन्त० क०	292/EE6/00 dt.15.3.02	5.18	19.3.02	18.7.02	3.27	1.91	5.18	100 %	
28	नन्दग्राम में बैथे योजनों 250 EWS मवनों का निर्माण कार्य(ए)	श्री एन0के0एन0	381/EE6/00 dt. 18.12.02	109.62	18.12.02	16.12.02	28.99	59.76	88.76	90 %	
29	नन्दग्राम में बैथे योजनों 250 EWS मवनों का निर्माण कार्य(बी)	श्री एन0के0एन0	375/EE6/00 dt. 10.12.02	109.62	12.12.02	10.12.03	49.19	50.81	100.00	90 %	
30	नन्दग्राम में बैथे योजनों 500 EWS मवनों का निर्माण कार्य।	श्री एन0के0एन0	482/EE6/03 dt. 5.9.03	253.66	5.9.03	4.6.04				5 %	
31	योग		1200.52				201.27	212.61	413.89		
अभियन्त्रण खंड - विद्युत											
1	वैशाली योजना में नाला रोड पर स्ट्रीट लाइट का कार्य	श्री सीमा कन्त०	425/25.3.03	3.67	25.3.03	25.5.03		3.67	3.67	100 %	
2	वैशाली योजना में सौ 5 से मुख्य सड़क तक स्ट्रीट लाइट का कार्य	श्री विशाल इलै०	417/11.3.03	0.68	11.03.03	25.4.03		0.66	0.66	100 %	
3	वैशाली योजना में 4वेंकट पोल पर लाइट लगाने का कार्य	श्री दर्मा एस०	324/	1.83	15.03.03	25.5.03	4.70	1.83	1.83	100 %	
4	वैशाली योजना में 3 एफ. में प्लाट का विद्युतीकरण का कार्य	श्री आर० के० इलै०	307/21.5.03	7.59	21.5.02	4.4.03		2.90	7.60	100 %	
5	वैशाली योजना के सौ 3 xDpe cable डालने का कार्य	श्री आर० के० इलै०	313/15.3.03	0.41	15.3.03	4.4.03		0.41	0.41	100 %	
6	वैशाली योजना के 4 व 5 में रोड,गामप्रस्थ में रोड पर स्ट्रीट लाइट कार्य।	श्री विशाल इलै०	382/11.12.03	1.23	11.12.03	10.4.03		1.23	1.23	100 %	

क्र.सं.	कार्य का नाम	उत्केदार का नाम	अनुबन्ध सं०	अनुबंध / विवरण धनराशि लाख में	समाप्ति तिथि/ समय वृद्धि तिथि	प्रारम्भ से 31.3.03 तक व्यय लाख में	14.03 से 15.12.03 तक व्यय लाख में	कुल व्यय	भौतिक प्रगति % में	अन्य विवरण
			4	5	7	10	11	12	13	14
1	वैशाली योजना में एनीमल पार्क स्थित 33 KV S/S पर 11 के वी केबिल लगाने का कार्य	मै० केपिटल इंजी०	577/24.5.03	0.45	24.5.03	27.5.03	0.45	0.45	100 %	
8	वैशाली योजना में सै०-1 में S/S पर 132 KV S/S पर केबिल टच बनाने व केबिल डालने का कार्य	मै० केपिटल इंजी०	468/24.6.03	9.05	24.6.03	30.10.03	9.05	9.05	100 %	
9	वैशाली योजना में मुख्यण्ड सं० 6/242 से 6/217 तक बाह्यविद्युतीकरण का कार्य।	मै० राजेश्वर बिल्डर्स	350/20.9.03	4.40	20.9.03	20.11.03	4.40	4.40	100 %	
10	लिक रोड पर सिग्नल लाईट लगाने का कार्य	मै० जे०के०इले०	397/8.1.03	3.18	8.1.03	30.7.03	3.28	3.28	100 %	
11	कौशाम्बी योजना में ए सी डी ब्लाक के बाह्यविद्युतीकरण का कार्य	मै० आर० के० इले०	511/1.10.03	10.48	1.10.03	31.12.03	6.79	6.79	79 %	
12	बनाने का कार्य	मै० कैपिटल इंजी० वर्क्स	358/8-10-02	35.00	9.10.02	30.5.03	9.89	32.81	100 %	
13	इन्दिरापुरम में शक्ति खण्ड-3 में सबस्टेशन का कार्य तथा डबल फीडर का कार्य	मै० वर्मा एर्रो०	498/2.9.03	4.52	2.9.03	1.11.03	3.81	3.81	80 %	
14	अमय खण्ड-3 में अदरेश बाह्यविद्युतीकरण का कार्य	मै० आर पी इले०	503/10.9.03	18.41	10.9.03	9.2.04	16.24	16.24	80 %	
15	शक्ति खण्ड-4 में बाह्यविद्युतीकरण का कार्य	मै० जे०के०इले०	513/6.10.03	10.38	6.10.03	5.12.03	3.70	3.70	40 %	
16	नन्दग्राम यो० के आश्रय मदनो में एच टी लाईन तथा 2 नग S/S का निर्माण कार्य	मै० राजेश्वर बिल्डर्स	349/20.9.02	4.12	20.9.02	20.12.02	0.87	3.62	100 %	
17	देबे योजना(नन्दग्राम)के बाह्य विद्युतीकरण का कार्य	मै० नितेश इले०	414/5.3.03	7.01	5.3.03	4.12.03	1.83	1.83	40 %	
18	गोविन्द पुरम योजना के ए व जे ब्लाक में 2 नग S/S का बनाने का कार्य	मै० मवानी कन्स०	524/21.11.03	4.06	21.11.03	21.12.03			50 %	
19	इन्दिरापुरम हेतु 10एमवी0ए0 ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति का कार्य	मै०एस०एण्ड इले०	303/JEEE/03	28.44			28.44	28.44	100.00	
20	इन्दिरापुरम हेतु नये फिक्स्ड बैकटि क्लेम की आपूर्ति कार्य।	मै० कैपिटल इले०एण्डइले०	178 dt.9.3.03	0.61	9.3.03		0.61	0.61	100.00	
21	इन्दिरापुरम कोशक्ति खण्ड-4 में बाह्य विद्युतीकरण का कार्य।	मै० कैपिटल इले०एण्डइले०	357 dt. 7.10.03	44.64	7.10.03		4.36	4.36	100.00	
22	इन्दिरापुरम के अमय खण्ड में दो सब स्टेशन का कार्य।	मै० जे०के०इले०	360 dt. 17.10.03	3.53	17.10.03	15.5.03	1.03	3.53	100.00	
23	इन्दिरापुरम के शिवा सन सिटी हेतु चार सब स्टेशन का कार्य।	मै० ग्लोबल इले०	436 dt.31.5.03	5.62	31.5.03	19.9.03	5.86	5.86	100.00	
24	इन्दिरापुरम के न्याय खण्ड 2 में 1 नग सब स्टेशन का कार्य।	मै० नितेश इले०	453 dt. 31.5.03	2.10	31.5.03	30.8.03	1.88	1.88	90.00	
25	इन्दिरापुरम के अमय खण्ड 2 में 1 नग सब स्टेशन का कार्य।	मै० जे०के०इले०	396 dt. 8.1.03	3.40	8.1.03	21.7.03	1.08	3.46	100.00	
26	इन्दिरापुरम के विभिन्न चौराहों पर सेमी हाई मास्ट लाइट	मै० वेमव इले०	461 dt. 18.6.03	2.14	18.6.03	17.10.03	1.94	1.94	90.00	
27	इन्दिरापुरम में IRS पार्क की प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	मै० वेमव इले०	462 dt. 18.6.03	1.88	18.6.03	17.10.03	1.80	1.80	95.00	
28	इन्दिरापुरम में हिन्दन कट की प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	मै० सीमा इले०	509 dt. 30.4.03	4.41	30.9.03	1.12.03	4.41	4.41	100.00	
29	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं हेतु 21 नग 400 KVA ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति का कार्य	मै० युनाइटेड इले०	290 dt. 8.1.03	30.48	8.1.03	23.2.03	17.42	30.48	100.00	
30	सूर्यनगर छात्रावास के विद्युत बिलों का मुगतान						0.18	0.39		

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध सं०	अनुबंध / विचलन धनराशि लाख मे	प्रारम्भ तिथि	समाप्ति तिथि / समय वृद्धि तिथि	प्रारम्भ से 31.3.03 तक व्यय लाख में	14.03 से 15.12.03 तक व्यय लाख में	कुल व्यय	सौदिक प्रगति % में	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
16	केन्द्रीय मन्दार मे आर०सी०सी० पाइप की आपूर्ति का कार्य।	मै० विकास पाइप	369 dt. 8.12.03	8.59	8.12.03	7.3.04		0.00	0.00		
17	केन्द्रीय मण्डार मे ए०सी०पेशर पाइप की आपूर्ति का कार्य।	मै० नाथद्वारा पाइप	341 dt. 12.9.03	14.91	12.9.03	11.1.04					
		योग		176.70			3.06	120.79	123.85		
1	गडमुक्तेश्वर बजघाट क्षेत्र में घाट पर बलाक,आरती प्लेटफार्म व अन्य विकास कार्य	मै० किमोर विल्डर्स	507/25.9.03	गडमुक्तेश्वर							
				104.86	14.8.03	13.2.04		11.07	11.07	45 %	
2	गडमुक्तेश्वर में तहसील के समीप मुख्य चौचाहा का विकास एवं सौन्दर्यकरण,तहसील रोड का सुदृढीकरण,घोडीकरण एवं अल्लाबक्सपुर रोड का सुदृढीकरण का कार्य	मै० राज कन्स०	492/27.8.03	115.46	20.8.03	19.11.03		79.99	79.99	75 %	
3	गडमुक्तेश्वर बजघाट विकास क्षेत्र में रेटोफिलीकटिव बोर्ड लगाने का कार्य	मै० एन०सी०सी०एफ०इ०	23/31.5.03	19.73	2.6.03	1.8.03		19.73	19.73	100 %	
4	गड बजघाट में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य	मै० बायोफेन्ड सोसाइटी	512/03	7.98	29.8.03	28.12.03		5.98	5.98	75 %	
	योग			248.03			0.00	116.77	116.77		
	महायोग			13197.19			5513.05	3989.33	9503.45		

SUMMARY

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अलोकप्रिय / अनिस्तारित सम्पत्ति का मूल्यांकन हुडकों से कराकर ज्वाइन्ट-वेन्चर के आधार पर विक्रय करने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण द्वारा किये गये व्यापक प्रचार-प्रसार व निरन्तर प्रयासों के बावजूद प्राधिकरण की काफी बड़ी सम्पत्ति अनिस्तारित पड़ी हुई है । इस अलोकप्रिय / अनिस्तारित सम्पत्ति को चिन्हीकृत करते हुए इनका मूल्यांकन हुडकों से कराकर सम्पत्ति का निस्तारण ज्वाइन्ट-वेन्चर के आधार पर निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है :-

- 1- अनिस्तारित भवनों / सम्पत्तियों का मूल्यांकन हुडको / सरकारी संस्थान द्वारा किया जायेगा ।
- 2- इनभवनों / सम्पत्ति को विज्ञापन के माध्यम से प्रचार-प्रसार पर ज्वाइन्ट-वेन्चर के आधार पर किया जायेगा । विक्रय से पूर्व विस्तृत नियम व शर्तें प्राधिकरण द्वारा तैयार की जायेगी ।
- 3- ज्वाइन्ट वेन्चर में 5 करोड या इससे अधिक की सम्पत्ति को ही विक्रय किया जायेगा ।
- 4- भवनों का आवंटन संयुक्त हस्ताक्षर से ही किया जायेगा ।
- 5- ज्वाइन्ट वेन्चर के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि ज्वाइन्ट एकाउन्ट (एसको) में रखी जायेगी । इसको प्राधिकरण एवं वेन्चरकर्ता में आहरित किया जायेगा ,परन्तु इस खाते में प्राप्त होने वाली धनराशि पर प्रथम चार्ज गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का होगा ।
- 6- ज्वाइन्ट वेन्चर के लिए कुल कीमत की 5 प्रतिशत धनराशि जमा करने पर पंजीकरण किया जायेगा ।
- 7- 5 प्रतिशत धनराशि और जमा करने पर आवंटन किया जा सकता है । ज्वाइन्ट-वेन्चर के अन्तर्गत कुल कीमत की 25 प्रतिशत धनराशि जमाकराकर अपना कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं । शेष 75 प्रतिशत धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित 3 वर्षों में 6 छमाही किश्तों में जमा कराई जायेगी ।
- 8- आवंटन के उपरान्त 6 माह की मोराटोरिम अवधि रखी जायेगी, जिसमें कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा ।
- 9- भवनों में एडिशनल / आल्ट्रेडेशन अथवा पुर्ननिर्माण ज्वाइन्ट-वेन्चरकर्ता को अपने खर्च पर कराना होगा ।
- 10- भवनों हेतु पूर्व निर्धारित एफ0ए0आर0 नहीं बदला जाएगा ,परन्तु पुनः निर्माण / नया निर्माण की स्थिति में प्राधिकरण में प्रचलित वर्तमान भवन निर्माण उपविधि / शासनादेश के अनुसार प्राधिकरण की पूर्व अनुमति ली जानी आवश्यक होगी ।

कृपया उपरोक्तानुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अलोकप्रिय / अनिस्तारित सम्पत्ति को हुडको द्वारा मूल्यांकन कराकर ज्वाइन्ट वेन्चर के आधार पर विक्रय करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

मद सं० 4

विषय : शाहदरा से गाजियाबाद तक दिल्ली मेट्रो के निर्माण का अनुमोदन ।

गाजियाबाद नगर के सुनियोजित एवं सर्वांगीण विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि० नई दिल्ली को पत्र दिनांक 21-11-2003 प्रेषित किया गया था जिसमें शाहदरा दिल्ली से गाजियाबाद तक (लाईन एक) निर्मित करने हेतु अनुरोध किया गया था । इस सम्बन्ध में दिनांक 3 दिसम्बर 2003 को दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि० के प्रबन्ध निदेशक श्री ई० श्रीधरन के साथ बैठक की गयी । बैठक में दिल्ली गाजियाबाद के मध्य बढ़ते यातायात को दृष्टिगत रखते हुए मेट्रो सेवा प्रारम्भ करने पर सैद्धान्तिक सहमति थी ।

बैठक में प्रबन्ध निदेशक द्वारा यह अवगत कराया गया कि दिल्ली मेट्रो के निर्माण पर औसतन लगभग ₹ 100 करोड़ प्रति कि०मी० लागत आ रही है , जिसमें से 70 प्रतिशत धनराशि विभिन्न स्रोतों से ऋण आदि प्राप्त कर की जा रही है । शेष 30 प्रतिशत धनराशि में से 15 प्रतिशत अंश भारत सरकार एवं 15 प्रतिशत अंश दिल्ली प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है । यदि गाजियाबाद को मेट्रो से जोड़ा जाता है तो लगभग 16 कि०मी० लम्बाई में से 4 कि०मी० भाग दिल्ली में शेष 12 कि०मी० भाग गाजियाबाद यू०पी० में पड़ेगा एवं निर्माण लागत को उपरोक्त अंश में विभाजित करने का प्रयास किया जा सकता है । गाजियाबाद वाले भाग पर प्राधिकरण को 15 प्रतिशत अंशदान के अनुसार निर्माण लगभग रुपये 150 करोड़ से रुपये 180 करोड़ रुपये तक का भुगतान आगामी 3-4 वर्षों में करना होगा ।

प्राधिकरण गाजियाबाद वाले भाग पर आने वाली लागत को वहन करने के लिए तैयार है । अन्य सम्बन्धित विभागों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा । सम्पूर्ण प्रस्ताव प्रदेश सरकार की ओर, से भारत सरकार, दिल्ली सरकार, एवं दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि० को भेजना होगा एवं उनकी सहमति/स्वीकृति के उपरान्त ही इसके निर्माण के लिए कार्यवाही प्रारम्भ हो सकेगी ।

गाजियाबाद तक दिल्ली मेट्रो के निर्माण हेतु एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) भी तैयार की जानी होगी, जिसको दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा तैयार किया जायेगा, जिसे बनाने पर लगभग 70 लाख + 8 प्रतिशत सर्विस टैक्स लागत आयेगी । बैठक में अवगत करवाया गया था कि इसमें से 40 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा दी जा सकती है , यदि प्रस्ताव प्रदेश सरकार की ओर से ही भारत सरकार को भेजना होगा । प्राधिकरण को डी० पी० आर० तैयार करने हेतु उपरोक्त 60 प्रतिशत धनराशि भी वहन करनी होगी ।

प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में शासन की स्वीकृति मांगी गयी है एवं अनुरोध किया गया है कि गाजियाबाद को मेट्रो से जोड़ने हेतु प्राधिकरण का प्रस्ताव भारत सरकार, दिल्ली सरकार एवं दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि० को अपनी स्वीकृति/सहमति सहित प्रेषित कर दे ।

उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

Amr
A.T.P.

मद सं० 4(क)

विषय: मेट्रो रेल के निर्माण हेतु अर्थ प्रबन्ध।

मेट्रो रेल वर्तमान में मूल रूप से शाहदरा रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित है। इसका विस्तार गाजियाबाद तक कराने का प्रस्ताव के अन्तर्गत भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित योजना से बड़ी दूरों से प्राप्त राशि से कराये जाने का विकल्प है। इस संबंध में विवरण निम्नानुसार है:-

1. सम्भावित व्यय:-

(अ) शाहदरा रेलवे स्टेशन से प्रस्तावित स्थल तक मेट्रो रेलवे की सम्भावित लम्बाई-16 कि०मी० जिसमें से 30 प्र० की सीमा में 12 कि० मी० तथा 4 कि०मी० दिल्ली की सीमा में पड़ेगी, जिसका व्यय दिल्ली सरकार / भारत सरकार द्वारा किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष व्यय प्राधिकरण को करना होगा।

(ब) मेट्रो रेल की लाईन बिछाने पर सम्भावित व्यय रु० 10.00 लाख प्रति मीटर

अर्थात् रु० 120000.00 लाख

या रु० 1200.00 करोड़

मेट्रो रेल द्वारा वहन किये जाने वाला व्यय- 70 प्रतिशत

भारत सरकार द्वारा वहन किये जाने वाला व्यय- 15 प्रतिशत

प्राधिकरण पर सम्भावित व्यय- $15 \times 1200 / 100 = \text{रु० } 180.00 \text{ करोड़}$

(स) विकास पर सम्भावित व्यय-

(इन्द्रप्रस्थ योजना की विकास दरों के आधार पर)

(1-) आन्तरिक विकास व्यय:-

1. सड़कों का निर्माण-	350 एकड़/6.50 लाख रु०	2275/लाख
2. पार्क का कार्य-	350 एकड़/2.00 लाख रु०	750/लाख
3. आन्तरिक नालियों का कार्य-	350 एकड़/3.00 लाख रु०	1050/लाख
4. आन्तरिक जल वितरण प्रणाली-	350 एकड़/1.00 लाख रु०	350/लाख
5. आन्तरिक सीवर वितरण प्रणाली-	350 एकड़/2.50 लाख रु०	875/लाख
6. मार्कोरी कल्चर-	350 एकड़/0.50 लाख रु०	175/लाख
7. आन्तरिक विद्युतीकरण-	350 एकड़/2.50 लाख रु०	875/लाख
8. सोलिडवेस्ट	350 एकड़/0.50 लाख रु०	175/लाख
	कुल रु०	6525.00 लाख

(2-) वाह्य विकास कार्य:-

1. उच्च जलाशय 04 नं०-	रु० 500.00 लाख
2. नलकूप व राईजिंग मेन	रु० 200.00 लाख
3. मास्टर प्लान के अनुसार सड़क का चौड़ीकरण	रु० 400.00 लाख
4. नाले का निर्माण कार्य-	रु० 200.00 लाख
5. एस०पी०एस०	रु० 200.00 लाख
6. एस०टी०सी० का समानुपाती-	रु० 600.00 लाख
7. वाह्य विद्युतीकरण-	रु० 900.00 लाख

कुल रु० 3000.00 लाख

कुल व्यय (अ + ब)

रु0 9525.00 लाख

सुपरविजन चार्ज (15 प्रतिशत)

रु0 1429.00 लाख

रु0 10954.00 लाख

कुल विकास व्यय— $1095 \times 100000 / 708225$

= रु0 15550/- प्रति वर्ग मी0

(3) भू-अर्जन पर व्यय (रु0 300/- प्रति वर्ग मी0)

सम्भावित दर रु0 300/- प्रति वर्ग मीटर $350 \times 4047 \times 300 = 4250.00$ लाख

10 भू अर्जन— 30 प्रतिशत सोलिमियम = 1700.00 लाख

= 5950.00 लाख

कुल विकास व्यय = 16904.00 लाख

सम्भावित आय:-

$350 \text{ एकड़} \times 4047 = 1416450$ वर्ग मीटर

विक्रय योग्य उपलब्ध क्षेत्रफल:- 50 प्रतिशत = 708225 वर्ग मीटर

कुल सम्भावित आय:- $708225 \times 5500/- = 3895237500.00$

कुल रु0 38952.00 लाख

आय - व्यय

38952.00 लाख - 16904.00 लाख

= 22048.00 लाख (बचत)

मेट्रो का सम्भावित व्यय = 18000.00 लाख

अतः मेट्रो रेल का प्रस्ताव सम्भव है।

मद संख्या 5

विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग-58, दिल्ली सीमा से मेरठ तक , 8 लेन डिवाइडिड एक्सप्रेस -वे का बी0 ओ0 टी0 पर निर्माण के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद नगर के मध्य से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग-24, 58, एवं 91 गुजरते हैं , जिससे तेज गति के भारी वाहनो का आवागमन रहता है एवं सुगम यातायात में समस्या रहती है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग-58 (दिल्ली -मेरठ -हरिद्वार)गाजियाबाद नगर की कौशाम्बी ,वैशाली ,बसुन्धरा ,मोहननगर ,साहिबाबाद एवं मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र होते हुए मेरठ की ओर जाता है। बीच में यह मार्ग मुरादनगर एवं मोदीनगर, जो कि गाजियाबाद विकास क्षेत्र का ही भाग है ,के मध्य से गुजरता है । उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर प्रति दिन लगभग 80,000 वाहनो का आवागमन रहता है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में दिल्ली गुडगांव एक्सप्रेस-वे का निर्माण बी0 ओ0 टी0 पद्धति पर निजी क्षेत्र के माध्यम से करवाया जा रहा है । उसी आधार पर प्राधिकरण द्वारा एक प्रस्ताव सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ,भारत सरकार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया है कि दिल्ली- मेरठ मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-58 का भाग)को 8 लेन डिवाइडिड एक्सप्रेस-वे के रूप में बी0 ओ0 टी0 पद्धति पर विकसित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये । उपरोक्त 70 कि0मी0 मार्ग के निर्माण पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्पैसिफिकेशनस(4 लेन के लिए रू0 5.0 करोड प्रति कि0मी0) के आधार पर लगभग रूपये 700 करोड लागत का अनुमान है।

उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है ।

A.T.P.

मद संख्या 6

विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग-58 (मेरठ रोड) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-24 (हापुड रोड) बाईपास को जोड़ने हेतु 6 लेन लिंक रोड के निर्माण के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की 89 वीं बोर्ड बैठक दि० 30-11-2002 में राष्ट्रीय राजमार्ग-58 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-24 को जोड़ने हेतु लिंक रोड का निर्माण बी० ओ० टी० पद्धति पर करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । प्राधिकरण द्वारा मैसर्स फीड बैक बेंचर प्रा० लि० के माध्यम से योजना का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर तैयार कराया गया , जिसका अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड बैठक दि० 20-2-03 में प्रदान किया गया । प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अनुसार लगभग 4 कि०मी० लम्बी एवं 60 मीटर चौड़ी लिंक रोड पर लगभग 21.54 करोड़ का व्यय अनुमानित किया गया था ।

प्राधिकरण द्वारा शासन स्तर पर हुए विचार विमर्श तथा नोएडा टोल ब्रिज स्ट्रक्चर के आधार पर बिड केता कम्पनियों के साथ दिनांक 9 मई 2003 को विचार विमर्श किया गया एवं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में अधिकतम ग्रांट रूपया 4.0 करोड़ निर्धारित करते हुए तथा रेवेन्यू शेयरिंग कुछ नहीं रखते हुए दिनांक 30-6-2003 तक बिड आमंत्रित की गयी । निर्धारित समय में प्राधिकरण के पास मात्र एक बिड प्राप्त हुई, जो न्यूनतम ग्रांट रू० 3.09 करोड़ के साथ प्राप्त हुई तथा कम्पनी द्वारा टोल कलक्शन अवधि 20 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष किये जाने का अनुरोध किया गया । योजना में उक्त संशोधन को पुनः विज्ञापित करने पर भी अन्य कोई बिड प्राप्त नहीं हुई । प्रोजेक्ट हेतु एक मात्र बिड प्राप्त होने तथा इस प्रकार का यह प्रथम प्रोजेक्ट होने के कारण शासन के समक्ष पुनः इसका प्रस्तुतीकरण किया गया । शासन को स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रकरण सन्दर्भित किया गया ।

शासन द्वारा नगर के अवस्थापना सुविधाओं के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के उद्देश्य से विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं को बी०ओ०टी० पद्धति पर टोल कलक्ट करने की व्यवस्था का प्रोजेक्ट तैयार करते हुए , कराये जाने हेतु प्राधिकरणों को अधिकृत किया गया है । उक्त शासनादेश सं० 2572/ 9-आ-3-03-28वि/ 2003 दिनांक 27-8-2003 संलग्नक के रूप में प्रस्तुत है ।

प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित विभागों के साथ विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त मार्ग को चार लेन एवं सर्विस रोड के स्थान पर 6 लेन का निर्मित किया जाये , जिससे कि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति इस लिंक रोड के निर्माण से हो सके । साथ ही आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित की जा रही लगभग 703 एकड़ भूमि जिसका सर्वाधिक भाग मार्ग से लगा हुआ है , में आवासीय योजना के अनुसार मुख्य मार्ग, सर्विस रोड इत्यादि का निर्माण विभाग द्वारा ही कराया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित लिंक रोड की योजना को चार लेन के स्थान पर 6 लेन करते हुए पुनरीक्षित प्रोजेक्ट तैयार कर इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एवं नोएडा टोल रोड के स्ट्रक्चर के आधार पर पुनः योजना तैयार कर बी०ओ०टी० के आधार पर लिंक रोड के निर्माण किये जाने से सम्बन्धित योजना तैयार की गयी है । संशोधित योजना के अनुसार :-

1- मार्ग की लम्बाई 4.0 कि०मी०

2- चौड़ाई 60.0 मीटर , 6 लेन डिवाइडिड हाईवे एवं अण्डर ब्रिज रेलवे लाईन

3- अनुमानित लागत रू0 35.00 से 40.00 करोड (लगभग)

4- टोल दर रू0 10.00 पर पी0सी0यू0

5- कन्शेशन अवधि 30 वर्ष

6- बिड बैरिवेबिल – ग्रान्ट धनराशि

7- लिंक रोड के अन्तर्गत पडने वाली भूमि निःशुल्क कम्पनी को दी जायेगी ।

न्यूनतम ग्रान्ट मांगे जाने वाली कम्पनी को लिंक रोड के निर्माण का कार्य एवं 30 वर्षों तक मार्ग के रख -रखाव व टोल कलक्शन चार्ज प्राप्त करने के अधिकार शासनादेश सं0 2572/

9-आ-3-03-28वि/ 2003 दिनांक 27-8-2003 के अन्तर्गत दिये जाने प्रस्तावित हैं ।

संशोधित प्रस्ताव अनुमोदन एवं बिड आमंत्रित करने हेतु प्रस्तुत है ।

Signature
A-11

उत्तर प्रदेश सरकार
 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
 संख्या: 2572/9-आ-3-03-28वि./ 2003
 लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त, 2003

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 39-क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, विकास क्षेत्र में औद्योगिक वाणिज्यिक या आवासिक प्रयोजन के लिए और ऐसी अवस्थापना के संबंध में फीस के उद्ग्रहण और संग्रह के लिए अवस्थापना की व्यवस्था और अनुरक्षण करने की दृष्टि से अधिसूचित करते हैं कि प्राधिकरण ऐसी अवस्थापना के उपयोग के लिए इसमें आगे दी गयी रीति से पथ-कर लगायेगा और उपयोक्ताओं/परिदर्शकों से संग्रह करेगा :-

1. (क) प्राधिकरण या तो स्वयं या करार के आधार पर किसी विकासक के माध्यम से क्षेत्र में किसी अवस्थापना का विकास, निर्माण या उसकी व्यवस्था या अनुरक्षण कर सकता है अथवा व्यवस्था या अनुरक्षण को जारी रख सकता है।
- (ख) विशिष्टता, और इस निमित्त प्राधिकरण की शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, करार में निम्नलिखित विषयों में से किसी या सभी की व्यवस्था की जा सकेगी :-
 - (एक) करार की अवधि;
 - (दो) करार के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व;
 - (तीन) अवस्थापना के रूपांकन, निर्माण और अनुरक्षण के लिए मानक और विनिर्देश;
 - (चार) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित दर पर उद्गृहीत और

- संगृहीत की जाने वाली फीस,
- (पाँच) विकासक के लिए युक्तियुक्त प्रत्यागम की संगणना के लिए प्रक्रिया ;
- (छः) विकासक के अधिकारों के अभ्यर्पण, निर्माण या निर्वापन या अन्यथा किसी अवस्थापना के अन्तरण की प्रक्रिया ;
- (सात) किसी अवस्थापना के सम्बन्ध में विकासक के उधारदाताओं के अधिकार;
- (आठ) करार का पर्यवसान;
- (नौ) विवादों के निपटारे की पद्धति; और
- (दस) कोई अन्य निबन्धन और शर्तें, जो प्राधिकरण, विकासक या विकासक के उधारदाता द्वारा करार पाई जाय।

2. (एक) प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रत्येक करार प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी द्वारा विरचित और निष्पादित किया जाएगा जिसे प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया जाय।

(दो) मद (एक) के उपबन्धों के उल्लंघन में प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से किया गया कोई करार उस के लिए आबद्धकर नहीं होगा;

3. (1) स्वयं प्राधिकरण द्वारा या किसी विकासक के माध्यम से क्षेत्र में किसी अवस्थापना की व्यवस्था या अनुरक्षण करने अथवा व्यवस्था या अनुरक्षण को जारी रखने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर फीस का उद्ग्रहण और संग्रह करेगा। किसी अवस्थापना का विकास, निर्माण अथवा अनुरक्षण या व्यवस्था किसी करार के अधीन किये जाने की दशा में, ऐसा सूत्र वही होगा जो प्राधिकरण या विकासक के मध्य अवधारित या करार किया जाय;

(2) प्राधिकरण को शक्ति होगी कि वह विकासक को फीस

का संग्रह और विनियोग करने के लिए प्राधिकृत कर सके। फीस के संग्रह और विनियोग संबंधी विकासक के अधिकार को विकासक के उधारदाताओं को समनुदेशित किया जा सकता है।

- (3) विकासक ऐसे रजिस्ट्रों और अन्य अभिलेखों का रख-रखाव करेगा जैसा प्राधिकरण द्वारा निदेशित किया जाय।

4. फीस की वसूली, जब तक कि पहले ही उसका भुगतान न कर दिया गया हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा-40 के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी।

जे.एस. मिश्र
सचिव।

संख्या-2572(1)/ 9-आ-3-03 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को एक अंग्रेजी प्रति सहित उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में दि० अगस्त, 2003 के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड-(ख) में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 20-20 मुद्रित प्रतियाँ पृष्ठांकन-2 में उल्लिखित सम्बन्धित अधिकारियों एवं शासन को उपलब्ध करायी जाय।

आज्ञा से,
(जावेद एहतेशाम)
उप सचिव।

मद सं०: 7

विषय : प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के भूखण्डों के ले-आउट प्लान के पुर्ननियोजन/
भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की उपरोक्त योजनाओं में नियोजन के समय कुछ बड़े भूखण्डों का विभिन्न उपयोगों हेतु आरक्षण किया गया था । कालान्तर में उक्त भूखण्डों का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के पश्चात भी आरक्षित उपयोग में कतिपय भूखण्डों का विक्रय नहीं हो पा रहा है । इससे स्वतः स्पष्ट है कि उक्त भूखण्डों का अरुचिपूर्ण उपयोग होने के कारण विक्रय नहीं हो पा रहा है ।

वर्तमान में प्राधिकरण को पूर्णतः ऋणमुक्त होने, योजनाओं में अधूरे पड़े विकास कार्यों को सुचारु रूप से चलाने तथा अग्रिम योजनाओं हेतु भूमि बैंक बनाने के लिए धन की आवश्यकता है , जो विभिन्न योजनाओं में अवशेष पड़ी रिक्त भूमि को विक्रय करने से प्राप्त किया जा सकता है ।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए इन योजनाओं के तलपट मानचित्रों का पुर्ननियोजन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है ।

अतः प्रस्तावित है कि :-

इन्दिरापुरम योजना :-

- 1- भूखण्ड सं० 16 क्षेत्रफल 5.14 हेक्टेयर जो वर्तमान में सुविधाओं हेतु आरक्षित है ।(परिशिष्ट 'क') को आवासीय (समूह आवास) उपयोग में परिवर्तित करने हेतु ।
- 2- इसी योजना में एक भूखण्ड डिग्री कालेज हेतु आरक्षित है जिसका क्षेत्रफल 18640 वर्गमीटर है । डिग्री कालेज हेतु पूर्व में दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिन्हें आवश्यक व निर्धारित अर्हतायें पूर्ण न होने के कारण आवंटन नहीं किया जा सका । वर्तमान में हायर सेकेण्ड्री स्कूल हेतु आवेदन आ रहे हैं । अतः ले-आउट प्लान में उक्त डिग्री कालेज हेतु आरक्षित भूखण्ड को हायर सेकेण्ड्री स्कूल उपयोग में निर्धारित किये जाने हेतु ।

कौशाम्बी योजना :-

- 1- कौशाम्बी योजना भूखण्ड सं० 2 क्षेत्रफल 11979 वर्गमी० जो वर्तमान में आवासीय (समूह आवास) हेतु आरक्षित है (परिशिष्ट-ख) को व्यवसायिक/ कार्यालय उपयोग में परिवर्तित करने हेतु ।
- 2- भूखण्ड क्षेत्रफल 8000 वर्गमी० जो वर्तमान में सुविधाओं (हास्पिटल) उपयोग हेतु आरक्षित है (परिशिष्ट-ख) को व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तन करने हेतु ।

प्रताप विहार योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत एक भूखण्ड 3765 वर्गमी० क्षेत्रफल, कारपेट आफिस एवं क्लब उपयोग हेतु उपलब्ध है । सन्दर्भित भूखण्ड की स्थिति संलग्न योजना मानचित्र में (परिशिष्ट-ग) जो वर्तमान में कई बार विक्रय करने के प्रयासों के बावजूद भी निस्तारित नहीं हो पाया है । अतः उक्त भूखण्ड को क्लब एवं कारपेट आफिस उपयोग से समूह आवास उपयोग में परिवर्तन हेतु ।

उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

संलग्नक - "क"



GHAZIABAD DEVELOPMENT
AUTHORITY

AREA SCHEDULE

- TOTAL AREA OF SCHEME
- CONCLUDING MASTER PLAN ROAD AREA
- AREA UNDER PLOTS
- AREA UNDER ROAD
- AREA UNDER PARK
- AREA UNDER COMMUNITY CENTRE
- AREA UNDER COMMUNITY CENTRE
- AREA UNDER MASTER PLAN ROAD

REVISIONS

PLAN NO 13 HAS BEEN RENAMERED
12 'X' INSTEAD OF 13 (27-11-02)

LAYOUT PLAN OF INDRAPURAM
RESIDENTIAL SCHEME (T.H.A.)
GHAZIABAD

DATE: _____

DRAWN: CHANDRAKUMAR

SCALE: 1: _____

N

TOUR PLANNER

CATER: _____

SECONDARY: _____

VICE CHAIRMAN: _____

LAYOUT PLAN OF KAUSHAMBI
TOWNSHIP, SECTOR NO. XIV
(T.H.A.) GHAZIABAD (REVISED)



VAISHALI SCHEME

ISBT
ANAND VIHAR

SECTOR IX



150' MASTER PLAN ROAD

PROPOSED MASTER PLAN ROAD 150' WIDE



मद सं० : 8

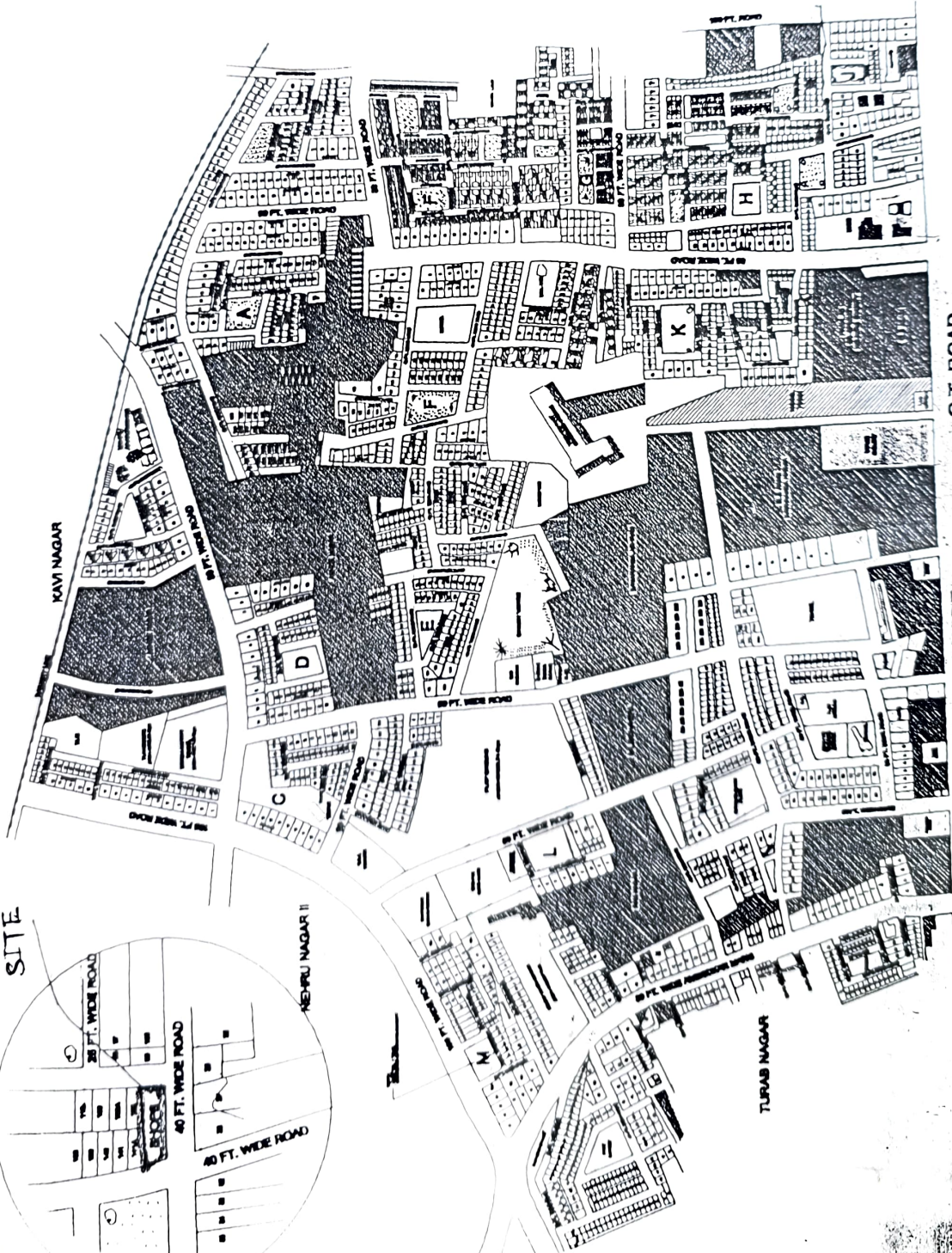
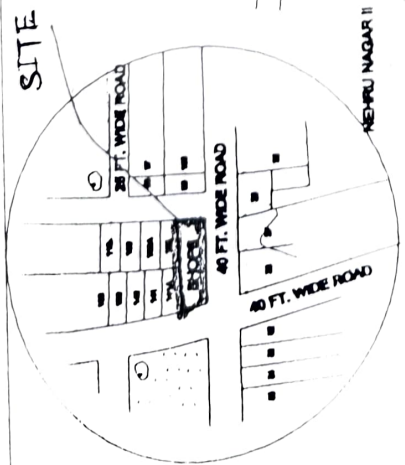
विषय : नेहरूनगर योजना के सेक्टर-3 स्थित एच ब्लॉक में 367.19 व०मी० व्यवसायिक भूखण्ड का भू-उपयोग आवासीय परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 23-6-03 के मद सं० 33 पर प्रस्तुत किया गया था । बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित करने का निर्णय लिया गया था । प्राधिकरण की नेहरूनगर योजना के सेक्टर-3 में एच ब्लॉक स्थित 367.19 व०मी० क्षेत्रफल के भूखण्ड को दिनांक 18-9-2001 को नीलामी प्रक्रिया द्वारा मैसर्स दूधेश्वर बिल्डर्स को विक्रय किया गया था । आवंटी द्वारा वांछित धनराशि जमा कराते हुए भूमि का कब्जा प्राप्त किया जा चुका है । आवंटी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूखण्ड के आस पास व्यवसायिक मांग व आवश्यकता न होने तथा आवासीय वातावरण होने का उल्लेख करते हुए भूखण्ड को आवासीय उपयोग में अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उल्लेखनीय है कि समीप के क्षेत्र में ही राकेश मार्ग तथा जी०टी० रोड व्यवसायिक क्षेत्र के रूप में विकसित है । उक्त भूमि (भूखण्ड) का भू-उपयोग परिवर्तन व्यवसायिक से आवासीय में इस शर्त के साथ किये जाने पर विचार किया जा सकता है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के विरुद्ध जमा की गयी धनराशि की कोई वापसी नहीं की जायेगी । साथ ही चूंकि विन्यास मानचित्र में भूखण्ड का भू-उपयोग परिवर्तित किया जायेगा, अतः उक्त परिवर्तन के सम्बन्ध में जन सामान्य से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित करानी होगी ।

अतः उपरोक्तानुसार नेहरूनगर सेक्टर-3 योजना के एच०- ब्लॉक में स्थित 367.19 व०मी० क्षेत्रफल के व्यवसायिक भूखण्ड का भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

Hum
A.T.P.



150 FT. WIDE
G.T. ROAD

SITE

AREA SCHEDULE

TOTAL AREA OF SITE: 10000 SQ. YDS.
 AREA OF OPEN SPACES: 1000 SQ. YDS.
 AREA OF BUILDING FOOTPRINTS: 9000 SQ. YDS.
 AREA OF PAVED ROADS: 1000 SQ. YDS.
 AREA OF UNPAVED ROADS: 1000 SQ. YDS.
 AREA OF UTILITIES: 1000 SQ. YDS.

REVISIONS

LAYOUT PLAN OF NEHRU NAGAR
 SECTOR NO. III G.M.P.
 CHANDINAGAR (REVISED)

DATE: 11-03-1967

SCALE: 1" = 100' 1/2"

SCALE: 1" = 100'



TOWN PLANNER: KALASHAN

IN CHARGE: P.P.

C.A.P.

48

मद सं०

9

विषय: पटेलनगर ए-ब्लाक में स्थित लोकल शाप भूखण्ड को आवासीय में परिवर्तन में सम्बन्ध में ।

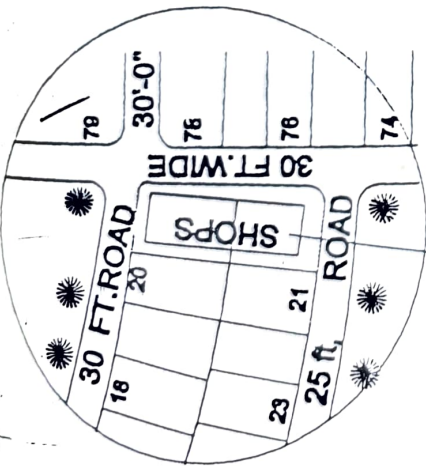
प्राधिकरण द्वारा विकसित पटेलनगर योजना के 'ए' ब्लाक में कनविनियंट शापिंग हेतु भूखण्ड आरक्षित है , जिसका क्षेत्रफल लगभग 609 व०मी० है । उक्त भूखण्ड की व्यवसायिक अनुभाग द्वारा 4-5 बार नीलामी लगाई जा चुकी है । लेकिन कोई बोलीदाता उपस्थित नहीं हुआ , चूंकि उक्त भूखण्ड आन्तरिक भाग में स्थित है , अतः व्यवसायिक उपयोग हेतु सम्भवतः बोलीदाता नहीं आ रहा है । उक्त भूखण्ड को कनविनियेन्ट शाप से आवासीय किये जाने पर जन सामान्य से आपत्तियां/ सुझाव हेतु विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी ,परन्तु इस पर कोई आपत्ति /सुझाव निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं हुई ।

उपरोक्त सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 23-6-2003 के मद सं०-25 पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ,जिसे आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित करने का निर्णय लिया गया था ।

उपरोक्त भूखण्ड संलग्न साईट प्लान में प्रदर्शित किया गया है । गाजियाबाद महायोजना -2001 में उक्त भूखण्ड का भू- उपयोग आवासीय दर्शित है तथा पटेलनगर के तलपट मानचित्र में कनविनियेन्ट शाप प्रदर्शित किया गया है । उक्त कनविनियेन्ट शाप के भूखण्ड को तलपट मानचित्र में कन्विनिएट शाप से आवासीय में परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव है ।

उपरोक्तानुसार पटेलनगर कालोनी में 'ए' ब्लाक स्थित लगभग 609 व०मी० के उक्त भूखण्ड को कनविनियेन्ट शाप से आवासीय किये जाने तथा इसे व्यवसायिक आरक्षित दर पर नीलामी प्रक्रिया द्वारा विक्रय किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

Atank.
A.T.P



मद सं० :

10

विषय : गाजियाबाद नगर में फ्लाई ओवर, रोड ओवर ब्रिज एवं ग्रेडसैपरेटर्स बनाये जाने के सम्बन्ध में ।

इससे सम्बन्धित विषय प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 23-6-03 में मद सं० 45 पर प्रस्तुत किया गया था जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव एवं लिये गये निर्णय की प्रति संलग्न है ।

इसके उपरान्त इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस एवं अन्य विभागों के साथ बैठक की गयी एवं कुछ और स्थानों पर रोड ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर व ग्रेड सैपरेटर्स बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी । इसको सम्मिलित करते हुए अब जो रोड ओवर ब्रिज फ्लाई ओवर बनाने प्रस्तावित हैं । इनका विवरण निम्न प्रकार हैं :-

विवरण	अनुमानित लागत
<u>फ्लाई ओवर</u>	
1- कैनिल वर्थ चौराहे पर फ्लाई ओवर	15.0 करोड
2- मेरठ तिराहे को एन०एच०-24 को मिलाने हेतु प्रस्तावित लिंक रोड पर कलोवर लीव फ्लाई ओवर रोड ओवर ब्रिज	25.0 करोड
1- शास्त्रीनगर व कविनगर इन्डस्ट्रियल एरिया के बीच से जाने वाले मास्टर प्लान रोड जो एन०एच०-24 से मिलती है । गाजियाबाद हापुड रेलवे लाईन पर रोड ओवर ब्रिज	15.0 करोड
2- राजनगर ए०एल०टी० के सामने से जाने वाली मास्टर प्लान रोड (जो मेरठ रोड से मिलती है) पर गाजियाबाद मेरठ रेलवे लाईन पर रोड ओवर ब्रिज	15.0 करोड
3- हापुड रोड पर गाजियाबाद लखनऊ रेलवे लाईन पर रोडओवर ब्रिज (डासना के पास)	15.0 करोड
4- शहादरा सहारनपुर रेलवे लाईन पर गाजियाबाद लोनी रोड पर रोड ओवर ब्रिज	15.0 करोड
<u>अण्डर ब्रिज</u>	
1- नेहरू नगर से कविनगर को जाने वाली सडक पर मेरठ रेलवे लाईन पर (नासरपुर फाटक) पर अण्डर ब्रिज का निर्माण कार्य	10.0 करोड

कार्य	10.0 करोड
2- मेरठ तिराहे को एन0एच0 24 को मिलाने वाली प्रस्तावित लिंक रोड हेतु दिल्ली गाजियाबाद रेलवे लाईन पर अण्डर ब्रिज का निर्माण	10.0 करोड
ग्रेड सैपरेटर्स	
1- मोहन नगर दिल्ली लिंक रोड व जी0टी0 रोड के 'टी' जंकशन पर ग्रेड सैपरेटर्स	07.0 करोड
2- अम्बेडकर रोड व जी0टी0 रोड के 'टी' जंकशन (चौधरी मोड) पर ग्रेड सैपरेटर	07.0 करोड
3- अम्बेडकर रोड व मेरठ रोड के 'टी' जंकशन पर ग्रेड सैपरेटर	07.0 करोड
4- हापुड रोड व जी0टी0 रोड के 'टी' जंकशन पर (ठाकुरद्वारा के पास) ग्रेड सैपरेटर	07.0 करोड
5- मेरठ तिराहे को एन0एच0-24 को मिलाने वाली प्रस्तावित लिंक रोड व एन0एच0-24 के 'टी' जंकशन पर ग्रेड सैपरेटर	07.0 करोड
कुल सं० 10	कुल 155.0 करोड

उपरोक्त सभी कार्य प्राधिकरण के द्वारा अगले 5 वर्षों में बनाये जाने प्रस्तावित हैं । ये सभी कार्य अवस्थापना निधि से धनराशि उपलब्धता के अनुसार कराये जायेंगे । इनमें से अगले वित्तीय वर्ष 2004-2005 में प्राथमिकता एवं धनराशि उपलब्धता के आधार पर निम्न कार्य प्रारम्भ किये जाने पर विचार हेतु प्रस्तुत है ।

- 1- कैनिलवर्थ चौराहे पर फ्लाई ओवर
- 2- शास्त्रीनगर कविनगर के बीच से जाने वाली मास्टर प्लान रोड (जो एन0एच0-24 से मिलती है) पर गाजियाबाद हापुड रेलवे लाईन पर रोड ओवर ब्रिज ।
- 3- राजनगर ए0एल0टी0 के सामने से जाने वाली मास्टर प्लान रोड पर (जो मेरठ रोड से मिलती है) पर गाजियाबाद रेलवे लाईन पर रोड ओवर ब्रिज ।

प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।

मदसंख्या :-

गाजियाबाद नगर में रोड ओवर ब्रिज तथा फ्लाई ओवर

बनाये जाने के सम्बन्ध में :-

पिछले 10-15 वर्षों में गाजियाबाद नगर के क्षेत्रफल में व जनसंख्या में आशातीत वृद्धि हुयी है। इस विकास के फलस्वरूप नगर से जाने वाली रेल लाईनें नगर के बीच में आ गयी हैं तथा निवासियों को एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए अक्सर इन रेलवे लाईनों को पार करना पड़ता है। इस अवधि में रेल ट्रैफिक में भी काफी वृद्धि हुयी है तथा गाजियाबाद नगर से गुजरने वाली ट्रेन की फ्रीक्वेन्सी में भी वृद्धि होने के कारण नगर के बीच में आये लेवल क्रॉसिंग अक्सर बन्द रहते हैं। जिसके कारण निवासियों को इन लेवल क्रॉसिंग्स पर घंटों खड़े रहना पड़ता है। जिससे समय व धन की बर्बादी के साथ-साथ दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है। साथ ही साथ नगर के मुख्य मार्गों के चौराहों पर भी यही स्थिति बनी हुयी है। अतः नगर के बहुमुखी विकास व निवासियों की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न स्थानों पर फ्लाईओवर तथा रेलवे क्रॉसिंग के स्थान ^{पर} रोड ओवर ब्रिज बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। साथ ही साथ यहां के जनप्रतिनिधियों की भी यही मांग है।

इस प्रकार की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के रेल मंत्रालय की नीति भी शहर के मध्य ^{अर्थात्} लेवल क्रॉसिंग्स पर रोड ओवर ब्रिज बनाये जाने की है। इसके अनुसार जो लेवल क्रॉसिंग्स शहर के मध्य में आ गये हैं उन पर दू लैन रोड ओवर ब्रिज बनाये जाने की दशा में उस पर आने वाले व्यय की 50 प्रतिशत धनराशि रेलवे विभाग द्वारा वहन की जाती है तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय अथवा रैगुलेटरी अथोरिटी को वहन करनी होगी तथा यदि दू लेन से अधिक चौड़ा रोड ओवर ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित हो तो अतिरिक्त चौड़ाई पर आने वाला ^{उपरास्त} व्यय लाभार्थी संस्था को स्वयं वहन करना होगा।

उपरोक्त सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्न स्थानों पर रोड ओवर ब्रिज बनाये जाने प्रस्तावित हैं :-

1. दिल्ली लखनऊ राजमार्ग पर अध्यात्मिक नगर के पास रोड ओवर ब्रिज का निर्माण

क्रमशः.....

2. ए.एल.टी. सेंटर के सामने से होते हुए मेरठ रोड़ पर जाने के लिए पार किये जाने वाले रेलवे क्रासिंग पर रोड़ ओवर ब्रिज का निर्माण।
3. कविनगर इंडस्ट्रीयल ऐरिया एवं शास्त्री नगर के बीच जाने वाली मास्टर प्लान रोड़ से होकर एन.एच.-24 पर जाने हेतु पार किये जाने वाले लेवल क्रासिंग पर रोड़ ओवर ब्रिज का निर्माण।
4. नेहरू नगर को कविनगर से जोड़ने वाली सड़क पर स्थित नासिर पुर फाटक पर अंडर ब्रिज का निर्माण।
5. मेरठ तिराहे को एन.एच. 24 से जोड़ने वाली प्रस्तावित 75 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान रोड़ पर दिल्ली गाजियाबाद रेलवे लाईन के नीचे अंडर ब्रिज का निर्माण।
6. अम्बेडकर रोड़ पर संतोष अस्पताल (कैनिल बर्थ चौराहा) के पास फ्लाई ओवर का निर्माण
7. जी.टी. रोड़ पर दिल्ली यू.पी. सीमा पर फ्लाई ओवर का निर्माण // रेल मंत्रालय की उपरोक्त वर्णित नीति का लाभ उठाने व नगर की यातायात समस्या के समाधान हेतु उपरोक्त रोड़ ओवर ब्रिज/फ्लाई ओवर का निर्माण विभिन्न चरणों में कराया जाना प्रस्तावित है तथा प्रथम चरण में क्रम संख्या 1 ~~क~~ ^{इस} पर उल्लिखित रोड़ ओवर ब्रिज बनाये जाने प्रस्तावित हैं। ~~इस~~ रोड़ ओवर ब्रिज के बनने से राजनगर, कविनगर, शास्त्री नगर, गोविन्दपुरम आदि विकास प्राधिकरण की योजनाओं के निवासी तथा नगर से होकर गुजरने वाले लाखों नागरिक लाभान्वित होंगे।

इस प्रकार के रोड़ ओवर ब्रिज के निर्माण में रेलवे लाइन के ऊपर बनाये जाने वाले भाग का निर्माण रेलवे विभाग स्वयं करेगा तथा दोनों ओर के रोड़ व अन्य सम्बन्धित कार्य सरकारी संस्थाओं (जो इस प्रकार के कार्य करती हैं) से कराया जाना प्रस्तावित है ^{यह कार्य नगर निगम परियोजना द्वारा} तथा दोनों रोड़ ओवर ब्रिज पर आने वाले व्यय की अवशेष धनराशि लाभान्वित होने वाली संस्थाओं (नगर निगम, यू.पी.एस.आई.डी.सी. आदि) के द्वारा वहन किया जायेगा तथा विकास प्राधिकरण भी अपना योगदान अवस्थापना निधि से इसमें देगा।

अतः यह प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान

किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

- 40- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन / वर्कचार्ज कर्मचारियों को वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया ।
- 41- श्री प्रतोष कुमार शर्मा, अवर अभियन्ता के पिता के ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान किये जाने विषयक । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया ।
- 42- न्यू एडवांस एजुकेशनल सोसायटी ,38 रमते राम रोड, गाजियाबाद को वैशाली योजना में स्कूल भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया ।
- 43 ब्याज दर में कमी के सम्बन्ध में । प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
- 44 आयकर धारा- 10(20-ए) के अधीन छूट समाप्त होने के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली टैक्स प्लानिंग । प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
- 45 गाजियाबाद नगर में रोड ओवर ब्रिज तथा फ्लाई ओवर बनाये जाने के सम्बन्ध में । प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई ।
- 46 गढमुक्तेश्वर - ब्रजघाट क्षेत्र में मानचित्रों पर शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में । प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
- 47 रिट याचिका सं0 54927 /2002 मै0 खेमका स्टूअर्स लीजर लिमिटेड बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के सम्बन्ध में । प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया ।

21/3/25

मद :

11

विषय :- इन्दिरापुरम योजना के स्वर्ण जयन्ती पार्क का सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य।

महान महिला स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्मान में स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 25 एकड़ क्षेत्रफल में स्वर्णजयन्ती पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित किया गया था । यह ऐतिहासिक पार्क प्राधिकरण द्वारा 1122.00 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जा रही इन्दिरापुरम योजना के बीच में प्रस्तावित है। स्वर्णजयन्ती पार्क में वर्ष 1997 में महारानी लक्ष्मीबाई की विशाल मूर्ति स्थापित कर दी गयी थी। उसके उपरान्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण कार्य स्थगित कर दिया गया था । इस पार्क को गत वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण करने का निर्णय लिया गया था । इस पार्क में म्यूजिकल फाउन्टेन, ओपन थियेटर, क्राफ्ट बाजार, ओपन रेस्टोरैन्ट चिल्ड्रन प्ले ग्राउन्ड इत्यादि सुविधायें होंगी ।

उपरोक्त प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु प्रस्तुत है।

seyh

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रोपर्टी मैनेजमेन्ट साफ्टवेयर के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक लगभग एक लाख सम्पत्तियों का सृजन किया जा चुका है । वर्तमान में इसका रिकार्ड फाईलों में ही परम्परागत ढंग से रखा जाता है । इस विधि में अधिकतर रिकार्ड अद्यतन नहीं रह पाते हैं तथा आवंटियों को उनकी अद्यतन स्थिति से तुरन्त अवगत करा पाना कठिन होता है । विगत वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी सम्पत्तियों के कम्प्यूटराईजेशन कराने के प्रथम चरण में ज्यादातर सम्पत्तियों की प्रविष्टि कर उनका मास्टर बेस तैयार कर लिया गया है । लगभग (अस्सी हजार) एन्ट्री हो चुकी है इस डाटा बेस का समुचित उपयोग करने हेतु निम्न कार्य कराने होंगे ।

- 1- जो मास्टर डाटा बेस तैयार हो गया है वह अपडेट नहीं हो पा रहा है । उसे तुरन्त कैस काउन्टर से आन लाइन पर दिया जाये । जिससे वह अपडेट होता रहे व डाटा पुनः आउट डेटेड न हो जाय । इस हेतु जिस साफ्ट जरूरत पड़ेगी वह प्राधिकरण अपने स्तर से करा ले ।
- 2- शासन स्तर नर आवास बन्धु द्वारा पूर्ण कम्प्यूटराईजेशन हेतु साफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है । काफी समय से साफ्टवेयर प्राप्त नहीं हो पाया है । गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अपनी अलग समस्याये है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार साफ्टवेयर विकसित करना होगा अथवा शासन के द्वारा उपलब्ध कराया गया साफ्टवेयर अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधित करना होगा जिसमें काफी समय लग सकता है तथा प्राधिकरण ने अब तक जो भी डाटा बेस तैयार किया है वह आउट डेटेड हो जायगा तथा पुनः तैयार करना होगा । पूर्व में शासन द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा कानपुर विकास प्राधिकरण को अपना साफ्टवेयर विकसित कर कम्प्यूटराईजेशन करने की अनुमति दी है । गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को भी अपने स्तर से किसी पी.सी.यू. से कम्प्यूटराईजेशन करना उचित होगा ।

प्रस्ताव बोर्ड के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

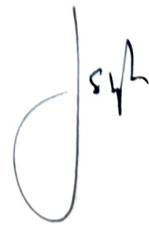
मद सं० :

13

विषय :- प्राधिकरण की योजनाओं की भूमि का लेण्ड आडिट सर्वे कराया जाना ।

प्राधिकरण द्वारा कभी भी अपनी भूमि का लेण्ड आडिट नहीं कराया गया है। इसी क्रम में प्राधिकरण द्वारा अपनी भूमि का आडिट कराने का निर्णय लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा सर्वप्रथम इन्दिरापुरम योजना के वैभव खण्ड एवं अहिंसा खण्ड का लेण्ड आडिट टोटल स्टेशन मैथड द्वारा कम्प्यूटराईज्ड सर्वे कराया गया, जिसमें ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के क्षेत्रफल में काफी वृद्धि हुई । प्राधिकरण को इससे करोड़ों रुपये की अतिरिक्त आय हुई । यह कार्य मैसर्स एक्सेटेक कन्सलटेन्ट्स प्रा० लि० से ₹० 275/- प्रति एकड लेण्ड आडिट सर्वे व ₹० 550.00 प्रति एकड कन्टूरिंग बिद प्लेनटेबल सर्वे के दर से कराया गया है। अब तक कौशाम्बी एवं वैशाली योजनाओं का सर्वे का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। इससे स्थल पर भूखण्ड, भवन, विकास कार्य, अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण इत्यादि जैसे स्थल पर हैं उनकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इसी की भांति प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी तथा की जा रही इन्दिरापुरम इत्यादि योजनाओं का भी लेण्ड आडिट सर्वे कराया जाना प्रस्तावित है। यहाँ पर यह भी अवगत कराना है इस कम्प्यूटराईज्ड सर्वे का उपयोग प्राधिकरण कम्प्यूटर द्वारा अपने कम्प्यूट्राइजेशन प्रोग्राम में तथा नियोजन में सीधे कम्प्यूटर द्वारा उपयोग में लाया जा सकेगा ।

प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।



मद सं०

14

विषय: गढमुक्तेश्वर में भूमि अर्जन के सम्बन्ध में ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 सं० 355/ 9-आ-6-03-3 गठन : 01 लखनऊ दिनांक 01 फरवरी 2003 की अधिसूचना के अनुसार गढमुक्तेश्वर शहर के सुनियोजित विकास के लिए शासन द्वारा उक्त शहर को गाजियाबाद विकास अधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया है। जिसके अनुसार राजस्व ग्राम गढमुक्तेश्वर, बांगर की 59.709 एकड़ भूमि एवं गढमुक्तेश्वर खादर की 69.0595 एकड़ भूमि के अर्जन प्रस्ताव जिलाधिकारी/ शासन को क्रमशः दिनांक 6-5-2003, 23-5-03 में प्रेषित किये जा चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशों के क्रम में गढमुक्तेश्वर बांगर की 59.709 एकड़ भूमि की स्वीकृति बोर्ड बैठक में ली जानी है तथा गढमुक्तेश्वर खादर की 69.0595 एकड़ भूमि के अर्जन प्रस्ताव को वापस लेने हेतु अनुमति बोर्ड बैठक में ली जानी है।

अतः गढमुक्तेश्वर बांगर की 59.709 एकड़ भूमि के अर्जन प्रस्ताव की स्वीकृति एवं गढमुक्तेश्वर खादर की 69.0595 एकड़ भूमि के अर्जन प्रस्ताव को वापस लेने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत है।

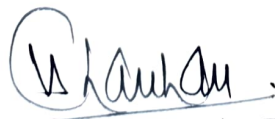

त. ६. २००३

मद सं० : 15

विषय : ग्राम मोरटा, रईसपुर, ढरगल, महीउद्दीनपुर, मैनापुर, हरसांव, सदरपुर, की 1000 एकड़ भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में ।

राजस्व ग्राम रहीसपुर, सदरपुर, महीउद्दीनपुर, मैनापुर, रसूलपुर-याकूतपुर, नगलापाठ की भूमि के अर्जन हेतु बोर्ड बैठक दिनांक 30-11-2002 की मद सं० 41 में प्रस्ताव रखा गया था । जिसका क्षेत्रफल अनुमानतः 2000 एकड़ था, जिसमें से प्रथम फेज में 1000 एकड़ भूमि का अर्जन प्रस्ताव बनाने हेतु बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की है । उक्त ग्रामों में सेक्टर-27 हेतु ग्राम सदरपुर की 666.5448 एकड़ भूमि व सेक्टर-25 ग्राम सदरपुर महीउद्दीनपुर, मैनापुर, नगलापाठ, रहीसपुर, रसूलपुर, याकूतपुर की 525.7148 एकड़ भूमि कुल 1192.2596 एकड़ भूमि के अर्जन प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी/ शासन को क्रमशः दिनांक 14-1-03 एवं 2-7-03 को प्रेषित किये जा चुके हैं ।

मेरठ दिल्ली सड़क से प्रस्तावित योजना को मिलाने वाली 150 फुट चौड़ी सड़क जो ग्राम रसूलपुर, याकूतपुर एवं मोरटा की औद्योगिक भूमि के अन्तर्गत पड़ती है, उसका भी अर्जन प्रस्ताव बनाने एवं सेक्टर 23, 24, 28, 28-ए के अर्जन प्रस्ताव भेजने हेतु तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 29-8-03 में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । अतः ग्राम मोरटा, रहीसपुर, ढरगल, महीउद्दीनपुर, मैनापुर, हरसांव, सदरपुर, जिसका क्षेत्रफल अनुमानतः 1000 एकड़ है जिसके अर्जन हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।



AOEO (CA)

विषय : ट्रान्सपोर्ट नगर योजना विकास हेतु ग्राम बाँझा एवं घूकना के अर्जन प्रस्ताव निरस्त करने हेतु ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 23-12-2000 में लिये गये निर्णय के अनुसार ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु ग्राम बाँझा एवं घूकना की 84.2492 एकड़ भूमि के अर्जन प्रस्ताव धारा-4(1) व धारा 6/ 17 के प्रकाशन हेतु जिलाधिकारी एवं शासन को दिनांक 29-6-2002 को प्रस्तुत किया गया था । वर्तमान में महायोजना 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर बोर्ड बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है । जिसमें ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु जो स्थिति पूर्व में है उसमें परिवर्तन प्रस्तावित है ।

अतः पूर्व में प्रस्तावित ग्राम बाँझा एवं घूकना की ट्रान्सपोर्ट नगर योजना हेतु 84.2492 एकड़ भूमि अर्जन प्रस्ताव को निरस्त करने का प्रस्ताव है । भविष्य में महायोजना 2021 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर ट्रान्सपोर्ट नगर योजना हेतु अर्जन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।

-E

am
SE.am
CATP

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन/ वर्कचार्ज कर्मचारियों को वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन/ वर्कचार्ज कर्मचारियों को वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 20-2-2003 में रखा गया था । विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए शासन को सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया । बोर्ड निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया गया । परन्तु अभी तक शासन की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है । पुनः शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 23-8-2003 में विचारार्थ रखा गया था । बोर्ड द्वारा प्रस्ताव आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया । इसी मध्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के 25 दैनिक वेतन कर्मचारियों द्वारा अपना विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं० 43366/ 2003 प्रेम कुमार एवं अन्य बनाम उ० प्र० सरकार एवं अन्य दायर की गयी । जिसका प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया । इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा किये गये अन्तरिम आदेश निम्न प्रकार है:-

“In the facts and circumstances of the case, I ~~am~~ uphold the objections of Sri H.R. Misra that so long petitioners are getting daily wages which are more than the minimum of the pay scale without any allowances, they are not entitled to any further relief. The petitioners, however, have made out the case for issuing interim mandamus to State Government to consider and decide the matter of requisition of Ghaziabad Development Authority for sanction of additional post.

In the facts and circumstances, an interim mandamus is issued to the State Government to consider and decide with regard to sanction of additional post of clerks in Ghaziabad Development Authority for which a resolution has been passed by the authority and requisitions have been sent, as expeditiously as possible, and in any case within two months, or to file counter affidavit within the said period.

List in second week of January, 2004.”

यहां यह उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत अकेन्द्रीयत सेवा के दैनिक वेतन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान दिये जाने पर रू० 1,08,181-00, वर्कचार्ज कर्मचारियों पर रू० 1,28,060-00 , कम्प्यूटर के कर्मचारियों पर रू० 29,178-00 तथा केन्द्रीयत सेवा के कर्मचारी दैनिक वेतन/ वर्कचार्ज को दिये जाने पर रू० 2,54,610-00 का व्ययभार प्रतिमाह आयेगा । विस्तृत गणना चार्ट संलग्न है ।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के परिप्रेक्ष्य में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के दैनिक वेतन/ वर्कचार्ज कर्मचारियों को वेतनमान बिना भत्ते के दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को अग्रसरित करने हेतु प्राधिकरण की बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।



दैनिक वेतन कर्मचारियों पर

क० सं० विवरण

कुल कर्मचारी की सं० मूल वेतन महगाई भत्ता वेतनमान देने पर कुल वर्तमान परिलब्धि अन्तर विन्दु-3 के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान देनेपर कुल व्ययभार

55 प्रति०

9

8

7

6

5

4

3

2

53,820 / -

1- लिपिक-81,अमीन-2,वाहन चालक-18

सुपरवाइजर-14

2- उद्यान सुपरवाइजर-6

3- पम्प ऑपरेटर- 3

4- गनमैन-2 ,सुरक्षागार्ड-24

5- प्लम्बर-2 ,इलैक्ट्रिशियन -1

6- फोटो स्टेट ऑपरेटर -1

7- चौकीदार-4,चपरासी-25, स्वीपर-11,

हेल्पर-1,माली-52,आया-2,सहचालक-1,

249

वर्कचार्ज कर्मचारी अकेन्द्रीयत सेवा अभियन्ता

129

1- सुपरवाइजर - 129

60,372 / -

468 / -

4260 / -

4728 / -

1678 / -

3050 / -

129

1,08,181-00

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन / वर्कचार्ज कर्मचारी जो 29-6-91 से पूर्व के अकेन्द्रीयत सेवा के हैं, को वेतनमान दिये जाने पर पडने वाले वित्तीय भार का विवरण ।

दैनिक वेतन कर्मचारियों पर

क्र० सं०	विवरण	कुल कर्मचारी की सं०	मूल वेतन	महगाई भत्ता 55 प्रति०	वेतनमान देने पर कुल	वर्तमान परिलब्धि	अन्तर	विन्दु-3 के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान देनेपर कुल व्ययभार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	लिपिक-81,अमीन-2,वाहन चालक-18	115	3050/-	1678/-	4728/-	4260/-	468/-	53,820/-
	सुपरवाइजर-14							
2-	उद्यान सुपरवाइजर-6	06	3200/-	1760/-	4960/-	4260/-	700/-	4,200/-
3-	पम्प आपरेटर- 3	03	2610/-	1436/-	4046/-	3480/-	566/-	1,698/-
4-	गनमैन-2 ,सुरक्षागार्ड-24	26	2750/-	1513/-	4263/-	4260/-	003/-	78/-
5-	प्लम्बर-2 ,इलेक्ट्रिशियन -1	03	2750/-	1513/-	4263/-	3480/-	783/-	2,349/-
6-	फोटो स्टेट आपरेटर -1	01	2650/-	1458/-	4108/-	3480/-	628/-	628/-
7-	चौकीदार-4,चपरासी-25, स्वीपर-11, हेल्पर-1,माली-52,आया-2,सहचालक-1,	96	2550/-	1403/-	3953/-	3480/-	473/-	45,408/-
		249						1,08,181-00

वर्कचार्ज कर्मचारी अकेन्द्रीयत सेवा अभियन्ता

1-	सुपरवाइजर - 129	129	3050/-	1678/-	4728/-	4260/-	468/-	60,372/-
----	-----------------	-----	--------	--------	--------	--------	-------	----------

2- इलेक्ट्रिशियन- 1	1	2750 / -	1513 / -	4263 / -	3480 / -	783 / -	783 / -
3- मेट-95, पम्पापरेटर -9	104	2610 / -	1436 / -	4046 / -	3480 / -	566 / -	58,864 / -
4- चौकीदार-4, स्वीपर-13	17	2550 / -	1403 / -	3953 / -	3480 / -	473 / -	8,0421 / -
	250						1,28,060 / -

कम्प्यूटर के अनुबन्ध के 29-6-91 से पूर्व के कर्मचारी जो वर्तमान में दौरे पर हैं ।

1- डाटा एन्ट्री आपरेटर-13	13	4000 / -	2200 / -	6200 / -	4260 / -	1940 / -	25,220 / -
2- टेलीफोन आपरेटर -1	01	3050 / -	1678 / -	4728 / -	4260 / -	468 / -	468 / -
3- सहायक प्रोग्रामर	01	5000 / -	2750 / -	7750 / -	4260 / -	3490 / -	3,490 / -
	15						29,178 / -

केन्द्रीयत सेवा (दैनिक वेतन)

1- उद्यान अधीक्षक-1, केयर टेकर -1 केन्द्रीयत सेवा (वर्कचार्ज अभियन्ता)	02	4500 / -	2475 / -	6975 / -	5130 / -	1845 / -	3,690 / -
1- अवर अभियन्ता -136	136	4500 / -	2475 / -	6975 / -	5130 / -	1845 / -	2,50,920 / -

मद संख्या :

18

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु उपरान्त उनके आश्रित को प्राधिकरण में रखे जाने विषयक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु उपरान्त उनके आश्रित समय समय पर प्राधिकरण में रखे जाने हेतु अनुरोध करते आ रहे हैं। जबकि मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अनुसार नियमित कर्मचारियों की मृत्यु उपरान्त उनके आश्रित को अभी तक सेवा में रखे जाने का प्राविधान है। तथा दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित को सेवा में रखे जाने का प्राविधान मृतक सेवा नियमावली में नहीं है, परन्तु प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा के कर्मचारियों की मृत्यु उपरान्त उनके आश्रितों द्वारा प्राधिकरण में रखे जाने का अनुरोध किया गया है। पूर्व में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज के आश्रित तीन कर्मचारियों को अनुबन्ध आधार पर प्राधिकरण में रखा गया है। जिसमें दो कर्मचारी वर्ष 98 से पूर्व के हैं तथा श्रीमती किरण देवी को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 20-2-2003 के निर्णय अनुसार अनुबन्ध पर रखा गया है तथा वर्तमान में 6 कर्मचारियों के मृत्यु उपरान्त उनके आश्रितों द्वारा सेवा में रखे जाने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण चार्ट संलग्न है।

अतः उक्त 6 कर्मचारियों को जो मृतक आश्रित हैं को मानवीय आधार पर प्राधिकरण में अनुबन्ध आधार पर रखे जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में संविदा पर मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण

क्र०सं०	मृतक आश्रित का नाम	वर्तमान पद	नियुक्ति की तिथि	मृतक कर्मचारी का प्राधिकरण में पद
1-	श्रीमती लक्ष्मी देवी	चपरासी	1-6-96	पी०डब्ल्यू०डी० वेतनमान वर्कसुपरवाईजर
2-	श्रीमती राजवती	स्वीपर	4-12-98	पी०डब्ल्यू०डी० वेतनमान स्वीपर
3-	श्रीमती किरण देवी	लिपिक	8-1-2003	पी०डब्ल्यू०डी० वेतनमान वर्कसुपरवाईजर

वर्तमान में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मृतक आश्रितों का विवरण जिनके द्वारा नौकरी पर रखे जाने का अनुरोध किया गया है

क्र०सं०	मृतक आश्रित का नाम/ पिता का नाम	जिस पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया है	मृत्यु का दिनांक	शैक्षिक योग्यता	मृतक कर्मचारी का प्राधिकरण में पद क्या था
1-	श्री मुकेश चन्द शर्मा पुत्र स्व० श्री रामकुमार शर्मा	पद का उल्लेख नहीं है।	26-10-99	हाईस्कूल फेल	पी०डब्ल्यू०डी० वेतनमान इलेक्ट्रिशियन
2-	श्री मजहर पुत्र स्व० श्री अजीजुल हक	चौकीदार	23-1-2000	हाईस्कूल	पी०डब्ल्यू०डी० वेतनमान चौकीदार
3-	श्री रबिन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री बालराम	स्वीपर	6-2-2003	—	पी०डब्ल्यू०डी० वेतनमान स्वीपर (उपाध्यक्ष के आदेश हो चुके हैं।
4-	श्री रामउदार पाण्डेय पुत्र स्व० श्री त्रिलोकीनाथ पाण्डेय	—	9-3-2003	कक्षा-8	मस्टर रोल पर चौकीदार
5-	श्री मौ० मुस्तफा पुत्र स्व० श्री यूसुफ	—	6-6-2003	वी० काम द्वितीय वर्ष	दैनिक वेतन माली
6-	श्री विशाल कुमार भारती पुत्र स्व० श्री श्यामलाल	चपरासी	13-6-2003	हाईस्कूल	पी०डब्ल्यू० डी वेतनमान वर्कसुपरवाईजर

मद सं०:

19(क)

विषय : श्री अजयपाल सिंह, दैनिक वेतन लिपिक की पत्नी के ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान विषयक ।

श्री अजयपाल सिंह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में दैनिक वेतन लिपिक के पद पर दिनांक 25-10-88 से कार्यरत हैं । इनके पहले बच्चे का जन्म आपरेशन द्वारा हुआ है । आपरेशन एवं ईलाज पर इनके द्वारा कुल रू० 17,150-00 तथा उसका भुगतान प्राधिकरण से किये जाने का अनुरोध किया गया कि वह एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं । अतः उनकी पत्नी के ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान प्राधिकरण से कराया जाये । इनके अनुरोध पर इनकी पत्नी के ईलाज से सम्बन्धित बिल प्राधिकरण द्वारा अधिकृत डा० को सत्यापन हेतु भेजा गया । डा० द्वारा भेजे गये बिल रू० 17,150-00 में से रू० 6,530-00 को भुगतान योग्य पाया गया । जिसका भुगतान इन्हें किया गया है । चूंकि श्री अजयपाल सिंह दैनिक वेतन के एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं । अतः इनकी पत्नी के ईलाज से सम्बन्धित भुगतान किये गये मेडिकल बिलों की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।



मद संख्या :

19 (ख)

विषय : श्री प्रतोष कुमार शर्मा अवर अभियन्ता के पिता के ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान किये जाने विषयक।

श्री प्रतोष कुमार शर्मा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अवर अभियन्ता के पद पर नियमित रूप से कार्यरत हैं। इनके पिता श्री एम0सी0 शर्मा कैंसर रोग से पीडित थे। जिसके कारण इनका ईलाज धर्मशिला कैंसर हास्पिटल रिसर्च सेन्टर दिल्ली में चल रहा था। इनके द्वारा उनके ईलाज पर पूर्व में बोर्ड बैठक दिनांक 20-2-2003 के अनुसार रू0 84,770-00 का भुगतान स्वीकृति उपरान्त स्वीकृति उपरान्त दिनांक 27-3-2003 को किया जा चुका है। अब पुनः इनके द्वारा उनके ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान प्राधिकरण से किये जाने का अनुरोध किया गया है। जिसकर रू0 1,26,978-55 का मेडिकल बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है। जो सत्यापन हेतु प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नियुक्त डा0 संजीव अग्रवाल को भेजा गया था। डा0 अग्रवाल द्वारा भेजे गये बिल रू0 1,26,978-55 के विरुद्ध रू0 1,00,501-55 को भुगतान योग्य पाया गया है। प्राधिकरण की पूर्व बोर्ड बैठक दिनांक 7-6-02 में लिये गये निर्णय अनुसार मात्र रू0 50,000-00 तक के मेडिकल बिलों का भुगतान का अधिकार अध्यक्ष को है तथा इससे अधिक के मेडिकल बिलों का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाना है।

अतः श्री प्रतोष कुमार शर्मा अवर अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत उनके पिता के ईलाज से सम्बन्धित मेडिकल बिलों का भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या :

19(ग)

विषय : श्री एच0के0 सिंघल अवर अभियन्ता के पुत्री के ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान किये जाने विषयक ।

श्री एच0 के0 सिंघल, गाजियाद विकास प्राधिकरण में अवर अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं । इनकी पुत्री कु0 अंशुल काफी दिनों से कोनिक डिजीज से पीडित हैं । इनका ईलाज पूर्व में यशोदा अस्पताल में कराया गया था , तथा हालत में सुधार न होने के कारण पुनः पुष्पावती सिंघानियां रिसर्च इन्स्टीट्यूट नई दिल्ली में कराना पडा । तथा ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 07-6-2002 में रखा गया । बोर्ड बैठक दिनांक 7-6-2002 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्री सिंघल को रू0 50000/- अग्रिम के रूप में दिया गया । श्री सिंघल द्वारा कुल रू0 1,52,126-65 का बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया जो प्राधिकरण के डा0 को सत्यापन हेतु भेजा गया । डा0 द्वारा भेजे गये बिल रू0 1,52,126-65 में से रू0 1,06,694-00 को भुगतान योग्य पाया गया है । जिसके विरुद्ध इन्हें रू0 50,000-00 अग्रिम दिया गया है ,जिसका समायोजन इनके मेडिकल बिल से किया जाना है ।

अतः श्री सिंघल की पुत्री के ईलाज से सम्बन्धित मेडिकल बिलों में रू0 50,000-00 अग्रिम का समायोजन करते हुए अवशेष रू0 56,694-65 का भुगतान श्री सिंघल को किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ / निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

मद सं० : 20

विषय : विजयनगर पुर्नवास योजना (सेक्टर 11 व 12) में झुग्गीवासियों को आवंटित भूखण्डों पर ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 1985 में झुग्गी झोपड़ी निवासियों को पुर्नवास योजना के अर्न्तगत सै० 11 व 12 विजय नगर में 28 वर्ग मीटर से 45 वर्ग मीटर के कुल 2106 भूखण्ड आवंटित किये गये थे । इन आवंटित भूखण्डों का मूल्य रू० 5000/- निर्धारित करते हुए भुगतान विवरण इस प्रकार बनाया गया कि प्रत्येक आवन्ती को रू० 50/- आवेदन के साथ एवं रू० 1-00 प्रतिदिन 4950 किस्तों में जमा करना था तथा बिलम्ब की दशा में दस पैसे प्रति किस्त प्रतिदिन विलम्ब शुल्क देय था ।

उपरोक्त योजना के अधिकांश आवन्तियों द्वारा निर्धारित समय पर धनराशि जमा नहीं की गई । भुगतान विवरण की शर्तों के अधार पर गणना कराये जाने पर यह तथ्य सामने आया कि अधिकतर आवन्ती डिफाल्टर हैं एवं उन पर पेनाल्टी सहित देय राशि रूपया 13लाख से 16 लाख तक बकाया है आवन्तियों के अनुरोध पर समिति द्वारा विचार करते हुए पूर्ण प्रकरण बोर्ड बैठक 23-6-2003 में रखा गया तथा बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बीस सूत्री-कार्यक्रम के अर्न्तगत होने के कारण इन प्रकरणों में भूमि की वर्तमान सैक्टर दर रू० 3000/-प्रति वर्गमीटर से जो भी भूखण्ड का मूल्य आता है उससे अधिक ब्याज की देयता निर्धारित न की जाय तथा आवन्तियों द्वारा पूर्व में जमा समस्त धनराशि इस निर्धारित देयता के विरुद्ध समायोजित की जाय । बोर्ड द्वारा यह लाभ लेने के लिए अन्तिम तिथि 30-9-03 निर्धारित की गई एवं इसके पश्चात भूखण्ड निरस्त्रीकरण का निर्णय लिया गया ।

उक्त योजना में बोर्ड निर्णय 23-6-03 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार देयता किसी आवन्ती द्वारा जमा नहीं की गई है तथा इन आवन्तियों ने एफ ब्लॉक विजयनगर सुधार समिति के माध्यम से प्रत्यावेदन दिया है कि सभी आवन्ती दलित एवं कमजोर वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं तथा उक्त आधार पर धनराशि जमा करने में असमर्थ हैं । यह भी अनुरोध किया गया है कि उन्हें पूर्व निर्धारित मूल्य रू० 5000/-पर ही रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान की जाय । क्योंकि कुछ लोग निर्धारित राशि जमा नहीं कर पाये हैं उनसे साधारण ब्याज लगाकर धनराशि जमा करा ली जाय । समिति का प्रत्यावेदन सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है ।

यदि बोर्ड निर्णय 23-6-03 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है तब एक सामान्य क्षेत्रफल (औसत) 40 वर्गमीटर भूखण्ड के विरुद्ध देयता की स्थिति निम्न प्रकार होगी ।

वर्ष 1985 में भूखण्ड का निर्धारित मूल्य रू० 5000/-

बोर्ड द्वारा निर्धारित ब्याज / पेनेल्टी की अधिकतम राशि = $40 \times 3000 = 1,20,000-00$

कुल देयता लगभग रू० 1,25,000-00

(उपरोक्त देयता से आवन्ती द्वारा पूर्व में जमा राशि का समायोजन किया जाना है ।)

विजयनगर सुधार समिति द्वारा किये गये प्रत्यावेदन अनुसार देयता की स्थिति निम्नानुसार होगी

पूर्व निर्धारित मूल्य रू० 5000/-

ब्याज दर 18 प्रतिशत से 1985 से 2003 तक ब्याज (लगभग) 16200/-

कुल देयता रू0 21200 /-

(उक्त राशि से पूर्व जमा का समायोजन भी किया जाना होगा)

इस प्रकार औसत क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर के एक भूखण्ड पर देयता का अन्तर लगभग रू0 1.04 लाख होता है ।

प्रस्ताव है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर लिया जाये जो विजयनगर में इन आवंटियों के प्रतिनिधियों व विजयनगर सुधार समिति से वार्ता कर समस्या के व्यवहारिक निदान हेतु संस्तुति दे । तदनुसार देयता निर्धारित करते हुए वसूली हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके ।



मद सं० : 21

विषय : कौशाम्बी योजना में रिययती दर पर रजिस्ट्री हेतु समय वृद्धि हेतु प्रस्ताव

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26-6-2003 में कौशाम्बी में रजिस्ट्रियों में गति देने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था , जिसमें यह निर्णय हुआ कि भवनों की रजिस्ट्री दिनांक 30-6-2003 से पूर्व कराने की दशा में अन्तिम व अनुमानित मूल्य के अन्तर की राशि बिना ब्याज व 10 प्रतिशत छूट के साथ जमा कराई जा सकती है ।

परन्तु समय कम होने के कारण सभी आवंटियों को सूचित नहीं किया जा सका , तथा वाद वापिस लेने हेतु समय की आवश्यकता को देखते हुए उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण बैठक की प्रत्याशा में दिनांक 31-3-2004 तक का समय स्वीकृत कर दिया है ।

अतः प्राधिकरण बैठक दिनांक 26-6-2003 द्वारा दी गयी छूट सुविधा को अब दिनांक 30-6-2004 तक की कार्योत्तर समय अवधि दिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है ।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ निवेदित है ।

मद सं०: २२

विषय : संजयनगर योजना में रिक्त भवनों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में ।

संजयनगर आवासीय योजना में एच०आई०जी० तीन मंजिले, एम०आई०जी० तीन मंजिले एवं एल०आई०जी० चार मंजिले रिक्त भवनों के आवंटन हेतु समय समय पर तत्काल आवंटन योजना चलाई गयी है परन्तु भवनों का मूल्य बाजारी मूल्य से अधिक होने के कारण भवनों का विक्रय नहीं हो पाता है । प्राधिकरण द्वारा जब भी इन भवनों को विक्रय करने हेतु अन्तिम मूल्य निकाला जाता है तो पूर्व स्वीकृत मूल्य में 18 प्रतिशत ब्याज जोड़ दिया जाता है । अन्तिम बार तत्काल आवंटन योजना दिनांक 1-6-2003 से 30-6-2003 तक चलाई गयी थी जिसमें भवनों का मूल्यांकन दिनांक 30-4-2002 तक ब्याज जोड़कर अन्तिम मूल्य निर्धारित किया गया था । किन्तु भवन उक्त मूल्य में नहीं बिक पा रहे हैं ।

अतः प्रस्ताव है कि जो भवन वर्तमान में रिक्त हैं या किसी भी कारण रिक्त हो रहे हैं, का मूल्यांकन दिनांक 30-4-2002 तक ब्याज जोड़कर निर्धारित किया जाना उचित होगा और यह मूल्यांकन दिनांक 30-6-2004 तक मान्य होगा एवं 30-6-2004 तक इसी मूल्यांकन पर भवनों का विक्रय किया जाये । प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

मद संख्या : 23

विषय: शास्त्रीनगर लाजपतनगर अपार्टमेन्ट मय गैराज व राजेन्द्रनगर के रिक्त भवनों को नीलामी द्वारा बेचे जाने के सम्बन्ध में ।

शास्त्रीनगर, लाजपतनगर व राजेन्द्रनगर में प्राधिकरण के रिक्त भवनों को तत्काल आवंटन योजना के माध्यम से समय समय पर विक्रय हेतु प्रयास किया गया एवं शास्त्रीनगर एवं लाजपतनगर अपार्टमेन्ट के भवनों में ब्याज फीज कर मूल्य में कमी की गयी जिसकी स्वीकृति समय समय पर बोर्ड से प्राप्त की जाती रही है ,परन्तु बहुत ही कम संख्या में अर्थात् केवल चार भवन ही बिक पाये हैं । राजेन्द्रनगर में एक भी भवन विक्रय नहीं हो पाया अभी तक उपरोक्त योजनाओं में क्रमशः 35,06,09 भवन रिक्त हैं जो तत्काल आवंटन योजना के माध्यम से नहीं बिक पा रहे हैं । अतः इनके विक्रय हेतु विस्तृत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।

शास्त्रीनगर योजना ई-ब्लॉक में टाईप ए,बी व सी के डुपलेक्स भवनों के विक्रय हेतु समय समय पर तत्काल योजना के अन्तर्गत बेचे जाने का प्रयास बार बार किया गया । दिनांक 1-8-2003 से 30-8-2003 व दिनांक 1-9-2003 से 30-9-2003 तक तत्काल आवंटन योजना खोली गयी जिसमें मात्र 3 भवन विक्रय हुए इसके पश्चात दिनांक 15-10-2003 से दिनांक 31-12-2003 तक पुनः योजना खोलकर भवन विक्रय करने का प्रयास किया गया किन्तु इस अवधि में एक भी भवन विक्रय नहीं हो पाया । इस योजना में ब्याज की गणना दिनांक 31-1-2002 तक फीज करते हुए तत्काल आवंटन योजना खोली गयी थी । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह मूल्य बाजार मूल्य से अधिक है । यदि यह भवन विक्रय नहीं होते हैं तो भवनों की हालत क्षतिग्रस्त होती रहेगी । प्राधिकरण के वित्तीय हित को देखते हुए तथा प्राधिकरण की आय बढ़ाने के लिए उचित होगा कि इन भवनों के मूल्यांकन में दो वर्ष का (अर्थात् दिनांक 31-1-2000 तक का ब्याज) फीज काते हुए दिनांक 31-1-2000 के मूल्य पर नीलामी के माध्यम से बेचे जायें ।

लाजपतनगर अपार्टमेन्ट योजना के अन्तर्गत मय गैराज 7 भवनों के लिए दिनांक 5-7-2002 से दिनांक 31-7-2002 एवं दिनांक 20-1-2003 से दिनांक 20-2-2003 तक योजना खोली गयी जिसमें कोई भवन विक्रय नहीं हो पाया जिसको पुनः ब्याज दिनांक 31-7-2000 तक फीज करते हुए दिनांक 31-12-2003 तक तत्काल आवंटन योजना खोली गयी जिसमें एक भवन विक्रय हुआ । अतः शेष बचे 6 भवनों के लिए ब्याज दो वर्ष का और फीज करते हुए दिनांक 31-7-98 के मूल्यांकन पर नीलामी के माध्यम से विक्रय कर दिया जाय ।

राजेन्द्रनगर के अन्तर्गत 9 एच0आई0जी0 भवनों के लिए तत्काल आवंटन दिनांक 15-7-2003 से 31-7-2003 तक एवं दिनांक 22-10-2003 से 15-11-2003 तक खोली गयी जिसमें ब्याज 15-11-2003 तक लिया गया था ,परन्तु प्रयास करने पर भी कोई भवन विक्रय नहीं हो पाया । अतः इस योजना में दिनांक 15-11-99 के पश्चात का ब्याज फीज

करते हुए दिनांक 15-11-99 के मूल्य पर भवनों को नीलामी के माध्यम से विक्रय कर दिया जाये ।

अतः शास्त्रीनगर , लाजपतनगर अपार्टमेन्ट मय गैराज व राजेन्द्रनगर के भवनों को प्राधिकरण हित में उपरोक्तानुसार ब्याज को फीज करते हुए आ रहे मूल्य पर भवनों को खुली नीलामी के माध्यम से विक्रय करने हेतु उपरोक्त प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

मद संख्या : 24(क)

विषय : किराये की सम्पत्तियों के निस्तारण की सीमा दिनांक 31-3-04 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 23-6-2003 में लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण की अमितव्ययी सम्पत्तियों को स्पेशल पैकेज के अधीन वर्ष -2000 के मूल्यांकन पर विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया था । निर्णय के परिपालन में प्राधिकरण के 296 किराये के भवन दिनांक 31-7-03 तक बिक गये हैं तथा उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार बोर्ड के निर्णय की प्रत्याशा में भवन दिनांक 30-9-03 तक पूर्व मूल्यांकन पर विक्रय किये गये हैं । इनके विक्रय से 6.08 करोड़ की आय प्राधिकरण को हुई है । दिनांक 30-9-03 तक विक्रय किये गये भवनों के विषय में बोर्ड द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जानी है ।

1- अभी तक कुछ किरायेदार भवन वित्तीय संसाधनों की कमी या बैंक इत्यादि के ऋण प्राप्त में विलम्ब होने के कारण क्रय नहीं कर सके हैं जिसके फलस्वरूप इन्हें दिनांक 31-3-2004 तक एक मुश्त पैकेज जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित है के आधार पर विक्रय करने की अनुमति प्राप्त की जानी है ।

2- एक मुश्त योजना के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत मूल्य / स्पेशल पैकेज की अवधि दिनांक 31-3-04 तक बढ़ाते हुए पूर्व अवधि 01-8-03 से 30-9-03 तक कार्योत्तर स्वीकृति जो उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दी गयी है की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें ।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रेषित है ।

संख्या : 32

:- किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों को विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या-2798-आ-9-95-8-86 आवास अनुभाग दिनांक 16.6.93 के द्वारा किये गए अमितव्ययी सम्पत्तियों को विक्रय के निर्देश दिये गये थे। शासनादेश के अनुपालन में दिनांक 11.96 में मद संख्या -20 पर किराये पर उठी 746 सम्पत्तियों के विक्रय हेतु प्रस्ताव गया था जिसमें अनुसार निर्णय हुआ :-

"अनुमोदित, 10 वर्ष की समान किश्तों में ब्याज सहित धनराशि ली जाए। इसके अतिरिक्त अन्य भवन जो किराये पर अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये हुए हैं लेकिन स्टाफ प्रसिग नहीं है, इसी शर्त पर उन्हें भी विक्रय कर दिया जाए।"

बोर्ड प्रस्ताव व निर्णय की प्रति संलग्न है।

इन 746 में से 271 भवन विक्रय किये जा चुके हैं। अवशेष भवनों हेतु शासन स्तर पर अभी विचाराधीन है। वस्तुतः किराये पर तद्दिनांक को 746 भवन न होकर 840 भवन आवंटित इस प्रकार पूर्व प्रस्ताव में सम्मिलित न किये गये 94 भवनों का विवरण निम्नवत है।

डासना रोड	04 भवन
पटेल नगर	01 भवन
विवेकानन्द नगर	01 भवन
लोहिया नगर	11 भवन
शास्त्रीनगर	26 भवन
राज नगर (आरडीसी)	02 भवन
संजयनगर	43 भवन
राजनगर सैक्टर-7	02 भवन
नेहरू अपार्टमेंट	02 भवन
लाजपत नगर	02 भवन

चूँकि यह भवन भी अमितव्ययी की श्रेणी में ही है किन्तु बोर्ड की एतदर्थ घोषणा के अभाव अमितव्ययी मानकर इन्हें विक्रय नहीं किया जा सका है। अतः प्रस्ताव है कि इन्हें अमितव्ययी घोषित हुए शासनादेश संख्या-4872-9-आ-1-99-72 बैठक/1998 दिनांक 4.11.99 के द्वारा विक्रय की अनुमति दी जाए।

एतदर्थ अनुमति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचाराधीन है।

संलग्नक : उपरोक्त।

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

महोदय के आदेश दिनांक 4.4.2001 के अनुसार किराये की सम्पत्ति का मूल्यांकन करते हुये बोर्ड बैठक में अमितव्ययी घोषित रखने हेतु प्रस्तावित है :-

डासना रोड	C-02, D-04, D-40, E-50
पटेल नगर	B-125
विवेकानन्दनगर	1172
लोहियानगर	B-08, B-20, B-27, B-32 C-13, C-14, C-16, C-29, C-30, C-31, C-32
शास्त्रीनगर	C-27, C-61B, C-62, C-62A, C-62B, C63A, C-64B, 579A, BSHF-11A, BSHF-2A, DSHF-07, DSHF-2, HSF-01, HSHF-3, HSF-2A, HSHF-3A, HSHF-4A, SHFJ-2A, SGF- 11, JSHF-01, JSHF-1A, JSHF-02, JSJF-03, JSHF-3A, JSHF-04, JSHF-4A,
संजयनगर	B-44, B-46, B-537, BSHF-01, BSHF-6, BSHF-5, BSHF-07, DSAF-2, DSHF-04, M-452, M-468, M-380, N-03, N-14, N-117, N-71, N-83, N-51, N-100, N-109, N-41, N-89, N-43, N-44, N-115 N-53, N-113, N-54, N-58, N-69, N-70, N-94, N-105, N-118, N-129, N-110, N-96, N-481A, N-435A, N-39, N-98, N-93, N-81
राजनगर इन्जी0	R7/B-01, R7/B-03,
राजनगर	RDC-4, RDC-36,
नेहरू अपार्टमेंट	B-24, B-46
लाजपत नगर	C-06, D-506

C. C. (U. M. 100)

आरक्षित करने सम्बन्धी प्रस्ताव ।

श्री शिरडी साई दिव्य ज्योति को आवंटित भूखण्ड जो निरस्त किया गया था, को बहाली विषयक ।

श्री गिरधारी लाल पाहवा पत्रकार द्वारा प्रदत्त प्रार्थना पत्र के कम में ब्याज माफी विषयक प्रकरण ।

भवन संख्या -9 / 22 एच0आई0जी0 (सिंघल स्टोरी) वैशाली पर देय ब्याज पर छूट के सम्बन्ध में ।

किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों को विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की अमितव्ययी सम्पत्ति के निर्धारित किये जा रहे मूल्य में (एकमुश्त) जगा किये जाने की दशा में 20 प्रतिशत छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी को आर0जी0 स्टोन यूरोलाजिकल रिसर्च सेंटर में ईलाज कराने पर भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, जन सम्पर्क अधिकारी को वेतन वृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण में एक इसूज ए0सी0 अग्वेरोडर

प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।

प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।

प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।

इस शर्त के साथ प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि इन भवनों का निस्तारण प्रत्येक दशा में 31-3-2003 तक हो जाए । साथ ही बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अमितव्ययी सम्पत्तियों के विक्रय किए जाने के सम्बन्ध में मूल्यांकन पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु आयुक्त, मेरठ मंडल के स्थान पर अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अधिकृत करने हेतु शासन को प्रकरण सन्दर्भित कर दिया जाए ।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई ।

प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।

प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

मद सं० ८४(ख) 24(ख)

विषय : - भवन संख्या एन० -80 संजयनगर ,सैक्टर -23 ,जी० एम० पी० को अमितव्ययी घोषित करने के संबन्ध में ।

भवन संख्या एन -80 सै० 23 संजयनगर श्री राजेन्द्र प्रसाद ,दौ० वे० लि० को किराये पर आवंटित है । इनके द्वारा भवन को मूल्यांकन कराकर कय करने हेतु सहमति दी है अतः प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 23-6-03 के अनुसार भवन सं० एन-80 संजयनगर का मूल्यांकन कराते हुए शासनादेश संख्या 4872-9-आ-1-99-72 बैठक 1998 दिनांक 4-11-99 के अनुसार अमितव्ययी घोषित करते हुए विक्रय करने की अनुमति दी जाय एवं पूर्व में बैठक दिनांक 30-11-02 में अमितव्ययी घोषित भवन संख्या एन-81 संजयनगर की सूची में हटाया जाना प्रस्तावित है ।

अतः प्रस्ताव बोर्ड बैठक के समक्ष विचारार्थ प्रेषित है ।

मद सं० : 24(ग)

विषय : संजयनगर योजना के अन्तर्गत एन ब्लॉक में स्टाफ के लिए निर्धारित मूल्य पर भवन सं० एन०-९० कय करने के सम्बन्ध में ।

भवन सं० एन-९० संजयनगर, गाजियाबाद जो वर्तमान में रिक्त है को श्री कमलेश दत्त पाण्डेय अवर अभियन्ता (अस्थाई) द्वारा कय करने का अनुरोध किया गया है । यह भवन अभी अमितव्ययी घोषित नहीं किया गया है । संजयनगर में पूर्व में ४३ भवनों को अमितव्ययी घोषित किया गया था । यह समस्त भवन स्टाफ क्वार्टर के रूप में आवंटित थे एवं इन भवनों की विक्रय की अनुमति शासनादेश सं० ४८७२/ ९-आ-१-९९-७२, दिनांक ४-११-९९ के अनुसार प्रदान की गयी है ।

श्री कमलेश दत्त पाण्डेय द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उक्त भवन को शासनादेश दिनांक ४-११-९९ के अनुसार अमितव्ययी घोषित करते हुए इनको आवंटन/ विक्रय कर दिया जाये एवं इसका मूल्यांकन बोर्ड बैठक दिनांक २३-६-०३ के अनुसार किया जाये ।

प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित है ।

मद संख्या: 25

विषय:- कुरसैला बिल्डर्स को वैशाली योजना में आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-21 पर देयता के सम्बन्ध में।

शासन के पत्र संख्या 4500/ 9-आ-1-01-139 जीडीए0/ 99 टी0सी0 दिनांक 17 अक्टूबर, 2001 के द्वारा मै0 कुरसैला बिल्डर्स के प्रकरण में यह निर्णय लिया गया था कि जिस प्रकार वर्ष 1989 मूल आवंटन तत्कालीन ग्रुप हाउसिंग सैक्टर दर पर किया गया था, उसी आधार पर भूमि का मूल्य आज का ग्रुप हाउसिंग सैक्टर दर पर ले लिया जाये तथा पक्ष द्वारा जो धनराशि पूर्व में जमा करायी गयी है, उस पर आज तक का ब्याज उसी दर पर क्रेडिट कर दिया जाये जिस पर प्राधिकरण अपने आवंटियों को उनकी जमा धनराशि पर ब्याज देता है।

उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में मै0 कुरसैला बिल्डर्स द्वारा जमा धनराशि पर 5 प्रतिशत ब्याज देते हुए इसे क्रेडिट करते हुए वर्तमान ग्रुप हाउसिंग सैक्टर दर पर इन्हें देयता की सूचना भेजी गयी और इनके द्वारा उपरोक्तानुसार समस्त देय धनराशि जमा करा दी गयी है। आवंटी द्वारा वर्ष 1989 के आवंटन के समय की सैक्टर दर पर लीज रेन्ट तथा फ्रीहोल्ड चार्ज भी जमा कराया गया है। इन्होंने इस आशय का प्रार्थना पत्र भी दिया है कि इनसे तत्कालीन दर पर ही लीज रेन्ट लिया जाये क्योंकि शासन द्वारा विशेष पैकेज के अन्तर्गत इन्हें इस प्रकार की सुविधा दी गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह मार्गदर्शन अपेक्षित है कि इनसे वर्ष 1989 के सैक्टर दर पर लीज रेन्ट एवं फ्रीहोल्ड चार्ज लिया जाये या जिस तारीख पर उपरोक्त प्रक्रिया के अनुरूप बाद में ग्रुप हाउसिंग सैक्टर दर पर धनराशि जमा करायी गयी है, उसी दर पर।

77

विषय: कुरसैला प्रेसीजन बिल्डर्स को वैशाली में आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-21 की देयता के सापेक्ष एकमुश्त समाधान के सम्बन्ध में।

फर्म को वर्तमान एकमुश्त प्रकरण पर प्राधिकरण में लागू एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु सुझाव दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत फर्म को लगभग 5.00 लाख रुपये की राहत मिल रही है। अतः फर्म द्वारा पत्र में वर्णित विशेष परिस्थितियों में और अधिक छूट के लिये निवेदन किया है।

प्रकरण की पृष्ठभूमि निम्न प्रकार है:-

वैशाली में 1989 में भूखण्ड सं0-21 आवंटित कर दिनांक 17-4-89 को भुगतान विवरण जारी किया गया जिसमें भूखण्ड की कीमत 1.20 करोड़ रुपये तथा 10 प्रतिशत लीज रेन्ट निर्धारित था। ₹0 60.00 लाख बिना ब्याज के 3 माह में जमा कराने के उपरान्त अवशेष 50 प्रतिशत राशि अर्थात् 60.00 लाख रुपये 6 छःमाही किश्तों में ब्याज सहित जमा करनी थी। निर्दिष्ट समय के अन्दर फर्म द्वारा 50 प्रतिशत राशि अर्थात् 60.00 लाख रुपये जमा करा कर दिनांक 5-10-89 को भूखण्ड का कब्जा प्राप्त कर लिया गया। जारी भुगतान विवरण के अनुसार भूखण्ड की पूर्ण राशि दिनांक 15-4-1992 तक प्राप्त हो जानी चाहिये थी परन्तु इसी बीच भूखण्ड आवंअन के सम्बन्ध में शासन द्वारा जनवरी-1990 (दिनांक 11-1-90 से 23-1-91 तक) में रोक लगा दी गयी थी जो कि 1 वर्ष 15 तक लगी रही। इस रोक के कारण समस्त बिल्डर्स के भुगतान विवरण को प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 11:5:94 में रखकर संशोधित पैमेन्ट शेड्यूल जारी किया गया। इस फर्म को भी दिनांक 20.6.94 को संशोधित पैमेन्ट शेड्यूल जारी किया गया जिसमें अन्तिम किश्त 30-4-95 को देय थी। दिनांक 30-6-94 तक देयता ₹0 43,47,135.00 बनती थी जिसमें से फर्म द्वारा दिनांक 16-8-96 को ₹0 1,00,000.00 दिनांक 14-7-97 को ₹0 10,00,000.00 दिनांक 30-12-97 को ₹0 7,30,000.00 कुल ₹0 37,30,000.00 जमा किया। दिनांक 31-12-97 तक ₹0 46.32 लाख देय थी।

इस प्रकार 20-6-94 को जारी संशोधित पैमेन्ट शेड्यूल के अनुसार फर्म डिफाल्टर हुई और देयता बनी रही। भवन निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति अवधि दिनांक 30-3-96 तक थी और यह अवधि बीत जाने के पश्चात फर्म द्वारा मानचित्र के नवीनीकरण हेतु निवेदन किया गया। प्राधिकरण द्वारा देयता वसूली के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए यह मत था कि प्रथमतः प्राधिकरण की देयता जमा कराने के उपरान्त ही नवीनीकरण किया जायेगा जबकि फर्म द्वारा यह अनुरोध किया गया कि भवन मानचित्र के नवीनीकरण होने के पश्चात आवंटित भूमि पर भवनों को पूर्ण कर फ्लैटों के निस्तारण के उपरान्त प्राधिकरण की देयता का भुगतान कर दिया

जायेगा। इसी विवाद के कारण न ही मानचित्र का नवीनीकरण हो पाया और साथ ही फर्म पर ब्याज का अतिरिक्त भार बढ़ता ही गया। अन्त में फर्म के निरन्तर अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा 3 बार मानचित्र की स्वीकृति अवधि बढ़ाने हेतु अनापत्ति दी गयी लेकिन केवल 33 माह हेतु जो कि इतनी कम थी कि 10 मंजिले भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता था। पूर्व में प्राधिकरण द्वारा नवीनीकरण हेतु यदि एक वर्ष की स्वीकृति दी जाती तो यह सम्भव था कि फर्म निर्माण कार्य को फिर से प्रगति पर लाकर फ्लैटों को बेचकर प्राधिकरण की देयता का भुगतान कर देती। यह नवीनीकरण करने से पूर्व देयता के सम्बन्ध में शपथ पत्र लेकर कार्यवाही की जा सकती थी एवं आपसी समझौते पर फर्म यदि पैसा जमा नहीं कराती तो प्राधिकरण आवंटन निरस्त कर सकता था। यह सब न होने के कारण पिछले 3 साल से न तो बहुमंजिला भवन पूर्ण हो पाया और न ही आवंटि द्वारा देयता प्राधिकरण में जमा करायी गयी। वर्तमान तक फर्म पर ₹0 67,17,191.00 बकाया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए देयता प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा क्षेत्र के विकास के हित को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा अपने पत्र सं० 4590/ 9-आ-1-01-139जीडीए/ 99 दिनांक 17-7-01 द्वारा यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में जिस प्रकार वर्ष 1989 में मूल आवंटन तत्कालीन ग्रुप हाउसिंग सैक्टर दर पर ले लिया जाये तथा पक्ष द्वारा जो धन पूर्व में जमा किया गया है, उसे आज तक का ब्याज उसी दर पर क्रेडिट कर दिया जाये जिस पर प्राधिकरण अपने आवंटियों को उनकी जमा धनराशि पर ब्याज देता है।

इसी क्रम में प्राधिकरण द्वारा पक्ष से बकाया राशि एवं नयी कीमत का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क की मांग की गयी जिसके विरोध में पक्ष द्वारा पत्र दिया गया कि उनके भूखण्ड का आवंटन ₹0 1,20,000.00 है, अतः इसी दर पर 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क लिया जाये।

मद संख्या

26

विषय: श्री शिरडी साई दिव्य ज्योति को आवंटित भूखण्ड संख्या जो निरस्त किया गया था, की बहाली विषयक।

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 22-2-1986 के अनुपालन में श्री शिरडी साई दिव्य ज्योति को वर्ष 1987 में पटेलनगर बी ब्लॉक में 499.76 वर्ग मीटर भूखण्ड का आवासीय सैक्टर दर रु० 262.50 प्रति वर्ग मीटर की दर पर आवंटित किया गया था जिसके अनुसार भूखण्ड का कुल मूल्य रु० 1,31,187.00 था। संस्था को आवंटित भूखण्ड ग्रीनबैल्ट में स्थित है। संस्था के द्वारा भूखण्ड की देय राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण भूखण्ड का आवंटन दिनांक 21-5-2002 को निरस्त कर दिया गया है।

संस्था द्वारा आवंटित भूमि पर साई मन्दिर का निर्माण अस्थायी रूप से कर लिया गया है। संस्था पर वर्तमान में रु० 5.50 लाख देय है जिसके विरुद्ध संस्था द्वारा 1.00 लाख का ड्राफ्ट प्रस्तुत करते हुए भूखण्ड की बहाली की मांग की है। संस्था के द्वारा निर्मित अस्थायी रूप से साई मन्दिर को प्राधिकरण के द्वारा हटाने/खाली कराने से धार्मिक विवाद एवं विरोध होने की सम्भावना है।

अतः भूखण्ड का आवंटन बहाल करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत है।

मद सख्या : 27

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रोग्रामर के पद पर कार्यरत श्री अतुल शर्मा का विनियमितीकरण किये जाने विषयक ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा श्री अतुल शर्मा की नियुक्ति प्रोग्रामर के पद पर अनुबन्ध आधार पर हुई थी तथा अन्य पदों के साथ प्रोग्रामर का पद स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 18-6-88 में रखा गया तथा बोर्ड द्वारा पद स्वीकृति उपरान्त शासन को स्वीकृति हेतु पत्र भेजा गया । परन्तु शासन से पद की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई तथा प्राधिकरण के तत्कालीन अधिकारीगण द्वारा श्री अतुल शर्मा की नियुक्ति शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 28-4-90 को पूर्णतया तदर्थ एवं अस्थाई रूप से की गयी । समय समय पर प्रोग्रामर के पद की स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु शासन को पत्र भेजे जाते रहे हैं । शासन द्वारा अपने पत्र सं० 371/9आ-6-2003-204डी०ए०/88, दिनांक 28 मई 2003 द्वारा प्रोग्रामर के पद की स्वीकृति दिनांक 29-2-2004 तक के लिये प्रदान की गयी है । जिसके क्रम में श्री अतुल शर्मा का प्रोग्रामर के पद पर विनियमितीकरण किये जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की नियुक्ति/पदोन्नति समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया था । समिति द्वारा विचारोपरान्त श्री शर्मा का विनियमितीकरण किये जाने की संस्तुति की गयी है । इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रोग्रामर का पद वेतनमान रु० 2200-4000/- का है तथा नये वेतनमान में पुनरीक्षित वेतनमान रु० 8000-13500/- का है जो सहायक अभियन्ता के वेतनमान के समकक्ष है तथा सहायक अभियन्ता का पद प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा का पद है, जिसके कारण इस सम्बन्ध में शासन को पत्र भेजा गया था । शासन द्वारा अपने पत्र सं० 2461/9-आ-03-204डी०ए०/88, दिनांक 11 अगस्त 03 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उ०प्र० विकास प्राधिकरण सेवा नियमावली में प्रोग्रामर का पद सम्मिलित नहीं है । इसलिए प्रोग्रामर का पद अकेन्द्रीयत सेवा के अन्तर्गत ही माना जायेगा ।

अतः श्री अतुल शर्मा को प्रोग्रामर के पद पर अकेन्द्रीयत सेवा के अन्तर्गत (शासन के पत्र संख्या 2461/9-आ-6-03-204 डी.ए./88 लखनऊ दिनांक 11 अगस्त 2003) एवं विनियमितीकरण हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 07.07.03 के परिपेक्ष्य में, विनियमितीकरण किये जाने हेतु विचारार्थ/निर्णयार्थ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद । (टिप्पणिया एवं आदेश)

सचिव/उपाध्यक्ष

श्री अतुल शर्मा प्रोग्रामर का विनियमितीकरण शासनादेश संख्या 371/9आ-6-2003-204डी0ए0/88, दिनांक 28 मई, 2003 के क्रम में किये जाने के सम्बन्ध में चयन समिति की बैठक दिनांक 24.06.03 की अपरान्ह में हुई । प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 18.06.88 में कम्प्यूटर अनुभाग हेतु निम्नलिखित पदों का सृजन किया गया था ।

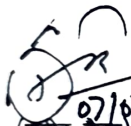
क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	डायरेक्टर सिस्टम	2050-2500	01
2.	प्रोग्रामर	770-1600	01
3.	सहायक प्रोग्रामर	690-1420	01
4.	जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर	690-1420	01

उपरोक्त पद सृजन को शासन से अनुमोदित हेतु प्राधिकरण के पत्र संख्या 334/74/कम्प्यूटर सैल/88 दिनांक 23.08.88 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया । पुनः प्राधिकरण के पत्र क्रमशः 1588/74/कम्प्यूटर सैल/89 दिनांक 19.07.89, 2050/कम्प्यूटर सैल/90 दिनांक 24.01.90 द्वारा शासन को अनुस्मारक भेजे गये किन्तु अनुमोदन अप्राप्त रहा । इसी मध्य शासन से अनुमोदन की प्रत्याशा में श्री अतुल शर्मा को प्रोग्रामर के पद पर वेतनमान रु० 2200-4000 में तदर्थ रूप से 28.04.90 को तैनात कर दिया गया । श्री अतुल शर्मा द्वारा शासन को 21.09.98 को अपनी पदोन्नति हेतु प्रत्यावेदन प्रेषित किया गया । इस प्रत्यावेदन के क्रम में शासनादेश संख्या 7/9-अ-6-2000-240 डी0ए0/88 दिनांक 20.10.2000 द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि प्रोग्रामर का पद केन्द्रीयत सेवा का है अथवा अकेन्द्रयीता सेवा का है, एवं प्रोग्रामर के पद पर कार्यरत श्री शर्मा किस वेतनमान में कार्य कर रहे है तथा प्रोग्रामर से कम्प्यूटर शाखा के पोषक संवर्ग में कोई उच्च पद उपलब्ध है अथवा नहीं, जिससे श्री शर्मा की पदोन्नति पर विचार किया जा सके । इस पत्र के उत्तर में शासन को अवगत कराया गया कि प्रोग्रामर का पद प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा नियमावली में नहीं है तथा पोषक संवर्ग में कोई बैद्य ढंग से सृजित पद प्राधिकरण में उपलब्ध नहीं है एवं प्रोग्रामर का वेतनमान रु० 2200-4000/- का है । पुनः शासन के अ०शा० पत्र संख्या 37/9-आ-6-2001-204डी0ए0/88 दिनांक 27.01.01 द्वारा वेतनमान रु० 2200-4000/- में एक रिक्त पद समर्पित कर प्रोग्रामर का पद स्वीकृत करने का विकल्प दिया गया है । परन्तु उक्त वेतनमान में सृजित कोई पद समर्पित करने का विकल्प नहीं दिया गया तथा बोर्ड बैठक दिनांक 18.06.88 में स्वीकृत पद पर शासन की स्वीकृति मांगी गयी । पुनः पत्र संख्या 1070/स०सचिव/2002, दिनांक 23.03.02 द्वारा प्रोग्रामर के पद की स्वीकृति प्राप्ति करते हुए पदोन्नति किये जाने का अनुरोध किया गया था । इस पत्र के क्रम में शासन द्वारा कम्प्यूटर में पुनः पदों की स्वीकृति के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी

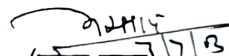
Officer Intiitiin
Tender

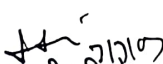
इस पत्र के क्रम में पुनः शासन को अन्तिम पत्र संख्या 295/प्रशा0अनु0/2002, दिनांक 31.01.03 भेजा गया, जिसमें वर्तमान में कार्यरत कम्प्यूटर के कर्मचारियों के विरुद्ध पद की स्वीकृति मांगी गयी थी, परन्तु अन्य पदों को छोड़कर शासनादेश संख्या 371/9आ-6-2003-204डी0ए0/88, दिनांक 28 मई, 2003 द्वारा केवल प्रोग्रामर के पद वेतनमान 8000-13500 की स्वीकृति 29 फरवरी, 2004 तक की अवधि के लिए इस शर्त पद दी गयी है कि इसके पूर्व बिना सूचना के यह पद समाप्त न कर दिया जाये।

श्री अतुल शर्मा की नियुक्ति प्रोग्रामर के पद पर, कार्यालय आदेश संख्या 552/प्रशा0अनु0/90, दिनांक 28.04.90 द्वारा वेतनमान 2200-4000/- में शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में तदर्थ रूप से की गयी थी तथा अब शासनादेश दिनांक 28.05.2003 द्वारा प्रोग्रामर के पद के सृजन की शासन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, तथा दिनांक 29.06.91 से पूर्व के कार्यरत कर्मचारियों का विनियमितीकरण शासनादेश अनुसार किया जा सकता है श्री अतुल शर्मा दिनांक 28.04.90 से शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में तदर्थ रूप से नियुक्त है, जो शासनादेश अनुसार 29.06.91 से पूर्व की तिथि है। अतः श्री शर्मा का विनियमितीकरण नियमावली के तहत नव सृजित पद पर विनियमितीकरण किये जाने की समिति संस्तुति करती है।


07/07/03
(श्री. ह. ह. ह.)
सहायक अभि०


21/7
(दीपक श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक


22/7
(महेन्द्र प्रसाद)
वित्त नियंत्रक


21/7
(डा० अरुणबीर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी


27/7/2003
(जे० सी० आदेश)
विशेष कार्याधिकारी

LAI
12-pt exam discus
2nd
7/7/03
सचिव
मा० प्रि० मा०

PA

Discussed with LAI.
I discussed with Spl. Dy. L. Sanjay kv 143 in LKO.
Whether the post is Centralised or not clarification
be sought
2nd
8/7/03.

829
21/8/03

28
21/8/03
7/2

प्रेषण,

सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद।

सेवा में,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अगुभाग-6

बापू भवन, लखनऊ।

पत्र संख्या

84

गुशा0अनु0/2003

दिनांक: 2-8-03

विषय:

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रोग्रामर के पद का गृजन

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र सं० 371/9आ-6-2003-204 डी0ए0/88, दिनांक 28 मई, 2003 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में अवगत करना है कि प्रोग्रामर का पद वेतनमान रु० 8000-275-13500/- में स्वीकृत किया गया है, जो विकास प्राधिकरण केन्द्रीय सेवा के सहायक अभियन्ता के वेतनमान के समकक्ष है। जबकि प्रोग्रामर से निम्न स्तर का पद, सहायक प्रोग्रामर एवं एकाउन्टेन्ट का डाटा सुपरवाइजर का पद शासनादेश सं० 1701/11-4-डी0ए0/89-204 डी0ए0/88, दिनांक 22 जनवरी, 1990 [प्रति संलग्न] द्वारा वेतनमान रु० 1400-40-1600-50-2300-दरारो-60-2600/- में स्वीकृत किया गया है। जिसमें विन्दुसं०-2 में यह उल्लेख किया गया है कि "उपर्युक्त समस्त पदों के पदधारकों को विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों को अनुमत्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। इन पदों पर नियुक्ति उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीय सेवा नियमावली के अंतर्गत निर्धारित शर्तों तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सन्दर्भित पत्र के संलग्नक में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर की जायेगी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रोग्रामर का पद प्राधिकरण की केन्द्रीय सेवा नियमावली में अंकित नहीं है। कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि प्रोग्रामर का पद प्राधिकरण केन्द्रीय सेवा का पद है अथवा अकेन्द्रीय सेवा का पद है।

भवदीय,

[Handwritten Signature]

१ यूपएन0ठापुर

प्रेषक,

शाहजादे लाल,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 11 अगस्त, 2003

विषय:- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रोग्रामर के
पद का सृजन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 84/प्रशा.अनु.0/2003
दिनांक 02 अगस्त, 2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है
कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1995
में प्रोग्रामर का पद सम्मिलित नहीं है, अतः प्रोग्रामर का पद अकेन्द्रीयित
सेवा के अन्तर्गत ही माना जायेगा ।

2— कृपया उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति से अवगत होने का
कलट करें ।

भावदीप

24/8/03

शाहजादे लाल

उपसचिव ।

039/11/03

Put up with fl

3/8/03

HC 1321210

h

03-03

विषय : श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल भूखण्ड स्थित नीती खण्ड-इन्दिरा पुरम पर भुगतान विवरण में भुगतान में विलम्ब एवं तदनुसार ब्याज को माफ करने के सम्बन्ध में

श्रीकृष्ण पब्लिक स्कूल (प्रबन्धक श्री इच्छा राम यादव) को इन्दिरापुरम के नीति खण्ड तृतीय में स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल लगभग 4704.91 वर्ग मी० रुपये 2500.00 की दर से आवंटन किया गया है। इस भूखण्ड का मूल्य 51,75,401.00 मात्र है। आवंटी आवंटन पत्र को दिनांक 2.2.2001 को जारी किया गया था। आवंटी द्वारा वर्तमान तक रू० 9,65,000.00 जमा कराये गये हैं। आवंटी पर दिनांक 31.12.2003 बकाया राशि निम्न प्रकार है:

1.	मूल्य	रू० 28,46,972.00
2.	किश्तों में शामिल ब्याज (शासनादेश के अनुसार लिया जाता है)	रू० 14,67,227.00
3.	देरी का ब्याज	रू० 11,48,934.00

कुल देयता

रू० 54,63,133.00

आवंटी द्वारा देय धनराशि जमा न करने के कारण तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया गया था। निरस्तीकरण की सूचना आवंटी को प्राधिकरण के पत्र दिनांक 23.6.2003 द्वारा दी गयी थी। आवंटी द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र दिया गया कि वह अब तक समस्त देय धनराशि जमा करने को तैयार हैं और इनका भूखण्ड बहाल कर दिया जाए। इनकी प्रार्थना पर इनका भूखण्ड आवंटन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा बहाल कर दिया गया। आवंटन बहाल की सूचना प्राधिकरण के पत्र दिनांक 12.11.2003 को दी जा चुकी है। पत्र में आवंटी पर देय राशि रू० 52,22,961.00 दिनांक 30.11.2003 तक जमा कराने हेतु स्पष्ट किया गया था।

आवंटी द्वारा दिनांक 30.11.2003 पत्र की मांग के अनुरूप कोई धनराशि जमा नहीं की गयी है। स्कूल भूखण्ड पर देय ब्याज माफी के लिए माननीय सांसद श्री उदय प्रताप सिंह का पत्र प्राप्त हुआ है, जो पत्रावली पर संलग्न है, अवलोकनीय है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ब्याज की देयता नियमानुसार है। ब्याज माफी के संबंध में निर्णय हेतु प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ व आदेशार्थ प्रस्तुत है।



सत्यमेव जयते

उदय प्रताप सिंह
संसद सदस्य (राज्य सभा)

302, राजेन्द्र मार्ग, शिकोहाबाद (उ० प्र०)
फोन : 05676-236100

19, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001
दिल्ली : 2378 2757

दिनांक:- 03-01-2004

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद, उ०प्र० ।

इस पत्र के साथ एक पत्र श्री इन्छाराम यादव, प्रबन्धक श्री कृष्ण सीनियर सैकेण्डरी पब्लिक स्कूल गाजियाबाद का संलग्न है । जनहित में विद्यालय की स्थिति को देखते हुए ब्याज माफ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ।

भवदीय

उदय प्रताप सिंह

(उदय प्रताप सिंह)

र.स. श्री तालिमान

[Signature]

03/01/04

V

मद संख्या 29

विषय: रिट याचिका संख्या 54927 / 2002 खेमका स्टुअर्ट लीजर लि० बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 29-6-96 द्वारा मै० खेमका स्टुअर्ट लीजर लि० नयी दिल्ली को भूखण्ड सं० डब्लू-1 जो ग्रीन बैल्ट की जमीन है (क्षेत्रफल 40168 वर्ग मीटर) को रू० 1.00 प्रति वर्ग मीटर लीज पर एवं भूखण्ड संख्या डब्लू-2 (क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर) को आवासीय सैक्टर दर पर दिये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया था। तत्कम में इन भूखण्डों की लीजडीड प्राधिकरण द्वारा फर्म के पक्ष में कर दी गयी किन्तु फर्म द्वारा इन भूखण्डों पर लीज शर्तों के विरुद्ध व्यवसायिक गतिविधियों के दृष्टिगत दिनांक 2-12-02 को प्राधिकरण ने पट्टा निरस्त कर दिया। प्राधिकरण के निरस्तीकरण के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर फर्म द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं० 54927 / 2002 दायर की गयी। उक्त रिट याचिका पर दिनांक 28-3-03 को मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश पारित किये गये जिसके मुख्य अंश निम्नवत हैं:

It is true that in case the land is used for commercial purposed, the commercial rate will be applicable. The petitioner itself has admitted that it is prepared to pay commercial rate for plot No. W-2, Sector-1 Vaishali Scheme, Ghaziabad.

In view of the above the writ petition is allowed and the impugned order dated 2-12-2002 is hereby quashed. The payment of the lease amount shall be taken according and if the petitioner has submitted any map it shall be duly considered keeping in view the above observations.

मा० उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में मै० खेमका स्टुअर्ट लीजर लि० गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को देय शुल्कों के रूप में रू० 63,84,000 / - की धनराशि जमा करायी गयी।

मा० उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28-3-03 के अनुपालन में निर्धारित प्रक्रिया / नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये तथा जहां तक भूखण्ड संख्या डब्लू-1 का सम्बन्ध है, ग्रीन बैल्ट होने के कारण यह सम्बन्धित फर्म को केवल लीज पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों व उपबन्धों के अधीन आवंटित रहेगी और फर्म द्वारा आवंटन की शर्त को पूरा न करने पर आवंटन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

मा० उच्च न्यायालय पारित आदेश तथा शासनादेश सं० 3353/9-आ-1/1जीडीए/2003 दिनांक 11 जून 2003 के अनुपालन में प्रश्नगत भूखण्ड की लीज डीड बहाल कर दी गयी है जो बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

भूखण्ड सं० डब्लू-2 क्षेत्रफल 4000 वर्ग मी० पर अनुमन्य उपयोग की जो अनुमति दी गयी थी, वह व्यवसायिक प्रवृत्ति की है तथा वर्ष 1996 में ही तत्कालिक व्यवसायिक दर के हिसाब से धनराशि जमा करा लेनी चाहिये थी जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरणद्वारा कोई मांग नहीं भेजी गई। मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में याची द्वारा तत्कालीन सेक्टर दर के हिसाब से 63,84,000/- व्यवसायिक दर, लीज रेन्ट एवं फीहोल्ड जोड़ते हुये जमा कराया गया है। इस सम्बन्ध में तत्कालीन उपाध्यक्ष जी०डी०ए० द्वारा गठित समिति ने दिनांक 02-08-2003 को प्रेषित रिपोर्ट में निर्णय दिया है कि आवंटन के समय फरवरी 96 की व्यवसायिक एवं आवासीय दर के अन्तर की धनराशि पर बैंक ब्याज दर से आवंटी से धनराशि जमा कराई जाये। श्री अजय कुमार मिश्रा प्राधिकरण अधिवक्ता की राय भी वर्ष 96 में प्रभावी व्यवसायिक दर प्राप्त करने की प्राप्ति हुई है।

प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा समिति की रिपोर्ट को तत्कालीन अध्यक्ष जी०डी०ए० श्री अतुल गुप्ता के संज्ञान में लाया गया एवं मा० उपाध्यक्ष द्वारा पत्रावली पर अंकित किया गया कि बोर्ड के समक्ष स्पष्ट किया जाये कि कोस्टिंग का सामान्य सिद्धांत है कि आवंटन के समय का ही मूल्य लिया जाता है। अतः इस दृष्टि से प्रकरण में कोई संशय नहीं रह जाता है।

बोर्ड के अवलोकनार्थ प्रस्तुत ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

(टिप्पणिया एवं आदेश)

सचिव/उपाध्यक्ष ।

कृपया पूर्व आख्या पृष्ठ-90 पर उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 2-7-2003 के अनुसार गठित समिति द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया, जिसके अनुसार गठित समिति को भूखण्ड सं० डब्लू-2 क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर का मूल्य लिये जाने के विषय में समिति द्वारा विचार किया जाना है। आख्या निम्नवत है :-

मै० खेमका स्टूअर्ट लीजर लि० को प्राधिकरण के पत्र संख्या 480/काम सैक्स/96 दिनांक 21-3-96 द्वारा 4000 वर्ग मीटर भूमि आवासीय सैक्टर दर 1400/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मेन्टीनेन्स फैसिलिटी होटल के डीलक्स रूम एवं प्रशासनिक बिल्डिंग आदि के निर्माण हेतु आवंटित की गयी थी। इसी पत्र में भूखण्ड के अनुमानित मूल्य रु. 56,00,000/- को पत्र में अंकित विवरण के अनुसार जमा करने हेतु भी कम्पनी को सूचित किया गया था तथा पत्र में यह भी उल्लेख था, कि कब्जा बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात दिया जायेगा। यह प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड कि सम्मेलन दिनांक 29-2-96 को रखा गया, जो पत्रावली के सम्मुख पृष्ठ सं-11 पर उपलब्ध है तथा बोर्ड का निर्णय पताका क पर उपलब्ध है। सम्मुख पृष्ठ क्रमांक-115 के अनुसार धनराशि देयता का विवरण प्रेषित किया गया तथा क्रमांक सं-123 पर उपलब्ध कब्जा भीमो के अनुसार दिनांक 25-7-96 को भूखण्ड का कब्जा प्राप्त किया गया।

यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि पोलो एम्यूजमेन्ट पार्क लि० द्वारा एक याचिका उच्च न्यायालय में याचिका सं० 13479/96 मै० पोलो एम्यूजमेन्ट पार्क लि० बनाम उ०प्र० सरकार एवं अन्य इस आशय से प्रस्तुत की गयी कि मै० खेमका स्टूअर्ट लीजर लि० के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 21-3-96 बिना किसी टैंडर व प्रकाशन के आवंटित किया गया, जिसका प्राधिकरण द्वारा प्रतिवाद किया गया और न्यायालय के सम्मेलन पब्लिसिटी के तथ्यों को रखते हुए प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय दिनांक 29-2-96 के आधार पर 4000 वर्ग मीटर भूमि 1400 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मेन्टीनेन्स फैसिलिटी, डीलक्स रूम व प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु आवंटित किये जाने से अवगत कराया, जिसके आधार पर उक्त याचिका दिनांक 26-6-97 को खण्डित हुई। न्यायालय का निर्णय सम्मुख पृष्ठ सं०-250-251 पर उपलब्ध है।

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 25-3-96 में मद सं०-1 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29-2-96 के कार्यवृत्त की पुष्टि विषय के अन्तर्गत मद सं०-28 के निर्णय में आवासीय शब्द हटाया गया तथा समिति के प्रत्यावेदन पर विचार कर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड की कीमत 20 प्रतिशत जमा कराकर कब्जा दे दिया जाये, शेष देय राशि की किश्तें बिना ब्याज पर नहीं की जा सकती, बल्कि 18 प्रतिशत ब्याज पर की जा सकती है, इस संशोधन के साथ कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। इस प्रकार मद सं०-28 पर प्राधिकरण बैठक दिनांक 29-2-96 का निर्णय निम्नवत है।

अनुमोदित। ग्रीन बैल्ट पर एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की लीज पर दे दी जाये। आवासीय भूखण्ड का क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर आवासीय सैक्टर दर पर दिया जाये। टिकट दर में प्राधिकरण स्टाफ एवं उसके परिवार के सदस्यों को 50 प्रतिशत की छूट रखी जाये।

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय दिनांक 25-3-96 के अनुसार आवासीय शब्द हट जाने के बाद भूखण्ड का क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर सैक्टर दर पर दिया जाये, बोर्ड का निर्णय प्रभावी है। कम्पनी को अनुमन्य किये गये उपयोगों की प्रकृति भी आवासीय से भिन्न होते हुए व्यवसायिक प्रकृति की है। अतः यह तथ्य निर्विवाद है कि कम्पनी को व्यवसायिक उपयोग वर्ष 98 में ही अनुमन्य किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 54927 सन 2002 खेमका स्टूअर्ट लीजर लि० बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में पारित आदेश दिनांक 28-3-2003 के अनुसार न्यायालय ने भी यह निर्देश दिये हैं कि याची को दिये गये उपयोग व्यवसायिक है। अतः व्यवसायिक मूल्य ही लागू होना चाहिए। शासनादेश संख्या 3353/9-आ-1/1जीडीए/2003 दिनांक 11-6-2003 के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28-3-2003 के अनुपालन में निर्धारित प्रक्रिया/नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

(टिप्पणिया एवं आदेश)

सचिव ।

सम्मुख पृष्ठ पर उपलब्ध खेमका स्टूअर्ट लीजर लि० के पत्र का अवलोकन करे, जिसके अनुसार कम्पनी द्वारा भूखण्ड सं० डब्लू-1 क्षेत्रफल 40167 वर्ग मीटर के विषय में प्राधिकरण द्वारा परित आदेश दिनांक 2-12-2002 के परिणामस्वरूप पट्टा निरस्तीकरण एवं मानचित्र निरस्तीकरण के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका सं० 54927/02 खेमका स्टूअर्ट लीजर लि० बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28-2-2003 के अनुसार प्राधिकरण के आदेश दिनांक 2-12-02 को निरस्त कर देने के आधार पर भूखण्ड सं० डब्लू-1 का मानचित्र बहाल किये जाने की प्रार्थना की है।

भूखण्ड सं० डब्लू-1 क्षेत्रफल 40167 वर्ग मीटर 90 वर्ष के पट्टे पर 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की वार्षिक दर से वाटर पार्क, एम्प्लूजमेंट कम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, रिक्रीशनल एवं स्पोर्ट क्लब के निर्माण हेतु दिया गया था। पत्र संख्या 145/वी.सी. कैम्प/02 दिनांक 2-12-2002 के द्वारा पट्टा विलेख निरस्त किया गया था तथा आदेश सं० 144/वी.सी.कैम्प/2002 दिनांक 2-12-2002 द्वारा मानचित्र संख्या 44/टी.एच.ए./जोन-3/कामी/99 दिनांक 25-10-2000 निरस्त किये गये थे। उक्त दोनों ही आदेशों माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं० 54927/02 खेमका स्टूअर्ट लीजर लि० में पारित आदेश 28-3-03 के अनुसार याचिका स्वीकार करते हुए विवादित आदेश दिनांक 2-12-2003 निरस्त किया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर आवंटी कम्पनी के पत्र दिनांक 16-5-2003 को संलग्न करते हुए कम्पनी द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के कम में जमा धनराशि रु. 56,00,000/- व उक्त राशि पर लीज किराया रु. 5,60,00/- व फीहोल्ड शुल्क रु. 2,24,000/- जमा करने के तथ्यों के साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर मार्गदर्शन करने हेतु निवेदन किया गया था। शासनादेश संख्या 3353/9-आ-1/जीडीए/03 दिनांक 12-6-2003 द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28-3-03 के अनुपालन में निर्धारित प्रक्रिया/नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। भूखण्ड सं० डब्लू-1 के विषय में शासन का स्पष्ट निर्देश है कि डब्लू-1 ग्रीन बैल्ट होने के कारण सम्बन्धित फर्म को केवल लीज पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों व उपबन्धों के अधीन आवंटित रहेगी और फर्म द्वारा आवंटन की शर्तों को पूरा न करने पर आवंटन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

भूखण्ड सं०-1 व डब्लू-2 का अलग-अलग विलेख निष्पादित है। अतः दोनों अलग सम्पत्तियां हैं तथा दोनों का अलग ही उपयोग है। भूखण्ड सं० डब्लू-1 ग्रीन बैल्ट में आवंटित है और ग्रीन बैल्ट में अनुमन्य उपयोग हेतु ही प्रयोग हो सकता है और पूर्व में उन्ही उपयोग हेतु मानचित्र स्वीकृत किया गया था, परन्तु डब्लू-2 पर आवासीय मूल्य अदा करने व व्यवसायिक प्रयोग होने के आधार पर पट्टा विलेख एवं मानचित्र निरस्त हुए थे। शासन द्वारा भी अपने निर्देश दिनांक 11-6-03 में ग्रीन बैल्ट के लिए अनुमन्य निर्धारित शर्तों व उपबन्धों के अधीन आवंटित रहने एवं उल्लंघन होने पर आवंटन निरस्त करने के निर्देश दिये हैं। यद्यपि भूखण्ड सं० डब्लू-1 का पट्टा विलेख पत्र दिनांक 23-6-03 द्वारा बहाल किया जा चुका है। अतः यदि आवंटी कम्पनी भूखण्ड सं० डब्लू-1 क्षेत्रफल 40,167 वर्ग मीटर के लिए निर्धारित शर्तों व उपबन्धों का पालन करने का इन्डेमनिटी बॉन्ड प्रस्तुत करे तो भूखण्ड सं० डब्लू-1 के विषय में मानचित्र बहाल किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 2-12-02 पूर्व में ही निरस्त किया जा चुका है और उसके विरुद्ध कोई एपेअल्स पीठ दाखिल नहीं हुई है, क्योंकि शासन ने निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमानुसार उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28-3-03 के अनुपालन के निर्देश दिये हैं। अतः उपरोक्तानुसार भूखण्ड सं० डब्लू-1 के मानचित्र बहाली पर विचार करना चाहें।

उपाध्यक्ष
मा० उच्च न्यायालय के आदेश सं० 54927/02
में (A) लीजदार एवं फार्मोवर दस्तावेज

PTD

2.11
1.9.03

मा० उच्च न्यायालय

Since order of the Honble
High Court dt 28-2-2005 has
annulled the order of the Auth. dt
2-12-02, the Bld Plan automatically
stand restored. Hence.


1/9/03
प्रशास्त्र त्रिवेदी
उपाध्यक्ष

LAF
Pl. put up a draft
letter in context to the chmn order
dt 28/8/03 on N93 also with a proposal for
Board meeting for approval of
2.12.03
1-9-03


रजिस्ट्रार
उपरोक्त निर्देश के अन्तर्गत जमा की गई सभी प्रस्तावों पर
जो बाला पत्रों पर अज्ञात रूप से जमा की गई हैं

उपाध्यक्ष
कृ. पू. N-93 पर अज्ञात तरीके से आदेशों का अनामान
आता-चर्चा PDR का पत्र आता ही मांगें डेटु मांगी जा दिते जाने वाले पत्र अनामान
नका के डेटु डेटु प्रस्तावों आलोचना की 2. अज्ञात रूप से।

OSD(A) Hq.
क. अज्ञात रूप से प्रस्ताव
प्रस्ताव नकल
2.12.03


2.12.03
5-9-03



5/9/03 VC

मद संख्या-

30

विषय : भूखण्ड संख्या-ए-309 व 309ए, सूर्यनगर, गाजियाबाद के पास रिक्त भूमि 131.81 वर्ग मीटर श्रीमति शैल कुमारी सिंह को आवंटन के विषय में ।

भूखण्ड संख्या-ए-309, सूर्यनगर श्रीमति शैल कुमारी सिंह को आवंटित था । भूखण्ड संख्या-ए-309 व 359 के बीच की भूमि जिसका क्षेत्रफल जो कि 231 वर्ग मीटर है, के आवंटन के विषय में उपरोक्त दोनों के भूखण्ड स्वामियों के द्वारा आवेदन किया गया और श्री गंगा प्रसाद अग्रवाल द्वारा न्यायालय में वाद भी दायर किया गया । इस कारण उक्त भूमि का आंशिक भाग ए-309ए सृजित करते हुए भूखण्ड संख्या-ए-309 व 309ए क्षेत्रफल 300.58 वर्ग मीटर श्रीमति शैल कुमारी सिंह को आवंटित कर पट्टा विलेख 6/12/96 को निष्पादित कर दिया गया । श्री गंगा प्रसाद द्वारा दायर वाद प्राधिकरण के पक्ष में निर्णित हो चुका है । श्री गंगा प्रसाद अग्रवाल को आवंटित ए-359, सूर्यनगर कोने का भूखण्ड है । इसलिए उनके भूखण्ड के साथ 3.66 मीटर का रास्ता छोड़ते हुए अवशेष भूमि क्षेत्रफल 131.81 वर्ग मीटर श्रीमति शैल कुमारी सिंह को उनके पूर्व आवंटित भूखण्ड संख्या-ए-309 व 309ए के साथ आवंटित की गयी है तथा आवंटित भूमि का विक्रय विलेख नियमानुसार तलपट मानचित्र में संशोधन के प्रकाशन के उपरान्त किया जायेगा । भूमि के मूल्य का निर्धारण विशेष परिस्थितियों में शासनादेश दिनांक 21/8/96 के आधार पर मूल भूखण्ड 300.58 वर्ग मीटर के साथ अतिरिक्त भूमि 131.81 वर्ग मीटर में से 10 प्रतिशत (30 वर्ग मीटर) पुरानी दर से अंकन 2000/- रुपये के हिसाब से अंकन 60,000/- रुपये व अवशेष क्षेत्रफल 101.81 वर्ग मीटर नयी दर 6000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अंकन 6,10,860/- कुल रुपये 6,70,860/- लिये जाने का कार्योत्तर स्वीकृत एवं भूखण्ड संख्या-ए-309 व 309ए के मध्य तलपट मानचित्र में दिखायी गयी सड़क मानचित्र को तलपट मानचित्र में संशोधन की कार्योत्तर स्वीकृति भी प्राप्त की जानी है जिसके अनुसार सड़क जो स्थल पर खाली भूमि है, के संशोधन के उपरान्त भूखण्ड संख्या-ए-359 के साथ 3.66 वर्ग मीटर का रास्ता छोड़ते हुए शेष खाली भूमि पर नया भूखण्ड सृजित करते हुए श्रीमति शैल कुमारी सिंह को उपरोक्त विवरण के साथ आवंटित किये जाने का प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृतार्थ एवं अनुमोदनार्थ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।


(००)

मद संख्या :- 31

विषय :- परमवीर चक्र, गोल्ड मैडल पाने वाले सैनिक अधिकारियों/कर्मचारियों और खिलाड़ियों को रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में।

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण की भांति आवासीय भूखण्ड आधी दर पर आवंटन करने का निर्णय हुआ था। इस निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए गा0 वि0 प्राधिकरण द्वारा रियायती दरों पर भूखण्ड आवंटित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें यह शर्त होगी कि आवंटित भूखण्ड को बेचने की अनुमति आवंटन पत्र की तिथि से 10 वर्ष तक नहीं दी जायेगी। आवंटन की सैक्टर दरों में निम्नानुसार रियायते प्रस्तावित हैं—

- 1- परमवीर चक्र और युद्ध विधवा महिला को निशुल्क भूखण्ड।
- 2- महावीर चक्र और अशोक चक्र पाने वाले को सैक्टर दर के 50 प्रतिशत छूट।
- 3- अन्य को सैक्टर दर के 25 प्रतिशत छूट।
- 4- ओलम्पिक में गोल्ड मैडल पाने वाले खिलाड़ियों को निशुल्क एव सिल्वर व कांस्य मैडल पाने वाले खिलाड़ियों को सैक्टर दर के 25 प्रतिशत छूट। एसियन, एफ्रो ऐशियन व कामन वेल्थ में गोल्ड मैडल पाने वाले खिलाड़ियों को सैक्टर दर के 50 प्रतिशत व कांस्य मैडल पाने वाले खिलाड़ियों को सैक्टर दर के 25 प्रतिशत छूट प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार मैडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से आवेदन प्राप्त होने पर 50 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर भूखण्ड आवंटन के प्रस्ताव पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

मद सं० : 32

विषय : उत्तर प्रदेश विधान सभा / विधान परिषद सदस्यों को प्राधिकरण योजना भूखण्ड आरक्षित करने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की गत बोर्ड बैठक दिनांक 23-6-2003 के मद सं०-22 पर प्रस्ताव पारित किया गया कि माननीय विधायकगणों को आवंटन शासनादेशों के अनुसार किया जाये । बोर्ड निर्णय अनुसार 10 विधायकों को आरक्षण पत्र जारी किये जा चुके हैं । पुनः और विधायकगणों / सांसदों द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये गये हैं , ऐसे माननीय विधायकों के नाम इस प्रकार हैं । श्री रमेश यादव, एम०एल०सी०, श्री राम कृष्ण, राज्यमंत्री, श्री विशम्भर प्रसाद निसाद, मंत्री, श्री शैलेश यादव ललई, राज्यमंत्री, श्री उदय प्रताप सिंह, संसद सदस्य राज्यसभा, श्री शारदा नन्द अंचल, राज्य मंत्री, श्री हरिकेवल प्रसाद, पूर्व सांसद लोकसभा , श्री जागेश्वर प्रसाद, पूर्व राज्य स्वास्थ्य मंत्री, श्री अम्बिका चौधरी, मंत्री श्री नारद राय, राज्य मंत्री, श्री शिवपाल सिंह यादव, मंत्री आदि ।

अतः पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव की भांति इन विधायक / सांसदों को इन्दिरापुरम योजना में उपलब्धता के आधार पर भूखण्ड की कीमत की 10 प्रतिशत राशि की मांग आरक्षण राशि के रूप में जमा करने सहित भूखण्ड आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है । आरक्षण राशि जमा होने पर औपचारिक आवंटन पत्र भूखण्ड संख्या सहित भेजा जायेगा ।

प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

विषय : खसरा नं० 781, 782, 776, 2524, (क)ग्राम डासना-मसूरी, गाजियाबाद में जमियत कालिज आफ फार्मसी एण्ड एलाईड साईसेज के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

मैसर्स जमियत उल्मा-ए-हिन्द संस्था द्वारा ग्राम डासना-मसूरी, गाजियाबाद के एन०एच०-24 पर लगभग 25,000 वर्ग मीटर भूखण्ड पर जमियत कालिज आफ फार्मसी एण्ड एलाईड साईसेज के निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत मानचित्र प्रस्ताव में वर्तमान में लागू जोनिंग रेगुलेशन के अन्तर्गत नियमानुसार 10 प्रतिशत से कम भू-आच्छादन एवं 0.15 प्रतिशत एफ०ए०आर० नियमानुसार प्रस्तावित किया गया है। पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के बारे में नियोजन अनुभाग/मास्टर प्लान अनुभाग/भू-अर्जन अनुभाग की तकनीकी आख्या प्राप्त हो चुकी है, जिसके अनुसार प्रस्तुत मानचित्र प्रस्ताव नियमानुसार है तथा प्रस्तुत मानचित्र प्रस्ताव के बारे में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, गाजियाबाद से भी निर्माण के बारे में एन०ओ०सी० प्राप्त हो चुकी है। प्रस्तुत मानचित्र प्रस्ताव तकनीकी रूप से नियमानुसार तथा स्वीकृति योग्य है तथा जिसकी स्वीकृति से प्राधिकरण को रु० 22.00 लाख की आय विकास शुल्क के रूप में होगी।

प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

मद संख्या :- 34

विषय : भवन संख्या बी-65 एच0आई0जी0 डुप्लेक्स संजय नगर के सम्बन्ध में ।

भवन संख्या बी-65 एच0आई0जी0 डुप्लेक्स संजय नगर श्री ओमपाल सिंह (भूतपूर्व सैनिक) को आवंटित है । इनके द्वारा भवन के खाते में देय धनराशि का भुगतान पैमेंट शेड्यूल के अनुसार नहीं किया गया था । एक मुश्त देय धनराशि का भुगतान करने के लिए आवंटी द्वारा ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत आवेदन किया गया है । ओ0टी0एस0 में इन्हें 3% ब्याज छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पूर्व में जारी पैमेंट शेड्यूल को दो वर्ष के स्थान पर चार वर्ष में 18% ब्याज की दर से संशोधित किया गया है । आवंटी द्वारा प्रार्थना की गयी है कि भारत-पाक युद्ध 1971 के मोर्चे पर लड़ते हुए विकलांग को ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत ब्याज में 3% का लाभ सभी आवंटियों की तरह दे दिया जाये । प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

 5.1.2004

मद संख्या :

35

विषय : हरित क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में नीति

सडक किनारे गाजियाबाद के बहुत से हरित क्षेत्रों को निजी संस्थाओं द्वारा अपनाकर विकसित किया गया है । इसी तरह समस्त सरकारी संस्थाओं द्वारा भी टुकड़ों में हरित पट्टियों का विकास किया जाता रहा है । यह कार्य समन्वयहीनता (Non integrated) की प्रक्रिया अपनाकर किये गये हैं । इस विषमता से निपटने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, नगर निगम निदेशक सामाजिक वानिकी, तथा ए०ई०जेड० जैसी निजी संस्था के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की । बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि साहिबाबाद, इन्दिरापुरम, कौशाम्बी, वैशाली, के हरित क्षेत्रों का विकास करने तथा मुख्य- मुख्य राजमार्गों के किनारे खाली पड़ी भूमि को हरा-भरा करने हेतु एक समन्वित योजना तैयार की जाय । जो निजी संस्थायें अथवा उद्यमी इस वृहत योजना के टुकड़ों के क्षेत्रों पर वृक्षारोपण करने अथवा सौन्दर्यीकरण का कार्य करने हेतु इच्छुक हैं उनको अनुमति दी जायेगी बसर्ते वे जी०डी०ए० द्वारा तैयार की गयी समन्वित विकास योजना के तहत कार्य करें । हरित क्षेत्र विकसित करने की इस समन्वित वृहत योजना के जिन टुकड़ों का कोई निजी उद्यमी अथवा सरकारी विभाग बीड़ा उठाने को तैयार न हो उस कार्य को जी०डी०ए० अपनाकर पूर्ण करेगा । इस महत्वाकांक्षी हरित क्षेत्र विकास योजना का महत्वपूर्ण अंग एक नगर वन विकसित करना है जो राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-24 के किनारे 6 कि०मी० गुणा 100 मीटर के क्षेत्र में होगा । ऐसी जमीने वन विभाग को वन विकसित करने तथा नगर वनों के संरक्षण हेतु स्थानान्तरित कर दी जायेगी । इस कार्य हेतु धनराशि निदेशक सामाजिक वानिकी गाजियाबाद को स्थानान्तरित कर दी जायेगी । यदि वे अपने विभागीय वजट से इसकी प्रतिपूर्ति नहीं कर पाते हैं तो डी०एफ०ओ० को यह धनराशि जी०डी०ए० से स्थानान्तरित कर दी जायेगी ।

निजी उद्यमियों/ संस्थाओं द्वारा अपनाये गये हरित योजना के हिस्सों को आम जनता व जी०डी०ए० के उपयोग हेतु खुला रखा जायेगा । यदि कोई इस हरित क्षेत्र का पार्किंग हेतु दुरुपयोग करता है अथवा इसपर किसी भी तरह का अतिक्रमण करते हुए निर्माण करता है अथवा निजी उद्यान के रूप में इसे घेर लेता है तो निजी संस्था/ उद्यमी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा दुरुपयोग जारी रहने पर हरित क्षेत्र अपनाने वाली संस्था/ उद्यमी सेक्टर रेट अथवा बाजार की कीमत (जो भी उच्चतर हो) के एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से आर्थिक दण्ड का भागी होगा । हरित क्षेत्र अपनाने वाला व्यक्ति / संस्था / उद्यमी की यह जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा अपनाये गये हरित क्षेत्र की सुरक्षा रहे । उसका यह तर्क कतई मान्य नहीं होगा कि उस भू-क्षेत्र का दुरुपयोग रोकना उसकी क्षमता से बाहर था ।

बोर्ड के समक्ष हरित क्षेत्र कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है । बोर्ड कृपया इसपर विचार करके इस नीति का अनुमोदन देना चाहे ।

मद सं० :- 36

विषय :- प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्कूल भूखण्डों के आवंटन हेतु नियम व शर्तों के सम्बन्ध में।

विभिन्न योजनाओं में प्राधिकरण द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूल भूखण्ड नियोजित किए गए हैं, जिनमें से अधिकतर स्कूल भूखण्डों का आवंटन शासनादेश के परिपेक्ष्य में पूर्व में बोर्ड स्वीकृति उपरान्त किये गये हैं तथा अभी भी कुछ भूखण्ड रिक्त हैं। आवंटन विषयक शासनादेश संख्या-231/9-आ-1-99-90/डी.ए./95 दि० 1 फरवरी 1999 एवं शासनादेश संख्या 1704/9-आ-1-96 दि० 19 अप्रैल 96 में इस सीमा तक नियम व शर्तों में संशोधन बोर्ड के समक्ष निम्नानुसार विचारार्थ प्रस्तावित है :-

1. शासनादेश के अनुसार भूमि के मूल्य की अदायगी में 21 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के स्थान पर बोर्ड बैठक दिनांक 23.06.03 के मद संख्या 43 के निर्णय अनुसार किशतों में 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर रखा जाना प्रस्तावित है।

2. आवंटन पत्र के साथ पंजीकरण राशि निम्न प्रकार प्रस्तावित है :-
क्रेच/नर्सरी (क्षेत्रफल 1000 वर्गमी० तक) — कुल प्रीमियम के 25 प्रतिशत
धनराशि की 50 प्रतिशत

नर्सरी/प्राईमरी/हाईस्कूल/डिग्री कॉलेज
(क्षेत्रफल 1000 वर्गमी० से अधिक) — कुल प्रीमियम के 25 प्रतिशत
धनराशि की 25 प्रतिशत

3. आवेदन के समय शिक्षण कार्य / अनुभव निम्न प्रकार प्रस्तावित है :-

क्रेच/नर्सरी (क्षेत्रफल 1000 वर्गमी० तक) — New
नर्सरी/प्राईमरी — किसी Recognized School के
(क्षेत्रफल 1000 वर्गमी० से 4000 वर्गमी० तक) साथ Collaboration

हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट/डिग्री कॉलेज
(क्षेत्रफल 4001 वर्ग मी० से 8000 वर्ग मी०) — 5 वर्ष
(क्षेत्रफल 8000 वर्ग मी० से अधिक) — 10 वर्ष

4. भूखण्डों का आवंटन पंजीकरण अवधि पूर्ण होने से 2 माह के अन्दर किया जायेगा। इस अवधि के बाद आवंटन न होने की दशा में आवेदक संस्था की पंजीकरण राशि पर 5 प्रतिशत वार्षिक का साधारण ब्याज देय होगा।

5. जिस संस्था द्वारा मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्कूल चलाया जायेगा, उन संस्थाओं को भूखण्ड का आवंटन सैक्टर दर की 20 प्रतिशत दर पर किया जाना प्रस्तावित है।

अन्य नियम व शर्तें शासनादेश के परिपेक्ष्य में पूर्व में दिनांक 10.02.03 से दि० 10.03.03 तक किये गये पंजीकरण हेतु ब्रोशर अनुसार प्रस्तावित हैं। कृप्या उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रेषित है।

मद सं० :- ३७

विषय :- प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित सामुदायिक केन्द्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में सामुदायिक केन्द्रों का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत कुछ योजनाओं में उक्त प्रयोजन हेतु भूखण्डों पर आंशिक निर्माण किया गया था एवं कुछ भूखण्ड अभी भी रिक्त हैं। 14 सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण प्राधिकरण द्वारा एवं 4 सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण विधायक निधि से नगर निगम/ डूडा द्वारा किया गया है। वर्तमान में कुछ सामुदायिक केन्द्रों को प्राधिकरण द्वारा किराये पर दिया जा रहा है तथा अधिकतर सामुदायिक केन्द्र यथास्थिति रिक्त पड़ें हैं जोकि पूर्णतया क्रियाशील नहीं हो पा रहे हैं एवं न ही इनका समुचित रखरखाव हो पा रहा है। इन सामुदायिक केन्द्रों को आवंटित करने हेतु समय समय पर जन सामान्य, संस्थाओं एवं आवासिक कल्याण समितियों से प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहते हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में प्राधिकरण में कोई नीति नहीं होने के कारण प्राप्त आवेदनों पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाती है। प्राधिकरण द्वारा प्राविधानित सामुदायिक केन्द्रों का रखरखाव न होने के कारण जहां एक ओर प्राधिकरण की सम्पत्ति का क्षय हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जनसामान्य को इसका उचित लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।

प्राधिकरण द्वारा रखरखाव किये जाने पर इसके लिये धनराशि एवं स्टाफ की आवश्यकता होगी जिसपर आय से अधिक व्यय की संभावना है। वर्णित परिस्थितियों में इन सामुदायिक केन्द्रों का रखरखाव एवं संचालन विभिन्न पंजीकृत रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन/संस्था/ट्रस्ट/पात्र व्यक्तियों द्वारा किया जाना अधिक सुविधाजनक एवं उपयोगी रहेगा। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए निस्तारण हेतु निम्न नियम व शर्तें विचारार्थ प्रेषित हैं :-

1. सामुदायिक केन्द्र के निर्मित भवन एवं भूमि का स्वामित्व प्राधिकरण का रहेगा।
2. संचालन हेतु आवन्टी द्वारा एक समिति इस प्रकार गठित की जाये जिसमें योजना के सभी ब्लॉक/सैक्टरों का प्रतिनिधित्व रहे।
3. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नामित सदस्य/सम्पत्ति प्रभारी तथा योजना के अधिशासी अभियन्ता समिति में प्राधिकरण के पदेन प्रतिनिधि रहेंगे, जिसके लिए आवंटी संस्था अपने संविधान में यथोचित संशोधन कर प्राविधान करेगी।
4. सामुदायिक केन्द्र में विद्यमान निर्माण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा नया निर्माण प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।


T. K. Sharma

5. समिति सामुदायिक केन्द्र को विवाह समारोह, गोष्ठी या अन्य इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों हेतु निर्धारित किराये पर जन सामान्य को आवंटित कर सकेगी।
6. सामुदायिक केन्द्र का उपयोग केवल सामाजिक/मनोरंजन/सांस्कृतिक कार्यों हेतु किया जायेगा। किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग अनुमन्य नहीं होगा।
7. किराये का निर्धारण समिति/संस्था एवं प्राधिकरण के नामित सदस्यों की अनुशंसा पर उपाध्यक्ष गा0वि0प्रा0 द्वारा समय समय पर (प्रतिवर्ष) निर्धारित किया जायेगा।
8. प्राधिकरण के कर्मचारी/अधिकारियों को निर्धारित शुल्क में 50 प्रतिशत छूट पर सामुदायिक केन्द्र उपलब्ध कराना होगा।
9. सामुदायिक केन्द्र का रखरखाव समिति द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा और प्राधिकरण का कोई दायित्व इसके रखरखाव का नहीं होगा। सामुदायिक केन्द्र पर रखरखाव एवं अन्य कार्यों हेतु समिति/संस्था द्वारा व्यवस्था की जायेगी तथा उसके खर्च का भुगतान का खर्चा संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। प्राधिकरण इनके लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
10. सामुदायिक केन्द्र का प्रयोग समिति द्वारा उस क्षेत्र/कॉलोनी के सभी निवासियों को बिना वर्ग जाति या धर्म भेद के समान रूप से "प्रथम आओ" के सिद्धान्त पर सांस्कृतिक, मनोरंजन व सामुहिक कार्यों हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
11. सामुदायिक केन्द्र के उपयोग हेतु समिति द्वारा लाईसेन्स फीस के रूप में संलग्न तालिका अनुसार धनराशि प्रतिवर्ष अग्रिम लीज किराये के रूप में जमा करनी होगी और इस राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। यदि निर्धारित अवधि में लीज किराये का भुगतान नहीं किया जाता है तो 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की देयतिथि से अदा करनी होगी। परन्तु समय पर लीज किराया भुगतान न करने की दशा में इस संविदा को भंग करने का विकल्प भी प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा। 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् प्राधिकरण को वार्षिक किराये को पुनरीक्षित करने व बढ़ाने का अधिकार प्राप्त होगा। जो तत्कालीन परिस्थितियों में सामुदायिक केन्द्र के उपयोग, उद्देश्य एवं उसमें प्राप्त आय एवं रखरखाव हेतु किये गये व्यय को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षित किया जायेगा। संस्था को सामुदायिक केन्द्र पर किये जाने वाले व्यय तथा इससे होने वाली आय का विस्तृत ब्यौरा रखना होगा, जिसे प्रत्येक वित्त वर्ष के अन्त में प्राधिकरण को सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
12. यह लाईसेन्स केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा, यदि आगे उल्लिखित किसी कारण से इसे निर्धारित अवधि से पूर्व भी समाप्त न कर दिया जाये। किन्तु 5



वर्ष की अवधि के उपरान्त इसके नवीनीकरण का विकल्प भी प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा।

13. उपाध्यक्ष द्वारा अधिकृत प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी को सामुदायिक केन्द्र को कभी भी निरीक्षण करने के अधिकार को संस्था द्वारा कोई आपत्ति या विरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
14. बिजली, पानी, फर्नीचर, अनुरक्षण आदि अन्य आवश्यक सुविधाओं हेतु किये जाने वाले व्यय का भार संस्था को स्वयं वहन करना होगा।
15. उपाध्यक्ष, गा0वि0प्रा0 द्वारा आवश्यकतानुसार इन शर्तों में संशोधन व परिवर्तन का पूर्ण अधिकार होगा।
16. यदि समिति/संस्था द्वारा वार्षिक किराया निर्धारित समय पर अदा नहीं किया जाता है अथवा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या किसी अन्य कारण से जो उपाध्यक्ष, गा0वि0प्रा0 के विवेक में उचित एवं आवश्यक समझा जाये, इस संविदा को भंग करने का अधिकार उपाध्यक्ष के पास सदैव सुरक्षित होगा।
17. यदि कोई देय समिति की ओर अवशेष पाया जाता है तो उसकी वसूली हेतु प्राधिकरण को मालगुजारी की भांति वसूल करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
18. यदि इस संविदा के अधीन किसी नोटिस के दिये जाने की अपेक्षा की गयी हो वह उस दशा में संस्था पर दी गयी साक्ष्य समझी जायेगी। जबकि यह प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की गयी हो और उसे सामुदायिक केन्द्र पर दिया गया हो और प्राधिकरण के किसी निर्णय की सूचना से ऐसे निर्णय का यथेष्ट साक्ष्य उस समय समझा जायेगा जबकि उस पर प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर हों।
19. सामुदायिक केन्द्र का रखरखाव इत्यादि व्यय प्रतिवर्ष प्राधिकरण के अनुमोदन कराने के उपरान्त ही संस्था द्वारा जन सामान्य से चार्जज किया जायेगा।
20. किसी कारणवश संस्था का पंजीकरण यदि लाईसेन्स अवधि से पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो लाईसेन्स स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
21. संस्था द्वारा प्राधिकरण को लाईसेन्स फीस/लीज किराये का भुगतान नकद या पे-ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट जोकि उपाध्यक्ष गा0वि0प्रा0 के पक्ष में देय एवं गाजियाबाद में भुगतान योग्य हो, करना होगा।
22. समिति/संस्था/ट्रस्ट को अग्रिम जमानत के रूप में वार्षिक लाईसेन्स फीस की 50 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण के पास जमा करानी होगी।


E.E.
T. K. Sharma

23. कब्जा देते समय प्राधिकरण समिति को सामुदायिक केन्द्र के भवन एवं खुले क्षेत्र को जिस स्थिति में (विकास कराकर) हस्तांतरण करेगा उसी स्थिति में समिति को कब्जा प्राधिकरण को वापिस देना होगा। यदि कोई कमी पायी जाती है तो उसका व्यय समिति की जमानत धनराशि से वसूला जायेगा।
24. ध्वनि प्रदूषण को निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ही रखा जायेगा जिससे क्षेत्रवासियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।
25. किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में उपाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा तथा समिति को मान्य होगा एवम् न्याय क्षेत्र गाजियाबाद होगा।

उपरोक्तानुसार नियम व शर्तों पर सामुदायिक केन्द्रों को निस्तारण किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है।


EE.
T.K.Sharma

मद संख्या—

38

विषय :- विभिन्न योजनाओं में पेट्रोल पम्प हेतु रिक्त भूखण्डों को नीलामी द्वारा आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में पेट्रोल पम्प के कुछ भूखण्ड रिक्त हैं तथा कुछ नियोजित किये जाने हैं। समय-समय पर विभिन्न पेट्रोलियम कम्पनियों तथा उनके लैटर ऑफ इन्डेन्ट द्वारा विभिन्न योजनाओं में पेट्रोल पम्प हेतु भूखण्ड आवंटन की मांग की जाती रही है। चूंकि रिक्त भूखण्डों की संख्या कम है एवम इनकी मांग अधिक है। अतः इन भूखण्डों के निस्तारण हेतु आवासिय सेक्टर दर की 50 प्रतिशत की दर को आरक्षित दर मानते हुए भूखण्डों को नीलामी द्वारा निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है। भूखण्डों के निस्तारण हेतु केवल पेट्रोलियम कम्पनियां तथा इनके लैटर ऑफ इन्डेन्ट ही नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। इन भूखण्डों को लीज आधार पर आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। अतः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में पेट्रोल पम्प हेतु रिक्त भूखण्डों को विभिन्न पेट्रोलियम कम्पनियों एवम इनके लैटर ऑफ इन्डेन्ट को लीज आधार पर आवासीय सेक्टर दर की 50 प्रतिशत की आरक्षित दर पर नीलामी द्वारा निस्तारित किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

PKS

EE (coml)
08/01/04

मद संख्या :

39

विषय : प्राधिकरण की वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 की बैलेन्सशीट अनुमोदन हेतु ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02, तथा 2002-03 की बैलेन्सशीट सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, द्वारा तैयार कर प्रस्तुत कर दी गयी है, जो प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

22/11/04
31/10/04
62

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY, GHAZIABAD -
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2001

TABLE 15	DATE NO.	AMOUNT	AMOUNT	DATE NO.	AMOUNT
Capital Fund	1	215778954.22	FIXED ASSETS	5	477812910.00
SECURED LOANS	2	2201483230.00	CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES		
HUDCO		428116094.00	(A) CURRENT ASSETS		
Bank & Financial Institution			(i) STOCK IN HAND	7	4939742.00
UNSECURED LOANS	3	866253000.00	Construction Material (Certified by the Management at cost)		
State Government			(ii) WORKS		
DEPOSITS			Cost of Work in progress		929856788.00
Money received at the time registration and under self-financing schemes	3A	1856761461.00	(iii) Unutilised land/unallotted plots/shops/commercial Complex (at estimated realisable value)		3750799499.56
Security from contractors & Employees	4	25860774.54	(iv) AMOUNT RECOVERABLE IN RESPECT OF		
CURRENT LIABILITIES	5	88689484.00	(a) Property sold on instalments	8	749465000.00
Expenses/Amount Payable			(b) commercial property		1348693014.00
Compensation including enhanced			(c) Rent receivable		180127.90
Compensation Payable		2186100000.00	(d) Stamp duty receivable		9515099.90
			(v) CASH & BANK BALANCES		396855.30
			(a) Cash in hand	9	126226749.46
			(b) Bank Balances	10	445302175.70
			(c) FDR with banks		
			(B) LOANS & ADVANCES		
			Advance to Contractors/Suppliers	11	18949072.00
			Advance to Staff	12	5806113.44
			Security Deposits	13	99850.00

TOTAL (Rs.)

7869042997.76

7869042997.76

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts As per Schedule 14

Computed from post-sal accounts information & explanations provided to us by the Management

For Ghaziabad Development Authority

(Account Officer) (Finance Controller) (Secretary) (Vice Chairman)

(Partner)

PLACE : GHAZIABAD
DATED : 04.09.2003



108

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY, GHAZIABAD
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2001

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Establishment Expenses	83299149 52	By Rental Income	
To Office Expenses	14746697 64	Freehold /Leasehold Rent	16247299 20
To Sundry Expenses	39017084 33	Rental Income from colonies, flats etc.	2423940 60
To Depreciation	1288083 55	Other Rent	430607 00
To Interest on Loan	627535118 41		19101846 80
		By Stamp Duty Income	25751704 15
		By Water Supply	8583593 25
		By Interest FDRs	25027468 00
		By Income from Master Plan	170376880 20
		By Sale of Forms etc.	637899 00
		By Income on Forfeiture/ Surrender of Property	2717777 00
		By Income from Levy	1639888 30
		By Transfer Charges	527499 00
		By Freehold Charges	10689093 90
		By Misc. Income	17277012 10
		By Excess of Expenditure over Income	483553451 75

TOTAL (Rs.)

765884113.45

TOTAL (Rs.)

765884113.45

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts : As per Schedule 14

Compiled from books of accounts, information & explanations provided to us by the Management

For DINESH JAIN & ASSOCIATES
Chartered Accountants

[Signature]

Partner

[Signature]
(Accountant)

For Ghaziabad Development Authority

[Signature]
(Account Officer)

[Signature]
(Finance Controller)

[Signature]
(Secretary)

[Signature]
(Vice)



PLACE: GHAZIABAD
DATED: 04.09.2003

108

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY, GHAZIABAD

Schedule of Establishment Expenditure During 2000-2001

<u>S. No.</u>	<u>PARTICULARS</u>	<u>AMOUNT (Rs.)</u>
1.	Salary	77020870.40
2.	Leave Encashment	384237.30
3.	Honorarium	0.00
4.	Medical Expenses	501050.87
5.	CPF Contribution	767703.70
6.	Pension, P.F. & Contribution	1087688.25
7.	Liveries to Staff	635600.00
8.	Bonus to Staff	1613865.00
9.	Other Allowance	23390.00
		82034405.52
	Add: Payable as on 31.03.2001	8890785.00
		90925190.52
	Less: Payable as on 31.03.2000	7626041.00
		83299149.52

DETAILS OF OFFICE EXPENSES DURING 2000-2001

<u>S. No.</u>	<u>PARTICULARS</u>	<u>AMOUNT (Rs.)</u>
1.	Conveyance	1378612.99
2.	Books & Periodicals	11024.30
3.	Printing & Stationery	2427651.88
4.	Postage & Telegram	370442.00
5.	Telephone Expenses	1597380.00
6.	Electricity Expenses	492903.72
7.	Rent & Rates	100000.00
8.	Maintenance of Vehicles	6777525.90
9.	Repair & Renewal of Office	1591156.85
		14746697.64



108

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY, GHAZIABAD

DETAIL OF SUNDRY EXPENSES DURING 2000 2001

<u>S. No.</u>	<u>PARTICULARS</u>	<u>AMOUNT (Rs.)</u>
1.	Advertisement & Publicity	5676629.00
2.	Entertainment Expenses	327221.86
3.	Misc. Expenses	2937390.87
4.	Computer Maintenance	413600.00
5.	Legal Expenses	10937973.00
6.	Sports	203105.00
7.	Computer Software	527390.00
8.	Scheme Announcement	5405093.00
9.	Audit Fees	1500000.00
10.	Consultancy, R&D, Designing	658623.00
11.	Electricity Repair	2573925.16
12.	Maintenance of Residential Houses	603384.27
13.	Other Maintenance	7192749.17
14.	Discretionary Expenses	60000.00
		<u>39017084.33</u>

DETAIL OF INTEREST DEBITED DURING 2000-2001

<u>S. No.</u>	<u>PARTICULARS</u>	<u>AMOUNT (Rs.)</u>
1.	Government Loan	202803265.00
2.	HUDCO	243085126.00
3.	Loan from Financial Institution	156497094.00
4.	Other (Allotees)	25149633.41
		<u>627535118.41</u>



109

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY, GHAZIABAD

Schedule of Capital Fund as at 31st March, 2001

Schedule - 1

Balance as at 01.04.2000
Less: Excess of Expenditure over Income
Balance as on 31.03.2001

699332405.97
483553451.75

215778954.22

Schedule of Secured Loans as at 31st March, 2001

Schedule - 2

(A) FROM HUDCO

Balance as at 01.04.2000
Add: Interest liability recomputed at settlement

761079642.00
1540403588.00

2301483230.00
100000000.00

Less: Repaid during 2000-2001

Balance as at 31.03.2001

2201483230.00

(B) FROM BANKS & FINANCIAL INSTITUTION

Balance as at 01.04.2000
Add: Interest/ overdue etc.

828462000.00
155497094.00

983959094.00
555843000.00

Less: Repaid during 2000-2001

Balance as at 31.03.2001

428116094.00

Schedule - 3

Schedule of Unsecured Loans as at 31st March, 2001

From State Govt.

Balance as at 01.04.2000
Add: Received/Interest
Less: Repaid with intt. during the year
Balance as at 31.03.2001

742637036.00
405903265.00

282287301.00

866253000.00

Schedule - 3A

Schedule of Money Received on Registration as at 31st March, 2001

Balance as at 01.04.2000
Add: Received during the year
Less: Refunded during the year
Balance as at 31.03.2001

1902568319.00
44101575.00

89908433.00

1856761461.00



Schedule - 4

Schedule of Security from Contractors/Employees as at 31st March, 2001

Balance as at 01.04.2000	25607166.00
Add: Security deducted during 2000-2001	3259874.00
Less: Adjusted/refunded during 2000-2001	3006265.46
Balance as at 31.03.2001	<u>25860774.54</u>

Schedule - 5

Schedule of Expenses/Amount Payable as at 31st March, 2001

Salary	4273714.00	
Salary of Work Charge Employees	2646930.00	
Bonus (2000-2001)	<u>1970141.00</u>	8890785.00
Amount Payable to contractors		78758000.00
Trade Tax deducted at source		155543.00
Income Tax deducted at source		803247.00
Electricity Expenses		9709.00
Telephone Expenses		<u>72200.00</u>
		<u>88689484.00</u>



SCHEDULE - 6FIXED ASSETS AS AT 31.03.2001

DESCRIPTION	W.D.V. AS ON 01.04.2000	ADDITIONS DURING 2000-01	SOLD DURING THE YEAR	TOTAL AS ON 31.03.2001	DEPRECIATION FOR THE YEAR	W.D.V. AS ON 31.03.2001
LAND & BUILDING	488443838.00	0.00	14634000.00	473809838.00	0.00	473809838.00
VEHICLE	724408.96	0.00	0.00	724408.96	144881.96	579527.00
OFFICE EQUIPMENTS & MACHINERY	3458513.59	1106213.00	0.00	4564726.59	1141181.59	3423545.00
TOTAL	492626760.55	1106213.00	14634000.00	479098973.55	1286063.55	477812910.00



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY, GHAZIABAD

Schedule - 7

Stock of Construction Material as at 31st March, 2001

<u>S. No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Unit</u>	<u>Qty.</u>	<u>Amount</u>
1.	Cement	Bag	7033 000	989894 00
2.	Tot Steel	MT	7 686	132218 00
3.	C.I. Pipe	RM	756 000	822553 00
4.	G.I. Pipe	RM	13604 000	629440 00
5.	A.C. Pressure Pipe	RM	980 100	745369 00
6.	PVC Pipe	RM	5488 650	665408 00
7.	RCC Pipe	Nos	2374	766594 00
8.	Manhole Cover	Nos	163	167341 00
9.	Dustbin	Nos	1 00	20925 00
				<u>4939742 00</u>

Schedule - 8

Rent Receivable from Colonies as on 31st March, 2001

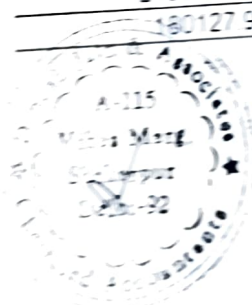
Balance as on 01.04.2000

Add: Rental Income due for F.Y. 2000-01

Less: Rent Received during the year

Balance as on 31.03.2001

254789 00
<u>2423940 60</u>
2678729 60
<u>2498601 70</u>
180127 90



Schedule - 9

Bank Balance as at 31st March, 2001

<u>S. No.</u>	<u>NAME OF BANK</u>	<u>Amount</u>
1	Vysya Bank, Navyug Market	10223284.40
2	Vysya Bank, IDSMT, Loni	6628.00
3	Vysya Bank, IDSMT, Dadri	19319.00
4	Vysya Bank, IDSMT, Murad Nagar	29075.00
5	PNB Kaushambi	4364386.70
6	Allahabad Bank	513301.16
7	Oriental Bank of Commerce	165103.00
8	Oriental Bank of Commerce	99055.00
9	Oriental Bank of Commerce	21040.00
10	Oriental Bank of Commerce	7445.00
11	Oriental Bank of Commerce	157260.00
12	Oriental Bank of Commerce	832268.19
13	Oriental Bank of Commerce	3706360.00
14	Oriental Bank of Commerce	1502300.00
15	Oriental Bank of Commerce	38660.00
16	Oriental Bank of Commerce	93395.58
17	Oriental Bank of Commerce	5750.85
18	State Bank of Patiala	278000.00
19	Dena Bank	20803.00
20	Corporation Bank	135204.00
21	PNB Navyug Market	60899684.00
22	Union Bank	203799.14
23	PLA Treasury	369614.78
24	SBI, Navyug Market	895060.58
25	SBI, Modinagar	142715.18
26	SBI, Modinagar	92815762.04
27	SBI, Modinagar	810755.47
28	SBI, Modinagar	18330.00
29	Vijaya Bank	38117.50
30	Vijaya Bank	14747.00
31	Vijaya Bank	7041524.89
		185468749.46
		59242000.00
		126226749.46

Less: PLA Treasury not belonging to GDA
Total Balance (Rs.) Subject to Reconciliation



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY, GHAZIABAD

FDRs AS AT 31ST MARCH, 2001

Schedule - 10

S. No.

Name of Bank	Date of Issue	Rate of Interest	FDR No.	Cumulative Balance As on 31.03.01
Oriental Bank of Commerce	07.06.90	10.00	235/90	3271500.00
Oriental Bank of Commerce	23.03.90		169/90	1433843.00
Oriental Bank of Commerce	22.08.90		322/90	1660430.00
Oriental Bank of Commerce	09.11.90		346/90	2202388.00
Oriental Bank of Commerce	13.11.90		348/90	2251900.00
Oriental Bank of Commerce	24.03.00	10.50	4344A	1190578.00
Oriental Bank of Commerce	19.01.98	-	980064	4582818.00
Vijaya Bank (Under court attachment)	19.01.98	-	980063	1435272.00
Vijaya Bank (Under court attachment)	25.04.00	10.80	VSU 992308/4	107546014.00
Vijaya Bank			VSU 992308/5	
Vijaya Bank	18.09.00	10.80	KTB/0181822	99859793.00
Vijaya Bank	24.11.00	10.80	VSU 992756	17817875.00
Vijaya Bank	08.12.00	10.50	0169062/VSU 992793	50537505.00
Vijaya Bank	08.12.00	10.50	0169063/VSU 992793	41980811.00
Vijaya Bank	15.12.00	10.50	169098/VSU 992809	55454064.00
Vijaya Bank	27.12.00	9.00	169129/VSU 992833	16396833.00
Vijaya Bank	10.01.01	7.75	356467	3449152.00
Vijaya Bank	10.01.01	7.75	356476	5042534.00
Allahabad Bank	22.01.01	7.75	625601	3374025.00
Allahabad Bank	30.03.01	9.00	582754	10440984.00
Vysya Bank	08.12.00		579828	6483694.00
Vysya Bank	16.06.97	-	299254/2211	7313262.00
Oriental Bank of Commerce	-	12.00	A/c No. 3145	1476783.70
Oriental Bank of Commerce				445302175.70

Schedule - 11

Schedule of Advance to Contractors/Suppliers as at 31st March, 2001

16496647.00

Balance as at 01.04.2000

Add: Advance given during 2000-01

Contractors
Suppliers
Others

407265.00
0.00
3000000.00

3407265.00

Less: Adjusted during 2000-01

Contractors
Suppliers
Others

0.00
954840.00
0.00

954840.00

18949072.00

Balance as at 31.03.2001



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY, GHAZIABAD

Schedule - 12

Schedule of Advance to Staff as at 31st March, 2001

Balance as at 01.04.2000			7,480,694.00
<u>Add: Advance given during 2000-01</u>			
Permanent Imprest	620,577.00		
Temporary Imprest	2,980,862.17		
House Construction Advance	564,500.00		
Vehicle Advance	<u>40,000.00</u>		4,205,939.17
<u>Less: Adjusted during 2000-01</u>			
Against Permanent Imprest	569,000.00		
Against Temporary Imprest	2,961,250.23		
Against House Construction Advance	1,122,100.50		
Against Vehicle Advance	<u>228,169.00</u>		4,880,519.73
Balance as at 31.03.2001			<u>6,806,113.44</u>

Schedule - 13

Schedule of Security Deposits as at 31st March, 2001

Balance as on 01.04.2000		99,850.00
Add: Security Deposits received during 2000-01		-
Less: Security Deposits returned during 2000-01		-
Balance as at 31.03.2001		<u>99,850.00</u>



118

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY, GHAZIABAD

SCHEDULE : '14'

**ACCOUNTING POLICIES AND NOTES ON ACCOUNT FORMING PART OF
ACCOUNTS FOR THE YEAR 31.03.2001**

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Income and Expenditure are accounted on accrual basis except in some cases.
2. Fixed Assets are accounted on historical cost basis less accumulated depreciation and carried at written down value.
3. Depreciation on Fixed Assets is provided on written down value method as per rates prescribed in Income Tax Act, 1961. Depreciation on building is not provided due to non-availability of bifurcation of land and building.
4. Stock in hand in respect of construction material and work-in-progress are valued at cost whereas unutilized land/unallotted plots/shops/commercial complex are stated at estimated realisable value.

NOTES TO ACCOUNTS

1. Money received at the time of registration represents amount received as registration fee and where draw has not been made and amount received under self financing scheme where title has not been transferred to allottees.
2. Compensation payable includes /represents amount where competent authorities have awarded final amount and there is no dispute between authority and person concerned.
3. Excess of expenditure over income is due to interest paid/provided on various loans charged to Income & Expenditure Account.
4. Bank balances are under reconciliation.
5. Current year's interest of various loans is charged to Income & Expenditure Accounts and earlier year's interest is added to various works
6. Amount in respect of Item No. A(iii) and A(iv) (a) and (b) of the Balance Sheet are subject to reconciliation as data updation in respect of individual properties and receivables is in progress on computer.

LIABILITIES	SCHEDULE	AMOUNT (RS.)	ASSETS	SCHEDULE	AMOUNT (RS.)
				6	
OWNED FUND			FIXED ASSETS		
Capital Fund		1064552234.13	INVESTMENTS	7	230052209.70
LOANS FUNDS			CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES		
Secured loans	1	1983390327.00	A) CURRENT ASSETS		
Unsecured loans	2	729718929.78	Stock in Hand	8	8162306226.77
DEPOSITS			Receivables agst. Sale of Properties		4357590722.71
Deposits Against Works	3	26197466.54	Other Receivable	9	52052993.00
Deposits Against Properties	4	148243790.58			
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			Closing Balances		
Expenses Payable	5	8659777.00	- Cash In Hand		57386.50
			- Stationery in Hand		666788.62
			- Balances with Banks	10	95872453.47
			B) LOANS & ADVANCES		
			Housing/Vehicle Advances to Staff	11	3046160.00
			Other Advances to Staff	12	7423624.03
			Advances to Contractors/Suppliers		63866.00
			Security Deposits		105000.00
			Advance Compensation		153952727.23

13541732525 03

13541732525 03

COMPILED FROM THE BOOKS OF ACCOUNTS AND OTHER RECORDS
PRODUCED BEFORE US FOR OUR VERIFICATION
For SAHNI BANSAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants

DATED 01-11-2003
PLACE GHAZIABAD

(PARDEEP S. SAHNI)
F.C.A.

ACCOUNTANT
G.D.A.

ACCOUNTS OFFICER
G.D.A.

FINANCE CONTROLLER
G.D.A.

SECRETARY
G.D.A.

VICE CHAIRMAN
G.D.A.

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

DEPOSITS AGAINST PROPERTIES AS ON 31-03-2002

Registration Money/Allottement Money

Balance as on 31-03-01	1856761461.00
Add: Received during the year	23140315.20
Less: Refunded during the year	106043097.36
Less : Adjustement during the year	1625614888.26

	148243790.58



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

EXPENSES PAYABLE AS ON 31-03-2002

Salary & Wages payable	4313447.00
Electricity Expenses payable	31922.00
Telephone Expenses payable	71870.00
Audit Fees payable	2051840.00
PF/GPF payable	420809.00
L.S./Pensionary Contribution payable	817768.00
GIS payable	12111.00
TDS payable	626094.00
Trade Tax payable	313916.00

8659777.00



120 GAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2002

EXPENDITURES	SCHEDULE	AMOUNT (RS.)	INCOME	SCHEDULE	AMOUNT (RS.)
TO DEVELOPMENT & MAINTENANCE	13	954727147.93	BY DEVELOPMENT CHARGES AND LEVIES		
TO ESTABLISHMENT EXP.	14	99636393.94	- Betterment Charges		1088731.0
TO ADMINISTRATION EXP.	15	41613269.54	- Coumpounding Charges		60638800.0
TO INTEREST ON LOAN	16	253209858.00	- Malwa/Staking Charges		7119207.5
TO INTEREST ON REFUND		18863502.87	- Development Charges		58520655.2
TO DEPRECIATION		1362250.91	- Plan Sanction Charges		1881183.0
TO OTHER EXPENSES	17	19583144.16	- Surveyors License Fee		142850.0
			- Levy for Non-Construction		2520990.0
			- Water Charges		3184182.0
			- Supervision Charges		5190997.0
			- Completion Charges		15974273.0
			BY INCOME FROM PRPPERTIES		
			- Lease Rent		13207957.0
			- Building Rent		1350308.0
			- Shop Rent		2789781.0
			- Other Rent		475384.0
			- Transfer Charges		897420.0
			- Freehold Charges		8322767.0
			- Land Use Change Charges		37297454.0
			- Chowkidar Fees		2478072.0
			BY INTEREST INCOME		
			- Interest on Instalment		6198435.0
			- Interest on FDR's		40096675.0
			- Interest on Saving Bank A/C		1442271.0
			- Interest on Loans to Staff		
			BY OTHER INCOME		
			- Sale of Forms/Brochers/Master Plan		781100.0
			- Registration Fees from Contractors		326250.0
			- Recoveries	18	26484203.0
			- Penalty		792474.0
			- Other Income		13286142.0
			- Income from Stamp Duty		39835917.0
			BY EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURES		
			INCOME		
					1036671084.0

1388995567.35

COMPILED FROM THE BOOKS OF ACCOUNTS AND OTHER RECORDS
PRODUCED BEFORE US FOR OUR VERIFICATION
For SAHNI BANSAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants

(PARDEEP S. SAHNI)
F.C.A.

DATED 01-11-2003
PLACE GHAZIABAD

ACCOUNTANT
G.D.A.

SECRETARY
G.D.A.

ACCOUNTS OFFICER
G.D.A.

VICE CHAIRMAN
G.D.A.

FINANCE CONTROLLER
G.D.A.

1388995567

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

SECURED LOANS AS ON 31-03-2002

BALANCE AS
ON 31-03-2002

PNB HOUSING FINANCE LTD.	85478488.00
HUDCO	1751259970.00
LIC HOUSING FINANCE LTD.	126325738.00
HDFC BANK LTD.	20326131.00

1983390327.00



109
124

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

UNSECURED LOANS AS ON 31-03-2002

LOAN FROM STATE GOVERNMENT

- LOAN NO 1007/UD	15610 00
- LOAN NO 1053-9AABUDJET/98	185010000 00
- LOAN NO 109	5625000 00
- LOAN NO 1111 LAD/78	120000 00
- LOAN NO 1154 LIGH/80	172928 00
- LOAN NO 1154	43232 00
- LOAN NO 1226 37 U D /73	6657 00
- LOAN NO 1238 37 LAD/84	14810 00
- LOAN NO 1304 9A/LOW/95	40000000 00
- LOAN NO 1308 9A/NCR/96	15000000 00
- LOAN NO 1518 LAD/79	48000 00
- LOAN NO 1522 9 ABUDGET/2000	254205600 00
- LOAN NO 1519 3761C/82	640000 00
- LOAN NO 1519 3761C/82	160000 00
- LOAN NO 1555 LAD/82	192000 00
- LOAN NO 1555 LAD/82	48000 00
- LOAN NO 1551 LAD/82	800000 00
- LOAN NO 1551	200000 00
- LOAN NO 1524 37 LAW/83	888384 00
- LOAN NO 1524	222096 00
- LOAN NO 1525 37 LOW/83	264192 00
- LOAN NO 1525	66048 00
- LOAN NO 2074 LOW/80	160000 00
- LOAN NO 2074	40000 00
- LOAN NO 2403 37 LOW/80	144896 00
- LOAN NO 2403	37224 00
- LOAN NO 2404 37 LOW	6777 90
- LOAN NO 277 37 LAD/84	1152000 00
- LOAN NO 277	288000 00
- LOAN NO 303 LAF/83	336000 00
- LOAN NO 303	84000 00
- LOAN NO 3091	595555.71
- LOAN NO 3091 LOW/86	148888.97
- LOAN NO 3906	6985000 00
- LOAN NO 3929/EWS/84	868979 00
- LOAN NO 3929	213945 00
- LOAN NO 400 LAD/70	128000 00
- LOAN NO 417 37 U D /72	30000 00
- LOAN NO 4367 A/EWS/84	1142784 00
- LOAN NO 4367	285696 00
- LOAN NO 4459	9982 00
- LOAN NO 4615 UD/71	7513 00
- LOAN NO 467/37/U D /72	6657 00
- LOAN NO 473/37/LAW/77	24000 00
- LOAN NO 4810/37ALD /75	80000 00
- LOAN NO 481/37/LIGH/79	777600 00
- LOAN NO 481	194400 00
- LOAN NO 5320/LOW	56296 80
- LOAN NO 5320	225187 20
- LOAN NO 5427/37MIGH/77	26400 00
- LOAN NO 5716/LIGH/80	945152 00
- LOAN NO 5716	236288 00
- LOAN NO 592/37/LOW	82836 00
- LOAN NO 592	20704 00
- LOAN NO 6012/EWS/83	1301583 36
- LOAN NO 6012	325395 84
- LOAN NO 6037/UD	32000 00
- LOAN NO 60	8000 00
- LOAN NO 6219/37/LAD/80	256000 00
- LOAN NO 6219	64000 00
- LOAN NO 736/LAD/79	32000 00
- LOAN NO 900	512000 00
- LOAN NO 963/UD/73	4631 00
- LOAN NO HUDCO)	208100000 00

729718929 78

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY**DEPOSITS AGAINST WORKS AS ON 31-03-2002****Security From Contractor**

Balance as on 31-03-2001	25860774.54
Add: Security deducted during the year 2001-02	4859246.00
Less: Adjustment/Refunded during the year 2001-02	5103935.00
TOTAL	----- 25616085.54
Withheld Amount	581381.00
GROSS TOTAL	----- 26197466.54 -----



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

FIXED ASSETS AS ON 31-03-2002

S. NO.	PARTICULARS	W.D.V. AS ON 01-04-01	ADDITIONS DURING THE YEAR	SOLD DURING THE YEAR	TOTAL AS ON 31-03-02	DEPRECIATION FOR THE YEAR	W.D.V. AS ON 31-03-02
1	LAND & BUILDING	473809838.00	0.00	0.00	473809838.00	0.00	473809838.00
2	VEHICLES	579527.00	1817408.81	0.00	2396935.81	479387.16	1917548.65
3	OFFICE/MACHINICAL EQUIPMENTS & OTHER MACHINERY	3423545.00	0.00	0.00	3423545.00	855886.25	2567658.75
4	COMPUTERS	0.00	89925.00	0.00	89925.00	26977.50	62947.50
5	FURNITURE & FIXTURES	0.00	194078.00	0.00	194078.00	9703.90	184374.10
TOTAL		477812910.00	1907333.81	0.00	479720243.81	1362250.91	478542367.00



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

INVESTMENT AS ON 31-03-2002

FDR'S WITH BANKS

With Allahabad Bank

- FDR NO. 625601	3625308.00	
- FDR NO. 227977	<u>3757573.00</u>	7382881.00

With Corporation Bank

- FDR NO. 18219	280102.00	280102.00
-----------------	-----------	-----------

With Oriental Bank of Commerce

- FDR NO. 188490	5563707.00	
- FDR NO. 169/90	1433843.00	
- FDR NO. 235/90	3271500.00	
- FDR NO. 322/90	1616430.00	
- FDR NO. 346/90	2202388.00	
- FDR NO. 348/90	2172566.00	
- FDR NO. 434/90	1211573.00	
- FDR NO. 299254/2211 RAJAPUR	8002862.00	
- FDR NO. 3145 RAJAPUR	<u>1476783.70</u>	26951652.70

With State Bank of Patiala

- FDR NO. 360494	3900000.00	3900000.00
------------------	------------	------------

With Viya Bank

- FDR NO. VSY 169507	19149596.00	
- FDR NO. VSY 210675	16132401.00	
- FDR NO. VSY 210759	22576773.00	
- FDR NO. VSY 210998	40000000.00	
- FDR NO. VSY 211226	25800000.00	
- FDR NO. VSY 211027	19742838.00	
- FDR NO. VSY 211043	30000000.00	
- FDR NO. VSY 980063	1424500.00	
- FDR NO. VSY 980064	<u>4548424.00</u>	179374532.00

With Punjab National Bank

- FDR NO. 741691 IN PNB	10512363.00	10512363.00
		1650679.00

With The Nantial Bank Ltd.

230052209.70

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE-8

CLOSING STOCKS AS ON 31-03-2002
(AS VALUED & CERTIFIED BY THE MANAGEMENT)

S.NO	PARTICULARS	AMOUNT(RS.)
1	PLOTS/FLATS	5860914399.75
2	UNDEVELOPED LAND	1908840000.00
3	STORES IN HAND	4851374.00
4	WORK IN PROCESS	387700453.02
TOTAL		8162306226.77

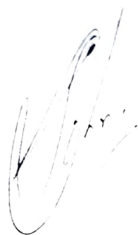


127
GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

OTHER RECEIVABLE AS ON 31-03-2002

1	Rent Receivable	2701976.00
2	Stamp Duty Receivable	49351017.00

52052993.00



128

AMOUNT (RS.)

52628324.80

SB-0674-0-000-007603 4045898.72
48582426.08

6309455 49

01100/025484	931221 08
01100/025952	384547 22
01100/025951	148480 88
C & I 14	466785 80
PLA A/C NO 8448022	1351184 00
01100/028024	250171 53
1100031494	2777064 98

744319 31

58971 (SB-11004)	30250.16
508010058947 (11001)	687073.83
508010058955 (11002)	6896.24
508010058963 (11003)	20099.08

5780699.72

SB-66 5194002 59

SB-66	5194002 59
SB-1968	163622.50
CA-14143	99055.00
CA-990156	165103.90
CA-15999	2150.00
CA-16006	8580.00
CA-770156	21040.00
CA-13678	7445.00
CA-15964	18120.00
CA-15981	6360.00
CA-709	4315.30
CA-763	67.15
CA-770	588.40
CA-836	24.80
CA-837	1887.40
CA-838	544.95
CA-839	20.05
CA-840	3202.85
CA-842	4.15
CA-843	465.40
CA-858	353.00
SB-4394	<u>83747.26</u>

92895.58

1000007860	92895.58
------------	----------

140680.00

18759	140680.00
-------	-----------

29713506 21

60002	162785220.20
-------	--------------

60002	44938.42
60020	

60020	
60021	59865.00

60021	
60022	14097725.27

60023 -213800824.06

60025	23827.00
-------	----------

60026	-224106.20
-------	------------

60027	2612.00
-------	---------

60028	132439.00
-------	-----------

60029	508200.00
-------	-----------

60030	62739304.00
-------	-------------

60032	219004.00
	2185331.58

VC-GDA 3125301.58

462572.36

SB-107953 462572.36

95872453.47

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY
HOUSING ADVANCES TO STAFF AS ON 31-03-2002

Balance as on 31-03-01

776403.58

Add: Adjustment for last year

3178281.42

Add: Advance given during the year 2001-02

104200.00

Less: Adjusted during the year 2001-02

1012725.00

3046160.00



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY**OTHER ADVANCES TO STAFF AS ON 31-03-2002****Permanent Imprest**

Balance as on 31-03-01	279277.00
Add: Advance given during the year 2001-02	643500.00
Less: Adjusted during the year 2001-02	504084.00

	418693.00

Temporary Advance

Balance as on 31-03-01	5750432.86
Add: Advance given during the year 2001-02	6744614.84
Less: Adjusted during the year 2001-02	5490116.67

	7004931.03

GRAND TOTAL	7423624.03



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY**OTHER ADVANCES TO STAFF AS ON 31-03-2002****Permanent Imprest**

Balance as on 31-03-01	279277.00
Add: Advance given during the year 2001-02	643500.00
Less: Adjusted during the year 2001-02	504084.00

	418693.00

Temporary Advance

Balance as on 31-03-01	5750432.86
Add: Advance given during the year 2001-02	6744614.84
Less: Adjusted during the year 2001-02	5490116.67

	7004931.03

GRAND TOTAL	7423624.03



1009
131

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

ADVANCES TO SUPPLIERS /CONTRACTORS AS ON 31-03-2002

Balance as on 31-03-2001

18949072.00

Add: Advance given during the year 2001-02

0.00

- Contractor

134900.00

134900.00

- Suppliers

Less: Adjusted during the year 2001-02

19020106.00

63866.00



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

ESTABLISHMENT EXPENSES AS ON 31-03-2002

SALARY	94750720.20
PENSION P.F. CONTRIBUTION	1273168.00
CPF CONTRIBUTION	128920.35
MEDICAL	592602.39
HONORARIUM	56912.00
BONUS	1063277.00
LEAVE ENCASHMENT	518845.00
ALLOWANCES	853683.00
TRAINING & DEVELOPMENT	398266.00

99636393.94



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

ADMINISTRATION EXPENSES AS ON 31-03-2002

REPAIRING		1875557.59
DIESEAL, PETROL & OTHER OIL		5087481.72
STATIONERY	1680608.65	
PRINTING EXPENSES	<u>1737581.00</u>	
	3418189.65	
	<u>666788.62</u>	
LESS: CLOSING STOCK		2751401.03
UNIFORM		454962.00
TELEPHONE		1759064.14
ELECTRICITY		83123.00
POSTAGE		490573.00
AUDIT FEES		2000000.00
LIBRARY, MAGZINE & NEWS PAPER		8195.00
EXPENSES ON V.C. DISCRETION		3300.00
SPORTS		31500.00
TRAVELLING ALLOWANCE		1201517.85
COMPUTER SOFTWARE		88387.00
AVAS BANDHU U.P.		2000000.00

REPAIR & MAINTENANCE

-TYPE MACHINE & DUPLICATE MACHINE MAINT.	172950.00	
-OFFICE BUILDING REPAIR & MAINTENANCE	3060065.18	
-RESIDENTIAL BUILDING REPAIR & MAINTENANCE	1714007.00	
-ELECTRIC MAINTENANCE	8005375.80	
-COMPUTER MAINTENANCE	315610.80	
-PARK MAINTENANCE	2389436.24	
-MAINTENANCE OF AUTHORITY AREA COLONY	<u>3084133.09</u>	
		18741578.11
		243766.00
		1683119.22
		3109743.88
DRAINAGE		
SEWERAGE		
WATER SUPPLY		

41613269.54



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

INTEREST ON LOAN AS ON 31-03-2002

INTEREST TO PNB HOUSING FINANCE LTD.	13676266.00
INTEREST TO HUDCO	214376740.00
INTEREST TO LIC HOUSING FINANCE LTD.	20606871.00
INTEREST TO HDFC BANK LTD.	4043681.00
INTEREST TO UCO BANK	506300.00

253209858.00



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

OTHER EXPENSES AS ON 31-03-2002

LEGAL EXPENSES	6408094 00
ADVERTISMENT	6880495 00
ENTERTAINMENT	338526 00
MISCELLANEOUS EXPENSES	1516834 16
AUDIT FEES	48000 00
PUBLICITY OF SCHEME	4391195 00

19583144 16



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

DEVELOPMENT AND MAINTENANCE EXPENSES AS ON 31-03-2002

OPENING STOCK OF WORK IN PROCESS		929856788.00
ROADS & BRIDGES		74594279.24
WATER SUPPLY		55721736.05
DRAINAGE		92125880.81
RAIN WATER DRAINAGE		29016662.00
SPORTS GROUNDS		777947.99
ELECTRIFICATION		24261123.78
HORTICULTURE		1031226.20
PLANTATION		1055871.30
GREEN BELT & PARKS		1216657.00
ENTERTAINMENT PLACES DEVELOPMENT		70500.34
COLONY HANDOVER CHARGES		22172000.00
CONSTRUCTION WORKS :-		
HIG (HP)		18219233.41
MIG (HP)		1768525.00
LIG (HP)		170000.00
EWS (HP)		2793498.99
HIG (SELF FINANCE)		8165409.00
MIG (SELF FINANCE)		5899184.00
LIG (SELF FINANCE)		2537114.00
EWS (SELF FINANCE)		1424855.00
COMMERCIAL CENTER & SHOP		791503.00
KIOSK		11972.00
OTHER CONSTRUCTION		1272990.00
OPENING STOCK	4939742.00	
CEMENT	17730033.00	
STEEL	6204576.92	
OTHER STORES	22586245.92	
JAL NIGAM	2000000.00	
OTHER DEPARTMENT	18863420.00	
	72324017.84	
	4851374.00	
LESS: CLOSING STOCK		67472643.84
		1342427600.95
		387700453.02
LESS: CLOSING STOCK OF WORK IN PROCESS		954727147.93



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

INTEREST RECD. DURING THE YEAR 2001-02

Interest on Saving Accounts

-From State Bank of India	8371.18	
-From Oriental Bank of Commerce	765264.00	
-From Vijaya Bank	668636.00	
	-----	1442271.18

Interest on FDRS

-From Corporation Bank	3391.00	
-From Allahabad Bank	274874.00	
-From The Vysya Banl Ltd.	468845.00	
-From Punjab Nation Bank	624970.00	
-From Oriental Bank of Commerce	975894.00	
-From Vijaya Bank	37748701.00	
	-----	40096675.00

41538946.18



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

RECOVERIES DURING THE YEAR 2001-02

-FROM DEDUCTION FOR CEMENT	21782477.00
-FROM DEDUCTION FOR STEELS	4180690.00
-FROM OTHER DEDUCTION	273922.60
-FROM DEDUCTION FOR G.I. PIPES	247114.00

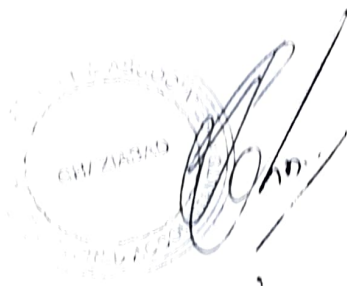
26484203.60



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

CAPITAL FUND AS ON 31-03-2002

Balances as on 31-03-2001	215778954 22
Add Adjustment during the year	<u>11466414364 29</u>
	11682193318 51
Less Excess of Expenditures over Income	1036671084 38
	<u>10645522234 13</u>



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2003

EXPENDITURES	SCHEDULE	AMOUNT (RS.)	INCOME	SCHEDULE	AMOUNT (RS.)
DEVELOPMENT & MAINT. EXP	14	547077411.04	BY DEVELOPMENT CHARGES AND LEVIES		
ESTABLISHMENT EXP	15	89292301.84	- Betterment Charges		645593.00
ADMINISTRATION EXP	16	48132146.11	- Compounding Charges		45394029.43
INTEREST ON LOANS	17	261040145.56	- Malwa/Staking Charges		9392239.00
DEPRECIATION		2323670.08	- Development Charges		54725109.00
OTHER EXPENSES	18	29470444.69	- Plan Sanction Charges		3412257.00
			- Surveyors Licence Fee		76589.00
			- Levy for Non-Construction		3100752.00
			- Water & Maintenance Charges		36960693.66
			- Completion Charges		67236919.07
			BY INCOME FROM PROPERTIES		
			- Lease Rent		39114630.00
			- Building Rent		5401155.50
			- Shop Rent		7496223.00
			- Other Rent		5345641.00
			- Transfer Charges		6473603.00
			- Freehold Charges		16850032.00
			- Land Use Change Charges		11665661.00
			- Deduction on Refund		8436940.00
			BY INTEREST INCOME		
			- Interest on Instalment		109801118.00
			- Penal Interest		11709146.79
			- Interest on FDR's		15225376.66
			- Interest on Saving Bank A/C		2516320.37
			- Interest on Loans to Staff		169606.00
			BY OTHER INCOME		
			- Sale of Forms/Brochures/Master Plan		3554831.00
			- Recoveries	19	20956606.00
			- Penalty		5431348.66
			- Other Income		230872902.63
			- Income from Stamp Duty		90379238.00
			BY EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURES		
			<i>Expenditure</i>		
			<i>Income</i>		
			164971558.55		
TOTAL		977336119.32	TOTAL		977336119.32

AS PER SEPERATE REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

For **SAHNI BANSAL & ASSOCIATES**
Chartered Accountants

(**PARDEEP S. SAHNI**)
F.C.A.

ACCOUNTANT
G.D.A.

SECRETARY
G.D.A.

ACCOUNTS OFFICER
G.D.A.

FINANCE CONTROLLER
G.D.A.

VICE CHAIRMAN
G.D.A.

149

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE-1

AMOUNT(RS)

CAPITAL FUND AS ON 31-03-2003

Balance as on 31-03-2002 10645522234.13

Less : Excess of Expenditures over Income 164971558.55

TOTAL

10480550675.58



143 HAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

GOVERNMENT LOANS AS ON 31-03-2003

SCHEDULE-3
AMOUNT(RS.)

LOANS FROM STATE GOVERNMENT

- LOAN NO. 1007/UD	13380.00
- LOAN NO. 1053-9AABUDJET/98	213686550.00
- LOAN NO. 109	3750000.00
- LOAN NO. 1111/LAD/7B	60000.00
- LOAN NO. 1154/LIGH/80	148224.00
- LOAN NO. 1154	37056.00
- LOAN NO. 1238/37 LAD/84	12680.00
- LOAN NO. 1304/9A/LOW/95	45800000.00
- LOAN NO. 1308/9A/NCR/96	7500000.00
- LOAN NO. 1518/LAD/79	24000.00
- LOAN NO. 1522/9 ABUDGET/2000	245692327.00
- LOAN NO. 1819/3761C/82	512000.00
- LOAN NO. 1819/3761C/82	128000.00
- LOAN NO. 1865/LAD/82	160000.00
- LOAN NO. 1865/LAD/82	40000.00
- LOAN NO. 1891/LAD/82	640000.00
- LOAN NO. 1891	160000.00
- LOAN NO. 1924/37 LAW/83	740320.00
- LOAN NO. 1924	185080.00
- LOAN NO. 1925/37 LOW/83	220160.00
- LOAN NO. 1925	55040.00
- LOAN NO. 2074/LOW/80	128000.00
- LOAN NO. 2074	32000.00
- LOAN NO. 2403/37 LOW/80	120080.00
- LOAN NO. 2403	31020.00
- LOAN NO. 2404/37 LOW	5638.90
- LOAN NO. 277/37 LAD/84	1008000.00
- LOAN NO. 277	252000.00
- LOAN NO. 303/LAF/83	288000.00
- LOAN NO. 303	72000.00
- LOAN NO. 3091	541414.26
- LOAN NO. 3091 LOW/86	135353.61
- LOAN NO. 3906	7997825.00
- LOAN NO. 3929/EWS/84	740979.00
- LOAN NO. 3929	181945.00
- LOAN NO. 400/LAD/70	96000.00
- LOAN NO. 417/37U.D./72	25000.00
- LOAN NO. 4367/A/EWS/84	1015808.00
- LOAN NO. 4367	253952.00
- LOAN NO. 4469	6648.00
- LOAN NO. 481/37/LIGH/79	518400.00
- LOAN NO. 481	129600.00
- LOAN NO. 5320/LOW	50041.60
- LOAN NO. 5320	200166.40
- LOAN NO. 5716/LIGH/80	708864.00
- LOAN NO. 5716	177216.00
- LOAN NO. 592/37/LOW	74554.40
- LOAN NO. 592	18633.60
- LOAN NO. 6012/EWS/83	1115642.88
- LOAN NO. 6012	278910.72
- LOAN NO. 60/37/UD	16000.00
- LOAN NO. 60	4000.00
- LOAN NO. 6219/37/LAD/80	192000.00
- LOAN NO. 6219	48000.00
- LOAN NO. 736/LAD/79	16000.00
- LOAN NO. 900	384000.00
- LOAN NO. 963/UD/73	3084.00
- LOAN (HUDCO)	208100000.00

TOTAL

744531594.37

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

SECURED LOANS AS ON 31-03-2003

SCHEDULE-2

S.NO. NAME OF THE INSTITUTION

BALANCE AS
ON 31-03-2003

RS.

- 1 PNB HOUSING FINANCE LTD.
- 2 HUDCO

12346107.00
52022.00

TOTAL

12398129.00



145

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE-4 AMOUNT(RS.)

DEPOSITS AGAINST WORKS AS ON 31-03-2003

Security From Contractor

Balance as on 31-03-2002

25616085.54

Add: Security deducted during the year 2002-03

4860576.37

Less: Adjustment/Refunded during the year 2002-03

6906043.00

TOTAL

23570618.91



148

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE-5

DEPOSITS AGAINST PROPERTIES AS ON 31-03-2003

AMOUNT(RS)

Registration Money/Allotment Money

Balance as on 31-03-02	148243790.58
Add: Received during the year	127622783.00
Less: Refunded during the year	160924477.58

TOTAL

114942096.00



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE-6 AMOUNT(RS)

EXPENSES PAYABLE AS ON 31-03-2003

Salary & Wages payable	4542621.00
Electricity Expenses payable	45379.00
Telephone Expenses payable	85990.00
Audit Fees payable	129600.00
PF/GPF payable	428614.00
L.S./Pensionary Contribution payable	288789.00
GIS payable	12106.00
TDS payable	2993336.00
Trade Tax payable	48787.00

TOTAL

8575222.00



SCHEDULE OF FIXED ASSETS AND DEPRECIATION THEREON AS ON 31-03-2003

S. NO.	PARTICULARS	W.D.V. AS	ADDITIONS	DATE OF	SOLD	TOTAL AS	DEPRECIATION	W.D.V. AS
		ON 01-04-02	DURING	PUT TO	DURING	ON 31-03-03	FOR THE	ON 31-03-03
		RS.	THE YEAR	USE	THE YEAR	RS.	YEAR	RS.
AS PER SHEETS ATTACHED								
1	BLOCK - 0%	473809838.00	0.00		0.00	473809838.00	0.00	473809838.00
2	BLOCK - 10%	184374.10	656721.00		0.00	841095.10	69944.36	771150.74
3	BLOCK - 20%	1917548.65	1703971.00		0.00	3621519.65	724303.93	2897215.72
4	BLOCK - 25%	2567658.75	1315975.00		0.00	3883633.75	861603.19	3022030.56
5	BLOCK - 50%	62947.50	1372881.00		0.00	1435828.50	667818.60	768009.90
TOTAL		478542367.00	5049548.00		0.00	483591915.00	2323670.08	481268244.92



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE-8

CLOSING STOCKS AS ON 31-03-2003
(AS VALUED & CERTIFIED BY THE MANAGEMENT)

S.NO.	PARTICULARS	AMOUNT(RS.)
1	PLOTS/FLATS	5553915522.75
2	UNDEVELOPED LAND	1908840000.00
3	STORES IN HAND	2715627.01
4	WORK IN PROCESS	348113923.00
TOTAL		7813585072.76



148 150

HAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

OTHER RECEIVABLE AS ON 31-03-2003		SCHEDULE-9 AMOUNT(RS)
1	Rent Receivable	1938476 00
2	Stamp Duty Receivable	94357170 00
TOTAL		96295646 00



HAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

BANK BALANCES AS ON 31-03-2003

SCHEDULE-10

WITH PUNJAB NATIONAL BANK
KALUSHAMBI
NAVYUG MARKET, HAZIABAD

ACCOUNT NO

AMOUNT (RS.)

SB-2670 726944.55
SB 0674 0 000 007603 175024.55 9029293.90

WITH STATE BANK OF INDIA
MODI NAGAR
MODI NAGAR
MODI NAGAR
NAVYUG MARKET, HAZIABAD
RAJ NAGAR, HAZIABAD
RAJ NAGAR, HAZIABAD
RAJ NAGAR, HAZIABAD
RAJ NAGAR, HAZIABAD

01100/025484 262542.40
01100/025952 450130.90
01100/025951 154479.55
C & I 14 485544.59
PLA A/C NO 8448022 1437513.50
01100/028024 261273.47
1100031494 101331.72
0122/031494 101331.72 4.53926.47

WITH THE VYSYA BANK LTD
HAZIABAD

508010058947 (11001) 754511.44 754511.44

WITH ORIENTAL BANK OF COMMERCE

LOHIA NAGAR, HAZIABAD SB-66 250173.19
LOHIA NAGAR, HAZIABAD CA-14143 99115.00
LOHIA NAGAR, HAZIABAD CA-990156 165113.90
LOHIA NAGAR, HAZIABAD CA-15999 3110.00
LOHIA NAGAR, HAZIABAD CA-16006 441.00
LOHIA NAGAR, HAZIABAD CA-15964 1314.00
LOHIA NAGAR, HAZIABAD CA-15981 6110.00
LOHIA NAGAR, HAZIABAD CA-709 4110.30
RAJAPUR, HAZIABAD CA 770 424.40
RAJAPUR, HAZIABAD CA 837 1751.40
RAJAPUR, HAZIABAD CA-838 434.95
RAJAPUR, HAZIABAD CA 839 711.00
RAJAPUR, HAZIABAD CA-840 1230.85
RAJAPUR, HAZIABAD CA-843 145.40
RAJAPUR, HAZIABAD CA-858 330.00
RAJAPUR, HAZIABAD SB-4394 67131.28 724785.57

WITH VIJAYA BANK

HAZIABAD 12993 264392.00
HAZIABAD 60002 329137.00
HAZIABAD 60020 46553.42
HAZIABAD 60021 871753.00
HAZIABAD 60022 14572739.27
HAZIABAD 60023 920037.57
HAZIABAD 60025 24759.00
HAZIABAD 60026 91153332.20
HAZIABAD 60027 2710.00
HAZIABAD 60028 137139.00
HAZIABAD 60029 612604.00
HAZIABAD 60030 705440.00
HAZIABAD 60032 1601125.51
HAZIABAD 60033 1715132.20
HAZIABAD 60034 160791.00
HAZIABAD 60035 255524.00
HAZIABAD 60036 193094.00
HAZIABAD 60037 22149763.00
HAZIABAD 60039 173365.00
HAZIABAD 60040 105565280.39
HAZIABAD 60041 9583343.58
HAZIABAD E-1 23411974.03 82132978.07

WITH ALLAHABAD BANK
NAVYUG MARKET, HAZIABAD

SB-107953

471823.36 471823.36

52089131.00

149949609.81

WITH HDFC BANK LTD

TOTAL

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE-11 AMOUNT(RS.)

FDR'S WITH BANKS AS ON 31-03-2003

With Oriental Bank of Commerce

- FDR NO. 272046	105518.00	
- FDR NO. 272108	2251271.00	
- FDR NO. 74477	1297914.00	
- FDR NO. 74485	1790567.00	
- FDR NO. 74493	3454190.00	
- FDR NO. 74507	1935801.00	
- FDR NO. 74523	2563678.00	
- FDR NO. 2103	4000000.00	
- FDR NO. 299254/2211 RAJAPUR	9014166.00	
- FDR NO. 3145 RAJAPUR	<u>1476783.70</u>	27889888.70

With Vijaya Bank

- FDR NO. VSY 210447		
- FDR NO. VSY 210665		
- FDR NO. VSY 210759		
- FDR NO. VSY 211027		
- FDR NO. VSY 980063	1424500.00	
- FDR NO. VSY 980064	<u>4548424.00</u>	5972924.00

With VYSYA Bank Ltd.

- FDR NO. 508092114066	
------------------------	--

TOTAL

33862812.70



150
152

15B

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

HOUSING ADVANCE TO STAFF AS ON 31-03-2003

Balance as on 31-03-02

Add: Interest on Loan

Less: Adjusted during the year 2002-03

TOTAL

SCHEDULE-12
AMOUNT(RS.)

3046160.00

169606.00

135087.00

3080679.00



154

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE-13
AMOUNT(RS.)

OTHER ADVANCES TO STAFF AS ON 31-03-2003

Permanent Imprest

Balance as on 31-03-02	418693.00
Add: Advance given during the year 2002-03	443307.00
Less: Adjusted during the year 2002-03	292000.00
TOTAL	570000.00

Temporary Advance

Balance as on 31-03-02	7004931.03
Add: Advance given during the year 2002-03	13111394.67
Less: Adjusted during the year 2002-03	15957947.56
TOTAL	4158378.14
GRAND TOTAL	4728378.14



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE-14

DEVELOPMENT & MAINTENANCE EXPENSES AS ON 31-03-2003

AMOUNT(RS)

OPENING STOCK OF WORK IN PROCESS	387700453.02
ROADS & BRIDGES	111991478.46
WATER SUPPLY	231244897.80
SEWERAGE	30751691.33
RAINAGE	8839552.24
SPORTS GROUNDS	176332.50
ELECTRIFICATION	19839327.85
HORTICULTURE	6177056.75
PLANTATION	3910344.00
GREEN BELT & PARKS	553020.00
CONT. TOWARDS VAMBAY	20000000.00
CONSTRUCTION WORKS :-	
HIG (HP)	22161016.00
LIG (HP)	692274.00
EWS (HP)	2167228.00
HIG (SELF FINANCE)	5205959.00
MIG	1270716.00
LIG (SELF FINANCE)	1752097.00
EWS (SELF FINANCE)	470144.00
COMMERCIAL CENTER & SHOP	198831.00
OTHER CONSTRUCTION	2914393.00
OPENING STOCK OF STORES	4851374.00
CEMENT	12197884.00
STEELS	7679156.10
G.I. PIPES ETC.	2918487.00
OTHER STORES	12243248.00
	39890149.10
LESS: CLOSING STOCK OF STORES	2715627.01
	37174522.09
LESS: CLOSING STOCK OF WORK IN PROCESS	895191334.04
	348113923.00
TOTAL	547077411.04



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

156

SCHEDULE-15 AMOUNT(RS.)

ESTABLISHMENT EXPENSES AS ON 31-03-2003

SALARY	81561603.80
P.F. CONTRIBUTION	137718.60
CPF/GPF CONTRIBUTION	2480139.93
MEDICAL	1239574.51
BONUS	2197313.00
LEAVE ENCASHMENT	250857.00
SPORTS DEVELOPMENT	43541.00
TRAINING & WORK SHOP	1381554.00

TOTAL

89292301.84



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

ADMINISTRATION EXPENSES AS ON 31-03-2003

SCHEDULE-16 AMOUNT(RS.)

DIESEL , PETROL & OTHER OILS		8500658 70
STATIONERY	2571313 82	
PRINTING EXPENSES	2583194 40	
ADD. OPENING STOCK	666788 62	
LESS. CLOSING STOCK	<u>1010684 38</u>	4810612 46
UNIFORM		705736 00
TELEPHONE		1774141 21
ELECTRICITY		240176 00
POSTAGE		602620 90
LIBRARY , MAGAZINE & NEWS PAPER		41693 85
EXPENSES ON V.C. DISCRETION		15375 00
SPORTS		49560 00
TRAVELLING ALLOWANCE		1592003 65
COMPUTER CONSUMABLES & EXPENSES		552419 00
AVAS BANDHU U.P.		1000000 00

REPAIR & MAINTENANCE

-OFFICE BUILDING-REPAIR & MAINTENANCE	6191221 39	
-RESIDENTIAL BUILDING-REPAIR & MAINTENANCE	1059295 00	
-OTHER BUILDING-REPAIR & MAINTENANCE	1543538 50	
-ELECTRIC MAINTENANCE	3592175 28	
-COMPUTER MAINTENANCE	896974 00	
-PARK MAINTENANCE	1988096 22	
-MAINTENANCE OF AUTHORITY AREA COLONY	<u>4386495 45</u>	19657795 84
		146937 00
		2803808 76
		5638607 74
DRAINAGE		
SEWERAGE		
WATER SUPPLY		

TOTAL

48132146 11



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE-17

INTEREST ON LOANS AS ON 31-03-2003

AMOUNT(RS.)

INTEREST ON GOVT. LOANS

76406163.59

INTEREST TO FINANCIAL INSTITUTIONS

165543215.00

OTHER INTEREST PAID

19090766.97

TOTAL

261040145.56

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized loops and a long horizontal stroke at the end.

HAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE-18

OTHER EXPENSES AS ON 31-03-2003

AMOUNT(RS.)

LEGAL EXPENSES	6319971.85
ADVERTISEMENT	3542685.00
ENTERTAINMENT	633091.00
FUNCTION, INAUGURATION & WELCOME/FAREWELL	1282170.00
MISCELLENEOUS EXPENSES	2286173.19
PUBLICITY OF SCHEME	13671141.00
AUDIT FEES	77760.00
BANK CHARGES	1291187.65
TRADE TAX ON SALE OF FORMS	366260.00

TOTAL

29470444.69



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE-19

RECOVERIES DURING THE YEAR 2002-03

AMOUNT(RS.)

-FROM DEDUCTION FOR CEMENT

12860462.00

-FROM DEDUCTION FOR STEELS

4296526.00

-FROM DEDUCTION FOR G.I. PIPES

3799618.00

TOTAL

20956606.00

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

(CS) 161

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY
GHAZIABAD(U.P.)
(F.Y.2002-03)

Schedule-"20"

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES:

i) BASIS OF ACCOUNTING:

- A. The Financial statements are prepared under the historical cost convention following accrual system of accounting and as per the generally accepted accounting principles & Accounting Standards as issued by Institute of Chartered Accountants of India unless otherwise stated.
- B. Accounting Policies are consistent with generally accepted accounting principles except where-ever stated otherwise.

C. FIXED ASSETS:-

All Fixed Assets are shown at Historical cost Less Depreciation thereon.

The Depreciation on the fixed assets have been provided as per Income Tax Rules.

D. INVENTORIES:-

Inventories are valued as under:-

- i. Building Materials, Stores & Consumables are valued at lower of cost or net realizable value.
- ii. Unsold plots, Shops, Flats/Houses, Undeveloped land & work-in- process & other properties in inventories are valued at Cost.

E. GRANT IN AID:-

Government Grants/Subsidies are recognized only on receipt through Government Order & Compliance to the conditions attached thereto.

F. COMPENSATION ON LAND ACQUISITION

The amount of compensation paid (Part Payment) as per the orders of Court & the cases which are still Pending with higher Court, have been treated as Advance Compensation. Since the same have not been acknowledged as Debts.

G. REVENUE RECOGNITION:-

- i. Sale of land/Plots/Flats/Houses/Shops etc. are recognized on registry of same in favour of Buyer (s) or possession thereof handed over to buyer(s) or execution of lease deed in favour of buyer whichever is earlier.

Cont..2..

1..



..2..

ii. Penal interest & other charges on sale of properties remaining unpaid on allotted properties is accounted for on realisation basis due to uncertainty of its realisation.

(ACCOUNTANT) (ACCOUNTS OFFICER) (FINANCE CONTROLLER)

(SECRETARY)

(VICE CHAIRMAN)

PLACE: GHAZIABAD
DATED: 29-11-2003

FOR SAHNI BANSAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants

(PARDEEP S. SAHNI)
M.NO. 093866

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY Schedule- "21"
F.Y.R.2002-03

NOTES TO THE ACCOUNTS FORMING PART OF THE BALANCESHEET:

The Income of Housing Development Authorities was Exempt u/s 10(20A) of the Income Tax Act, 1961 up to the F.Yr.2001-02. However, with the abolition of Sec. 10(20A), their income became taxable due to which it became mandatory for the Housing Development authorities to maintain books of accounts on Double entry system, following accrual system of accounting. The authority was preparing its accounts on cash basis up to the F.Y. 2001-02.

Considering the main objects of the institution Ghaziabad development Authority had filed an application with the office of CIT, Income Tax Office, Ghaziabad for the purpose of its Registration as a Charitable Institution u/s 12(A) of the Income Tax Act, 1961. The approval of same is still awaited.

1. CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

All the Current Assets, Loans & Advances, in the opinion of the management have a value on Reacquisition, which in the ordinary course of Business, shall at least be equal to the amount at which it is stated in the Balancesheet except otherwise stated & provisions for all known liabilities have been made except otherwise stated.

2. INVENTORIES:

The cost of inventory in the form of properties is determined as cost of purchase of land plus Cost of Development thereon & interest up to the extent the inventory is not sold at the end of the Financial Year 2001-02. However from F.Yr.2002-03, the accounting policy for valuation of inventory has been changed by not including (loading) interest thereon.

The inventories have been valued & verified by the Management of the Authority. Verification & valuation of individual property item of inventory is not possible, in the absence of regular stock records.

4. The balance amounts receivable from sale of properties, advances to staff & Security Deposits and the amounts payable to Sundry contractors Suppliers & registration money, are subject to confirmation & reconciliation with the concerned parties.

5. The books of accounts were previously prepared on receipt basis, so no provision for interest due on account of receivables from sale of properties etc. were made in the books of accounts. The accounts were finalised with respective allottee at the time of registration of properties in their. During the Current Financial Yr.2002-03, all the accounts of the allottees were prepared on accrual basis, the balances of which are pending reconciliation with the respective allottees.

6. All the Government Loans are subject to Reconciliation from the concerned authorities. The Government had made direct payment of Rs.20.81 Crores to HUDCO, in the account of Ghaziabad Development Authority & the same has been treated as Loan from Government in our records, however in the absence of any specific instructions from the Government, no provision of interest thereon has been made in the books of accounts.

7. GOVERNMENT GRANTS:-

Govt. Grants received in VAMBAY Scheme & Contribution by the Authority are directly credited to VAMBAY FUND A/C & expenditures on said project (VAMBAY PROJECT) have been debited to VAMBAY FUND.

CONT-2



8. GRATUITY:-

The authority has not made any provision for accrued liability on account of Gratuity on Retirement of Employees, as per the requirements of Accounting Standard AS-15, as the same are being accounted for on payment basis.

9 FIXED ASSETS:-

The Physical verification of fixed assets has not been done since long & no provision for any short fall of the assets has been made in the books of accounts.

Moreover, in the absence of necessary details, the Value of Land & Building being brought forward from earlier years, could not be allocated & hence no depreciation has been provided thereon. In the absence of any specific information regarding the date on which the assets have been put to use, the date of payments for fixed assets has been taken as the date of put to use, for the purpose of calculation of depreciation on the fixed assets acquired during the year.

10. BONUS:-

The Bonus to the staff has been accounted for only after receiving instruction from the Government regarding its payment & hence no provision thereof has been made in the books of accounts.

11. PROVISION FOR TAXES:-

No provision for the Income Tax has been made in the books of accounts, considering the institution as a Charitable u s 11 of the Income Tax Act, 1961.

12. CONTINGENT LIABILITIES:

(i) Sundry Disputes with the allottees or other parties etc. (subjudice or otherwise) to the extent not ascertainable.

(ii) Land Acquisition Compensation:- Number of cases are pending in the High Court against the orders of Court. In number of cases the stay have been granted subject to payment of 50% of Decreeal amount. Total reported Estimated Contingent liability in respect of such cases is Rs. 218.61 Crores. (approx.)

(iii) Income Tax:- Against a Demand of Rs. 10.23 Lacs for the A.Yr. 1999-2000, the authority has preferred an appeal, which was still pending with the CIT (Appeals), Ghaziabad as on 31-03-2003.

(ACCOUNTANT) (ACCOUNTS OFFICER) (FINANCE CONTROLLER)
(SECRETARY) (VICE CHAIRMAN)

FOR SAHNI BANSAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants

(PARDEEP S. SAHNI)
M.NO. 093866

PLACE: GHAZIABAD
DATED: 29-11-2003

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

ADVANCES TO SUPPLIERS /CONTRACTORS AS ON 31-03-2003

AMOUNT(RS.)

Balance as on 31-03-2002 63866.00

Add: Advance given during the year 2002-03

- Contractor 0.00

- Suppliers 55000.00 55000.00

Less: Adjusted during the year 2002-03

- Contractor 0.00

- Suppliers 118866.00 118866.00

0.00



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY
F.Y. 2002-03

OPENING STOCK	7769754399.75
SALE	306998877.00
CLOSING STOCK OF PLOTS/FLATS & UNDEVELOPED LAND (AS VALUED & CERTIFIED BY THE MANAGEMENT)	7462755522.75
GROSS PROFIT	----- 0.00 -----



GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

RECEIVABLES AGST. SALE OF PROPERTIES AS ON 31-03-2003 AMOUNT(RS.)

BALANCE AS ON 31-03-2002 4357590722.71

LESS: RECD. IN SALE A/C

2222516780.71

2135073942.00

306998877.00

109801118.00

ADD: SALES FOR THE YEAR

ADD: INTT. DUE DURING THE YEAR

2551873937.00

BALANCE AS ON 31-03-03

- PRINCIPAL

- INTEREST

2074122861

477751076

2551873937.00



मद सं० :

40

विषय : गाजियाबाद महायोजना -2021(प्रारूप) की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 12-2-1999 के मद सं०-8 में गाजियाबाद महायोजना 2001 के पुनरीक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया था । महायोजना पुनरीक्षण के कार्य हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एन०सी०आर० नियोजन सैल, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० गाजियाबाद को अभिकरण (एजेन्सी) नियुक्त किया गया था ।

एन०सी०आर० सैल गाजियाबाद को महायोजना 2021 (प्रारूप) का आधार मानचित्र तैयार करने के लिए एन०आर०एस०ए० हैदराबाद के माध्यम से आईकनोज इमेजरी 1:4000 के स्केल पर प्राप्त की गयी तथा लोनी, मुरादनगर व गाजियाबाद का आधार मानचित्र इन्ही का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है । एन०सी०आर० सैल द्वारा गाजियाबाद महायोजना 2021(प्रारूप) के लिये वर्तमान भू-उपयोग सर्वेक्षण कराते हुए आवश्यक विवरण विभिन्न विभागों से प्राप्त कर महायोजना 2021 (प्रारूप) तैयार किया गया है । गाजियाबाद महायोजना 2021 (प्रारूप) विशेष रूप से अवस्थापना सुविधाओं की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की आवश्यकताओं को आंकलित करते हुए तैयार की गयी है, जिसमें गाजियाबाद नगर के सुनियोजित विकास हेतु प्रस्तावित विजन स्टेटमेन्ट 2021 के प्रस्तावों को भी यथा सम्भव सम्मिलित कर लिया गया है ।

गाजियाबाद महायोजना 2021 (प्रारूप) में गाजियाबाद नगर की जनसंख्या 23.5 लाख तथा लोनी की जनसंख्या 6.5 लाख, कुल जनसंख्या लगभग 30 लाख व मुरादनगर हेतु 1.5 लाख जनसंख्या प्रक्षेपित करते हुए कमशः लगभग 19000 हेक्टेयर तथा 1500 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के नगरीय क्षेत्र पर विभिन्न भू-उपयोगों की प्रस्तावना की गयी है । गाजियाबाद महायोजना 2021 (प्रारूप) के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।

मोदीनगर महायोजना वर्ष 2001 के लिए 2.40 लाख जनसंख्या हेतु तैयार की गयी थी किन्तु वर्ष 2001 में नगर की जनसंख्या केवल 1.39 लाख ही हो पायी है । विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों के बन्द होने के कारण नगर के स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है, जिस कारण वर्तमान महायोजना 2001 के प्रस्तावों को लागू करना सम्भव नहीं है । अतः प्रस्तावित है कि मोदीनगर महायोजना 2001 के प्रस्तावों के पुनरीक्षण का कार्य नगर एवं नियोजन विभाग उ०प्र० को एजेन्सी के रूप में चयन करते हुए कार्य सौंप दिया जाये ।

एन०सी०आर० सैल, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० गाजियाबाद द्वारा तैयार की गयी गाजियाबाद महायोजना 2021 (प्रारूप) प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं जनसामान्य से आपत्तियां/ सुझाव आमंत्रित करने हेतु अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

A.P.
A.T.P.

गाजियाबाद महायोजना प्रारूप -2021

नगर के विकास को नियोजित दिशा देने के प्रयास 30प्र0 शासन द्वारा कई दशक के पूर्व ही आरम्भ कर दिये गये थे शासन के उपरोक्त सकारात्मक प्रयासों के फलस्वरूप गाजियाबाद नगर के विकास को वर्तमान प्रवृत्तियों, जन आकांक्षाओं एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तावित करने के उद्देश्य से नगर की तीसरी महायोजना का प्रारूप वर्ष 2021 हेतु तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है। नगर के विकास को नियोजित करने के उद्देश्य से नगर एवं समीपवर्ती 137 ग्राम को सम्मिलित कर शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 2 पी/37-50 एवं 57, लखनऊ दिनांक 10.12.1958 से गाजियाबाद नगर को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया उसके उपरान्त विकास की तीव्र गति एवं प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए ऊ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अन्तर्गत विनियमित क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र को ही अधिसूचना संख्या 738 (1) सैंतीस-2-47-डी.ए./76 लखनऊ दिनांक 9 मार्च 1977 के द्वारा गाजियाबाद विकास क्षेत्र घोषित किया गया है। उसके उपरान्त मोदीनगर विनियमित क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र को भी गाजियाबाद विकास क्षेत्र का भाग बनाया गया है तथा शासन की अधिसूचना संख्या 355/9-आ-6-03-3 गठन/01 लखनऊ दिनांक 14 फरवरी 2003 द्वारा गढमुक्तेश्वर एवं ब्रजघाट एवं 13 ग्रामों को भी गाजियाबाद विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।

गाजियाबाद विकास क्षेत्र में गाजियाबाद नगर के अतिरिक्त लोनी, मुरादनगर एवं मोदीनगर भी सम्मिलित हैं। अतः विकास क्षेत्र के समग्र एवं समन्वित विकास हेतु गाजियाबाद के अतिरिक्त अन्य नगरों को भी नियोजित किया जाना आवश्यक है। इसी कारण गाजियाबाद के साथ मुरादनगर एवं लोनी नगरों की जनसंख्या का प्रक्षेपण कर महायोजना प्रारूप भी तैयार कर विचारार्थ प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

गढमुक्तेश्वर एवं बजघाट गाजियाबाद नगर से 70 कि०मी० की दूरी पर स्थित है अतः इस क्षेत्र की महायोजना पृथक रूप से बना कर विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

गाजियाबाद नगर की प्रथम महायोजना 1961-81 की अवधि हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गई थी जिसमें केवल 5853.50 हैक्टेयर क्षेत्र नगरीय विकास हेतु प्रस्तावित किया गया था जिसके विरुद्ध बड़े पैमाने पर विकास हुआ और 1985 तक कुल 5969 हैक्टेयर क्षेत्र नगरीय उपयोग हेतु विकसित हो चुका था। वर्ष 1985 तक गाजियाबाद उत्तर क्षेत्र का एक प्रमुख औद्योगिक नगर के रूप में स्थापित हो चुका था। वर्ष 1986 में नगर की दूसरी महायोजना वर्ष 2001 तक के लिए तैयार कर लागू की गयी जिसमें कुल 10039 है० क्षेत्र नगरीय विकास हेतु प्रस्तावित किया गया। इस महायोजना में लोनी क्षेत्र की महायोजना भी तैयार की गयी जिसमें 989 है० क्षेत्र विकास हेतु प्रस्तावित किया गया।

गाजियाबाद नगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना 2001 के अनुसार दिल्ली मेट्रोपोलिटन नगर घोषित किया गया है तथा इस क्षेत्र में मध्यम विकास प्रस्तावित किया गया है, परन्तु गाजियाबाद नगर की जनसंख्या अत्यन्त तीव्र गति से बढ़ी है तथा विकास क्षेत्र में विशेष कर लोनी एवं मुरादनगर की जनसंख्या भी अत्यन्त तेजी से बढ़ी है। इन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये निर्माणधीन क्षेत्रीय योजना 2021 में गाजियाबाद एवं लोनी नगरों की 2021 की जनसंख्या 30 लाख निर्धारित की गई है जिसमें गाजियाबाद (डासना सहित) एवं लोनी नगरों की 2021 की जनसंख्या क्रमशः 23.50 लाख एवं 6.50 लाख तक पहुँचनी सम्भावित है, जबकि मुरादनगर की महायोजना 2021 (प्रारूप) 1.50 लाख जनसंख्या हेतु तैयार की गयी है प्रस्तुत महायोजना प्रस्तावों के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है।

- 1- महायोजना प्रस्तावों को यथासम्भव व्यवहारिक एवं सुगमता से क्रियान्वयन योग्य बनाने हेतु यथार्थ एवं भावी अनुमानों से सामंजस्य के आधार पर प्रस्ताव दिये गये हैं।

- 2- महायोजना के भावी प्रस्तावों को पर्यावरण धर्मी बनाने के लिये भूमिगत जल पोटेंशियल इनफिल्ट्रेशन रेट, भूमिगत जल क्वालिटी, संवेदनशील क्षेत्रों आदि लक्षणों की प्रस्तावों का मुख्य आधार बनाया गया है।
- 3- पर्यावरण की दृष्टि से एवं एनसीआर क्षेत्रीय योजना 2001 में निर्धारित अनावश्यक नगरीकरण से कृषि क्षेत्र को संरक्षित करने की नीति के अनुसार मोडरेट हाई 160-170 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर घनत्व प्रस्तावित कर भूमि संसाधन का सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग किया गया है।
- 4- गाजियाबाद विकास क्षेत्र के नगरों के आर्थिक आधार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हाईटेक प्रदूषण मुक्त उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है तथा व्यापार वाणिज्य एवं आधुनिक प्रवृत्ति के अनुसार शैक्षिक संस्थानों को बढ़ावा देने के लिये भी पर्याप्त प्राविधान किया गया है।
- 5- इसी क्रम में मेरठ रोड को नालेज करीडोर का नाम दिया गया है जहां शैक्षिक संस्थानों के विकास को बढ़ावा दिया जायेगा।
- 6- महायोजना के ढांचे को लचीला बनाने हेतु मिश्रित भू-प्रयोग की अवधारणा का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया है अर्थात् मिश्रित व्यवसायिक एवं सामुदायिक सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं।
- 7- गाजियाबाद नगर हेतु तैयार विजन डॉक्यूमेंट में दिये गये प्रस्तावों का समायोजन महायोजना में कर लिया गया है।
- 8- नगर की सांस्कृतिक छवि को बढ़ावा देने हेतु मनोरंजन क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं।
- 9- वर्ष 2009 में होने वाले राष्ट्रमण्डलीय गेम्स की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर मनोरंजन भू प्रयोग में पर्याप्त प्राविधान किया गया है।

यातायात एवं परिवहन -

महायोजना प्रारूप 2021 में यातायात एवं परिवहन पर विशेष ध्यान दिया गया है। ट्रांसपोर्ट प्लान के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार है :-

- 1- संगठित नेटवर्क के माध्यम से सम्पूर्ण विकास क्षेत्र में यातायात एवं सवारी परिवहन को सुगम बनाने का प्रयास किया गया है।
- 2- यातायात को सुनियोजित रूप से नियंत्रित करने के उद्देश्य से तीन मुख्य रेडियल पर ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित किये गये हैं।
- 3- नगर के यातायात की समस्याओं के निराकरण के लिये विस्तृत यातायात एवं परिवहन योजना तैयार करने का कार्य एक विशेष कन्सल्टेंट को दिया गया है।
- 4- नगर की वर्तमान समस्याओं के चलते व्यवसायिक पार्किंग के प्रस्ताव दिये गये हैं।
- 5- ट्रांस एवं सिस हिंडन क्षेत्र की सम्बद्धता को सुदृढ बनाने के लिए एक नया मार्ग प्रस्तावित किया गया है जो मेरठ रोड एवं लोनी रोड को जायेगा।
- 6- नगर के मध्य से गुजरने वाले क्षेत्रीय यातायात के प्रवाह को सुगम बनाने के उद्देश्य से महाराजपुर से मोदीनगर तक मेरठ मार्ग को एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है।
- 7- दिल्ली जाने वाले दैनिक यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखकर मेट्रो रेल का गाजियाबाद तक विस्तार का प्रस्ताव दिया गया है जो स्टेट ऑफ़ आर्ट तकनीक के आधार पर बड़ी संख्या में यात्रियों की ढलाई कर सड़क परिवहन को सुगम बनायेगी।

महायोजना में परियोजना में आवश्यक क्षेत्र का आरक्षण किया जायेगा।

अवस्थापना सुविधा योजना :-

गाजियाबाद विकास क्षेत्र के नगरों में जलापूर्ति, सीवरेज ड्रेनेज एवं सोलिड वेस्ट निस्तारण का विस्तृत अध्ययन कर प्रारम्भिक योजना भी प्रस्तावित की गयी है।

1. जलापूर्ति के वर्तमान अभाव, मानक के आधार पर भावी आवश्यकता एवं प्रारम्भिक लागत अनुमान प्रस्तुत किये गये हैं।
2. समस्त प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र को सीवरेज प्रणाली से आच्छादित करने के आशय से उत्पादित होने वाली सीवरेज का अनुमान प्रस्तुत किये गये हैं तथा शोधन हेतु भूमि भी आरक्षित की गयी है।
3. नगर के सामान्य ढाल, ड्रेनेज के मुख्य चैनल, ड्रेनेज की मुख्य समस्याओं पर आधारित जल निकासी के प्रस्ताव दिये गये हैं।
4. क्षेत्रीय ढाल एवं नालों के आधार पर सीवेज शोधन संयंत्र, सोलिड वेस्ट निस्तारण स्थल आदि हेतु पर्याप्त क्षेत्रों का आरक्षण किया गया है।

मद संख्या :

41

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार कराये गये विजन स्टेटमेन्ट- 2021 का प्रस्तुतीकरण व अनुमोदन ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर के सुनियोजित विकास हेतु विजन स्टेटमेन्ट 2021 तैयार करने हेतु मैसर्स दलाल मोट मैक्डोनाल्ड ,नई दिल्ली को चयनित किया गया था । उनके द्वारा विभिन्न चरणों में रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा प्राधिकरण के अधिकारियों के समक्ष इनका प्रस्तुतीकरण किया गया । विजन स्टेटमेन्ट में मुख्य रूप से नगर के आर्थिक आधार में सुधार तथा नागरिकों के अच्छे जीवन स्तर को महत्व दिया गया है ।

ड्राफ्ट विजन स्टेटमेन्ट रिपोर्ट में नगर के पर्यावरण ,नगरीय अवस्थापना सुविधाओं जिसमें समस्त फिजिकल व सोसियल अवस्थापनाओं का आंकलन करते हुए उनमें कमी,विकास की सम्भावनाएं एवं सम्भावित कठिनाईयों का अध्ययन करते हुए सुझाव प्रस्तुत करते हुए सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं ।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण की अलोकप्रिय सम्पत्ति (पेसिवएसैट) के विक्रय व प्रबन्धन तथा प्राधिकरण के अधिष्ठान में सुधार हेतु 'ओरगनाईजेशन मैनेजमेन्ट' सम्बन्धित सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं ।

मैसर्स दलाल मोट मैक्डोनाल्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये विजन स्टेटमेन्ट की सुसंगतता व कार्य योजना तैयार कर एजेण्डा के साथ संलग्न किया गया है ।

प्रस्तावित गाजियाबाद महायोजना 2021 में नगर के विकास हेतु दिये गये मार्गदर्शन एवं अन्य विवरण को समायोजित करने हेतु एन0सी0 आर0 सेल, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0शासन से समय समय पर समन्वय व सहयोग प्राप्त किया गया है ।

गाजियाबाद नगर के सुनियोजित विकास हेतु तैयार किया गया विजन स्टेटमेन्ट 2021 प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

A.T.P.

विजन स्टेटमेंट रिपोर्ट की सुसंगतता एवं क्रियान्वयन हेतु रणनीति एवं कार्य योजना

विजन स्टेटमेंट की सुसंगतता :-

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा "विजन स्टेटमेंट" तैयार किये जाने का मुख्य उद्देश्य नगर की आर्थिक उन्नति के आवश्यक प्राविधान करते हुए नागरिकों के जीवन स्तर का सुधार करना तथा नगर का एक विशेष नगरीय छवि के रूप में विकसित करना है। आर्थिक उन्नति से नगर के संसाधनों में वृद्धि होगी तथा उच्च स्तर के पर्यावरण व अवस्थापना सुविधाओं का विकास संभव हो सकेगा। विजन स्टेटमेंट की सुसंगतता इस कारण से और भी अधिक हो गई है चूँकि इसे नगर की अगामी 20 वर्षों में आनेवाली आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है तथा यह गाजियाबाद की तैयार की जा रही महायोजना-2021 के लिए दिशा निर्देशक का कार्य करेगा। विजन स्टेटमेंट तैयार करते समय विशेष रूप में विभिन्न प्रभावित वर्गों, विभागों तथा जन सामान्य से खुले रूप में विचार विमर्श किया गया है, अतः उनकी अपेक्षाएँ भी इसमें परिलक्षित हैं।

कार्य योजना :-

विजन स्टेटमेंट में नगर के समग्र विकास हेतु चरणबद्ध रूप से 5, 10, 15 व 20 वर्षों हेतु संस्तुति व प्रस्तावनाएं दी गई हैं। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय स्तर के संस्तुतियों को अलग-अलग उल्लेखित किया गया है।

प्रदेश सरकार स्तर की मुख्य संस्तुतियाँ

1. जलापूर्ति

भवन उपविधि में रेनवाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधानों का अनुपालन नहीं करने पर दण्डात्मक कार्यवाही का प्राविधान किया जाये।

2. सोलिडवेस्ट मैनेजमेंट

भवन उपविधि/रेगुलेशन में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण करने की व्यवस्था हेतु प्राविधानों को सम्मिलित किया जाये तथा अनुपालन नहीं करने पर दण्डात्मक कार्यवाही का प्राविधान किया जाये।

3. विद्युत आपूर्ति

विद्युत उत्पादन, वितरण तथा रख-रखाव व निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त किया जाये।

4. आवास

आवश्यकतानुसार हरियाणा मोडल, एल०डी०ए० मोडल, गुजरात मोडल, सिडको मोडल व जी०डी०ए० के ज्वाइन्टवेंचर मोडल का परिक्षण कर तेजी निजी क्षेत्र/ संयुक्त क्षेत्र के माध्यम से आवासीय निर्माण एवं विकास को तेजी से लागू करने पर विचार किया जाए। जिसमें आवासीय मांग की पूर्ति शीघ्र हो सके।

5. ट्रैफिक एण्ड ट्रांसपोर्ट

ईन्टीग्रेटेड रेलवे बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आई.आर.बी.टी.) के शीघ्र क्रियान्वयन तथा दिल्ली के मेट्रो (एम.आर.टी.एस.) को गाजियाबाद तक विस्तार हेतु तेजी से प्रयास किये जाए।

6. स्लम सुधार

अरबन वेज इम्प्लोयमेन्ट योजना, जिसमें स्लम में रहने वालों को निर्माण सम्बन्धित गतिविधियों में शामिल किया जाता है, को लागू किया जाए। मुम्बई की स्लम सुधार योजना की भाँति स्लम सुधार में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के प्राविधान एवं टी.डी.आर. योजना बनाई जाए।

7. अनाधिकृत निर्माण

(अ) अनाधिकृत कालोनियों को रोकने हेतु हरियाणा के पेटर्न पर नीति तैयार की जाए। जिसके अन्तर्गत भूमि के विक्रय/पंजीयन में छोटे भू-खण्डों के विक्रय पर रोक लगाते हुए एच. यू.डी.ए. एक्ट, 1997 की भाँति एक हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की भूमि के विक्रय से पूर्व विकास प्राधिकरण की अनापत्ति को अनिवार्य किया जाए।

8. पर्यावरण

महायोजनाओं में आरक्षित ग्रीनबेल्ट व ग्रीन एरियास् /पार्कस आदि के भू उपयोग परिवर्तन को प्रतिबन्धित किया जाए।

9. उद्योग

- (अ) उद्योगों की स्थापना हेतु प्रोत्साहनात्मक तथा सुविधा प्रदायक प्राविधान किया जाए।
- (ब) सूचना व संपार टेक्नोलोजी के विकास को प्रोत्साहन देते हुए गति प्रदान की जाए।
- (ब) बन्द होने वाले उद्योग की पुनर्स्थापना हेतु पैकेज तैयार किया जाए।

10. समग्र विकास

- (क) नगर के समग्र विकास हेतु एवं विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय स्थापित करने व अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक उच्च स्तरीय समिति जिसे सम्पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त हो तथा वह नगर विकास से जुड़े सभी विभागों की महायोजनाओं की समीक्षा एवं वार्षिक योजनाओं को क्रियान्वित कर सके।
- (ब) विकास तथा रख-रखाव हेतु नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा की भाँति एक ही संस्था रखी जाए।

11. संस्थागत प्रबन्धक

- (क) प्राधिकरण बोर्ड में विभिन्न क्षेत्र विशेष के प्रोफेशनल्स को सदस्य के रूप में नामित किया जाए।
- (ब) भूमि अर्जन प्रक्रिया तथा अधिनियम में संशोधन किया जाए जिससे भू-अर्जन में लगने वाला समय कम किया जा सके।
- (द) भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु निजी क्षेत्र के आर्किटेक्ट्स को भवन उपविधि व रेगुलेशन्स के अनुरूप स्वीकृति सम्बन्धित स्वायत्ता प्रदान की जाए।
- (द) कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्त (सी.आर.एस.) की योजना लाई जाए तथा नये ऊर्जा से भरी नई पीढ़ी से कार्य लिया जाए।

स्थानीय स्तर की संस्तुतियाँ

1. जलापूर्ति

- (अ) पार्इपलाईन लीकेज डिटेक्शन के लिए नियमित जाँच की जाए जिससे पानी के नुकसान से बचा जा सके।
- (ब) पानी के पुनः उपयोग (रीसाइक्लिंग) को बढ़ावा दिया जाए। किचन

तथा बाथरूम के वेस्ट पानी को सामान्य ट्रीटमेन्ट के बाद गार्डनिंग व प्लसिंग में उपयोग में लाया जाए।

- (स) रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लगाये जाने हेतु जागरूकता उत्पन्न करते हुए तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
- (द) 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर पूर्णता प्रमाण पत्र (कम्प्लीशन सर्टिफिकेट), रूफ टोप रेनवाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधान के उपरान्त किया जाए।
- (य) नगर का हाईड्रो-जियोलोजिकल मानचित्र तैयार किया जाए, जिससे रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जा सकें।
- (र) जलापूर्ति में वृद्धि हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी प्राप्त की जाए। (विशेष रूप से गंगावाटर योजना के ट्रीटमेन्ट, वितरण एवं रेवेन्यू एक्सीक्यूटिव हेतु)
- (ल) भूगर्भ जल के अनियन्त्रित दोहन को रोकने हेतु नगरीय क्षेत्र में प्राईवेट ट्यूबवैल के खोदने पर रोक लगाई जाए।

2. सीवेज एवं सेनीटेशन

- (अ) सीवर से अनाच्छादित क्षेत्र में सीवर का प्राविधान किया जाए।
- (ब) वर्तमान एस.टी.पी. की पूर्ण क्षमता पर उपयोग किया जाए।
- (स) ग्राउड वाटर कोर्स में मिलाये जाने से पूर्व वेस्ट वाटर की बी.ओ.डी. पर प्रभारी नियंत्रण किया जाए।
- (द) नवीन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त एस.टी.पी. की प्रस्तावना की जाए।
(गोविन्दपुरम की प्रस्तावना के अतिरिक्त)
- (य) निजी क्षेत्र एवं गैर सरकारी संस्थाओं (यथा सुलभ इण्टरनेशनल) के सहयोग से सार्वजनिक टायलेट्स का निर्माण तथा रख-रखाव कराया जाए।
- (र) ट्रीटेड सीवेज वाटर को पार्को/गोल्फ कोर्स ग्रीन बेल्ट व खुले स्थानों में वाटरिंग हेतु उपयोग किया जाए।
- (ल) अनाधिकृत कालोनियों में सीवर लाइन के निर्माण हेतु नीति (पालिसी) बनाई जाए, जिससे नगर के 100 प्रतिशत क्षेत्र को आच्छादित किया

3. सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट

- (अ) वेस्ट के एकत्रीकरण के स्थान पर ही बायोडिग्रेडिबल तथा अनबायोडिग्रेडिबल वेस्ट को पृथिवृत किया जाए।
- (ब) वेस्ट एकत्रीकरण की पर्याप्त व्यवस्था तथा इन्हें डलावघर तक पहुँचाने का उचित नेटवर्क तैयार किया जाए।
- (स) गार्बेज एकत्रीकरण में स्थानीय आवासीय वेलफेयर एसोसियेशन (आर.डब्ल्यू.ए.)का सहयोग व साथ लिया जाए।
- (द) भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए लिए सेनेटरी लैण्डफिल साइट्स का प्राविधान किया जाए।
- (य) सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के लिए नवीन तकनीकों, जिसमें वरमी कम्पोस्टिंग व विद्युत उत्पादन में उपयोग के लिए प्रयास किये जाए।

4. ट्रैफिक एण्ड ट्रांसपोर्टेशन

- (अ) सभी मुख्य मार्गों का सुधार तथा रख-रखाव।
- (ब) रोड ज्योमेट्रीक्स तथा इन्टर सैक्शनस का सुधार।
- (स) पुराने बस स्टैण्ड को नये स्थान पर स्थानान्तरण।
- (द) ट्रांसपोर्ट नगर का विकास।
- (य) निजी क्षेत्र के सहयोग से इफोफ्रेन्डली नगर बस सेवा को प्रारम्भ करना।
- (र) राष्ट्रीय राजमार्ग-24 व 58 को जोड़ने हेतु लिफ रोड का निर्माण।
- (ल) विभिन्न चयनित स्थानों पर ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर का निर्माण तथा तत्काल प्राथमिकता से मोहननगर ओवर हैड ब्रिज का चौड़ीकरण किया जाए।
- (व) विभिन्न स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण, बी.ओ.टी.के. आधार पर कराया जाए।
- (स) नगर का ट्रैफिक मैनेजमेन्ट प्लान तैयार किया जाए।

5. विद्युत आपूर्ति

- (अ) गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों, जैसे सोलिड वेस्ट तथा बगासे से ऊर्जा उत्पादन।

- (व) वर्तमान पावर स्टेशन की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु नवीन तकनीकों का उपयोग।
- (स) ट्रांसमिशन लाँस को कम करने हेतु वर्तमान कन्डेक्टर के स्थान पर हाईकैपेसिटिटी कन्डेक्टर का उपयोग।
- (द) नवीन कालोनियों में अन्डरग्राउण्ड केबल का प्राविधान किया जाए।
- (य) भवन निर्माण स्वीकृति में विद्युत से सम्बन्धित प्रतिबन्धों का कड़ाई से पालन किया जाए।

6. आवास

- (अ) निजी क्षेत्र की भागीदारी व पब्लिक व प्राइवेट सेक्टर के ज्वाइंट वेन्चर को प्राथमिकता दी जाए।
- (ब) कोई भी आवासीय योजना प्रारम्भ करने से पूर्व डिमाण्ड सर्वे आवश्यक रूप से किया जाए।
- (स) जी.डी.ए. निजी क्षेत्र व व्यक्तियों को भूखण्ड/भूमि उपलब्ध कराने में सुविधा प्रदायक का कार्य करें।
- (द) प्रत्येक योजना में 5 से 10 प्रतिशत आवासीय भवन सर्विस पर्सनल (इकोनोमिकल क्लास) के लिए आरक्षित किया जाए।
- (य) पर्याप्त संख्या में ई.डब्लू.एस. श्रेणी के भवन निर्मित किए जाए।

7. स्लम सुधार

- (अ) स्लम सुधार हेतु गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) को शामिल किया जाए।
- (ब) विनियमित स्लम क्षेत्रों में समय-समय पर स्वास्थ्य कैंप आयोजित किये जाए तथा साक्षरता हेतु विशेष कैंपों का आयोजन किया जाए।
- (स) स्लम क्षेत्रों के सुधारों में कम्युनिटी एप्रोच अपनाई जाए।
- (द) मुख्य मार्गों, महायोजना के भू-उपयोग के विरुद्ध बने स्लम्स की पुनर्स्थापना नये क्षेत्रों में की जाए।
- (य) नये स्लम न बनने पाये, इसके लिए नये क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावी नियंत्रण किया जाए।

8. पर्यावरण एवं प्रदूषण

- (अ) भू-जल की गुणवत्ता (क्वालिटी) की जाँच हेतु पहल की जाए।

- (य) वन विभाग के सहयोग से ग्रीनवेन्ट, पार्क तथा फोरेस्ट क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ लगाये जाए।
- (स) हिण्डन नदी के दोनों ओर 100 मी० स्थान को बोटनीकल गार्डन , व वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व मनोरंजन सुविधाओं हेतु हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए।
- (द) वाहनों की समय-समय पर प्रदूषण जाँच, विशेष रूप से भारी वाहनों की जाँच आवश्यक की जाए।
- (य) उद्योग में एफ्लूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये जाने के प्राविधानों को कड़ाई से लागू किया जाए।

9. उद्योग

- (अ) एग्रोपार्क एवं फ्लोरीकल्चर पार्क विकसित किया जाए।
- (ब) ट्रेनिंग सेन्टर, औद्योगिक प्रोत्साहन केन्द्र, औद्योगिक पार्क व इन्कोटेक पार्क के विकास पर बल दिया जाए।
- (स) औद्योगिक अवस्थापनाओं का स्तर बढ़ाया जाय, जिससे उद्योग आकर्षित हो सकें।
- (द) वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार आपुनिक योकेशनल तथा प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाए।
- (य) स्थानीय उत्पादों की एक वार्षिक औद्योगिक प्रदर्शनी लगाई जाए।

10. नगर का समग्र विकास

- (अ) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर के विकास में एक सुविधादायक तथा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करें।
- (य) नगर के विकास में नागरिकों के अधिक से अधिक सहयोग व सहभागिता प्राप्त की जाए।
- (स) नगर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ जैसे वार्षिक मेला व महोत्सव का आयोजन किया जाए।
- (द) कानून व्यवस्था के विषय में जिला प्रशासन के सहयोग से वर्तमान स्थिति में सुधार कराया जाए।

11. औरगनाइजेशनल मैनेजमेन्ट

- (अ) प्राधिकरण के वर्तमान औरगनाइजेशनल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करते हुए

मानव संसाधन (ह्यूमन रिसोर्स) एवं मार्केटिंग के लिये दो नये अनुभाग सृजित किए जाए।

- (ब) प्राधिकरण कार्यालय भवन को अच्छा दिखाने वाला तथा आवंटियों/आगंतुकों हेतु सुविधा के लिए रिशेपन डेक्क, पीने के पानी की उचित व्यवस्था अन्य सुविधाओं का प्रावधान विरो जाए।
- (स) कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए उचित कैंटीन की व्यवस्था की जाए।
- (द) कर्मचारियों को ट्रेनिंग मुख्य रूप से कम्प्यूटर ट्रेनिंग की आवश्यकता का आकलन किया जाए जो वर्तमान तथा भविष्य के लिए उपयोगी हों।
- (च) नवीन विचारों तथा प्रस्तावनाओं के लिए एक व्यवस्था बनाते हुए इन्हें प्रोत्साहित किया जाए।
- (र) अधिकारियों/कर्मचारियों की समय-समय पर की विभिन्न बैठके कर सहभागिता बढ़ाई जाए।
- (ल) कार्यालय प्रक्रिया को सरल करते हुए पूर्ण कम्प्यूटराइजेशन का प्रयास किया जाए।
- (व) विकास प्राधिकरण की वेबसाइट को और व्यापक बनाया जाए तथा चालू योजनाओं का पूर्ण विवरण साईट पर उपलब्ध हो। ऑनलाइन आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए।
- (श) पत्रावलियों के निस्तारण में पत्रावलियों का मूवमेन्ट न्यूनतम चैनल्स के आधार पर किया जाए।
- (ष) ई-गवर्नेंस के लिए व्यापक प्रयास किया जाए।
- (स) नगर स्तर का एक इन्फोमेशन सिस्टम विकसित किया जाए, जिसमें भूमि, सम्पत्ति, समस्त इन्फ्रास्ट्रक्चर व नगर की महत्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध हों।

विषय: प्राधिकरण में एक नग इन्डिका कार कय करने के सम्बन्ध में ।

कार्यालय में एक वाहन संख्या यू०वी०एन०-९ एम्बेसडर कार को नियमानुसार निष्प्रयोज्य कराकर प्राधिकरण द्वारा दिनांक ०८-१-२००४ को नीलाम किया जा चुका है

वाहन को नीलाम किये जाने के फलस्वरूप प्राधिकरण द्वारा कोई अन्य वाहन कय नहीं किया गया है । यहां यह भी अवगत कराना है कि प्राधिकरण एन०सी०आर क्षेत्र में स्थापित है और आये दिन उ०प्र० शान के वरिष्ठतम अधिकारी / वी०आई०पी० अधिकारियों का आवागमन बना रहता है तथा समय असमय जिला प्रशासन द्वारा भी प्रायः वाहन की मांग प्राधिकरण से की जाती है जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण में वाहनों की कमी बनी रहती है ।

कार्यहित में व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक नग इन्डिका कार कय करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड बैठक के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

17.1.2004

विषय: उ0प्र0 सरकार द्वारा आवासीय क्षेत्र में पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की नीति निर्धारण के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निजी निवेशकों को विकास प्राधिकरण में कार्य करने हेतु आकर्षित करता रहा है । उसी क्रम में दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्र में बड़े एवं प्रतिष्ठित निवेशकों को पूंजी निवेश कराने के उद्देश्य से एक योजना प्रस्तावित है जिससे प्राधिकरण की छवि में सुधार होगा । प्रतिष्ठित पूंजी दाताओं द्वारा जो क्षेत्र विकसित किये जायेंगे उसमें अन्तराष्ट्रीय मानकों एवं सुविधाओं का समावेश होगा । भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बड़े पूंजी निवेशकों की सहभागिता करानी उपयुक्त रहेगी ।

1- भूमि:-

प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान के अनुसार भूमि विभिन्न प्रयोगों के लिए चिन्हित किया जाना उपयुक्त रहेगा ।

क- भूमि के प्रतिकर की धनराशि निजी पूंजीदाताओं द्वारा वहन की जायेगी ।

ख- इस भूमि का अधिग्रहण प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा ।

ग- इस भूमि को करार नियमावली के तहत अधिग्रहण कराया जा सकेगा ।

2- भूखण्डों का आवंटन :-

प्राधिकरण द्वारा इस भूमि पर 50 एकड़ , 100 एकड़, 150 एकड़, व 200 एकड़ तक भूखण्डों को विभिन्न प्रयोगों (आवासीय, व्यवसायिक, ग्रीन बैल्ट एवं सामुदायिक केन्द्र) का नीलामी / टेन्डर पत्र के द्वारा प्रचार-प्रसार के उपरान्त बेचा जायेगा ।

3- विकास कार्य :-

क- वाह्य विकास कार्य :-

इसमें मुख्यतः सड़क , जल निकासी, जलपूर्ति , सीवरेज एवं विद्युत का कार्य प्राधिकरण द्वारा कराया जायेगा । वाह्य विकास कार्य पर आने वाला व्यय निजी निवेशक द्वारा प्राधिकरण में जमा कराना होगा जिसे निर्धारित किया जायेगा ।

ख- आन्तरिक विकास कार्य :-

इन बड़े भूखण्डों में आन्तरिक विकास कार्य निवेशकों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा । इन विकास कार्य को पूर्ण कराने हेतु प्राधिकरण के पक्ष में बैंक गारन्टी अथवा कुछ भूमि को बन्धक बनाया जाना उपयुक्त रहेगा जिससे कि आन्तरिक विकास कार्य के लिए निवेशक की प्रतिबद्धता बनी रहे ।

4- विकसित भूमि का मूल्य :-

भूमि में ले-आउट प्लान के मानकों के अनुरूप लगभग 50 प्रतिशत भूमि विक्रय योग्य उपलब्ध होगी । इस भूमि को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों पर एफ0ए0आर0 विक्रय किया जाना उपयुक्त होगा । भूमि की दरों का निर्धारण तत्कालीन सेक्टर रेट के आधार पर विक्रय किया जाना भी एक सुझाव हो सकता है ।

5- सेवाओं का हस्तान्तरण

इस भूमि को 5 वर्ष के अन्तर्गत विकसित करना होगा । सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने हेतु आवश्यकतानुसार कम्पीटेन्ट अथारटी/ नगर निगम को हस्तान्तरित करना होगा ।

SR snf

विषय : गाजियाबाद महायोजना -2001 तथा मोदीनगर महायोजना-2001 में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/ उपयोगों की अनुमति के सम्बन्ध में ।

शासन द्वारा अनुमोदित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन के अन्तर्गत कतिपय क्रियाओं / उपयोगों की विशेष अनुमति से अनुमन्य की श्रेणी में रखा गया है , जिसके सम्बन्ध में जोनिंग रेगुलेशन के क्रमांक-4 में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अपेक्षाएँ निर्धारित की गयी हैं । उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से पूर्व एक समिति का गठन किया गया है । प्राधिकरण में उपरोक्त प्रकार के तीन प्रकरण विचाराधीन हैं , जिन्हें गठित समिति की संस्तुति सहित निम्नानुसार प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

1-गाजियाबाद महायोजना 2001 के अन्तर्गत ग्राम सदरपुर स्थित खसरा नं० 1601 मि० की भूमि पर कार्यालय भू-उपयोग के अन्तर्गत बैंकट हाल/ बारातघर की अनुमन्यता के सम्बन्ध में ।

प्रश्नगत प्रकरण में भूमि का कुल क्षेत्रफल 2960.98 वर्गमी० है ,जो वर्तमान में लागू महायोजना 2001 के अनुसार कार्यालय भू-उपयोग में प्रदर्शित है । पूर्व में आवेदक द्वारा एक तलपट मानचित्र स्वीकृत कराया गया था , एवं उसके द्वारा विकास शुल्क के मद में लगभग रु० 14.00 लाख जमा किये गये हैं , परन्तु किन्ही कारणवश उपरोक्त स्वीकृति के अनुक्रम में कोई विकास नहीं किया गया ।

स्थल पर आवेदक द्वारा अधिकृत रूप से टीनशेड, टायलेट एवं किचन बनाकर बरातघर चलाया जा रहा है । आवेदक इस अनाधिकृत निर्माण को शमन कराकर नियमित कराना चाहता है

कार्यालय भू-उपयोग के अन्तर्गत जोनिंग रेगुलेशन में बरातघर/ बैंकटहाल की अनुमति विशेष अनुमति से दिये जाने का प्राविधान है । विशेष अनुमति में प्रकरण ,समिति की संस्तुति के उपरान्त बोर्ड बैठक में रखकर ही निर्णय किया जाना है । प्रश्नगत प्रकरण समिति में रखा जा चुका है एवं समिति द्वारा तत्समय संस्तुति भी दी गयी है , जिसकी प्रति संलग्न है ।

आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि वह उक्त निर्माण को कम्पाउण्ड कराने को तैयार है तथा समस्त शुल्क आदि भी देने को तैयार है ,किन्तु शमन शुल्क की गणना तभी की जा सकती है जब उपरोक्त प्रस्तावित भू-उपयोग अनुमन्य हो ।

उपरोक्त प्रश्नगत भूखण्ड खसरा सं० 1601मि० ग्राम सदरपुर गाजियाबाद का कार्यालय भू-उपयोग कार्यालय में बैंकटहाल/ बारातघर की अनुमति हेतु बोर्ड के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

2- मोदीनगर महायोजना 2001 के अन्तर्गत ग्राम कादराबाद मोदीनगर के खसरा नं० 642 मि० एवं 632 मि० की भूमि पर कृषि हरित पट्टी भू-उपयोग के अन्तर्गत हाईस्कूल/ माध्यमिक स्कूल की अनुमति के सम्बन्ध में ।

मोदीनगर महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कादराबाद के खसरा नं० 642 मि०, 632 मि०की लगभग 8685 वर्गमी० भूमि पर माध्यमिक/ इंटरमीडियट स्कूल स्वीकृत किये जाने हेतु

आवेदन किया गया था । उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत स्थल मुख्य दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है तथा महायोजना मार्ग 200 फिट (60 मीटर) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रिजनल प्लान के प्राविधानों के अनुरूप 100 मी० ग्रीन बेल्ट का स्थान छोड़े जाने के उपरान्त शेष भूमि का भू-उपयोग कृषि हरितपट्टी निर्दिष्ट है । उक्त संस्था द्वारा स्थल का निर्माण किया जा चुका है , जिसे शमन कराने का अनुरोध किया गया है । प्रश्नगत प्रकरण प्राधिकरण स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा समिति द्वारा महायोजना मार्ग तथा ग्रीन बेल्ट छोड़े जाने के उपरान्त शेष भाग में कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत स्कूल निर्माण की अनुमति प्रदान करने की संस्तुति की गयी है । समिति की संस्तुति की छाया प्रति संलग्न करते हुए उपरोक्त प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

3- मोदीनगर महायोजना 2001 के अन्तर्गत ग्राम अबूपुर की खसरा नं० 223 कुल क्षेत्रफल 9218.43 व०मी० के अन्तर्गत कृषि हरितपट्टी भू-उपयोग में मार्डन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी के शिक्षण संस्थान की अनुमति के सम्बन्ध में ।

मोदीनगर महायोजना के अन्तर्गत ग्राम अबूपुर के खसरा नं० 223 कुल क्षेत्रफल 9218.43 व०मी० भूमि पर मार्डन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी द्वारा बी०एड० कालेज खोले जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग मोदीनगर महायोजना में कृषि हरित पट्टी निर्दिष्ट है । उक्त संस्था द्वारा स्थल पर निर्माण किया जा चुका है, जिसे शमन कराने हेतु अनुरोध किया गया है । जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानों के अनुसार कृषि हरित पट्टी भू-उपयोग के अन्तर्गत महाविद्यालय, विश्व विद्यालय, पालीटेक्निक, इन्जीनियरिंग, मेडिकल / डेंटल कालेज को विशेष परिस्थिति में अनुमन्य की श्रेणी में रखा गया है ,परन्तु प्रअन्ध संस्थान / विशिष्ट शैक्षिक संस्थान को निषिद्ध होना दर्शित किया गया है । बी०एड० कालेज सामान्यतः महाविद्यालय में ही चलाये जाते हैं । जोनिंग रेगुलेशन्स की परिभाषाओं में विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है । अतः प्रश्नगत प्रकरण में समिति की संस्तुति संलग्न करते हुए मोदीनगर महायोजना में ग्राम अबूपुर के खसरा नं० 223 में शिक्षण संस्थान बी०एड० कालेज के निर्माण को विशेष अनुमन्य किये जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

खसरा नं० 1601 मि० ग्राम सदरपुर, गाजियाबाद की भूमि पर बैकट हाल/बारात घर की अनुमति के सम्बन्ध में ।

श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री दिलावर सिंह का आवेदन महायोजना में प्रस्तावित गोविन्दपुरम योजना के निकट कार्यालय क्षेत्र में 2460.98 वर्ग मी० के भूखण्ड पर बारात घर/बैकट हाल की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है । प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग गाजियाबाद महायोजना 2001 में प्राधिकरण के सम्बन्धित नियोजन अनुभाग द्वारा प्रस्तुत सत्यापित अभिलेखों के अनुसार कार्यालय है ।

प्रार्थी के उक्त स्थल पर कार्यालय निर्माण हेतु तलपट मानचित्र प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.05.1999 को स्वीकृत किया गया था । प्रार्थी द्वारा उक्त स्वीकृति के आधार पर कोई विकास कार्य नहीं किया गया प्रार्थी द्वारा उक्त स्वीकृत तलपट मानचित्र को अस्वीकृत कराने का अनुरोध किया गया है जिसे प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यह अनुरोध किया गया है कि स्थल के आस-पास आवासीय विकास हुआ है तथा भविष्य में भी आवासीय विकास ही होने की संभावनायें हैं तथा स्थल पर कार्यालय हेतु तलपट मानचित्र का विकास किया जाना व्यवहारिक नहीं है । प्रार्थी का स्थल प्राधिकरण द्वारा विकसित गोविन्दपुरम आवासीय योजना की 45.00 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित हैं तथा प्रार्थी द्वारा स्थल पर मिट्टी भराई तथा टीन शैड का निर्माण कार्य किया जा चुका है । स्थल के दक्षिण में एक अनाधिकृत आवासीय कालोनी विकसित हो चुकी हैं तथा पूर्व दिशा में प्राधिकरण की गोविन्दपुरम आवासीय योजना स्थित हैं तथा उत्तर में प्राधिकरण की डी स्वर्ण जयन्तीपुरम योजना विकसित की जा रही है । शासन द्वारा अनुमोदित जॉनिंग रेगुलेशन के अनुसार कार्यालय भू-उपयोग में बारात घर की अनुमति सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अनुमत्त है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्थल का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि वर्तमान में स्थल 45.00 मी० चौड़े मार्ग से सम्बद्ध है तथा प्राधिकरण की आवासीय योजना गोविन्दपुरम से सटा हुआ है । प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार 2460.98 वर्ग मीटर के भूखण्ड में केवल 503.99 वर्ग मीटर क्षेत्र ही भू-आच्छादन निर्मित किया जाना प्रस्तावित है । यू. तो बारात घर की स्थापना से आवासीय क्षेत्र में कुछ विषमताएं उत्पन्न हो सकती हैं परन्तु भूखण्ड का आकार बड़ा होने के कारण, स्थल के भीतर ही पार्किंग सुविधा उपलब्ध होने के कारण तथा 45 मी० चौड़े पहुँच मार्ग पर स्थित होने के कारण महायोजना में कार्यालय हेतु प्रस्तावित प्रश्नगत स्थल पर बारात घर / बैकट हाल के निर्माण की संस्तुति प्राधिकरण की समझ रखने हेतु की जाती है ।


(अनिल भटनागर)
एसोसिएट प्लानर
एन०सी०आर० सेल


(आशीष मेहरोत्रा)
सदस्य
गा० वि० प्रा०


(सी०एस्०एस्०)
विरोध कार्याधिकारी
गा० वि० प्रा०

ग्राम कादराबाद (मोदीनगर) के खसरा नं० 642 मि० एवं 632 मि० पर हाई स्कूल/माध्यमिक भवन के निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में ।

श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री सीताराम, उप प्रबंधक, बालवारी स्कूल एवं श्रीमती रंजना जैन पत्नी श्री संजय कुमार जैन द्वारा उक्त खसरा नम्बरों की कुल 8685 वर्ग मीटर भूमि पर हाई स्कूल / माध्यमिक स्तर के बालवारी पब्लिक स्कूल हेतु मोदीनगर महायोजना-2001 की कृषि हरित पट्टी भूमि में स्वीकृति हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग मोदीनगर महायोजना एवं प्राधिकरण के नियोजन द्वारा सत्यापित अभिलेखों के अनुसार कृषि हरित पट्टी (पी-4) है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्थल के आस-पास एन०एच०-58 पर अनेक शिक्षण संस्थान के विकसित होने का उल्लेख कर अपने बालवारी पब्लिक स्कूल के मानचित्र को स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त क्रम में स्थल का निरीक्षण किया गया। प्रार्थी का स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग एन०एच०-58 पर स्थित हैं। जिसकी चौड़ाई महायोजना के अनुसार 250 फिट है। स्थल पर पक्ष द्वारा मिट्टी भराई एवं तीन कमरों का निर्माण कार्य करा लिया गया है। प्रश्नगत स्थल के उत्तर में भूखण्ड के सन्निकट डेन्टल कॉलेज चल रहा है। एन०एच०-58 की इसी पूर्वी पट्टी पर प्रश्नगत स्थल के सन्निकट की बी०एड एजुकेशन कॉलेज एवं शताब्दी पब्लिक स्कूल चल रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की पश्चिम दिशा की दूसरी पट्टी पर प्रश्नगत स्थल के निकट की तुलप पब्लिक स्कूल, महिला पॉलिटेक्निक एवं अन्य शिक्षण संस्थाएँ स्थित हैं।

शासन द्वारा अनुमोदित जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार महायोजना में निर्धारित कृषि हरित पट्टी में माध्यमिक शिक्षा हेतु भवन निर्माण की अनुमति सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अनुमन्य हैं।

प्रार्थी द्वारा एन०सी०आर० क्षेत्रीय योजना 2001 के प्राविधानों के अनुसार 100मी० चौड़ी कृषि हरित पट्टी छोड़ी जा रही है तथा स्थल का आकार भी पर्याप्त बड़ा है जिस कारण पार्किंग आदि का प्राविधान भी स्थल के भीतर हो सकेगा तथा मार्ग पर यातायात को बाँधा उत्पन्न नहीं होगी। इस सम्बन्ध में नियोजन की अन्य आवश्यकताओं के परीक्षण के उपरान्त स्थल पर प्रस्तावित कृषि क्षेत्र में स्कूल हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु संस्तुति प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु की जाती है।


(अनिल भटनागर)
एसोसिएट प्लानर
एन०सी०आर० सेल


(आशीष मेहरोत्रा)
सदस्य
गा० वि० प्रा०


(सी०एस०वर्मा)
विशेष कार्याधिकारी
गा० वि० प्रा०

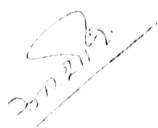
सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत उपसमिति की संस्तुति

मॉडर्न इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी सीकरी कलॉ, मोदीनगर द्वारा बी.एड. कालेज के लिये 9218.43 वर्ग मीटर पर भवन निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग प्राधिकरण के नियोजन अनुभाग की आख्या के अनुसार मोदीनगर महायोजना में पी-4 कृषि हरित पट्टी है।

महायोजना में प्रस्तावित कृषि हरित पट्टी में शासन द्वारा स्वीकृत जोनिंग रेगुलेशनस के अनुसार महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग / मेडिकल कालेज सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अनुमत्य है परन्तु प्रबन्ध संस्थान/विशिष्ट शैक्षिक संस्थान निषिद्ध है। बी.एड. के कोर्स प्रायः महाविद्यालयों में ही चलाये जाते हैं, अतः इस संस्थान को विशिष्ट शिक्षण संस्था की श्रेणी में मानना उचित प्रतीत नहीं होगा। जोनिंग रेगुलेशनस की परिभाषाओं में भी विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं को परिभाषित नहीं किया गया है, अतः इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा विचार कर अन्तिम निर्णय लिया जाना उचित होगा। आवेदक का स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग से 100 मी. से अधिक दूरी पर है, अर्थात् एन.सी.आर. क्षेत्रीय योजना-2001 के प्राविधानों के अनुरूप है। स्थल के निकट एक और शिक्षण संस्थान निर्माणाधीन है। अतः यदि बोर्ड द्वारा संस्थान को महाविद्यालय की श्रेणी में रखे जायें तो प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित कृषि क्षेत्र में मॉडर्न इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी के भवन निर्माण को अनुमत्य करने पर बोर्ड द्वारा विचार किये जाने की संस्तुति की जाती है। उपनियमों के अनुसार अनुमत्य कवर्ड एरिया, एफ.ए.आर. मानचित्र स्वीकृति के समय सुनिश्चित किये जाने आवश्यक होंगे।


(अनिल भटनागर)

सहयुक्त नियोजक
एन.सी.आर. नियोजन सेल


(आशीष मेहरोत्रा)

सदस्य,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण


(वी.सी. सिंह वर्मा)

विशेष कार्याधिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

मद संख्या 45

विषय : प्राधिकरण में ई0डब्ल्यू0एस0 वैशाली योजना में समर्पण / निरस्तीकरण के फलस्वरूप रिक्त हुए भवनों के मूल्यांकन हेतु ब्याज की गणना अवधि के पुनरीक्षण हेतु प्रस्ताव ।

बोर्ड बैठक दिनांक 23-8-96 के मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करते हुए यह निर्णय लिया गया था कि भवनों के मूल्यांकन हेतु मूल योजना के स्वीकृत मूल्य पर योजना की तिथि से 18 प्रतिशत ब्याज जोड़ते हुए मूल्यांकन गणना की जायेगी एवं 15-2-94 से 31-12-95 तक ब्याज मुक्त अवधि मानते हुए इस अवधि का कोई ब्याज नहीं जोड़ा जायेगा, परन्तु कुछ अलोकप्रिय योजना हेतु यह निर्णय लिया गया कि इनके अग्रिम आदेशों तक 15-2-94 के पश्चात का कोई ब्याज न जोड़ा जाये । वैशाली ई0डब्ल्यू0एस0 भवन योजना उक्त सन्दर्भित योजनाओं में से एक थी । तदनुसार ही वैशाली ई0 डब्ल्यू0एस0 भवनों का मूल्यांकन केवल 15-2-94 तक ब्याज लगाते हुए किया जा रहा है । अब क्योंकि ब्याज फ्रीजिंग के निर्णय को लगभग 7 वर्ष व्यतीत हो गये हैं, अतः इस निर्णय पर पुनः विचार करते हुए यह किया जाना है कि अब रिक्त भवनों को तत्काल आवंटन योजना में बेचने हेतु पूर्व निर्णय अनुसार ब्याज की गणना 15-2-94 तक सीमित रखी जाये अथवा अन्य योजनाओं की भांति 15-2-94 से 31-12-95 की अवधि छोड़कर शेष अवधि हेतु ब्याज जोड़ा जाये । यह उल्लेखनीय है कि ब्याज गणना 15-2-94 तक सीमित रखने पर प्रति भवन मूल्य रु0 80,000/- से 1,00,000/- तक आता है जबकि अध्यावधिक ब्याज लगाने पर यह मूल्य लगभग रु0 1.75 लाख से 1.90 लाख आयेगा जिसपर इन भवनों को बेचा जाना बहुत कठिन होगा । अतः पूर्व बोर्ड निर्णय दि0 23-8-96 के अनुसार ही भवनों का मूल्यांकन भवनों की जर्जर स्थिति व बाजार मूल्य को देखते हुए किया जाना उचित होगा ।

प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

मद सं० 46

विषय श्रीमती सुधा गुप्ता का परिवर्तन शुल्क माफी के सम्बन्ध में ।

श्रीमती सुधा गुप्ता द्वारा योजना सं० 615-41 डी आवेदन सं० 3523 द्वारा (ई०डब्ल्यू०एस) भूतल के भवन हेतु आवेदन किया गया था जिसके विपरीत दिनांक 02-1-92 में इन्हें भूतल का भवन आरक्षित किया गया दिनांक 15-6-94 में भुगतान विवरण जारी किया गया । भूतल का भवन उपलब्ध न होने के कारण प्रथम/ द्वितीय तल के भवन के लिए दिनांक 23-1-95 में आफर पत्र भेजा गया तद् दिनांक 5-10-96 में भूतल का भवन उपलब्ध न होने के कारण रिफण्ड हेतु सूचित किया गया । इसके उपरान्त आवंटी द्वारा प्राधिकरण के विरुद्ध वाद योजित कर दिया गया ।

आवंटी द्वारा अपने पत्र में लिखा गया कि ' यदि भवन 1992 के रेट पर उस पर ब्याज न जोड़ा जाये आवंटन मुमकिन न हो तो गोविन्दपुरम 'ए' ब्लॉक इन्दिरापुरम या वैशाली में 200 या 250 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित कर दिया जाये ।' इसपर सम्यक विचारोपरान्त उपाध्यक्ष द्वारा आदेश दिये गये कि ' यदि वाद वापस ले लेते हैं तो परिवर्तन शुल्क के साथ अनुमोदित ' इसी के अनुरूप आवंटी को भूखण्ड सं० एस० के०-3/ 699 इन्दिरापुरम आवंटन/ मागपत्र भेजा गया । अब आवंटी द्वारा तर्क रखा जा रहा है कि पूर्व भवन आवंटी को मिला ही नहीं है इस कारण परिवर्तन का प्रश्न पैदा ही नहीं होता । इसलिये परिवर्तन शुल्क लिया जाना न्यायसंगत नहीं है ।

अतः परिवर्तन शुल्क माफी का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

मद सं० ५७

विषय: भूखण्ड सं० 9, 10, 10-ए व 10 बी प्रताप विहार शिक्षक सहकारी आवास समिति को (सामुदायिक एवं शिक्षक भवन) पर देय लेवी भू-उपयोग परिवर्तन की तिथि तक प्राप्त करने व इसके पश्चात की लेवी माफ करने तथा 5 वर्ष का निर्माण हेतु समय प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड सं० 9, 10, 10-ए एवं 10 बी प्रताप विहार शिक्षक सहकारी आवास समिति को आवंटित किये गये थे । समिति द्वारा चारों भूखण्डों को सामुदायिक केन्द्र / शिक्षक भवन में परिवर्तन करने की मांग की गयी है । उपरोक्त भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 672.58 वर्गमी० है । भूखण्डों को आवासीय से सामुदायिक केन्द्र में परिवर्तन की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 29-6-2001 को दी जा चुकी है । चूंकि प्रश्नगत भूखण्डों की लीज डीड दिनांक 4-11-93 को हो चुकी थी । अतः रजिस्ट्री से 5 वर्ष का समय देते हुए निर्माण दिनांक 4-11-98 से पूर्व होना था । अतः दिनांक 4-11-98 से लेवी देय होती है जिस कारण नियमानुसार दिनांक 4-11-98 से अब तक की लेवी वर्तमान दर पर सरचार्ज के रूप में देय होती है जो दिनांक 28-2-2004 तक 2 प्रतिशत की दर से अंकन रुपये 2,11,862-00 होती है परन्तु समिति का कथन है कि जिस तिथि को भू-उपयोग परिवर्तन हुआ है तब तक की लेवी ले ली जाये और भू-उपयोग परिवर्तन के उपरान्त भवन निर्माण का समय 5 वर्ष हेतु दिनांक 22-10-2007 तक का प्रदान कर दिया जाये ।

प्रस्ताव बोर्ड बैठक के समक्ष विचारार्थ / निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।



28/11/04

मद सं० : ५८

विषय : भूखण्ड सं० आर-171 नन्दग्राम पर देय चौकीदारा शुल्क माफ करने के सम्बन्ध में ।

भूखण्ड सं० आर-171 नन्दग्राम श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द गुप्ता को आवंटित है, जिसका क्षेत्रफल 26.56 व०मी० है । भूखण्ड का कुल मूल्य 6319/- मात्र है तथा चौकीदारा शुल्क दिनांक 1-1-89 से दिनांक 31-12-2003 तक रू० 27495-00 मात्र है । श्रीमती गायत्री देवी द्वारा अपने पति के पैरालिसिस की बीमारी के कारण अपने भूखण्ड का स्थल कब्जा नहीं लिया जा सका है । इनके द्वारा अपने पति की बीमारी के कारण उक्त चौकीदारा शुल्क जमा करने में असमर्थता व्यक्त की गयी है तथा चौकीदारा शुल्क माफ करने का अनुरोध किया गया है । अतः इनकी दयनीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भूखण्ड सं० आर-171 नन्दग्राम पर देय चौकीदारा शुल्क रू० 27495-00 मात्र माफ किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

Ne
28.1.24

मद सं० ५१

विषय : महाविद्यालय श्रेणी के दो विद्यालयों का मानचित्र स्वीकृत किये जाने विषयक

गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत महाविद्यालय स्तर के दो संस्थाओं के मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

- 1- पशुपति इन्स्टीट्यूट आफ स्टडीज द्वारा बी०एड० की शिक्षा हेतु खसरा नं० 547 ग्राम दुहाई मेरठ रोड गाजियाबाद क्षेत्रफल लगभग 8998 वर्ग मीटर द्वारा महाविद्यालय का मानचित्र कृषि भू-उपयोग भूमि से शिक्षण संस्थान में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु अनुरोध किया है ।
- 2- इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर हेतु बी०आर० जनसेवा सोसायटी द्वारा खसरा नं. 446 रकबा लगभग 16510 वर्गमीटर की औद्योगिक भू-उपयोग भूमि को शिक्षण संस्थान में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु अनुरोध किया गया है ।

वर्तमान में जनपद गाजियाबाद में शिक्षा का स्तर सुधारने के दृष्टिकोण से उक्त दोनों संस्थाओं का भू-उपयोग कृषि तथा औद्योगिक से शिक्षण संस्थान हेतु किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

मद सं० 50

विषय: बिन्सार कोपरेटिव सोसायटी को इन्दिरापुरम में अभयखण्ड -4 में मोडयूल-1 को जारी भुगतान विवरण दिनांक 11-8-99 से 31-1-2004 तक अक्टूबर 1999 में जारी भुगतान विवरण में प्रेषित शर्तों के अनुसार भुगतान विवरण बढ़ाने के सम्बन्ध में ।

बिन्सार कोपरेटिव सोसायटी को इन्दिरापुरम योजना के अभय खण्ड-4 मोडयूल एक निविदा के आधार पर आवंटित किया गया था । मोडयूल का मुल मूल्य रु० 3,61,11,0001-00 प्राप्त हुआ था जिसे बोर्ड बैठक दिनांक 26-9-98 में स्वीकृति हेतु रखा गया था जिसे बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया एवं सोसायटी को दिनांक 28-10-1998 को आवंटन पत्र जारी कर दिया गया था । प्राधिकरण द्वारा जारी भुगतान विवरण के अनुसार समय समय पर धनराशि जमा की जाती रही है ।

बिन्सार कोपरेटिव सोसायटी द्वारा अनुरोध किया गया कि कुछ लोगों द्वारा मालिकाना हक को लेकर एम०आर०टी०पी० में वाद दायर करने व उक्त वाद के कारण आवंटी पैसा देने में झिझक रहे हैं ,इसके बावजूद भी पत्र द्वारा समय समय पर भुगतान विवरण के अनुसार धनराशि जमा की जाती रही ।

पक्ष द्वारा पूर्व में अनुरोध किया गया था कि जिस अवधि में एम०आर०टी०पी० में वाद चलता रहा है इस अवधि को शून्य पीरियड मानते हुए इस अवधि का भुगतान विवरण आगे बढ़ा दिया जाये । पक्ष द्वारा वर्णित परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर थीं इसलिए कदाचित वे भुगतान विवरण के अनुसार धनराशि आगे जमा नहीं कर पाये ।

इन्दिरापुरम योजना के अभयखण्ड-4 के अर्द्धनिर्मित व भवनों में दो मोडयूल बेचे गये थे । अभयखण्ड-4 मोडयूल (एक) बिन्सार कोपरेटिव को व अभयखण्ड-4 मोडयूल(2) मीडिया टाईम्स सहकारी आवास समिति को आवंटित किया गया है ।

मीडिया टाईम्स सहकारी आवास समिति को व बिन्सार कोपरेटिव सोसायटी को दिनांक 11-8-1999 से 20-10-2000 को शून्य पीरियड मानने के आदेश पूर्व में बोर्ड द्वारा दिनांक 20-2-2003 की बैठक में दिये गये थे परन्तु समिति द्वारा धनराशि जमा नहीं की गयी एवं उक्त सुविधा मीडिया टाईम्स को भी दी गयी थी ।

अब बिन्सार कोपरेटिव सोसायटी द्वारा कहा गया है कि उक्त सदस्य मध्यम श्रेणी के हैं एवं विष्णु दत्त डिमरी पावर ग्रेड कारपोरेशन आफ इन्डिया का वाद अभी भी विचाराधीन बताया गया है ।

अतः बिन्सार कोपरेटिव सोसायटी को दिनांक 11-8-1999 से 31-1-2004 तक के पीरियड को शून्य मानने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रेषित है ।

मद संख्या. 51

विषय:- राजेन्द्रनगर एवं शालीमार गार्डन कालोनी में 500 वर्गमीटर से बड़े भूखण्डों पर अतिरिक्त चौथी मंजिल की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

भूखण्डीय विकास के अंतर्गत शासन द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2000 में संशोधन करते हुए आवास अनुभाग-1 के पत्र संख्या 553 /9-आ-1-29 विविध /98 दिनांक 25-01-2003 में निर्देश दिये गये हैं कि "500 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्ड जो 24 मीटर अथवा अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित हैं, में भू-आच्छादन के बराबर अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुमन्य होगा और भवन की अधिकांश ऊंचाई 15 मीटर (चार मंजिल) होगी । चार मंजिल का तात्पर्य स्टिल्ट - चार तलों से है । अतिरिक्त तल क्षेत्रफल हेतु सम्बन्धित कालोनी के वर्तमान लागत पर आगणित विकास शुल्क आन्तरिक एवं बाह्य का 50 प्रतिशत प्रभार शुल्क देय होगा, परिधार किया गया है ।" (प्रतिलिपि संलग्न) । इसके साथ-2 आवास अनुभाग के पत्र संख्या 4141 /9-आ-1-29 विविध /98 अनुभाग-1 दिनांक 29-08-2003 के द्वारा आदेश दिये गये हैं कि उक्त प्रकृति के भवन मानचित्र तकनीकी समिति के परीक्षणोपरांत प्राधिकरण बोर्ड बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे । (प्रतिलिपि संलग्न)

उपरोक्त के सन्दर्भ में भूखण्ड संख्या ए-3 शालीमार गार्डन-11, भूखण्ड संख्या ए-36 शालीमार गार्डन-1, भूखण्ड संख्या 8 /3 राजेन्द्रनगर-111 व भूखण्ड संख्या 28 शालीमार गार्डन-1 के भू-आच्छादन के बराबर चौथी मंजिल के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो कि निर्धारित बाईलाज एवं शासनादेश के अंतर्गत नियमानुसार उचित हैं ।

अतः शासनादेश के क्रम में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।



संख्या: 553/9-आ-1-201/मिनि/08 (आ.व.)

प्रपक,

श्री जे. एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
रामरत विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 25 जनवरी, 2003

विषय: भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत भवन की अधिकतम ऊँचाई, तलों की संख्या, सेट-बैक, भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. तथा इकाईयों की संख्या के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत बहुमंजिले निर्माण के विनियमन से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 3001/9-आ-3-2001-19 विविध/2001 दिनांक 29.8.2002 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उक्त शासनादेश के अनुसार "लो-राईज" निर्माण हेतु निर्दिष्ट मानकों तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में विद्यमान प्राविधानों के दृष्टिगत भवन की अधिकतम ऊँचाई एवं तलों की संख्या के सम्बन्ध में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, ग्रुप हाऊसिंग के लिए भूखण्ड का न्यूनतम आकार 2000 वर्ग मीटर निर्धारित कर दिए जाने के फलस्वरूप 1000 वर्ग मीटर से अधिक एवं 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड एकल भवन की परिधि में आ गए हैं, अतः ऐसे भूखण्डों हेतु सेट-बैक, भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं इकाईयों की संख्या से सम्बन्धित मानकों का भी निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

2. इस सम्बन्ध में शासन को प्राप्त प्रत्यावेदनों में इंगित विसंगतियों पर सम्यक विचारोपरान्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000, शासनादेश संख्या 3001/9-आ-3-2001-19 विविध/2001 दिनांक 29.8.2002 एवं अन्य संगत शासनादेशों में निहित भवन की अधिकतम ऊँचाई, तलों की संख्या, सेट-बैक, भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. तथा इकाईयों की संख्या सम्बन्धी प्राविधानों में मुझे निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है -

2.1 भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के एकल भवनों की अधिकतम ऊँचाई 12.5 मीटर (तीन मंजिल) अनुमत्य है, जिसका तात्पर्य है कि डिप्ले फ्लोर के अतिरिक्त तीन मंजिल का निर्माण अनुमत्य होगा। स्टिप्ट फ्लोर का प्राविधान न किए जाने की दशा में मंजिलों की अधिकतम संख्या तीन ही अनुमत्य होगी। परन्तु भवन उपविधि, 2000 के प्रस्तर- 3.5.1 में यह भी प्राविधान है कि 300 वर्ग मीटर या अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्ड जो 24 मीटर या अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित हैं, में भू-आच्छादन के बराबर

मिनि (अ.व.)
मिनि (अ.व.)

25/1/03
CATP

अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुमन्य होगा और भवन की अधिकतम ऊँचाई चार मंजिल होगी। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 3001/9-आ-3-2001-19 विविध/2001 दिनांक 29.8.2002 के अनुपालन में अगल-बगल स्थित भूखण्डों की "प्राइवैसी" तथा "लाइट एण्ड वेन्टीलेशन" की अपेक्षाओं के दृष्टिगत उक्त प्राविधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

500 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्ड जो 24 मीटर अथवा अधिक चौड़ाई पर स्थित हैं, में भू-आच्छादन के बराबर अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुमन्य होगा और भवन की अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर (चार मंजिल) होगी। चार मंजिल का तात्पर्य स्टिल्ट+चार तलों से है। अतिरिक्त तल क्षेत्रफल हेतु सम्बन्धित कालोनी के वर्तमान लागत पर आगणित विकास शुल्क (आन्तरिक एवं वाह्य) का 50 प्रतिशत प्रभार शुल्क देय होगा। स्टिल्ट फ्लोर को अन्तर्गत किया गया अवैध निर्माण शमनीय नहीं होगा तथा स्टिल्ट को पार्किंग के अतिरिक्त अन्य उपयोग से लाए जाने पर नियमानुसार वैधानिक/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। उक्त प्रकृति के भवन मानचित्र विकास प्राधिकरण में पूर्व गठित समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। समिति की अध्यक्षता विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा आवास एवं विकास परिषद के प्रकरण में आवास आयुक्त द्वारा की जाएगी।"

2.2 शासनादेश संख्या 3001/9-आ-3-2001-19 विविध/2001 दिनांक 29.8.2002 के अनुसार भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत 2000 वर्ग मीटर से अधिक परन्तु 4000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग/अन्य भवनों की अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर (चार मंजिल) अनुमन्य है, जिसका तात्पर्य है कि स्टिल्ट फ्लोर के अतिरिक्त चार मंजिल (स्टिल्ट+चार मंजिल) का निर्माण अनुमन्य होगा।

2.3 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के अनुसार एकल आवास में 500 वर्ग मीटर से अधिक एवं 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु सेट-बैक निर्धारित हैं। शासनादेश संख्या 3001/9-आ-3-2001-19 विविध/2001 दिनांक 29.8.2002 द्वारा ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड का न्यूनतम आकार 2000 वर्ग मीटर कर दिए जाने के फलस्वरूप 1000 से अधिक एवं 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड भी एकल भवन की परिधि में आ गए हैं, अतः 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों के लिए सेट-बैक निम्न तालिकानुसार होंगे :-

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सेट-बैक (मीटर)			
	सामने	पीछे	साइड-1	साइड-2
• 501-1000	6.0	6.0	3.0	1.5
• 1001-1500	9.0	6.0	4.5	3.0
• 1501-2000	9.0	6.0	6.0	6.0

2.4 ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड का न्यूनतम आकार 2000 वर्ग मीटर निर्धारित कर दिए जाने के फलस्वरूप 500 वर्ग मीटर से अधिक एवं 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भवनों हेतु भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं इकाईयों की संख्या से सम्बन्धित मानकों को भी पुनर्निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि भूमि का "आप्टिमम" उपयोग सुनिश्चित हो सके। अतः

नगरों की महागोजनाओं में प्रस्तावित औसत जनसंख्या घनत्व को दृष्टिगत रखते हुए भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं इकाईयों की संख्या निम्न तालिकाानुसार अनुमान्य होगी :-

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	भू-आच्छादन (प्रतिशत)	एफ.ए.आर.	अनुमान्य इकाईयों की संख्या		
			प्रकार सहित	प्रकार सहित	कुल इकाईयों
• 501-750	45	1.25	5	3	8
• 751-1000	45	1.20	6	4	10
• 1001-1500	40	1.20	8	6	14
• 1501-2000	40	1.20	10	8	18

- 2.5 भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत एकल भूखण्डों (2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल) पर 12.5 मीटर ऊँचाई तक के भवन निर्माण हेतु सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होगी।
- 2.6 विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में निहित तथा पूर्व में जारी संयुक्त शासनादेशों के प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे।
- 2.7 उपर्युक्त प्राविधान उन मानचित्रों पर भी लागू होंगे जो स्वीकृति हेतु जमा हैं, परन्तु स्वीकृत नहीं हुए हैं।
3. कृपया उपरोक्त आदेशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(जे. एस. मिश्र)
सचिव

संख्या: 553 (1)/9-आ-1-29विधि/98 (आ.व.) तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी आवास संघ लि., लखनऊ।
5. अध्यक्ष, यू.पी.आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
6. अध्यक्ष, यू.पी.रेडको, लखनऊ।
7. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से
(संयुक्त मूहसिली)
निर्माण अधिकारी

19/200

संख्या-11111/9-आ-1-20विधि/98(आ.व)

प्रेषक,

श्री जे.एस.मिश्र
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सीमा में,
1-

आवास आयुक्त,
उप आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2-

उपाध्यक्ष,
नगर विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 22 अगस्त, 2003

विषय: मुख्यण्डीय विकास के अन्तर्गत भवन की अधिकतम ऊँचाई, तलबो संख्या, सेट-बैक, गू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. तथा इकाईयाँ संख्या से संबंधित शासनादेश दिनांक 25.01.2003 में संशोधन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या-553/9-आ-1-20विधि/98 दिनांक 25.01.03 का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2.1 में यह प्राविधान है कि 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्ड, जो 24 मीटर अथवा अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है में गू-आच्छादन 3 मीटर (चार मजिल) होगी। परन्तु उक्त प्रकृति के भवन मानचित्र विकास प्राधिकरण में पूर्व गठित समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायें और समिति की अध्यक्षता विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। प्रश्नगत प्राविधान के संशोधन में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15(3) के अन्तर्गत उपाध्यक्ष को ही यह अधिकार है कि वह भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करें। उपाध्यक्ष के निर्णय से मुख्य व्यक्ति धारा-15(5) के अधीन अलग से अपील कर सकता है। ऐसे में अध्यक्ष द्वारा मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया धारा-15(5) के अधीन कोई भी कार्यवाही विचारणीय नहीं होगी और वह भी अपील ही आदेशों के विरुद्ध सुनी पड़ेगी। उक्त के दृष्टिगत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने शासनादेश दिनांक 25.01.2003 में पुनर्विचार करते हुए आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया है।

2- इस संघ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उठाया गया बिन्दु विधिसंगत है। अतः शासन द्वारा समर्थन

AWAS-I.G.O. (10) 000/98
19-8/11-98
19/8
19/8

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्ड, जो 24 मीटर अथवा अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित हैं, के भू-आच्छादन के बराबर अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुमत्य होगा, और भवन की अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर (चार मजिल) होगी। परन्तु उक्त प्रकृति के भवन **आवासीय तकनीकी समिति के परामर्शोपरान्त विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।**

3- कृपया शासनादेश संख्या-553/9-आ-1-29 विविध/98 दिनांक 25.01.2001 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(ज.एस.मिश्र)
सचिव।

संख्या-1114/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.व.) तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- अध्यक्ष, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
- 2- अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 3- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर भारतीय सहकारी आवास निगम, लखनऊ।
- 5- अध्यक्ष, यू.पी. आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
- 6- अध्यक्ष, यू.पी. रेडको, लखनऊ।
- 7- अपर निदेशक नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से

(संजय गुप्ता रेड्डी)
विशेष सचिव।

मद सं० 52

विषय : स्व० वित्त पोषित आधार पर थोक विक्रेताओं की मार्बल मार्केट के विकास के लिए प्रस्ताव

गाजियाबाद शहर में मार्बल पत्थर आदि की दुकानें बनी हुई हैं जिसके द्वारा सड़क के किनारे का भाग भी घेर लिया जाता है। इससे यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है तथा उस विशेष क्षेत्र की छवि भी खराब होती है।

मार्बल एसोसिएशन सोसायटी(रजि) का यह अनुरोध है कि एन०एच०-24 के दक्षिण में ग्राम डूडाहेडा की लगभग 50 एकड़ जमीन को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अधिग्रहण करे। इस भूमि को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उचित दर पर एसोसिएशन को देगा एवं एसोसिएशन अपने सदस्यों के बीच आवश्यकतानुसार (बिना किसी लाभ हानि) के वितरित करेगा। जिससे गाजियाबाद तथा नोएडा के समक्ष मार्बल व्यापारियों को व्यापार करने का एक अलग स्थान मिल जायेगा तथा शहर के वातावरण का भी सुधार होगा।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त मार्बल एसोसिएशन की योजना को मंजूरी देने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

स्वः वित्त पोषित आधार पर थोक विक्रेता
मारबल मार्किट के विकास के लिए प्रस्ताव

गाजियाबाद में मारबल डीलर एसोसिएशन की मांग है कि गा0बाद शहर के आन्तरिक भाग जिसमें नोयडा सम्मिलित है एवं वाहनों के स्वतन्त्र संचालन के लिए मारबल डीलरों का हटाया जाना आवश्यक है। इसके साथ-2 आवासीय क्षेत्र का वातावरण प्रभावित हो रहा है। यद्यपि प्राधिकरण, इस योजना को लाभ के लिए व्यवसायिक आधार पर ले सकता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-24 के पूर्व की भूमि, जो अनाधिकृत कॉलोनी के पीछे उपलब्ध है, उसमें से 30 एकड़ भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है $1/2$ कि0मी0 $\times$ 50 मीटर भूमि की पट्टी इसके लिए उपयुक्त है।

$30 \times 400 =$	1,20,000.00 वर्ग मी0
$500 - 500 =$	25,000.00 वर्ग मी0
	1,45,000.00 वर्ग मी0

अर्जन व्यय = $\text{रु0 } 350 \times 14,500 = \text{रु0 } 5.07$ करोड़

कुल विक्रय योग्य क्षेत्र $\text{रु0 } 1,20,000.00$ का 80% जो 96,000। $\text{रु0 } 3500 = \text{रु0 } 3360$ करोड़

निम्नलिखित शर्तों पर मारबल डीलर एसोसिएशन को भूमि आवंटन का प्रस्ताव है।

आरक्षित मूल्य $\text{रु0 } 3500/-$ प्रति वर्ग मीटर

प्रवेश मार्ग जी.डी.ए. द्वारा बनाया जायेगा। जी.डी.ए. द्वारा सीवर कनेक्शन, वाटर सप्लाई नहीं की जायेगी। एसोसिएशन द्वारा स्ट्रीट लाईट, आन्तरिक सड़के, फुटकर/थोक विक्रेताओं को व्यक्तिगत विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे।

लाभांश

भूमि मूल्य	$\text{रु0 } 5.07$ करोड़
प्रवेश मार्ग मूल्य	$\text{रु0 } 3.50$ करोड़
$1/2$ किमी0 $\times$ 8 लेन	$\text{रु0 } 8.57$ करोड़
	(8.60 करोड़)
विक्रय मूल्य =	$\text{रु0 } 33.60$ करोड़
कीमत घटाने पर =	$\text{रु0 } 8.60$ करोड़
लाभ -	$\text{रु0 } 25.00$ करोड़

इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण सम्बन्धी उद्देश्य की पूर्ति होगी और प्राधिकरण को एक योजना मिलेगी, जो अवस्थापना, सुविधाओं को मजबूत करने में प्रयोग हो सकेगी। प्राधिकरण विजन स्टेटमेंट यह अनुचिन्हित करता है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण समस्त व्यापार केंद्र बन सकेगा।

मद सं० 53

विषय: गोविन्दपुरम योजना के 'ए' ब्लॉक स्थित स्कूल की भूमि पर जा रहे हाई-टेंशन लाईन के नीचे की भूमि का भू-उपयोग स्कूल से ग्रीन किये जाने के सम्बन्ध में ।

गोविन्दपुरम योजना के 'ए' ब्लॉक स्थित स्कूल की भूमि पर विद्युत की हाई-टेंशन लाईन जा रही है, क्योंकि ले-आउट से ही मौके की स्थिति थोड़ी भिन्न होने के कारण तथा जानकारी न होने के कारण उक्त भूमि को ब्राइट लैण्ड स्कूल को आवंटित कर दिया गया । स्कूल को कब्जा भी दे दिया गया । चूंकि उक्त लाईन एक किनारे पर सैटबैक के क्षेत्र में पड़ती है, अतः स्कूल का भवन उक्त सैट बैक में अनुमन्य नहीं है, जो स्कूल बनाया गया है वह स्थल को छोड़कर ही बनाया गया है ।

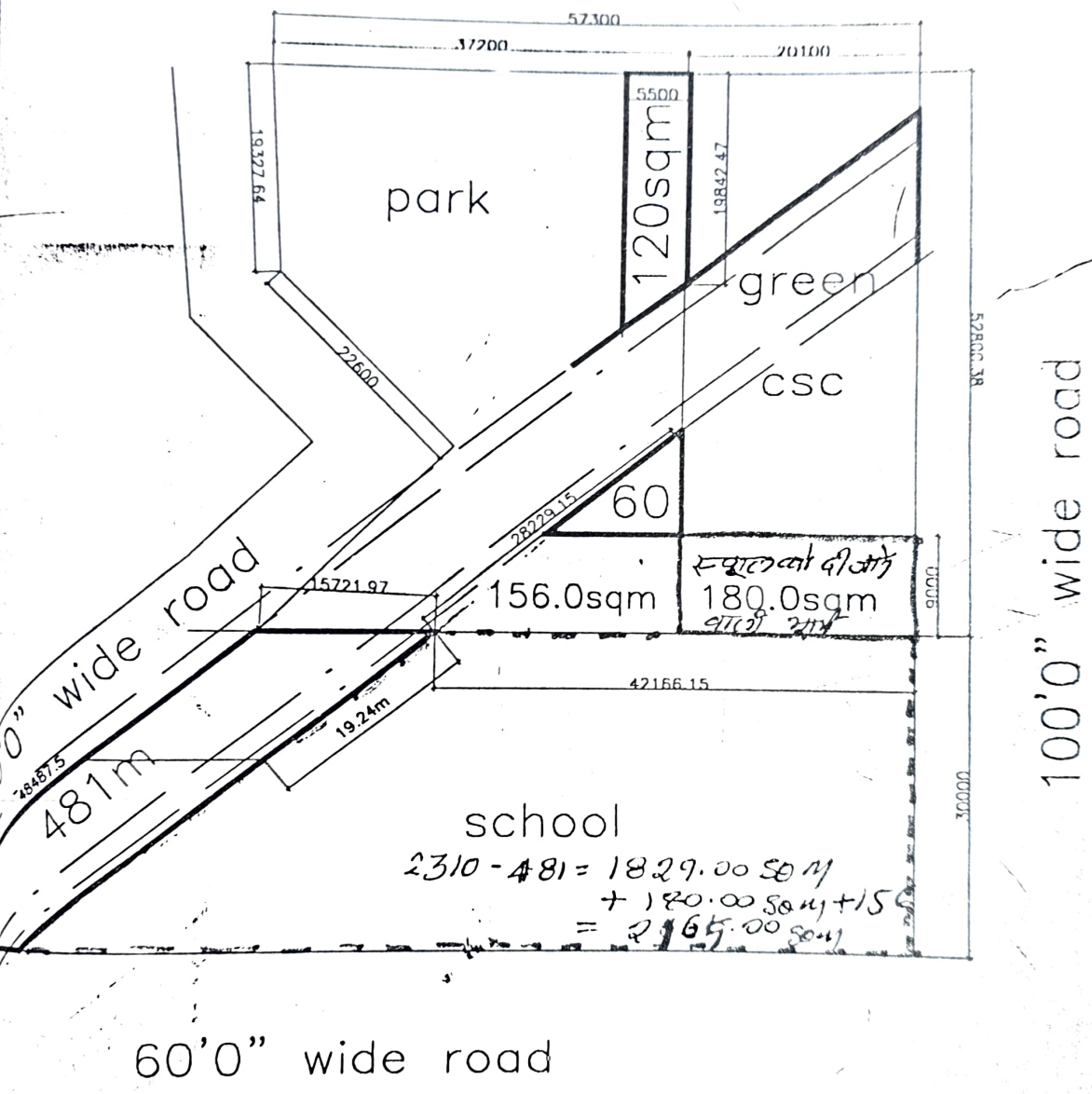
स्कूल के प्रबन्धक द्वारा प्रार्थना की गयी है कि हाई-टेंशन लाईन के नीचे हाई-टेंशन लाईन से प्रभावित 481 वर्गमीटर भूमि के बदले स्कूल को समीप में ही अन्य भूमि दी जाये । उक्त परिपेक्ष्य में मौके की स्थिति तथा ले-आउट को दृष्टिगत रखते हुए स्थल के बगल में कनविनियन्ट शोपिंग की $9.00 \times 20 = 180$ वर्गमीटर है तथा पार्क की भूमि में 156 वर्गमीटर भूमि है, जिसे दिया जा सकता है ।

प्रस्ताव के साथ स्थल स्केच से स्पष्ट है कि कनविनियन शोपिंग की व्यवसायिक में से 180 वर्गमीटर तथा पार्क की भूमि से 156 वर्ग मीटर अर्थात् 336 वर्गमीटर भूमि स्कूल का दिया जाना प्रस्तावित है । व्यवसायिक भूमि 180 वर्गमीटर जो कम होगी उतनी पार्क की भूमि को कनविनियन शोपिंग के लिए नियोजित कर दिया जाये तथा हाईटेंशन लाईन के नीचे वाली 481 वर्गमीटर भूमि को पार्क के लिए नियोजित कर दिया जाये । इस प्रकार पूर्व नियोजित पार्क की $180 + 156 = 336$ वर्गमीटर भूमि कम होगी व हाईटेंशन लाईन के नीचे वाली 481 वर्ग मीटर भूमि पार्क के लिए नियोजित करने पर पूरी हो जायेगी और स्कूल को स्कूल को हाईटेंशन लाईन के कारण 481 वर्गमीटर भूमि कम होने के कारण 336 वर्गमीटर भूमि मिल सकेगी । इस प्रकार स्कूल को कुल भूमि 2310 वर्गमीटर भूमि में से 2165 वर्गमीटर भूमि ही रह जायेगी । उक्त प्रक्रिया में ले-आउट भी परिवर्तन का मामला निहित है, जिसका अधिकार प्राधिकरण बोर्ड को है । उक्त परिवर्तन हेतु आम जनता से आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किये जा रहे हैं, जो आगामी बोर्ड बैठक में पुनः प्रस्तुत किये जायेंगे ।

अतः विवेचित परिस्थितियों में हाईटेंशन लाईन से स्कूल की 481 वर्गमीटर भूमि को पार्क के रूप में तथा पार्क की 481 वर्गमीटर भूमि व्यवसायिक के रूप में तथा व्यवसायिक की 180 वर्गमीटर स्कूल के रूप में परिवर्तित किये जाने हेतु प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 23-6-2003 में प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव पुनः बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।



201
H



low
156
336

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 31-01-2004 का कार्यवृत्त

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 92वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31-01-2004 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा भाग लिया गया : -

- 1- श्री जय शंकर मिश्र, अध्यक्ष-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण / सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- श्री डी०पी० सिंह, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
- 3- श्री सन्तोष कुमार यादव, जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 4- श्री आर०बी०मौर्य, नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
- 5- श्री एस०के० जमान, चीफ काउन्सिलर, एन०सी० आर० सैल, गाजियाबाद - मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ के प्रतिनिधि।
- 6- श्री भुकेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद-प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के प्रतिनिधि।
- 7- श्री अनिल स्वामी सदस्य (गैर सरकारी) (नगर निगम, गाजियाबाद) गा० वि० प्रा०।
- 8- श्री सतीश चोपड़ा सदस्य (गैर सरकारी) (नगर निगम, गाजियाबाद) गा० वि० प्रा०।
- 9- श्री एम० एफ० आजाद सदस्य (गैर सरकारी) (नगर निगम, गाजियाबाद) गा० वि० प्रा०।
- 10- श्री अमनदीप सदस्य (गैर सरकारी) (नगर निगम, गाजियाबाद) गा० वि० प्रा०।

बैठक प्रारम्भ से पूर्व अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों का औपचारिक परिचय प्राप्त किया गया तथा नव वर्ष की शुभकामनाएँ दी गयीं। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई एवं विचार विमर्श के उपरान्त सर्व-सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :-


J.P.M.

क्रम सं०	विषय	निर्णय
1-	प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 23-6-2003 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23-6-2003 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गयी।
2-	प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 23-6-2003 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या।	प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 23-6-2003 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई। बोर्ड बैठक दिनांक 23-6-2003 की अनुपालन आख्या के बिन्दु संख्या-3 में स्टैकिंग चार्जेज के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि स्टैकिंग चार्जेज का भुगतान गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को किया जाए। प्रथम किश्त का भुगतान 15 फरवरी-04 तक किया जायेगा। किश्तों का भुगतान विवरण उपाध्यक्ष एवं नगर आयुक्त द्वारा आपसी सहमति से निर्णित किया जायेगा। दिनांक 1-4-2003 से 15-12-03 तक निर्माण एवं विकास कार्यों पर किए गए विस्तृत विवरण चार्ट में विभिन्न कार्यों में विचलन की धनराशि का उल्लेख किया गया है, किन्तु विचलन यदि 10 प्रतिशत से अधिक हो तो क्यों एवं किस कारण हुआ, का उल्लेख किया जाये। इसके अतिरिक्त निर्माण/विकास कार्यों की मूल/पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत की लागत एवं दिनांक का भी विवरण दिया जाये।

9 JPSK

भविष्य हेतु निर्देश दिए गए कि चार्ट में इन सूचनाओं हेतु कालम अलग से हो एवं पूर्ण विवरण उपलब्ध रहे। विभागीय रूप से कराये जा रहे (सिविल एवं विद्युत) निर्माण कार्यो एवं कराये जाने वाले निर्माण कार्यो का भी पूर्ण विवरण दिया जाये।

मद संख्या 9 में पूर्व में लिये गये निर्णय जो कि 4 मंजिले फ्लैटों में स्टिल्ट के साथ पडोसी से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्वीकृति करने का निर्णय लिया गया था, के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी। सदस्यों का मत था कि यदि शासनादेश स्पष्ट है तो इस तरह की शर्त जोड़ना औचित्य पूर्ण नहीं है। अतः पुनर्विचार कर निर्णय लिया गया कि उक्त निर्णय को इस सीमा तक संशोधित किया गया कि पडोसियों से अनापत्ति लेने की आवश्यकता नहीं है और शासनादेशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3-

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अलोकप्रिय अनिस्तारित सम्पत्ति का मूल्यांकन हुडको से कराकर ज्वाइंट वेंचर के आधार पर विक्रय करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। जी0डी0ए0 द्वारा हुडको से अपनी सम्पत्तियों के कराये गये मूल्यांकन को आरक्षित मूल्य मानते हुए राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से विस्तृत प्रचार करके नीलामी के माध्यम से सम्पत्तियों का निस्तारण कराया जाये।

इसके उपरान्त भी जो सम्पत्तियां अनिस्तारित रह जाये, उन्हें ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से निस्तारण हेतु

8 JPSL

4

विस्तृत टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टो.ओ.आर.) बनाकर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर ऑफर प्राप्त किये जाये।

4-

शाहदरा से गाजियाबाद तक दिल्ली मेट्रो के निर्माण का अनुमोदन।

प्रस्ताव की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी। विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु डी०एम०आर०सी० को प्राधिकरण/ उ०प्र० सरकार का अंश रु० 42.00 लाख (60 प्रतिशत) के भुगतान हेतु भी स्वीकृति प्रदान की गयी, शेष 40 प्रतिशत के लिए प्रस्ताव को उ०प्र० शासन के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किए जाने हेतु भी स्वीकृति प्रदान की गयी। डी.पी.आर. तैयार हो जाने पर पूर्ण प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये। प्रस्ताव की प्रगति की समीक्षा हेतु निम्न समिति भी गठित की जाती है :-

- 1- उपाध्यक्ष
- 2- सचिव
- 3- मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक

4क

मेट्रो रेल के निर्माण हेतु अर्थ प्रबन्ध।

उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव वापिस लिया गया।

5-

राष्ट्रीय राज मार्ग -58 दिल्ली सीमा से मेरठ तक 6 लेन डिवाइडिड एक्सप्रेस वे का

प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली-गुडगांव के मध्य निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी प्राप्त करने का

बी0ओ0टी0पर निर्माण के सम्बन्ध में विचार व प्रस्ताव एम0एस0टी0 को प्रेषण ।

प्रयास किया जाये। प्रस्ताव का एक प्रस्तुतीकरण शासन स्तर पर करने हेतु भी निर्देश दिए गए ।

6- राष्ट्रीय राज मार्ग 58 (मेरठ रोड) एवं राष्ट्रीय राज मार्ग 24 (हापुड रोड) बाई पास को जोड़ने हेतु 6 लेन लिंक रोड के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया। वित्त पोषण, टोल टैक्स, साईट सर्विसेज का प्राविधान आदि मदों के परीक्षण हेतु निम्न समिति गठित की जाती है -

- 1- उपाध्यक्ष - अध्यक्ष
- 2- जिलाधिकारी, गाजियाबाद-सदस्य
- 3- सचिव-सदस्य
- 4- नगर आयुक्त-सदस्य
- 5- मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक-सदस्य
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0आवास विकास परिषद-सदस्य ।

7- प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के भूखण्डों के ले-आउट प्लान के पुर्ननियोजन / भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

इन्दिरापुरम योजना ले-आउट प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया एवं निर्देशित किया गया कि जन सुविधायें जैसे स्कूल, पुलिस स्टेशन, चिकित्सा सुविधा इत्यादि की व्यवस्था ले-आउट में करने के पश्चात ले आउट में भूखण्डों के पुर्ननियोजन / भूउपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव अगली बोर्ड की बैठक में रखा जाये।

कौशाम्बी योजना के भूखण्ड सख्या -2 के भू उपयोग आवासीय (समूह आवासीय) से व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। साथ ही यह निर्देश भी दिये गये कि

 18/5/14

अवस्थापना सुविधाएं भी देख ली जाए एवं इस क्षेत्र से लगे गाँव का विकास भी किया जाए। क्षेत्र से लगे गांव के विकास हेतु इस नीलामी से प्राप्त 30 प्रतिशत धन को सम्बन्धित निर्माण खण्ड से विकास कार्य कराने हेतु आवंटित कर दिया जाये।

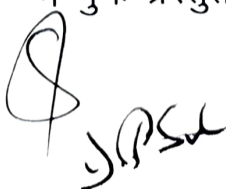
कौशाम्बी योजना के भूखण्ड जो कि क्षेत्रफल 8000 व०मी० का अस्पताल के लिए आरक्षित है, के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि पहले 15 दिन के अन्दर इसकी नीलामी की कार्यवाही की जाए तदोपरान्त क्या स्थिति आती है, के उपरान्त यदि निस्तारित नहीं होता है तो आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जाए।

प्रताप विहार योजना के 3765 व०मी० भूखण्ड क्षेत्रफल के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि कन्वीनियंट शॉपिंग हेतु पुर्ननियोजन किया जाए, जिसमें नीचे दुकानें हों व ऊंपरी मंजिल पर आवासीय भवन हों। निर्माण भूतल एवं प्रथम तल पर ही अनुमन्य होगा।

8-

नेहरुनगर योजना के
सैक्टर-3 स्थित एच
ब्लाक में 367.19
व०मी० व्यवसायिक भूखण्ड
का भू-उपयोग आवासीय
परिवर्तन के सम्बन्ध में।

यह निर्णय लिया गया कि मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य श्री अनिल स्वामी की एक समिति गठित कर ली जाए जो स्थल का निरीक्षण कर ले और यदि समिति द्वारा प्रस्ताव की आवश्यकता महसूस की जाती है तो आगामी बोर्ड बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाए।



- 9- पटेलनगर ए ब्लॉक में स्थित लोकल शॉपिंग भूखण्ड को आवासीय में परिवर्तन के सम्बन्ध में। यह निर्णय लिया गया कि पटेलनगर योजना के ए ब्लॉक में कनविनियंट शॉपिंग सैन्टर हेतु आरक्षित भूखण्ड को पटेलनगर के सैक्टर की व्यावसायिक दर पर एक मुश्त भुगतान किए जाने पर नगर निगम को विक्रय कर दिया जाए।
- 10- गाजियाबाद नगर में फ्लाई ओवर, रोड ओवर ब्रिज एवं ग्रेड सैपरेटर्स बनाये जाने के सम्बन्ध में। निम्न 5 कार्यो को वर्ष 2003-04 व 2004-2005 में प्राथमिकता पर निर्मित किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी :-
- 1- मोहननगर रेल ओवर ब्रिज का निर्माण लागत रू0-6.0 करोड (अवस्थापना निधि से)
 - 2- कैनिलवर्थ चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण लागत रू0 15.0 करोड
 - 3- हापुड रोड व जी0 टी0 रोड के टी जंकशन पर ग्रेड सैपरेटर का निर्माण लागत रू0 07.0 करोड
 - 4- मेरठ तिराहे को एन0एच0 -24 को मिलाने वाले प्रस्तावित लिंक रोड व एन0एच0 -24 के टी जंकशन पर ग्रेड सैपरेट का निर्माण लागत रू0 07.0 करोड
 - 5- राजनगर ए0एल0टी0 के सामने से जाने वाली मास्टर प्लान रोड (जो मेरठ रोड से मिलती है) पर गाजियाबाद मेरठ रेलवे लाईन पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण लागत रू0 15.0 करोड।

अवशेष कार्यो की उपयोगिता एवं प्राथमिकता के संबंध में



राइट्स/आई.आई.टी. दिल्ली जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं से अध्ययन कराकर धन की उपलब्धता के आधार पर निर्माण हेतु अवश्यकतानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि चूँकि मोहननगर के फ्लाई ओवर से उ०प्र० आवास विकास परिषद की वसुन्धरा योजना के निवासी भी लाभान्वित होंगे, अतः व्यय होने वाली धनराशि में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद का भी अंशदान प्राप्त किया जायें।

11— इन्दिरापुरम योजना के स्वर्णजयन्तीपुरम पार्क के सौन्दर्यीकरण एवं विकास के सम्बन्ध में।

आगामी बैठक में वित्त-पोषण व रख-रखाव विवरण के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

12— गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रापर्टी मैनेजमेंट साफ्टवेयर के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव वापिस लिया गया।

13— प्राधिकरण की योजनाओं का लैण्ड आडिट सर्वे कराये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा सेटेलाईट इमेजनरी सिस्टम हैदराबाद द्वारा सम्पूर्ण नगर का सर्वे कराया गया है। अतः नगर निगम द्वारा पूर्व में किए गए सर्वे को भी देख लिया जाए तदोपरान्त आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

8
JPSK

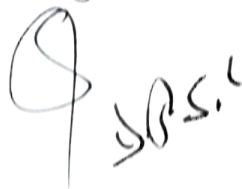
- 14- गढमुक्तेश्वर में भूमि अर्जन के सम्बन्ध में ।
प्रस्ताव के अध्ययन के लिए निम्न समिति गठित की जाती है एवं समिति के निष्कर्ष के उपरान्त प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाए :-
1- जिलाधिकारी-अध्यक्ष
2- सचिव
3- अधीक्षण अभियन्ता
- 15- ग्राम मोरटा, रईसपुर, ढरगल, महीउद्दीनपुर, मैनापुर, हरसांव, सदरपुर की 1000 एकड़ भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में ।
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। योजना की तकनीकी एवं वित्तीय वायविलिटी का परीक्षण उपाध्यक्ष द्वारा करा लिया जाये।
- 16- ट्रान्सपोर्ट नगर योजना विकास हेतु ग्राम बौझा एवं घूकना के अर्जन प्रस्ताव निरस्त करने हेतु।
प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
- 17- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन/ वर्कचार्ज कर्मचारियों को वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव शासन को संस्तुति सहित अग्रसारित किए जाने का निर्णय लिया गया।
- 18- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन/ वर्कचार्ज /संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु उपरान्त उनके आश्रित को प्राधिकरण में रखे जाने विषयक।
प्रस्ताव स्थगित किया गया एवं शासनादेश सहित अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

10

- 19क श्री अजयपाल सिंह, दैनिक वेतन लिपिक की पत्नी के ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान विषयक। प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
- 19ख श्री प्रतोष कुमार शर्मा, अवर अभियन्ता के पिता के ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान किये जाने विषयक। प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
- 19ग- श्री एच0के0सिंघल, अवर अभियन्ता की पुत्री के ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान किये जाने विषयक। प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
- 20- विजयनगर पुर्नवास योजना (सैक्टर-11 व 12) में झुग्गीवासियों का आवंटित भूखण्डों पर ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अगटित समिति की रिपोर्ट आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाए।
- 21- कौशाम्बी योजना में रियायती दर पर रजिस्ट्री हेतु समय वृद्धि हेतु प्रस्ताव। प्रस्ताव स्वीकार किया गया, किन्तु प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 23-6-2003 में प्रदत्त सुविधा को दिनांक 29-2-2004 तक ही प्रदान की जाए।
- 22- संजयनगर योजना में रिक्त भवनों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार किया गया कि संपत्तियों का निस्तारण मार्च 2004 तक कर दिया जाये।



- 23- शास्त्रीनगर, लाजपतनगर अपार्टमेंट मय गैराज व राजेन्द्रनगर के रिक्त भवनों को नीलामी द्वारा बेचे जाने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार किया गया कि संपत्तियों का निस्तारण मार्च 2004 तक कर दिया जाये।
- 24क किराये की सम्पत्तियों के निस्तारण की सीमा दिनोंक 31-3-04 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
- 24ख भवन संख्या एन-80 संजयनगर सैक्टर-23 जी0एम0पी0 को अमितव्ययी घोषित करने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
- 24ग संजयनगर योजना के अन्तर्गत एन-ब्लाक में स्टाफ के लिए निर्धारित मूल्य पर भवन संख्या एन-90 कय करने के सम्बन्ध में। इस प्रकरण पर वर्तमान शासनादेश व प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनोंक 23-6-2003 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुसार परीक्षण कर निर्णय लिए जाने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
- 25- कुरसैला बिल्डर्स को वैशाली योजना में आवंटित ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड सं0-21 पर देयता के सम्बन्ध में। इस प्रस्ताव पर पहले वित्त नियंत्रक सचिव के माध्यम से सुरपष्ट आख्या उपाध्यक्ष को प्रेषित करेंगे एवं तदोपरान्त प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
- 26- श्री शिरडी साई दिव्य ज्योति को आवंटित भूखण्ड जो निरस्त किया गया था, की बहाली प्रस्ताव स्वीकार किया गया, परन्तु बकाया धनराशि की वसूली हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये भुगतान विवरण के अनुसार भुगतान



12

विषयक।

सुनिश्चित करने का शपथ-पत्र, संस्था से लेकर भूखण्ड का आवंटन पुर्नजीवित किया जाये।
प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

27- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रोग्रामर के पद पर कार्यरत श्री अतुल शर्मा का विनियमितीकरण किये जाने विषयक।

28- श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल भूखण्ड स्थित नीति खण्ड-3 इन्दिापुरम पर भुगतान विवरण में भुगतान में विलम्ब एवं तदनुसार ब्याज को माफ करने के सम्बन्ध में।

यह निर्णय लिया गया कि पहले आवटी को 15 दिन का नोटिस धनराशि जमा किए जाने व धनराशि जमा न किए जाने की दशा में आवंटन निरस्त करने का भेजा जाए। तदोपरान्त आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

29- रिट याचिका सं० 54927 / 2002 मै० खेमका स्टूअर्स लेजर लि० बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के सम्बन्ध में।

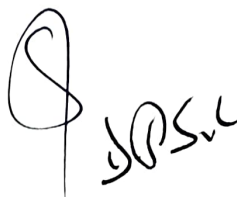
प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

30- भूखण्ड सं० ए-309 व 309ए सूर्यनगर गाजियाबाद के पास रिक्त भूमि 131.81 व०मी० श्रीमती शैलकुमारी सिंह को आवंटन के विषय में।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

31- परमवीर चक्र, गोल्ड मैडल पाने वाले सैनिक

प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।



अधिकारियों / कर्मचारियों और खिलाड़ियों को रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में।

- 32— उत्तर प्रदेश विधान सभा / विधान परिषद सदस्यों को प्राधिकरण योजना में भूखण्ड आरक्षित करने के सम्बन्ध में।

यह निर्णय लिया गया कि यह सुविधा केवल वर्तमान सदस्यों को ही दी जाए और उनसे यह वचनवद्धता (अन्डरटेकिंग) भी ले लिया जाए कि उन्हें पूर्व में उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद/उ.प्र. के किसी प्राधिकरण से भवन/भूखण्ड का आवंटन शासनादेशानुसार प्राथमिकता पर नहीं हुआ है।

- 33— खसरा नम्बर-781,782, 776, 2524 (क) ग्राम डासना मसूरी गाजियाबाद में जमियत कालिज आफ फार्मसी एण्ड एलाईड साईन्सेज के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव वापिस लिया गया।

- 34— भवन संख्या बी-65HIG डूप्लैक्स संजयनगर के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

- 35— हरित क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में नीति।

शासन स्तर पर नीति निर्धारण विचाराधीन है। अतः प्रस्ताव स्थगित किया गया।

- 36— प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्कूल भूखण्डों के आवंटन हेतु नियम व शर्तों के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। शासन स्तर से ब्याज सम्बन्धी जानकारी पत्र के माध्यम से प्राप्त कर ली जाए।


J.P.S.C.

- 37— प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित सामुदायिक केन्द्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में।
- 38— विभिन्न योजनाओं में पेट्रोल पम्प हेतु रिक्त भूखण्डों को नीलामी द्वारा आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।
- 39— प्राधिकरण की वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 की बैलेंस शीट अनुमोदन हेतु।
- 40— गाजियाबाद महायोजना 2021 (प्रारूप) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
- 4 सामुदायिक केन्द्रों (कौशाम्बी, कविनगर, शास्त्रीनगर एवं पटेलनगर सामुदायिक केन्द्र) को छोड़ते हुए शेष सामुदायिक केन्द्रों का हस्तान्तरण नगर निगम को रखरखाव हेतु दे दिया जाए।
- प्रस्ताव स्वीकार किया गया। पेट्रोल पम्प के भूखण्डों के निस्तारण हेतु व्यवसायिक दर को आरक्षित दर मानते हुए भूखण्डों की नीलामी द्वारा निस्तारित किया जाए। यह भी जांच कर ली जाये कि जोनिंग रेगुलेशनस के अनुसार अनुमन्य उपयोग हो।
- कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवाओं को आवंटन शासनादेशों के प्राविधान के अनुसार किया जाये।
- प्राधिकरण की वर्ष 2000-01, 2001-2002 व 2002-2003 की बैलेंसशीट इस निर्देश के साथ अनुमोदित की गयी कि सेविंग बैंक एकाउण्ट में जमा अतिरिक्त धनराशि का शीघ्र फिक्स्ड डिपोजिट कराया जाये। अथवा अन्य लागू की गयी क्रिया जाये।
- गाजियाबाद महायोजना 2021 (प्रारूप) का प्रस्तुतीकरण किया गया तथा बोर्ड द्वारा प्रारूप का अनुमोदन किया गया एवं उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत महायोजना 2021 की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाए। विशेषज्ञों से भी महायोजना प्रारूप पर सुझाव आमंत्रित

कर लिये जायें।

- 41— गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार कराये गये विजन स्टेटमेंट 2021 का प्रस्तुतीकरण व अनुमोदन।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार कराए गए विजन स्टेटमेंट 2021 का प्रस्तुतीकरण किया गया एवं प्रस्ताव स्वीकार किया गया। साथ ही एक्शन प्लान तैयार करने हेतु निर्देश दिए गए जिससे कि विजन स्टेटमेंट के अन्तर्गत दिए गए प्रस्तावों को शीघ्रता से लागू किया जा सके।
- 42— प्राधिकरण में एक नग इण्डिका कार क्रय करने के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
- 43— उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवासीय क्षेत्र में पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।
शासन स्तर पर नीति निर्धारण विचाराधीन है। अतः इसे स्थगित किया गया।
- 44— गाजियाबाद महायोजना 2021 तथा मोदीनगर महायोजना-2001 में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/ उपयोगों की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव पर चर्चा की गई, शासन द्वारा समय समय पर जो शासनादेश जारी किए गए हैं, उनके अन्तर्गत भी उक्त प्रस्तावों का पुनः परीक्षण कर लिया जाए एवं आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
- 45— प्राधिकरण में ई0डब्लू0एस0 वैशाली योजना में समर्पण/ निरस्तीकरण के फलस्वरूप रिक्त हुए
प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

भवनों को मूल्यांकन हेतु
ब्याज की गणना अवधि के
पुनरीक्षण हेतु प्रस्ताव।

- 46— श्रीमती सुधा गुप्ता का
परिवर्तन शुल्क माफी के
सम्बन्ध में। प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
- 47— भूखण्ड संख्या-9,10,10ए
व 10बी प्रताप विहार
शिक्षक सहकारी आवास
समिति को (सामुदायिक
एवं शिक्षक भवन) पर देय
लैवी भूउपयोग परिवर्तन
की तिथि तक प्राप्त करने
व इसके पश्चात की लैवी
माफ करने तथा 5 वर्ष का
निर्माण हेतु समय प्रदान
करने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
- 48— भूखण्ड सं0-आर-171
नन्दग्राम पर देय
चौकीदारी शुल्क माफ
करने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
- 49— महाविद्यालय श्रेणी के दो
विद्यालयों का मानचित्र
स्वीकृत किये जाने
विषयक। प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक हेतु
स्थगित किया गया।
- 50— बिन्सार कोआपरेटिव
सोसायटी को इन्दिरापुरम
में अभय खण्ड-4 में
मौडयूल-1 को जारी
भुगतान विवरण दि० दिनांक 15-3-2004 तक समस्त देय
धनराशि जमा करने की शर्त पर
प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

 J.P.S.R.

11-8-99 से
31-1-2004 तक
अक्टूबर-1999 में जारी
भुगतान विवरण में प्रेषित
शर्तों के अनुसार भुगतान
विवरण बढ़ाने के सम्बन्ध
में।

51- राजेन्द्रनगर एवं शालीमार
गार्डन कालोनी में 500
वर्ग मीटर से बड़े भूखण्डों
पर अतिरिक्त चौथी
मंजिल की स्वीकृति के
सम्बन्ध में।

पुनः परीक्षण कर लिया जाए। यदि
शासनादेश में किसी परिवर्तन की
आवश्यकता हो तो उस पर भी विचार
कर शासन को प्रेषित किया जाए एवं
पूर्ण औचित्य के साथ आगामी बैठक
में प्रस्तुत किया जाए।

52- स्ववित्त पोषित आधार पर
थोक विक्रेताओं की मार्बल
मार्केट के विकास के लिये
प्रस्ताव।

सभी प्रकार के भवन निर्माण सामाग्री
के मार्केट के विकास के लिए प्रस्ताव
स्वीकार किया जाता है। तदोपरान्त
प्लानिंग एवं डिजाईनिंग करके अलग
अलग मार्केटिंग कॉम्प्लैक्स बनाए
जायें।

53- गोविन्दपुरम योजना के
ए-ब्लाक स्थित स्कूल की
भूमि पर जा रही हाईटेंशन
लाईन के नीचे की भूमि
का भूउपयोग स्कूल से
ग्रीनवर्ज किये जाने के
सम्बन्ध में।

यह निर्णय लिया गया कि पहले निम्न
कमेटी गठित कर प्रकरण की जाँच
कर ली जाए एवं तदोपरान्त बोर्ड
बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए
:-

- 1-श्रीमती सुनिष्ठा सिंह-अध्यक्ष
- 2-नगर आयुक्त-सदस्य
- 3-मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक
-सदस्य



5/8/14

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।



(श्याम सिंह यादव)
सचिव



(डी०पी० सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित



23.02.04.

(जय शंकर मिश्र)

अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण/
सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ